राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] चौदहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का छठा दिवस [संख्या : 4

बुधवार,

16 जुलाई, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोतर

श्री अध्यक्ष: सबको प्रणाम।

प्रश्नकाल। श्री जगदीश नारायण। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++

श्री अध्यक्ष: यह है कि आप विराज जाइये। प्रश्नकाल में डिस्टर्ब मत कीजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++

श्री अध्यक्ष: मैं आपको यह कह रहा हूं कि आप यह बात एक घण्टे बाद भी कह सकते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++

श्री अध्यक्ष: एक घण्टे में कोई आसमान नहीं टूट सकता। सबका है। प्रश्नकाल चलने दीजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++

श्री अध्यक्ष: मैं कह रहा हूं कि प्रश्नकाल चलने दीजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): +++

श्री अध्यक्ष: मैं कह रहा हूं कि प्रश्नकाल चलने दीजिये। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: जो बात एक घण्टे बाद भी कही जा सकती है, उसको लेकर आप प्रश्नकाल में बाधा डाल रहे हैं। प्रश्न काल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप पूछिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान) आप बैठिये। आप बैठिये। मैं आपको नाम से पुकारूंगा। आप प्रश्न काल के बाद, यही बात एक घण्टे बाद भी कह सकते हैं। मैं आपको अलाउ करता। मैं आपको नाम से पुकारूंगा। आप बैठिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायकगण, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण काल होता है और एक घण्टे के इन्तजार के बाद भी जो बात कही जा सकती है, उस बात को लेकर प्रश्नकाल के चालू करने में बाधा डालने को मैं अलाउ किसी को नहीं करूंगा। यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) ।

जमवारामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने की कार्य योजना

26. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमवारामगढ़ (जयपुर) में दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2012 तक कितने-कितने मरीज किस-किस रोग के उपचार हेतु आये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार जन हित में उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, (1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमवारामगढ़ (जयपुर) के आउटडोर में दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2012 तक उपचार हेतु आये मरीजों का रोग के अनुसार एवं वर्षवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमवारामगढ़ के आउटडोर में आये मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमवारामगढ़ (जयपुर) में वर्तमान में 50 शय्याएं स्वीकृत हैं। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृत शय्याओं की वर्ष 2013 में 43.72 प्रतिशत उपयोगिता रही है। इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमवारामगढ़ (जयपुर) को 50 से 75 शैयाओं में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष जी, अभी आप बड़ा गुस्सा कर रहे थे। मेरे पर तो कुदृष्टि नहीं है? पर मामला बहुत गम्भीर है। आर पी एस सी का चेयरमैन उसमें हो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। मैंने एक बात कही है, प्रश्न काल के बाद भी यह मामला उठाया जा सकता है। क्या अभी उठाने से, एक घण्टे इन्तजार करने से, क्या आसमान फट जायेगा? (व्यवधान) खींवसर से आने वाले माननीय विधायक जो कुछ बोले, उस सबको एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये। (व्यवधान) डांटना भी पड़ेगा और बाहर भी निकालना पड़ेगा, यदि आप इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे तो। (व्यवधान) बैठिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जमवारामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वह केन्द्र है, वैसे तो मैं मंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं, पर थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में यह पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है और इसका 1989 में पी एच सी से सी एच सी में क्रमोन्नयन हुआ है और 1989 के बाद में 2010 और 2011 में इसको एफ आर यू बनाया गया है। उसके बाद में आठ डाक्टर्स की संख्या हुई थी। 2013 में एक दंत डाक्टर होने के बाद, नौ डाक्टर इसमें लग गये थे। उसके बाद में बच्चों का डाक्टर भी आ गया, एक महिलाओं से सम्बन्धित डाक्टर आ गया। कुल मिलाकर यह डाक्टर्स की व्यवस्था ठीक है, बिल्डिंग की व्यवस्था ठीक है और मरीजों की दिन-प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है।

(श्री जगदीश नारायण)

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा और उनको याद दिलाना चाहूंगा कि 1996 में आप वहां गये थे और महिला वार्ड का आप उद्‌घाटन भी करके आये थे। वही अस्पताल है। इसलिए इस अस्पताल को रेफरल अस्पताल बनाने के लिए मैं करबद्ध निवेदन करता हूं। क्योंकि मैं भी पब्लिक का दूत हूं और राजा के सामने आकर याचना कर रहा हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी याचिका पूरी हो, मुझे मेरी झोली में यह अस्पताल जरूर मिले, ऐसी मेरी प्रार्थना है और मुझे भरोसा है कि राठौड़ साहब जरूर देंगे। मुझे पूरा भरोसा है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, सकारात्मक जवाब दीजिये। याचिका की है इन्होंने, बढ़िया जवाब दीजिये इनको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में कहा था कि वर्तमान में जो स्वीकृत बेड वहां हैं, उनका उपयोग भी 43.72 परसेंट हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, इसके लिए भारत सरकार ने मापदण्ड बना रखे हैं। भारत सरकार के मापदण्ड के अनुसार, एक लाख की जनसंख्या पर एक रेफरल चिकित्सालय होता है और जमवारामगढ़ में जो जनसंख्या है, वह है 2.85 लाख; तीन रेफरल अस्पताल की आवश्यकता है और चार खुले हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें शक नहीं कि यह 50 बेडेड हास्पिटल है, पर इसमें शय्याएं अभी 31 ही लगी हुई हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि ये जो 31 शय्याएं लगी हैं और 50 बेडेड हास्पिटल में जो 19 शय्याएं वहां नहीं हैं, उनको हम एक महीने में लगवा देंगे और वहां की सारी आवश्यकताओं को देखते हुए, वहां अच्छी लोगों को चिकित्सा सुविधा मिले, इसका प्रबन्ध सरकार निश्चित तौर पर करेगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे? (व्यवधान) यह जवाब आ गया है।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट। श्री केसाराम चौधरी।

प्रदेश में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने हेतु कार्य योजना

27. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री केसाराम चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षक अध्यापन कार्य नहीं कर, विभिन्न विभागों तथा शिक्षा विभाग के कार्यालयों में भी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं? यदि हां, तो पाली जिले में ऐसे कितने शिक्षक हैं, जो प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त करने तथा प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों का एकीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि नियमों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान नहीं है? यदि हां, तो शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर किसके आदेश से लगाया गया? क्या सरकार इस सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षक, शिक्षा विभाग की विभिन्न परियोजनाओं, यथा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आदि में प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य विभागों में शिक्षा विभाग की अनापत्ति एवं राज्य सरकार की अनुमति से शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है।

पाली जिले में प्रतिनियुक्त कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट 'क-1' तथा 'क-2' पर संलग्न है।

(2) शिक्षा विभाग की विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत शिक्षक शिक्षा से सम्बन्धित कार्य ही सम्पादित कर रहे हैं। अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों की समीक्षा कर गुणावगुण के आधार पर प्रतिनियुक्ति समाप्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों का एकीकरण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। राजस्थान सेवा नियमों में प्रतिनियुक्ति का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में द्वितीय श्रेणी अध्यापक, श्यामलाल का मूल पदस्थापन बोरनेड़ी है। उसकी प्रतिनियुक्ति कहां पर की गई? और क्या इसकी प्रतिनियुक्ति करने वाला अधिकारी सक्षम था या नहीं? अगर नहीं था, तो उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? मैं यह मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न का जवाब आ जाये, फिर आप।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्यामलाल, वरिष्ठ अध्यापक, बोरनेड़ी को जिला साक्षरता अधिकारी, द्वारा ब्लाक कार्डिनेटर, सोजत के पद पर लगाया गया है। यदि यह सही है और यदि लगाने वाला अधिकारी सक्षम नहीं है, तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कठोर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: जैतारण से आने वाले माननीय विधायक, पूरक प्रश्न कीजिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उसके खिलाफ में क्या कार्यवाही करेंगे, अगर वह सक्षम नहीं है?

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अगर वह सक्षम नहीं है तो कठोरता से कार्यवाही की जायेगी और यह श्यामलाल, जो अभी आपने बताया कि लगा हुआ है, ब्लाक कार्डिनेटर, तो उसको बोरनेड़ी वापस मूल विभाग में भेजा जायेगा।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आज राजस्थान में व्याख्याताओं के पद हजारों की तादाद में रिक्त पड़े हैं और ऐसे व्याख्याता जो अंग्रेजी और गणित के हैं और अन्य सब्जेक्ट के हैं, उनको प्रतिनियुक्ति पर सर्व शिक्षा अभियान और आफिसों में लगा रखा है। क्या आप ऐसी प्रतिनियुक्तियां निरस्त करने का विचार रखते हैं? ऐसी प्रतिनियुक्तियां की हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखते हैं?

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी समानीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है और यह प्रक्रिया चलने के बाद, हमें पूरी आशा है कि कहीं पर भी कोई भी पद रिक्त नहीं रहेगा और जो प्रतिनियुक्ति की आपने बात कही, प्रतिनियुक्तियां निश्चित रूप से शिक्षक की शिक्षक के पद पर ही रहनी चाहिए, उनका जो मूल विभाग है। कहीं पर यदि किसी प्रकार की कमी आयेगी तो निश्चित रूप से उसको दूर किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: विधायक साहब। इनके बाद आप।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं हैं और फिर अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर क्यों रखा हुआ है? 'गुणावगुण के आधार पर

(श्री रमेश)

प्रतिनियुक्ति समाप्त करने' का क्या मतलब है? यदि शिक्षक अन्य विभागों में शिक्षा के अलावा काम करता है, तो शिक्षक पद पर क्यों भर्ती की गयी? कुल कितने शिक्षक राज्य भर में प्रतिनियुक्ति पर हैं और कितने शिक्षकों के रिक्त पद हैं? मंत्री महोदय बताएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। यह तो सारे राजस्थान का सवाल कर लिया आपने।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): पूरे राजस्थान का ही इन्होंने पूछा है, तो मैं आपको बता दूं कि सेकण्ड ग्रेड के 30,298 पद स्वीकृत हैं और रिक्त पद हैं 11,492; थर्ड ग्रेड के टीचर्स के पद 2,18,974 पद स्वीकृत हैं और रिक्त पद हैं 39,718; शारीरिक शिक्षकों के 10,452 पद स्वीकृत हैं और 1,017 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार से, पाली जिले में सेकण्ड ग्रेड 1,237 पद स्वीकृत हैं और 424 पद रिक्त हैं; थर्ड ग्रेड के 7,576 पद स्वीकृत हैं और 859 थर्ड ग्रेड के रिक्त हैं; शारीरिक शिक्षकों के 367 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 14 पद रिक्त हैं।

श्री अध्यक्ष: लूणी से आने वाले माननीय विधायक। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मैंने जैसा कहा कि समानीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है, यह होने के बाद शिक्षकों के पद रिक्त नहीं रहेंगे।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं यह पूछना चाहता हूं कि प्रतिनियुक्ति पर लगाते हो, तो उन पदों पर आप शिक्षकों को भर्ती क्यों करते हो? गुणावगुण के आधार पर, इसका आप मुझे मतलब समझाएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाइए, ये समझा देंगे।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): प्रक्रिया 5 साल से चल रही है। यहां यदि कहीं पर भी शैक्षणिक कार्य बाधित होगा, तो निश्चित रूप से उसको दुरुस्त किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि प्रतिनियुक्ति उन विद्यालयों से की गयी है जहां अपेक्षा के अनुरूप अध्यापक नहीं हैं और उन विद्यालयों से नहीं की

(श्री जोगाराम पटेल)

गयी है जहां अपेक्षा से अधिक अध्यापक हैं। साथ ही साथ, पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान, किसी संरक्षण से अनेक अध्यापक अपनी मनमर्जी से, चाहे वह कलक्टर कार्यालय हो, वह चुनाव कार्यालय हो, शिक्षा विभाग हो, या अन्यत्र हो, वहां बैठे हुए हैं। उन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार अध्यापक भी नहीं हैं। क्या उनकी प्रतिनियुक्ति तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर उनको मूल स्थान पर भेजने का सरकार विचार रखती है अथवा नहीं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): जैसा मैंने पहले कहा कि जहां शैक्षणिक व्यवस्था में कहीं कोई खामी आयेगी तो प्रतिनियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री देवेन्द्र कटारा।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में और डूंगरपुर जिले में प्रतिनियुक्ति से ज्यादा एक शिक्षण व्यवस्था के नाम से पूरी अव्यवस्था खड़ी हो रही है। डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में पालपादर गांव है, पिछले 5 साल से वह विद्यालय केवल रिकार्ड में चल रहा है। एक भी बच्चे का न एडमिशन हुआ है, न ही कोई वहां पर अध्यापक कार्यरत है। कागजों में पूरी तरह से सारी सुविधाएं, राज्य सरकार का खर्चा पूरी तरह से विधिवत उठाया जा रहा है।

इसी तरह से, ब्लाक शिक्षा अधिकारी, डूंगरपुर, जो कि जानता ही नहीं है और शिक्षण व्यवस्था के नाम पर एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अध्यापक जाता है। डूंगरपुर जिले का वह ग्रामीण व पहाड़ी इलाका है। वहां पर दूर क्षेत्र में कोई भी अध्यापक जाना नहीं चाहता है। शहर के आसपास ही सारे अध्यापक, जहां संख्या 10 बच्चों की है तो भी 6 अध्यापक हैं, 5 हैं तो भी 6 अध्यापक हैं। यह स्थिति है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आदिवासी इलाका है, आप इस पर गम्भीरता से जवाब दीजिए।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): गम्भीरता से विचार करेंगे। क्वेश्चन पाली से सम्बन्धित है, इसलिए डूंगरपुर के सारे आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं। यह अलग से प्रश्न है। अभी तो पाली से सम्बन्धित कोई बात है, तो पूछिए। बाकी हम देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंह।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का मामला कांग्रेस के टाइम पर बिगाड़ा हुआ है। इसको सुधारने में बहुत टाइम लगेगा। छह महीने ही हुए हैं। इसलिए इनका बिगाड़ा हुआ मामला धीरे-धीरे ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजो। श्री छोटू सिंह।

जैसलमेर जिले में अनाज भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण

28. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जैसलमेर शहर व विधान सभा क्षेत्र में सरकारी, सहकारी संस्थाओं या निजी संस्थाओं द्वारा अनाज भण्डारण हेतु कितनी क्षमता के कहां-कहां गोदाम/वेयरहाउस का निर्माण किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिले के लिए उक्त भण्डारण व्यवस्था पर्याप्त है? यदि नहीं, तो क्या सरकार जैसलमेर के नहरी क्षेत्र, चांदन, मूलाना व अन्य स्थानों में गोदाम/वेयरहाउस बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री हेमसिंह भड़ाना): (1) जैसलमेर शहर व विधान सभा क्षेत्र में अनाज भण्डारण हेतु निम्न क्षमता के गोदाम/वेयरहाउस उपलब्ध हैं:-

1. जैसलमेर में राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का वेयरहाउस, क्षमता 8,550 मै. टन; एवं
2. मोहनगढ़ में राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का वेयरहाउस, क्षमता 1,800 मैं. टन।

(2) जी हां। मासिक उठाव को देखते हुए यह क्षमता पर्याप्त है।

जी नहीं। जैसलमेर के नहरी क्षेत्र चांदन, मूलाना व अन्य स्थानों में गोदाम/वेयरहाउस बनाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में मोहनगढ़ में 3,600 मै. टन की भण्डारण क्षमता के गोदाम का निर्माण आर.डी.एफ. योजना के तहत करवाया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, आपने कहा कि वेयरहाउस उपलब्ध हैं, यदि वेयर हाउस उपलब्ध थे तो समर्थन मूल्य वर्तमान सरकार के द्वारा 24 जनवरी, 2014

(श्री छोटू सिंह)

और 9 मार्च तक लगातार चला; मूंगफली मूल्य का क्रय केन्द्र चांदन के अन्दर खुलवाया गया और व्यवस्था न होने के कारण काफी माल वहां भीगा। नैफेड की अव्यवस्था रही, राजफैड की भी अव्यवस्था रही, माल रखने को जगह नहीं थी, जबकि क्वेश्चन में यह जवाब है कि वहां पूर्णत: व्यवस्था थी। यदि व्यवस्था थी, तो 10 दिन तक माल बाहर रखा, फिर जोधपुर में व्यवस्था करनी पड़ी। उसका क्या कारण रहा?

उसके अलावा भी, जैसलमेर जिले के अन्दर नहर निर्माण हुआ और मोहनगढ़ के अन्दर 6 गोदाम बने हुए थे, जो सीमेंट के लिए बने थे। सीमेंट में यदि बरसात का थोड़ा छींटा लग जाता है तो भी खराब हो जाता है। वहां पर्याप्त व्यवस्था थी, 6 गोदाम थे, मोहनगढ़ में थे, रामगढ़ में थे; यहां तक, जो हमीरा गांव है, उसके पास में बहुत बड़े 6 गोदाम थे, लेकिन वह माल वहां न ले जाकर किसानों का माल भिगोया गया और वापस 10 दिन तक, उस क्रय केन्द्र को बंद करके जोधपुर लाया गया। इसलिए मेरा निवेदन है कि वह गोदाम होते हुए भी लापरवाही विभाग की क्यों रही? क्यों हैरेसमेंट किया गया?

दूसरा मेरा निवेदन है कि चांदन के अन्दर मूंगफली की फसल अपार होती है। अपार मूंगफली की फसल होते हुए भी, नहर में भी होती है, तो क्यों नहीं, चांदन, देलासर, इन गांवों में गोदाम बनाये जायें? क्योंकि आलरैडी इतना समर्थन मूल्य होता है, किसी का इतना उत्पादन हो जाता है, बिफोर लास्ट यीयर भी डेढ़ करोड़ की हमने मोहनगढ़ मण्डी से इस गवर्नमेंट को अर्निंग दी थी। फिर भी वहां व्यवस्था नहीं होती है। जबकि पूर्णत: वहां व्यवस्था है, लेकिन विभाग की लापरवाही से व्यवस्था नहीं हो पायी।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, कृपया इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, मंत्री महोदय से जवाब दिला देता हूं। मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जैसलमेर में पहली बार 10 साल में मूंगफली की खरीद प्रारम्भ हुई। क्योंकि बाजार मूल्य से समर्थन मूल्य अधिक होने की वजह से वहां पर मूंगफली की खरीद हुई और मूंगफली की खरीद होने के बावजूद, वहां पर जो नजदीकी जिले के अन्दर थे, जैसलमेर में खरीद करने के बावजूद, बाड़मेर, बीकानेर में स्थित, पड़ोसी जिलों के भण्डारों में उनके भण्डारण की व्यवस्था की गयी।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो धन्यवाद देता हूं कि जैसलमेर में पहली बार समर्थन मूल्य का खुला। यह किसानों के लिए लाभकारी रहा और बहुत बढ़िया चीज रही। जैसलमेर में समर्थन मूल्य का खुलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, मैं फिर धन्यवाद देता हूं कि रबी की फसल में भी समर्थन मूल्य चने का और रायड़े, दोनों का खुला, लेकिन वह भी अव्यवस्था यह रही...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जैसलमेर का विशेष ध्यान रखेंगे। आपने दो बार धन्यवाद दे दिया, अब आप विराजो। श्री प्रहलाद गुंजल। (व्यवधान) धन्यवाद दे दिया, अब और आपके लिए ध्यान रखेंगे।

श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): मंत्रीजी व्यवस्था यह करनी है, हम चाहते हैं कि जैसलमेर में गोदाम बनने चाहिए। स्टोरेज नहीं है, वेयरहाउस नहीं हैं। इसके लिए मंत्रीजी से चाहते हैं कि वेयरहाउस होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मिल लेना मंत्रीजी से। मंत्रीजी, इनकी बात सुन लेना।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): ध्यान रखेंगे और अतिरिक्त भण्डारण की व्यवस्था, प्रस्तावित, मोहनगढ़ में है।

न्यू मेडिकल चिकित्सा कालेज एवं चिकित्सालय, कोटा में चिकित्सक शिक्षकों के रिक्त पद

29. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) न्यू मेडिकल चिकित्सा कालेज एवं चिकित्सालय, कोटा में आचार्य एवं सह-आचार्य के किन-किन विभागों में कितने-कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) न्यू मेडिकल कालेज चिकित्सालय, कोटा के मनोचिकित्सा विभाग में 2 सह आचार्य एवं टी.बी. एवं चेस्ट विभाग में 3 सह आचार्य के पद रिक्त हैं।

(2) जी हां। डी.ए.सी.पी. के तहत पदोन्नति से चिकित्सक शिक्षक (सह आचार्य) उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने रिक्त पदों का जो वर्णन किया है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि हाल ही में एम.सी.आई. का औचक निरीक्षण हुआ और रिक्त पदों के कारण, विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए आरक्षित 150 सीटों में से 50 सीटें कम करने का निर्णय सुना दिया। अब तक जो एम.सी.आई. के सूचना देकर निरीक्षण हुआ करते थे, आनन-फानन में प्रतिनियुक्तियों से, डाक्टरों से अस्पताल के रिक्त पदों को भरकर, एक तरह से उधार की व्यवस्था से उस पूर्णता को दिखाया जाता था। तो यह व्यवस्था कब तक चलेगी?

माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ में एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में कोटा के अलावा 5 मेडिकल कालेज और हैं...

श्री अध्यक्ष: आपने कोटा का सवाल पूछा है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): कोटा का ही पूछ रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय। उन पांचों मेडिकल कालेजों में कोटा मेडिकल कालेज में सबसे कम शय्याएं स्वीकृत हैं और दो अस्पताल, न्यू मेडिकल कालेज, कोटा और महाराव भीमसिंह चिकित्सालय उसके अधीन कार्यरत हैं। महाराव भीमसिंह चिकित्सालय कोटा का सबसे पुराना अस्पताल है, कोटा डिविजन का सबसे बड़ा अस्पताल है। नये अस्पताल में आज भी 90 शय्याएं रिक्त चल रही हैं। लगातार एम बी एस अस्पताल, कोटा के कुछ विभागों को न्यू मेडिकल कालेज में शिफ्ट किये जाने का प्रयास होता रहा है, जबकि राजस्थान के इससे ज्यादा शय्याओं वाले तमाम मेडिकल कालेजों के अस्पताल पूर्ण कैपेसिटी में चल रहे हैं। वहां सम्पूर्ण प्रकार की स्पेशलिटी सर्विसेज उपलब्ध हैं। आप महाराव भीमसिंह चिकित्सालय के कुछ विभागों को शिफ्ट करने के बजाय, न्यू मेडिकल कालेज को पूर्ण क्षमता में चलाइये, वहां पर सुपर-स्पेशलिटी सेवाएं अलग से उपलब्ध करवाइये। आप एक अस्पताल की क्षमता को कम करके, दूसरे में शिफ्ट करके, कोटा के साथ अन्याय न करें। इस बारे में, माननीय मंत्री महोदय, आपका क्या कहना है, यह मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, उत्तर दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि प्रदेश में मेडिकल कालेजों में बड़ी मात्रा में पद रिक्त हैं। अध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, कुल मिलाकर, 1,088 पद पिछले दो वर्षों से लेकर पिछले 10 वर्षों तक, प्रोफेसर से लेकर सीनियर डेमोंस्ट्रेटर तक के रिक्त हैं। कोटा में भी पद रिक्त हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे थे कि एम.सी.आई. ने औचक निरीक्षण किया, उस औचक निरीक्षण के अन्दर कई तरह की बातें उन्होंने कही थीं; मुझे सदन को कहते हुए हर्ष है, राजस्थान के अन्दर एम.सी.आई. ने जो हमारी 1,150 सीटें थीं उनको कम करके 650 सीटें की थीं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीया मुख्य मंत्रीजी को, मुख्य मंत्रीजी खुद स्वास्थ्य मंत्रीजी से मिलीं और अभी-अभी जो हमें सूचना मिली कि हमारी सारी की सारी सीटें, जो पहले एम.सी.आई. ने कम की थीं, वे सीटें हमें वापस दे दी हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें शक नहीं कि भीमराव हास्पिटल, जो इस मेडिकल कालेज का अटैच हास्पिटल है, शुरू में जब कोटा में मेडिकल कालेज की स्थापना की बात आई थी, तब यह सोचकर न्यू मेडिकल कैम्पस बनाया गया था कि इसमें शनै: शनै: सारी सुपर-स्पेशलिटी स्थानांतरित की जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, अब तक इसमें 30 करोड़ का व्यय हुआ है। माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, थोड़े समय में, विरासत में हमें जो कुछ मिला, उसके बाद भी हमने इन छह महीनों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 227 पद, सीनियर डेमोंस्ट्रेटर के 100 आर.पी.एस.सी. से भरे; अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर के 79, सीनियर डेमोंस्ट्रेटर के 105 पद भरे; यानी, कुल मिलाकर, असिस्टेंट प्रोफेसर 306 और सीनियर डेमोंस्ट्रेटर के 305 पद भरे हैं। कोटा में भी 37 असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर डेमोंस्ट्रेटर इसी समय में लगे हैं। अभी पाइपलाइन में हमने 780 की अभ्यर्थना भेज रखी है।

मैं उम्मीद करता हूं, जिस प्रकार का फोकस हमारी मुख्य मंत्रीजी का है, इन्होंने साफ कहा कि नई चीज क्रीएट करने से पहले भी जो फैसिलिटी है, जनता के लिए, उसका पूरा लाभ मिले और इन सब पदों को हम भरें। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि कोटा मेडिकल कालेज के अन्दर न केवल सुपर स्पेशलिटी के लिए, अभी भारत सरकार ने 120 करोड़ रुपये देने की बात कही है, कोटा का मेडिकल कालेज पूर्ण रूप से चले, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। इन पदों की अभ्यर्थना हम भेज रहे हैं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जितना जल्दी हो सकेगा इन पदों को भरेंगे और कोटा के मेडिकल कालेज को सुचारु रूप से चलायेंगे।

श्री अध्यक्ष: इतना विस्तार से आ गया, और कुछ भी पूछेंगे क्या? हां, पूछ लीजिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): एक मामूली सा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि जयपुर मेडिकल कालेज में 4,354 सीट हैं, जोधपुर में 2,419 हैं, उदयपुर में 1,878 हैं, बीकानेर में लगभग 1,100-1,200 हैं और कोटा के मेडिकल कालेज के अधीन दो कालेजों में, एम.बी.एस. में 474 और न्यू मेडिकल कालेज में 470 सीट हैं। आप दोनों को पूर्ण कैपेसिटी से, सम्पूर्ण प्रकार की विशेषज्ञ सेवाओं के साथ संचालित करने के बजाय, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय की जो विशेषज्ञ यूनिट्स हैं, उनको आप 474 जिसमें सीट हैं, उसमें से हटाकर 470 वाले में शिफ्ट कर रहे हैं। मेरा जानना यह है, माननीय मंत्री महोदय सदन को यह आश्वस्त करें कि कोटा के दोनों अस्पताल, 474 वाला भी उसी क्षमता से चलेगा और 470 वाला भी पूर्ण कैपेसिटी में, सम्पूर्ण प्रकार की विशेषज्ञ सेवाओं के साथ, उसी स्थिति में चलेगा तो कोटा के साथ न्याय होगा। राजस्थान के तमाम मेडिकल कालेजों में सारे अस्पताल पूर्ण क्षमता में चल रहे हैं, कोटा के साथ व्यावहारिक दृष्टि से न्याय होना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: बढ़िया सवाल है। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भीमराव हास्पिटल कोटा का बड़ा, पुराना हास्पिटल है और निश्चित तौर पर अगर पिछले एक वर्ष में देखें तो 6 लाख 24 हजार 473 आउटडोर में पेशेंट आये थे, परन्तु मेडिकल कालेज जब बनाने की बात आई तो भीमराव हास्पिटल को वहां का अटैच हास्पिटल माना गया था। कुछ स्पेशलिटी मेडिकल कालेज की अभी वहां न्यू मेडिकल कालेज में शिफ्ट हुई हैं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि भीमराव हास्पिटल को बन्द करने की सरकार की मंशा नहीं है और उसका अधिकतम उपयोग किस प्रकार से किया जा सकेगा, वह आप सब की राय से करेंगे। पर न्यू मेडिकल कालेज के अन्दर एम.सी.आई. के इंस्पेक्शन में एक यह भी एतराज था कि इस कैम्पस को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिस तरीके से आपने बनाया, जिन-जिन सुपर स्पेशलिटी को लेकर बनाया, वहां उनको स्थानान्तरित करें।

मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, माननीया मुख्य मंत्रीजी से भी चर्चा हुई थी, आपसे बात करके हम कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें यह महसूस हो रहा है कि दोनों हास्पिटलों में दूरी है। उस न्यू मेडिकल कालेज के कैम्पस को और भीमराव हास्पिटल, दोनों का किस तरह से अधिकतम उपयोग हो सकेगा इसकी योजना बनाकर निश्चित तौर पर माननीय सदस्य को अवगत कराऊंगा।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा।

श्रीमती अलका सिंह।

देवनारायण गुरुकुल आवासीय योजना में अनियमितता की शिकायतों की जांच

30. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्तमान में देवनारायण गुरुकुल आवासीय योजना संचालित है? यदि हां, तो कब से व कहां-कहां तथा उक्त योजना का वर्षवार कुल बजट कितना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना में भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब तथा प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के निरीक्षण की क्या व्यवस्था है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) राज्य में देवनारायण गुरुकुल योजना वर्ष 2011-12 से 22 जिलों के 58 विद्यालयों में संचालित है। सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। सत्र 2013-14 से योजना में अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों को विद्यालय चयन की स्वतंत्रता दी गई है। इस योजना का वर्षवार कुल बजट निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्राप्त बजट (राशि लाखों में)
2011-12	100.00
2012-13	435.00
2013-14	900.00

(श्री कालीचरण सराफ)

(2) इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर, आवश्यकता होने पर जांच की जाती है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने आफिसर्स के द्वारा जो अपने बचाव में जवाब तैयार किया गया था, उसकी लीपापोती कर दी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह मांग करना चाहूंगी कि इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। यह एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, एस.बी.सी. के जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा दिलाने के लिए। इसका नाम जैसा दिया गया है कि गुरुकुल आवासीय योजना जिसमें, बच्चों के रहने की, खाने की और पढ़ाई की उसी जगह पर व्यवस्था होगी, पर इसमें ऐसे स्कूलों का चयन कर लिया गया है, भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है, रेवड़ियां बांटी गई हैं और ऐसे स्कूल हैं जो टीन-टप्पर में चल रहे हैं, एक कमरे में विद्यालय चल रहे हैं। वहां रहना-खाना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ाई तक की उचित व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करूंगी कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक इनके विभाग के जो अधिकारी हैं उनका इन्वाल्वमेंट इसमें है।

एक मांग मैं और करना चाहूंगी।

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आ जाए, फिर दूसरा पूरक प्रश्न कर लेना।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है। जब यह प्रश्न लगा तो मैंने इसकी पूरी जानकारी ली। इस योजना के तहत विद्यालयों के चयन में कोई विशिष्ट मापदण्ड नहीं अपनाये गये। योजना के तहत जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रवेश दिलाया गया, वे सामान्य श्रेणी के विद्यालय थे। इन विद्यालयों को किसी भी दृष्टि से उच्च प्रतिष्ठित विद्यालय नहीं माना जा सकता। इस योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता व भ्रष्टाचार की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। प्राइमाफेसी मुझे भी यह लगता है कि इसमें अनियमितता और भ्रष्टाचार हुआ है

(श्री कालीचरण सराफ)

अत: मैं इस योजना के क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय जांच की घोषणा करने के साथ ही, यह भी घोषणा करता हूं कि योजना के क्रियान्वयन हेतु नये मापदण्ड निर्धारित किये जाकर, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस योजना के तहत वास्तविक रूप से प्रतिष्ठित विद्यालयों का ही चयन हो ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी जानकारी ली है कि पिछली सरकार ने 2.7.2013 को एक आदेश निकाला, ''उपरोक्त विषय में आपके पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/... के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए अनुमोदित किया गया। इस योजनान्तर्गत एस सी, एस टी एवं एस बी सी के पूर्व में अध्ययनरत छात्रों के सम्बन्ध में उनके माता-पिता, अभिभावकों को विद्यालय चयन की स्वतंत्रता होगी। वे चाहे तो उसी विद्यालय में अध्ययनरत रह सकते हैं अथवा अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालय का चयन कर सकेंगे।'' यह जो इन्होंने लेटर निकाला, इससे योजना के तहत विद्यार्थियों को अपनी इच्छा से विद्यालय चयन की छूट देकर योजना की उपादेयता ही इन्होंने खतम कर दी। हमारा प्रयास यह होगा कि इन बच्चों को इस योजना के तहत प्रतिष्ठित विद्यालयों में ही अध्ययन का अवसर मिले, जिससे कि इस योजना की जो मूल भावना थी, उसका पालन हो सके।

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त जवाब आ गया है। और कुछ पूछना है आपको?

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): उच्च स्तरीय जांच के लिए मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगी।

एक चीज, मंत्रीजी, थोड़ा इसमें जांच करवायें कि अभी तक जो ये लाभान्वित थे, उनमें कितने वास्तविक लाभान्वित थे? क्या कोई ऐसे लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जो कि इसके पात्र नहीं हैं?

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मैंने जैसा कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जायेगी, तो उसमें सारे जितने भी मामले हैं, आपके पास और भी जो ध्यान में मामले हैं, वे दे दीजिये, उन सबकी जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

जोधपुर जिले में खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना में चयनित परिवार

31. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बाबू सिंह)

(1) क्या यह सही है कि खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को चिह्नित करने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर जिले में खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को चिह्नित कर लाभान्वित किया गया? तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना में चिह्नित योग्य व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कितने ए पी एल व बी पी एल राशन कार्डधारी पंजीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या वर्ष 2012 से मई, 2014 तक विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के सभी राशन कार्डधारियों को नियमानुसार राशन सामग्री वितरित की गई है? यदि हां, तो प्रत्येक कार्डधारी को कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के डीलरों के विरुद्ध उपभोक्ताओं द्वारा अनियमितताएं सम्बन्धी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं? यदि हां, तो किन-किन डीलरों के विरुद्ध व कब-कब एवं सरकार द्वारा प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री हेमसिंह भड़ाना): (1) जी हां। खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थी को चिह्नित करने के मानदण्डों (समावेशन एवं निष्कासन) की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जोधपुर जिले में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभान्वित किये गये व्यक्तियों का तहसीलवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	नाम तहसील/पंचायत समिति	चिह्नित लाभान्वितों की संख्या
1.	लूणी	2,15,905
2.	मण्डोर	2,86,582
3.	बावड़ी	1,42,417
4.	जोधपुर शहर	8,39,252
5.	बालेसर	2,40,827

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

क्र.सं.	नाम तहसील/पंचायत समिति	चिह्नित लाभान्वितों की संख्या
6.	बाप	2,29,268
7.	भोपालगढ़	1,55,352
8.	पीपाड़	1,57,949
9.	औसियां व तिंवरी	2,52,784
10.	फलौदी व लोहावट	3,03,521
11.	शेरगढ़	2,00,433
12.	बिलाड़ा	1,33,878

(3) जी नहीं। उक्त योजना में चिह्नित पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है।

(4) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में 53,498 ए पी एल व 12,222 बी पी एल, 2,593 स्टेट बी पी एल, 2,600 अन्त्योदय एवं 520 अन्नपूर्णा राशन कार्डधारी पंजीकृत हैं।

(5) जी हां। यह सही है कि वर्ष 2012 से सितम्बर, 2013 तक विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के सभी राशन कार्डधारियों को नियमानुसार राशन सामग्री वितरित की गई है। ए पी एल राशन कार्डधारियों को 10 किलोग्राम आटा, बी पी एल तथा स्टेट बी पी एल राशन कार्डधारियों को 25 किलोग्राम गेहूं, अन्त्योदय कार्डधारियों को 35 किलोग्राम गेहूं एवं अन्नपूर्णा राशन कार्डधारियों को 10 किलोग्राम गेहूं प्रति राशन कार्ड प्रति माह दिया गया। बी पी एल एवं अन्त्योदय कार्डधारियों को 500 ग्राम प्रति कार्ड लेवी चीनी तथा बिना गैस कनेक्शनधारी कार्डधारियों को 2.8 लीटर केरोसीन प्रति कार्ड प्रति माह वितरण किया गया।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2013 से बी पी एल व स्टेट बी पी एल कार्डधारकों को न्यूनतम 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति कार्ड प्रति माह, अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति कार्ड प्रति माह तथा अन्य पात्र परिवारों को खाद्यान्न वितरण करवाया जा रहा है।

(6) उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के डीलरों के विरुद्ध उपभोक्ताओं द्वारा अनियमितताएं सम्बन्धी दर्ज शिकायतों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, खण्ड-6 के अनुसार, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इस प्रणाली में शिकायतों में अनियमितताएं, गबन, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी के मामले उजागर हुए हैं। क्या सरकार इस व्यवस्था को सुधारने में, कालाबाजारी को, गबन को, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ पैटर्न लागू करने या कोई प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि रखती है, तो किस प्रकार? इसको स्पष्ट करिये।

प्रश्न-2, खण्ड-3 में आपने बताया कि खाद्य सुरक्षा में पात्र व्यक्तियों को पूरी सामग्री मिल रही है, जबकि पूरे जोधपुर जिले में जितने भी पंचायत समितिवार पात्र व्यक्ति हैं, इनको 60 परसेंट से 65 परसेंट ही सामग्री वितरित हो रही है। मेरे यहां दो-तीन पंचायतों का विवरण आपको देना चाहूंगा। खिरजा खास में 915 पात्र व्यक्तियों को 45 क्विंटल 75 किलो गेहूं मिलना चाहिए था, जो 30 क्विंटल ही मिल रहा है। गढ़ा में 2010 पात्र व्यक्ति हैं, 103 क्विंटल मिलना चाहिए, मार्च, 2014 में 33 क्विंटल ही मिला, अप्रैल में 11 क्विंटल, मई में 62 क्विंटल, जून में 75 क्विंटल। डहरिया में 2,426 पात्र व्यक्ति हैं, 121 क्विंटल मिलना चाहिए था, जो 77 क्विंटल मिल रहा है। यह पूरे जोधपुर जिले में या राजस्थान में भी हो सकता है, जितने पात्र व्यक्ति हैं, उनको 60-65 परसेंट सामग्री ही मिल रही है। तो क्या सरकार कम सामग्री की जांच कराकर पूरी सामग्री दिलवाने का विचार रखती है? इसको स्पष्ट करिये।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बिलकुल सही फरमाया है कि इसमें खामियां हैं। उसके अध्ययन के लिए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात हो, चाहे और जो भी स्टेट हों, जिनकी अच्छी व्यवस्था पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपभोक्ता को मिल सके, उस पर हम अध्ययन करेंगे।

दूसरा, इन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री जोधपुर जिले के अन्दर, अन्य तहसीलों में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नहीं मिल रही है। इस बात को हम स्वीकार करते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, 4.7.2013 को केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया और जिसको लागू करने की अवधि 365 दिन थी, जो कि 4.7.2014 को लागू होना चाहिए था। पूर्ववर्ती सरकार ने चुनावी लाभ लेने के लिए आनन-फानन में 2.10.2013 को यह खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर दिया और उसके अन्दर जो चयन व्यक्ति होने चाहिए

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

थे, मैं पूरे राजस्थान के सन्दर्भ में बात करूं, 53 परसेंट आबादी अरबन एरियाज की और 69 परसेंट रूरल आबादी को कंसिडर किया गया था। उसके विरुद्ध 446 लाख यूनिट हमको चाहिए थीं। जबकि यहां इन्होंने पात्र व्यक्तियों का चयन नहीं करके, अपने लाभ लेने के लिए, पूर्व सरकार ने, सरपंचों ने और पंचायत समितियों ने जिस तरह से रेवड़िया बांटीं, उस तरह से 85 लाख यूनिट अधिक बढ़ने से अन्न की संख्या आनुपातिक रूप से कम हो गई। लेकिन हम लाभार्थियों को बिलकुल दे रहे हैं, यह जरूर है कि उसमें आनुपातिक रूप से सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: हो गया सवाल आपका।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में है कि यह अब वितरण पूरा हो जायेगा कि नहीं हो जायेगा? एक तो मैंने यह पूछा है। दूसरा, जितनी अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, गबन और कालाबाजारी के मामले हमारे आये हैं, उन मामलों में मिलीभगत से या तो जो निलम्बित दुकानें हैं, वापस बहाल हो जाती हैं, या जो शिकायत हो जाती है, उसको मिलीभगत से दबाया जाता है। उसमें आप कैसे, क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: दोनों बिन्दुओं पर जवाब दे दीजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं बता देता हूं। शेरगढ़ के अन्दर 35 प्रकरण हमारे सामने आयें, तीन प्रकरण निलम्बित हैं, एक में एफ आई आर दर्ज है और एक कंसिडरेशन में है। निश्चित ही दोनों फाइलें मैंने मंगा ली हैं और दोनों पर उच्च स्तरीय जांच की जायेगी। चाहे उसमें डीलर है, चाहे कोई अधिकारी लिप्त है, गलत हुआ, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

दूसरा, इन्होंने कहा कि इसको किस तरह से करेंगे? पात्र व्यक्तियों का चयन करने के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर टास्क फोर्स, कमेटी का गठन कर दिया गया है और उन्होंने प्रभावी तरीके से अपना काम चालू कर दिया गया है। जल्दी से जल्दी हम पात्र व्यक्तियों का चयन कर लेंगे और अपात्र व्यक्तियों को उसमें से निष्कासित की प्रक्रिया हम चालू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: चौमूं से आने वाले माननीय विधायक, श्री रामलाल शर्मा। इसके बाद आप।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार

(श्री रामलाल शर्मा)

ने इस योजना को बहुत जल्दबाजी में लागू किया और आज भी पूरे राजस्थान के अन्दर देखें, तो जो पात्र व्यक्ति हैं, इस योजना के तहत जिनको लाभ मिलना चाहिए, आज भी उन पात्र व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल रहा है और कई ऐसे व्यक्ति हैं, जो सक्षम हैं लेकिन फिर भी वे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आपके माध्यम में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस पूरी सूची की समीक्षा करवाकर, जो पात्र व्यक्ति हैं, उनका नाम जुड़वाने के लिए और जो अपात्र व्यक्ति हैं, उनका नाम हटाने के लिए आप क्या विचार रखते हैं?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैंने अभी-अभी निवेदन किया, हमने टास्क फोर्स, कमेटी का गठन कर दिया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित नहीं कर रहे हैं। सीधे ही खड़े होकर, जैसे कोई बाजार में खड़े होकर जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप मुझे सम्बोधित कीजिये। आपका ठीक एतराज है, आपका एतराज माना जाता है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको तो बोलने से मतलब है, और कोई मतलब थोड़े ही है। उनको तो यह दिखाना है कि मैं सचेतक हूं विपक्ष का, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा तो कहीं नम्बर कम नहीं हो जाये। यहां नम्बर कम नहीं होंगे। गहलोत जी हैं नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज तो आपका ही नम्बर है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है, निश्चित रूप से टास्क फोर्स, कमेटी का गठन कर दिया है राजस्थान लेवल पर, उस टास्क फोर्स, कमेटी द्वारा जिला लेवल पर अपनी इकाई, यूनिट करके पात्र व्यक्तियों का चयन करने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है और जल्दी से जल्दी इसकी प्रक्रिया चालू कर पात्र व्यक्तियों का चयन कर लिया जायेगा और पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पांच किलोग्राम पर-यूनिट और 35 किलोग्राम अन्त्योदय योजना के तहत मिलने वाली सामग्री सम्पूर्ण रूप से जल्दी दिलाई जायेगी।

श्री अध्यक्ष: लूणी से आने वाले विधायक।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मेरा प्रश्न था, जिसका जवाब माननीय मंत्री महोदय ने दे दिया है। उसके लिए तो माननीय मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि ये पात्र व्यक्तियों की जांच कराएंगे और पात्र व्यक्तियों को उपयुक्त, जो मिलना चाहिए गेहूं, या जो भी साधन वे देंगे, उसके लिए तो बहुत-बहुत आभार।

दो प्रश्न हैं मेरे। क्या सरकार जिन राशन डीलरों के विरुद्ध शिकायतें आ रही हैं, या शिकायतें विचाराधीन हैं, उनको एक निश्चित समयावधि के अन्दर निस्तारित करने का विचार रखती है अथवा नहीं? क्योंकि एक शिकायत आने के बाद, वह अपने हिसाब से उसको वर्षों तक चलाता रहता है और उसके विरुद्ध कोई निस्तारित ही नहीं होता है। दूसरा, क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लूणी में जो शिकायतें विचाराधीन हैं, राशन डीलरों के विरुद्ध, उनके निस्तारण की कोई समयावधि निश्चित कर रही है अथवा नहीं? या उनका कब तक निस्तारण करेगी?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजिए।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी राशन डीलर के खिलाफ शिकायत होने के बावजूद, या कोई विभागीय जांच कराये, चाहे औचक निरीक्षण कराये, उसकी एक समय सीमा है कि जिला रसद अधिकारी 90 दिन तक उसके लाइसेंस को, प्रपत्र को निलम्बित करते हुए उस पर कार्यवाही करता है और यह सतत प्रक्रिया के अन्दर होता है। लूणी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जितनी भी, माननीय सदस्य, जो कि अनियमितताएं कीं या किसी डीलर के खिलाफ कार्यवाही होगी, मुझको जानकारी में ला दे, उनका जल्दी से जल्दी, समयबद्ध रहते, उनका निस्तारण करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, थोड़ा इधर भी नजर...

श्री अध्यक्ष: अब इधर भी नजर दौड़ाएंगे। आप यहां नोटिफाई कर देते ना। आप बटन यहां दबा देते तो यहां आ जाता। अब इधर लगाओ आप। जहाजपुर से आने वाले माननीय विधायक, अपना बटन दबा देना, जब पूरक प्रश्न करना हो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, एक पूरक सवाल मेरा भी है।

श्री अध्यक्ष: अब बैठो आप।

श्री शंकरसिंहजी राजपुरोहित।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आहौर का सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नयन

32. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आहोर में दिन-प्रतिदिन मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो गत एक वर्ष का आउटडोर/ओ पी डी के मरीजों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर बाड़मेर, पाली एवं सिरोही जिलों के मरीज भी काफी संख्या में आते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आहोर के आउटडोर में वर्ष 2013 में आये मरीजों की माहवार संख्या का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आहोर में बाड़मेर, पाली एवं सिरोही जिलों के मरीज आते हैं।

जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आहोर में वर्तमान में 50 शय्याएं स्वीकृत हैं। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृत शय्याओं की वर्ष 2013 में 29.59 प्रतिशत उपयोगिता रही है। इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आहोर को 50 से 75 शय्याओं में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आहोर का जो सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र है, आपने भी स्वीकार किया है और विभाग की रिपोर्ट भी आई है कि बाड़मेर, पाली और सिरोही, तीनों जिलों के बार्डर पर है और तीनों जिलों के मरीज वहां पर आते हैं। हमने इस हास्पिटल को एक

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

भामाशाह के द्वारा एडाप्ट भी करवाया और उसके बाद, मतलब यू एन ए की टीम भी उसको अवार्ड देकर के गई है। इतना बढ़िया हास्पिटल चल रहा है।

इसमें आज एक भी गायनिक नहीं है। उसके बावजूद भी, आप सुविधा देंगे तो इसमें आउटडोर/इन्डोर बढ़ेगा। पिछले समय में, पिछले वर्ष में आपने ही लिखा है, 88 हजार आउटडोर हुआ है और आउटडोर इतना हुआ है तो इन्डोर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां सुविधा नहीं है। तो सुविधा के लिए हम यह हास्पिटल क्रमोन्नत मांगते हैं। पिछले समय, छह महीने में, जब से हमने भामाशाह को यह गोद दिया है, उस गोद देने के बाद आउटडोर हुआ है, 95 हजार तो इतना होने के बाद आपसे इतना निवेदन है कि एक तो यहां की एस एम ओ की जो पोस्ट है, वह खारिज कर दी पूर्ववर्ती सरकार ने, वह एस एम ओ की पोस्ट कम से कम स्वीकृत करायें, जिससे पुराना डाक्टर तो कम से कम वहां मरीज को देख सके। हमारी यहां एक भी गायनिक नहीं है, उस गायनिक को आप करिये और बाकी की सुविधाएं, जैसे भी आप करिए, करें। यह हास्पिटल जालौर जिले में, सबसे हाइएस्ट हास्पिटल ओ पी डी है वहां पर, क्योंकि वहां पर बिलकुल सुविधाएं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी करवाते हैं।

तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि इस अस्पताल में शय्याएं तो बढ़ायें और रेफरल हास्पिटल, जब भी आपकी सुविधा या योजना में आये, तो करावें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे उत्तर में खण्ड-2 में यह कहा है कि अब जितनी शय्याएं वहां हैं, उसका औसतन एक वर्ष में उपयोग 29.59 हुआ है और मैंने यह भी स्वीकार किया है कि बाड़मेर, पाली और सिरोही जिलों के मरीज आते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह भी बात सही है कि राजस्थान में बड़ी संख्या में विरासत में हमें चिकित्सकों के पद रिक्त मिले हैं। लगभग 3 हजार 201 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, यह पद रिक्त होने का एक कारण है। चुनाव नजदीक देखकर वोट की फसल काटने के लिए जो संस्थाएं खोली गयीं, प्राथमिक चिकित्सा के अन्दर खोल गए 768, पद स्वीकृत नहीं साथ में; सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल के चले गये 179, पद नहीं; उप-केन्द्र खोलकर चले गए 3 हजार 455। अब विरासत में हमें जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

व्यवस्था मिली है, उसको सुधारने में समय लगेगा। इसीलिए जो हैल्थ इंश्योरेंस पालिसी की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में अभी घोषणा की है, यह एक अनूठी योजना होगी, 69 प्रतिशत वे लोग जो चिकित्सा सुविधा के लिए चिकित्सालयों में जाते हैं, राजकीय चिकित्सालयों में जाते हैं परन्तु वहां चिकित्सक नहीं होने के कारण पूर्णत: हम सुविधा दे नहीं पाते हैं, उन सबको कवर किया गया है। इसके लिए चिह्नित हमारे चिकित्सालय होंगे। निजी चिकित्सालयों में भी जाकर वे उसका लाभ उठा पाएंगे।

मैं माननीय सदस्य, आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो पद आपने रिक्त कहा है गायनिकी का, गायनिकी पद इसमें हैं नहीं, पर इसके बावजूद भी हम इस पद का सृजन करके आपके यहां गायनिक का डाक्टर भेजने की कोशिश करेंगे। हमारी कुछ मजबूरियां हैं, परन्तु शनै: शनै: जितने चिकित्सकों के पद रिक्त हैं, उनको भरने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न। आ गया, पर्याप्त है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी खाली। यह 29 परसेंट आप जो कह रहे हो, इसका कारण है कि आज एक भी लैडी डाक्टर नहीं है। आप गायनिक विशेषज्ञ तो छोड़िए, एक भी लैडी डाक्टर नहीं है।

इसके कारण महीने में कम से कम हजार लैडी मरीज, उनको बाहर भेजना पड़ता है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इतना बढ़िया हास्पिटल और भामाशाहों के द्वारा संचालित उसमें सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। हम लोग दे रहे हैं, हमने उसमें कई सामाजिक संस्थाओं को जोड़ा है। आपके जालौर जिले का आप चैक करवा लीजिए, आप पधारिए, सफाई के मामले में देख लें और व्यवस्था के बारे में आप देख लें। जालौर जिले में सबसे टाप का हास्पिटल हमने यह तैयार करवाया है।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें शक नहीं है कि माननीय सदस्य के निर्वाचन के बाद, जितना इन्होंने उस हास्पिटल के साथ अपना सम्पर्क रखा और जितनी कोशिश करके भामाशाह को जोड़ा है...

श्री अध्यक्ष: सम्पन्न क्षेत्र है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): निश्चित तौर पर, मैं कह सकता हूं, अगर देखा जाए तो आज के समय वह उस जिले में एक तरह से आदर्श चिकित्सालय बनता जा रहा है। इसमें जो भी कोशिश सरकार की तरफ से होगी, वह निश्चित तौर से करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्याम मेहर।

टोडाभीम में विद्यालयों का समानीकरण

33. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार की प्रदेश में समानीकरण के तहत विद्यालयों को बंद करने की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के विद्यालयों को समानीकरण के तहत बंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों को व क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए समानीकरण के तहत विद्यालयों को बंद करने से रोकने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) जी नहीं।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें समानीकरण जो लिखा है, इसमें एकीकरण लिखा था, इसमें टाइपिंग में कहीं त्रुटि हुई। तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एकीकरण में टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में कितने स्कूल बंद किए जा रहे हैं? मेरे विधान सभा क्षेत्र में में ऐसी कई ढाणियां हैं जो एक किलोमीटर के अन्दर आती हैं और वे नाली और तालाब, उनके बीच में जाकर पड़ती हैं। उनको बंद नहीं किया जाए। उसकी वजह से छोटे प्राइमरी स्कूल हैं, मिडल स्कूल हैं, उनके बच्चे दूसरे स्कूलों में नहीं जा सकते। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में एकीकरण में कितने स्कूल बंद किए जा रहे हैं?

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने मेरे जवाब में कहा कि एकीकरण में कोई स्कूल बंद नहीं किया जा रहा है, एकीकरण में स्कूल को मर्ज किया जा रहा है और उसमें मैं आपको यह बताना चाहूंगा...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मर्ज का मतलब, बंद करना ही तो हुआ, साहब।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): बंद होना अलग चीज है, बंद करना नहीं हुआ।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्योंकि उस स्कूल से आप दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर देंगे...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजिए। आपने समानीकरण ही लिखा है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): गलती हो गई, एकीकरण शब्द लिखा है, टाइप में त्रुटि हुई है।

श्री अध्यक्ष: यहां तो समानीकरण के हिसाब से उन्होंने तैयार किया है जवाब।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): टाइप में त्रुटि तो आपके यहां से एक क्वेश्चन में और हुई है। मैने माड विकास बोर्ड एक क्वेश्चन में लिखा है, वह भी मुद्दा आपके सामने आएगा, उसमें 'माड' के बजाय 'माडा' कर दिया।

श्री अध्यक्ष: उसको भी ठीक कर देंगे। गलती तो होती है ना। भूल-चूक-लेनी-देनी।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मैं आपको डिटेल बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, बता दो।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा, इस मामले में बिलकुल भ्रमित न हो कि एक गांव से दूसरे गांव में स्कूल बंद किए जाएंगे, या एकीकृत किए जाएंगे। जिस राजस्व ग्राम में तीन-चार स्कूल हैं, मान लीजिए एक सेकण्डरी स्कूल है, एक सीनियर सेकण्डरी स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है और एक मिडल स्कूल है, तो हम उनको एकीकृत करेंगे और उसकी जगह एक स्कूल होगा, जो पहली से लेकर 12वीं तक और जहां दसवीं है तो वहां पहली से लेकर दसवीं तक, यह

(श्री कालीचरण सराफ)

स्कूल चलेगा। उसमें उसका मैनेजमेंट एक होगा, यानी, प्रिंसिपल यदि वहां होगा तो सारी पहली से लेकर बारहवीं तक प्रिंसिपल उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा और कहीं पर हैडमास्टर होगा तो वह उसको देखेगा। इससे क्या फायदा होगा, जैसे मान लीजिये, अभी हम बीकानेर गये थे तो वहां एक गांव में एक प्राइमरी स्कूल में पहली में दो बच्चे थे, एक प्राइमरी स्कूल में एक बच्चा था और एक प्राइमरी स्कूल में दस बच्चे थे और उनके लिए अलग-अलग टीचर। अब हम तीनों को एकीकृत कर देंगे, एक ही जगह क्लास लगेगी तो 13 बच्चों पर एक टीचर रहेगा।

आज स्थिति यह है कि प्रदेश में जो हमने सर्वे किया, उसके आधार पर 142 विद्यालय इस प्रकार के हैं कि जहां जीरो नामांकन है, जीरो एन्रोलमेंट है, एक भी बच्चा नहीं है और 251 अध्यापक वहां केवल अख़बार पढ़ने की तनख्वाह ले रहे हैं। इसी प्रकार से, एक से 15 बच्चे जहां पर हैं, ऐसे स्कूल हैं 8,164 और यहां 14,655 अध्यापक मुकर्रर हैं। इसी प्रकार से, 16 से 30 नामांकन वाले जो बच्चे हैं, ये विद्यालय हैं 19,760 और इन पर अध्यापक लगे हुए हैं 42,150 । यानी, कुल 28,013 विद्यालय इस प्रकार के हैं, जहां तीस से कम बच्चे हैं और वहां 57,056 अध्यापक लगे हुए हैं। एक तरफ तो अध्यापक एक्सेस हैं और दूसरी तरफ, आप माननीय सदस्य सब जानते हैं कि स्कूलों में छात्र हैं पर शिक्षक नहीं हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप तो यह बता दो कि इतने अध्यापक लगाये हैं।

श्री अध्यक्ष: व्यवधान मत डालिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मैं यही बता रहा हूं। तो पांच साल में राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से आपने जो शैक्षणिक अराजकता का वातावरण पूरे प्रदेश में निर्मित किया, उसको सुधारने के लिए यह आवश्यक है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडाभीम का पूछा है इन्होंने और ये भाषण दिये जा रहे हैं। केवल टोडाभीम।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): ये बीच में कहां से आ गये? (व्यवधान) जो बात है, वह वास्तविकता बतानी पड़ेगी। पांच साल में जिस प्रकार का तांडव नृत्य आप लोगों ने किया है शिक्षा विभाग में, सारी शिक्षा

(श्री कालीचरण सराफ)

व्यवस्था चौपट कर दी, उसको एक साल में बिलकुल दुरुस्त कर देंगे और फिर किसी को भी यह शिकायत नहीं रहेगी कि यहां पर स्कूल में टीचर नहीं हैं, यहां पर ज्यादा टीचर हैं। यह आपकी शिकायत दूर हो जाएगी।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से यह जानकारी चाहता हूं कि टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में कितने स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है? और मर्ज किया जा रहा है तो उसमें क्या वे पुराने भवन में ही चलेंगे या नये भवन बनाये जाएंगे?

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): देखिये, इसका भी मैं आपको क्लीयर कर दूं। कहीं पर यदि पहली से बारहवीं तक एक भवन में पर्याप्त व्यवस्था होगी, तो वहां पूरी पहली से बारहवीं तक की कक्षा चलेगी और मान लीजिये, वहां पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी, तो स्कूल अलग-अलग बिल्डिंग में चलेंगे, पर उसका एडमिनिस्ट्रेशन एक रहेगा।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): टोडाभीम का जवाब नहीं आया। टोडाभीम में कितने स्कूल मर्ज किये जा रहे हैं, मैं यह जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। और मिल लेना आप।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अभी प्रक्रिया चल रही है; कितने विद्यालय एकीकृत किये जाएंगे, यह प्रक्रियाधीन है। प्रक्रिया चल रही है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): हमें तो समय देते नहीं हैं, साहब।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आपने यह पूछा कि टोडाभीम में कितने विद्यालय एकीकृत किये जाएंगे, तो इसकी प्रक्रिया अभी चल रही है और इसकी अभी पूरी संख्या मैं आपको नहीं बता सकता, पर पांच-सात दिन में जब इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष: भिजवा देंगे आपको।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): एक सुझाव और है मेरा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब नहीं। सुझाव आप दे देना अलग से। बैठिये आप।

डा. राजकुमार शर्मा।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट में 14 तारीख को घोषणा की है कि एकीकृत विद्यालय बनाये जाएंगे। इसकी पूरी प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रियाधीन है और जल्दी ही इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा।

श्री अध्यक्ष: मिल जाएगा न। डा. राजकुमार शर्मा।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्योंकि समानीकरण, एकीकरण, इन सारी चीजों से अगर सबसे ज्यादा कोई जिला प्रभावित हो रहा है तो वह झुंझुनूं जिला हो रहा है और झुंझुनूं जिला इसलिए हो रहा है कि वहां पर शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा रहा है, शुरू से। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, अभी आपने कह भी दिया कि तांडव नृत्य कर रही थी पिछली सरकार, तो आप भी कत्थक करने वाले हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। वह इसलिए कह सकता हूं कि इन्होंने स्कूलें बंद करने का निर्णय ले लिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, सरकारी स्कूल में बच्चा क्यों नहीं आ रहा, उसका कोई कारण ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। आज आप प्राइमरी स्टेज पर स्कूलें बंद कर रहे हों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सदन के अन्दर, पांच साल के भीतर-भीतर आप बारहवीं क्लास तक की भी स्कूलें बंद करने के कगार पर आ जाओगे। उसका कारण एक ही है कि बच्चे सरकारी स्कूल में आना नहीं चाहते। उसका कारण यह है...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न कीजिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): प्रश्न ही तो बोल रहा हूं न। प्रश्न यह कह रहा हूं कि समानीकरण के नाम पर शिक्षकों का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है; धरने पर बैठे हैं शिक्षक झुंझुनूं जिले में हर तहसील हैडक्वार्टर पर; सारी की सारी शिक्षण व्यवस्था ठप पड़ी है! तो इस गतिरोध को आप समाप्त कर दो। बार-बार अख़बार के माध्यम से आप स्टेटमेंट देते हो कि मैं जल्दी कर रहा हूं, जल्दी कर रहा हूं। सारी शिक्षण संस्थाएं ठप पड़ी हैं जो भी बच्चे दो-चार हैं, वे भी निकल जाएंगे।

हमने भी उस समय, हमारे समय में भी एक बार मैंने डी ई ओ को भेजा कि उस स्कूल में ढाणी में जाओ। अध्यक्ष महोदय, आप सुन कर ताज्जुब करोगे कि जिला शिक्षा अधिकारी को ढाणी वालों ने बुला कर बैठा लिया...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): प्रश्न क्या है?

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): प्रश्न मैंने कह दिया कि समानीकरण के नाम पर जो शिक्षकों का मानसिक शोषण किया जा रहा है, तो यह सरकार कब तक करेगी? यह बता दें आप तो।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिये। भूमिका रख चुके, आप सवाल कीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने बिलकुल सही कहा। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, ये बीच-बीच में बोल रहे हैं, आप उनको बोलने दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये। उनको भी नहीं बोलने देंगे और आपको भी नहीं बोलने देंगे।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बिलकुल सही कहा, आज तक समानीकरण और एकीकरण की बात तो बहुत की जाती है और एक जबरदस्ती का हौआ खड़ा करके कि शिक्षक विरोध में हैं, क्या पता क्या हो जाएगा, और समानीकरण और एकीकरण की प्रक्रिया रुक जाती है। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा, आश्वस्त करना चाहूंगा सदन को कि इस बार एकीकरण भी होगा और समानीकरण भी होगा, पर इसमें आप थोड़ा-सा समय दीजिये। कोई भी प्रक्रिया प्रारम्भ करते हैं तो शुरू-शुरू में कई भ्रम उत्पन्न होते हैं, कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। सारी व्यवस्थाएं माकूल करके, एक महीने बाद आप मेरे से मिल लेना, फिर आप कहोगे कि वाह भई, बहुत बढ़िया काम किया।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो एकीकरण के सन्दर्भ में 4,010 व्याख्याता पाइपलाइन में हैं और 9,000 सेकंड ग्रेड के पाइपलाइन में हैं और 20,000 थर्ड ग्रेड के टीचर्स का भी रिजल्ट आना बाकी है, तो ये करीब 33,000 शिक्षक हो जाएंगे। उनका एकीकरण के आधार पर जो इन्होंने बताया है कि प्राइमरी से मिडल में सत्रह से बीस हजार को मर्ज कर देंगे, लेकिन जो अधिशेष शिक्षक बचेंगे तीस से पैंतीस हजार, उनका मंत्रीजी क्या करेंगे? क्योंकि पहले ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो टीचर्स थर्ड ग्रेड के लगे हुए हैं, उनकी कैसे व्यवस्था की जाएगी? पहला प्रश्न।

दूसरा मेरा निवेदन है कि...

श्री अध्यक्ष: एक ही प्रश्न।

श्री रमेश (सपोटरा): एक और है, साहब, स्पेसिफिक। दूसरा मेरा यह है कि जो प्रबोधक तेईस हजार हैं, उनको पद के साथ स्थानांतरित करेंगे या उनको शिक्षक मानेंगे? और, लास्ट में, एक और स्पेसिफिक है कि इस पर

(श्री रमेश)

तीस करोड़ के करीब खर्चा होगा, वह जनता पर भार आएगा। उसके बारे में भी मंत्रीजी मुझे बतायें।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि 9 हजार टीचर्स सेकंड ग्रेड के, पांच-सात दिन में उसका रिजल्ट आ जाएगा, उनकी नियुक्ति निश्चित रूप से होगी; जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर आप चार हजार बता रहे हैं, वह भी पाइपलाइन में हैं, उनका रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, और बीस हजार टीचर्स जो थर्ड ग्रेड के हैं, आपने तो एस एल पी लगा कर उनको पेंडिंग कर दिया था, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस एल पी विथड्रा करने का निर्णय राज्य सरकार ने कर लिया है और वे बीस हजार जो टीचर्स हैं, उनकी नियुक्ति भी जल्दी ही हो जाएगी। जब ये बीस और ... (व्यवधान) बात तो सुनिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप एस एल पी विथड्रा करके एस सी/एस टी/ओ बी सी का जो कोटा है, उसको काट रहे हो। आप कुठाराघात कर रहे हो।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आप बैठिये, मैं जवाब देता हूं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आपने सदन में पिछली बार मुझे कहा था कि हम एस एल पी विथड्रा नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष: लालसोट से आने वाले विधायक, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी शहर से आते हैं, गांव के लोगों का नुकसान करने के लिए इस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं। यह गांव के लड़कों के साथ अन्याय है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): विराजिये। ये बात ही नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आसन पर विराजमान हैं...

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आप पूरा जवाब सुनिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): एस सी/एस टी के लोगों के लिए जबरदस्त कुठाराघात करने जा रहे हैं। इसलिए एस एल पी विथड्रा नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में।

श्री अध्यक्ष: नहीं होने देंगे।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): बहुत अच्छा, अध्यक्षजी।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। प्रश्नकाल समाप्त। मंत्रीजी, बिराजिए।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): क्लीयर तो कर दूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): राजस्थान में भ्रांति फैलाना चाहते हैं ...(व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री भंवर सिंह एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर के संसाधनों को कम करते हुए इसका संचालन रोकने की कथित कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में; एवं
2. श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से राजकीय महाविद्यालय, जहाजपुर का संचालन रोकने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी मा. सदस्य, श्री भंवर सिंह एवं श्री धीरज गुर्जर को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आफ डाइवर्जन डैम एंड वाटर सप्लाई चैनल, खोहरामुल्ला, तहसील महवा को एन आर डी डब्ल्यू पी मद से राशि उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।
2. श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से किशनगढ़-रेनवाल में सरकारी महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।
3. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से विद्यार्थी मित्र शिक्षकों को नियमित करने के सम्बन्ध में।
4. श्री बाबूसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के ग्राम देवातु से गोगादेवजी का मंदिर, सेखाला सड़क निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।
5. श्री ओटाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिरोही में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति ठीक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6. श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से जयपुर के आसपास के कस्बों को डी एम यू ट्रेन से जोड़ने के सम्बन्ध में।
7. श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से बाड़मेर-जैसलमेर जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए पर्याप्त राशि का आबंटन कर विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में।
8. श्री संजीव कुमार, सदस्य की ओर से भादरा में उपनिवेशन तहसील खोलकर 24 चकों/ग्रामों की रि-फिटिंग का कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में।
9. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में डोडा- पोस्त के सेवन से उत्पन्न हो रही समस्या के सम्बन्ध में।
10. श्री गिर्राज सिंह, सदस्य की ओर से चम्बल साबर पाडा से बरैठा टोल तक 25 किमी के डाइमेन्सन के रोड पर ओवरलोडिंग वाहनों से ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा अवैध वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।
11. श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से बूंदी-बिजोलिया-नैनवा-लाखेरी रोड को बूंदी शहर से दूर बाइपास बनाकर निकालने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

12. श्रीमती अनिता भदेल, सदस्या की ओर से महाविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त व्याख्याताओं का समायोजन राजकीय सेवा में करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री भंवर सिंह।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, आपने एक घण्टे बाद के लिए कहा था कि एक घण्टे बाद आप उस पर बात कर लेना आर पी एस सी...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। नो। (व्यवधान) आप किसी प्रकिया के अन्तर्गत आइये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह प्रकिया ही तो है।

श्री अध्यक्ष: कोई प्रक्रिया नहीं, आप बैठिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): विधान सभा साल में 20 दिन चलती है, फिर कब आएंगे हम? बताओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जब चाहो, तब आओ, लेकिन अभी बैठिये आप। यह भंवर सिंहजी बोल रहे हैं, इनके बाधा मत पहुंचाइये आप।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

राजकीय तकनीकी विद्यालय, बीकानेर के संचालन को कथित रूप से रोका जाना

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान, तकनीकी शिक्षा के विस्तार के लिए बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय की पिछले वर्ष 2013 के बजट में खोलने की घोषणा राजस्थान की विधान सभा में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा की गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सितम्बर 2013 में अध्यादेश के जरिये बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय को स्थापित किया

(श्री भंवरसिंह)

गया था। इसके बाद, सरकार ने कुलपति, कुलसचिव व वित्त नियंत्रक के पद भी भर दिये थे। एक करोड़ से ज्यादा का बजट भी राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया था, अध्यक्ष महोदय, जिसमें से आधे से ज्यादा बजट तकनीकी विश्वविद्यालय में समय-समय पर खर्च भी कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय 21 सितम्बर 2013 से 04 जुलाई, 14 तक अस्तित्व में रहा और रोजना के कार्य भी किये गये। 4 जुलाई, 2014 को तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने एक आदेश जारी कर यह कहा है कि यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में नहीं है तथा इसके समस्त कार्यरत कर्मचारियों को हटा दिया जाए व विश्वविद्यालय की गाड़ी को मोटर गैराज विभाग, जयपुर में जमा करा दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तकनीकी विभाग के इस आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि बीकानेर के तकनीकी विश्वविद्यालय को बंद करने की तैयारी सरकार के द्वारा कर ली गई है, जबकि पिछले दिनों सरकार-आपके-द्वार-कार्यक्रम के दौरान हमारे शिक्षा मंत्रीजी जब बीकानेर आए थे तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि बीकानेर का तकनीकी विश्वविद्यालय बंद नहीं होगा तथा बीकानेर का हक किसी भी स्थिति छीना नहीं जाएगा।

इसी दौरान, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे ही सम्भाग के मंत्री चिकित्सा मंत्रीजी ने भी समाचार पत्रों के माध्यम से कई बार यह कहा है कि बीकानेर के इस तकनीकी विश्वविद्यालय को बंद नहीं करके, पूर्ण स्वरूप में बनाया जाएगा। लेकिन इन सबके बावजूद, इस विश्वविद्यालय को बंद कर बीकानेर के आम जन और युवाओं के साथ कुठाराघात किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से और शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर जिले को दिया गया तकनीकी विश्वविद्यालय, जो बीकानेर का हक है, बीकानेर सम्भाग ही नहीं, बल्कि आसपास के 15 से ज्यादा जिलों में तकनीकी विश्वविद्यालय को खोलने की मांग बीकानेर सम्भाग से लगातार आती रही थी। इस मांग को पिछली सरकार ने बीकानेर के आम जन की, युवाओं की और तकनीकी शिक्षा के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, स्वीकार किया था। तकनीकी विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से

(श्री भंवरसिंह)

चालू हो गया। लेकिन अब इस सरकार के द्वारा जो स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि बीकानेर के इस तकनीकी विश्वविद्यालय को चालू रखा जाएगा या नहीं, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि बीकानेर के इस तकनीकी विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप में चालू किया जाए जिससे कि बीकानेर का युवा, बीकानेर का आम जो विद्यार्थी है, वह तकनीकी शिक्षा में अपनी एक अलग पहचान बना सके, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बीकानेर का विकास हो सके।

मुझे आपने अपनी बात कहने का मौका दिया, उसके लिए एक बार पुन: आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पांड कर रहे हैं?

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): हां, मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी मैटर पर मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: बोलिए।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): पिछली पूर्ववर्ती सरकार के समय बीकानेर में आई एम ए के लिए व्यास कमेटी बनी थी, उस व्यास कमेटी ने बीकानेर को उचित समझते हुए आई एम ए की अनुमति दी थी...

श्री अध्यक्ष: धीरजजी, बैठिये। इनके बाद।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): लेकिन पूर्ववर्ती सराकर ने, आई एम ए में भी हमें अनुमति नहीं मिली और इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जाते-जाते एक अध्यादेश तो जारी कर दिया, लेकिन बिल पास नहीं करवाया। तो यह बीकानेर के साथ एक तरीके का अन्याय हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि...

श्री अध्यक्ष: बिराजिए, शिक्षा मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): हमारी यह वाजिब मांग है। माननीय मंत्रीजी इसका जवाब दें। इन्होंने इसकी घोषणा भी की थी, यह सही है।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी जवाब दीजिए।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): उचित मांग है, बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय खुलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ रहा है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने जाते-जाते, आनन-फानन में, चुनावी लाभ प्राप्त करने के लिए, बिना बजटीय प्रावधान के टेक्निकल यूनिवर्सिटी की घोषणा कर दी। हमने बंद करने का निर्णय नहीं किया है। 6 महीने में जो निर्णय लास्ट में जाते-जाते उस सरकार ने किये, उनकी समीक्षा के लिए मंत्रिमण्डलीय उप-समिति के पास यह मामला विचाराधीन है। इसकी समीक्षा ...(व्यवधान) बैठिये। बैठो तो सही। उसकी समीक्षा करके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): 14 तारीख को जब राजस्थान की विधान सभा में बजट पेश हुआ था, उस दिन, मंत्री महोदय, पूरा बीकानेर जिला बंद रहा है, इस तकनीकी विश्वविद्यालय के मुद्दे पर। आने वाले समय में, आप आश्वस्त करें कि यह तकनीकी विश्विद्यालय खोलेंगे या नहीं? यदि नहीं, तो बीकानेर सम्भाग का आम आदमी, जो इस तकनीकी विश्वविद्यालय का अपना हक, जो छीनने जा रही है सरकार, इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार रहेगा।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मैंने अभी अपने जवाब में कहा कि बंद करने का निर्णय नहीं किया, इसकी समीक्षा हो रही है। समीक्षा होने के बाद ही, गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया न।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने बड़ी सफाई से तो कह दिया कि इसकी समीक्षा हो रही है, बजट के बाद में समीक्षा क्या काम आएगी? क्या यह रिवाइज्ड बजट, इसमें बजट प्रोविजन रखते। (व्यवधान) गुमराह करने की...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): यह सरकार कोई एक साल के लिए नहीं है, पांच साल के लिए है। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): गुमराह न करें। बीकानेर में खोला जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): यह सरकार एक साल के लिए नहीं, पांच साल के लिए है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री धीरज गुर्जर।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): यह छह महीने के कार्य समीक्षा में लिए गए हैं, जबकि यह एक साल पहले, मार्च 2013 के बजट में यह तय हो चुका है...

श्री अध्यक्ष: भंवरसिंहजी, अब आप शांत रहें। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय खोला जाता है। तो बजट के बावजूद आप ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भंवरसिंहजी, अब आप शांत रहिए। बहुत आपने ध्यान आकर्षित कर लिया। जवाब भी आ गया। आगे और परश्यू कर लेना।

राजकीय महाविद्यालय, जहाजपुर का संचालन रोका जाना

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने सदन में यह कहा कि मंत्रिमण्डलीय समिति की समीक्षा के लिए राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार के कुछ निर्णयों को रोका गया है। मैं अपनी बात यहीं से शुरू करना चाहता हूं कि क्या एक लिस्ट में जारी ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: दो मिनट में कितनी लम्बी बात करोगे?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): एक लिस्ट में जारी कालेज और उसमें स्वीकृत पदों में से दो कालेज चालू कर दी जाएं और एक कालेज को रोक दिया जाए, तो क्या मंत्रिमण्डलीय समीक्षा समिति, वह एक–एक बिन्दु की समीक्षा करती है? उसमें स्वीकृत सभी शिक्षकों की समीक्षा करती है?

विगत दिनों, 31 अगस्त, 2013 को राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने जहाजपुर उपखण्ड के अन्दर राजकीय महाविद्यालय की घोषणा की; उसी लिस्ट के अन्दर भीलवाड़ा जिले में रायपुर और आसींद के अन्दर भी राजकीय महाविद्यालय की घोषणा की और आगे 04 सितम्बर, 2013 को उसी लिस्ट के अन्दर 14 पद जहाजपुर महाविद्यालय के लिए और 14 पद रायपुर महाविद्यालय के लिए स्वीकृत किए। लेकिन सरकार बदलने के बाद, राजनीतिक द्वेषता-पूर्वक, रायपुर और आसींद महाविद्यालय, भीलवाड़ा के अन्दर चल रहे हैं और मेरे अतारांकित प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह जवाब दिया कि जहाजपुर का जो राजकीय महाविद्यालय है, उसको हम मंत्रिमण्डलीय समिति के लिए रोकते हैं क्योंकि वह विगत छह महीने में स्वीकृत नहीं हुआ। तो फिर क्या जहाजपुर के साथ स्वीकृत अन्य कालेजों को रोकने की जिम्मेदारी इनकी नहीं थी?

जहां-जहां पर कांग्रेस के सदस्य जीते हैं। खासकर मैं भीलवाड़ा जिले

(श्री धीरज गुर्जर)

की बात करना चाहता हूं, भीलवाड़ा में तीन कालेज स्वीकृत हुए, तीनों कालेजों में एक साथ पदों की स्वीकृति हुई, भीलवाड़ा में रायपुर चल रहा है, आसींद चल रहा है, जबकि जहाजपुर जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र है, वहां पर एस.टी., एस.सी. और ओ.बी.सी. की 70 प्रतिशत आबादी रहती है, पिछले सात वर्षों से हमारी यह मांग बाकी थी कि जहाजपुर में कालेज खोली जाए। 04 अक्टूबर को जहाजपुर महाविद्यालय के अन्दर कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के रूप में मदन लाल शर्मा को ब्यावर से लगाया गया। वे आज तक जहाजपुर के अन्दर कार्यरत हैं। वे अभी तक वहां पर आते हैं, बैठते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं। लेकिन जहाजपुर महाविद्यालय के अन्दर प्रवेश प्रक्रिया रोक कर जहाजपुर के बच्चों के साथ कुठाराघात किया गया है।

इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं आपको कि प्रवेश प्रक्रिया रायपुर में चल रही है, रायपुर में एडमिशन हो गये, बच्चे पढ़ने लग गए; आसींद में चल रही है और मंत्रिमण्डलीय समीक्षा सिर्फ जहाजपुर में ही क्यों हो रही है? आसींद और रायपुर में भी होनी चाहिए थी। इसका भी, मंत्रीजी, आप बड़े सहृदय हैं, मैं आपसे सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप अपना जवाब दे दें। हमारी याचिका भी आपसे है कि राजनीतिक कुठाराघात करते हुए जहाजपुर के बच्चों के साथ आप ऐसा व्यवहार न करें।

श्री अध्यक्ष: आप सहृदयता से जवाब दीजिए।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): जवाब दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ी लम्बी-चौड़ी बात कही कि राजनीतिक द्वेषता के आधार पर हमारे यहां पर कालेज नहीं खोला।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): खोल तो दिया। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): बैठो तो सही। बीच में ही खड़े हो गये। आप बोल रहे थे, तब मैं चुपचाप सुन रहा था न। तो आप भी मेरी बात सुनिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने जाते-जाते 42 राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। उनमें से 27 महाविद्यालयों में, क्योंकि वहां छात्रों ने प्रवेश ले लिया था, छात्र पर्याप्त संख्या में थे, इसलिए उनको चालू कर दिया; 13 महाविद्यालय ऐसे थे जिनमें एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया और उसमें हमारे जो जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य हैं,

(श्री कालीचरण सराफ)

उनका जहाजपुर का महाविद्यालय भी था। तो ऐसे महाविद्यालयों को, जहां पर एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): प्रवेश प्रक्रिया ही चालू नहीं हुई।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): क्या?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): प्रवेश प्रक्रिया ही चालू नहीं हुई।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): सुनिए; सुनिए। और बजटीय प्रावधान भी नहीं था तो ऐसे महाविद्यालयों को हमने रोक लिया। उनकी समीक्षा कर रहे हैं। कहीं पर भी बच्चे यदि होंगे, तो बिना किसी राजनीतिक द्वेष के, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के वहां पर भी कालेज खोले जाएंगे।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने। (व्यवधान) ये कह रहे हैं कि जहाजपुर में बच्चों ने प्रवेश नहीं लिया, इसलिए हमने कॉलेज वहां पर बंद कर दिया। मैं यह कहता हूं कि क्या जहाजपुर में आपने प्रवेश प्रक्रिया चालू की थी? पिछले सत्र के समाप्त होने के बाद ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब पर्याप्त आश्वासन मिल गया। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): नहीं, नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वरना आज बिलकुल भूख-हड़ताल पर बैठूंगा, वेल के अन्दर। जहाजपुर कालेज आज खुलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी हैल्थ ...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): वरना मैं मरूंगा। मेरी जिम्मेदारी सदन और आपके ऊपर है। आप भी हमारे पास में से ही आते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी हैल्थ ठीक हो जाएगी, हैल्थ। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जहाजपुर के अन्दर प्रवेश प्रक्रिया चालू नहीं हुई थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं कहता हूं कि बैठना ही चाहिए आपको। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ठीक है, साहब।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपका अच्छा इलाज करवाया जाएगा। आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, स्वास्थ्य मंत्रीजी बहुत ध्यान रखेंगे।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हमारे शिक्षा मंत्रीजी आज घोषणा करें।

(श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री अध्यक्ष: आश्वासन आ गया आपका। आप उचित नहीं कर रहे हैं। आप उचित नहीं कर रहे हैं। आश्वासन आ गया, उसके बाद और मिलिये। देखो, आश्वासन आ गया। मैं भी आपकी मदद करूंगा। आप उस कुर्सी पर विराजिए। उनके आश्वासन को आगे बढ़ाने में मैं भी मदद करूंगा। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): थोड़े दिन भूखे रहोगे तो शरीर अच्छा हो जाएगा आपका।

श्री अध्यक्ष: मैं उनके आश्वासन को आगे बढ़ाने में, जहाजपुर के माननीय विधायक, आपकी मदद करूंगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप ... (व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय सदस्य, एक बार स्वास्थ्य मंत्रीजी पूरा चैक-अप करवा लेंगे, फिर बैठ जाना आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, डा. किरोड़ी लाल मीणा।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): बैठो धरने पर।

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त हो गया, आपने ध्यान खींच लिया, मैंने भी आपको आश्वस्त किया है कि मैं भी मदद करूंगा। अब, देखिए, डिस्टर्ब मत करिए। दूसरे माननीय विधायक को डिस्टर्ब मत करिए। आप विराजिये।

295 । डा. किरोड़ी लाल मीणा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

खोहरामुल्ला (महवा) को NRDWP मद से राशि की उपलब्धि

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि पंचायत समिति महवा के ग्राम खोहरामुल्ला, बाड़ाबुजुर्ग, गौहण्डी मीणा, गौहण्डी गुजर, कौण्डला, खेड़लाबुजुर्ग, तेहरा, मिल्कीपुरा, बड़ागांव, रतनपुरा, सलेमपुर, सुल्तानपुर, जलालपुर,

(डा. किरोड़ी लाल)

आदि, 13-14 गांवों में पानी की भीषण समस्या को दृष्टिगत रखते हुए विभाग ने 413.76 लाख रुपए की एक रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम खेड़लाबुजुर्ग-सलेमपुर के नाम से स्वीकृत की थी जिसमें ग्राम खोहरामुल्ला में पहाड़ की तलहटी के नीचे 9 ट्यूबवैल प्रस्तावित किये गये एवं पहाड़ की तलहटी के नजदीक स्थित खोहरामुल्ला एनिकट में पहाड़ के बाएं एवं दाएं तरफ से पानी को एकत्र कर डाला जाना प्रस्तावित है। 413.76 लाख की इस रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम में करीबन 284 लाख रुपए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को आबंटित किये गये तथा मात्र 139.00 लाख रुपए पहाड़ों का पानी फीडर निर्माण कर एनिकट में डाले जाने हेतु सिंचाई विभाग को दिये गये, जो अपर्याप्त था।

एक माननीय सदस्य: आवाज दब गयी, साहब।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): बिलकुल दब गयी, साहब।

श्री अध्यक्ष: इनकी आवाज धीमी ही रहने दीजिए। हां, माननीय विधायक।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): पूर्व सांसद, दौसा ने माननीय जलदाय मंत्री को लिखे अपने पत्रांक 147-149 दिनांक 3.2.2011 द्वारा इस राशि को अपर्याप्त मानते हुए पर्याप्त राशि दिए जाने की मांग की थी। अभी हाल ही में लालसोट विधायक ने माननीय मंत्री जलदाय विभाग को लिखे अपने पत्रांक 97 दिनांक 18.06.2014 द्वारा उक्त राशि को अपर्याप्त बताया। सिंचाई विभाग द्वारा तैयार कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आफ डाइवर्जन डैम एण्ड वाटर सप्लाई, खोहरामुल्ला, तहसील-महवा, जिला-दौसा, एनिकट का तख़मीना करीबन 243.14 लाख बताया गया है।

अत: दर्जनों गांवों को पेयजल की गम्भीर समस्या को दृष्टिगत रखते हुए, सिंचाई विभाग को एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. मद से राशि 243.13 लाख रुपए अविलम्ब उपलब्ध कराई जाए जिससे डाइवर्जन डैम का निर्माण एवं वाटर सप्लाई चैनल फार एनिकट खोहरामुल्ला का निर्माण हो सके। इसके निर्माण के बाद करीबन दो दर्जन फ्लोराइड-युक्त गांवों में स्थायी रूप से स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष: इसमें है, वही पढ़िये आप। व्यक्तिगत निवेदन नहीं। इसमें है, वह ही पढ़िये आप।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हेर-फेर ज्यादा नहीं किया। इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाए, साहब।

श्री अध्यक्ष: आपकी आदत के विपरीत हुआ है यह।

माननीय सदस्य, श्री निर्मल कुमावत।

(अनुपस्थित)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यह बात तो गोलमाजी कहती हैं। आप क्यों कहते हो?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री हनुमान बेनीवाल।

विद्यार्थी मित्र शिक्षकों का नियमितीकरण

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव, विद्यार्थी मित्र शिक्षकों को नियमित करने के सम्बन्ध में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में उल्लेख करना चाहूंगा कि सरकार द्वारा शिक्षकों की कमी एवं शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने हेतु मदरसा शिक्षक, शिक्षाकर्मी एवं पैरा-टीचर्स के पदों को सुरक्षित कर उन्हें नियमित किया गया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसी तरह विद्यार्थी मित्रों के हितों की सुरक्षा एवं शिक्षण क्षेत्र में अध्यापकों की कमी को देखते हुए, विद्यार्थी मित्रों को भी नियमित पदों पर नियुक्ति दें, ताकि विद्यार्थी मित्रों को भी राहत मिल सके तथा शिक्षा का स्तर भी बना रहे।

इस सम्बन्ध में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि विद्यार्थी मित्र पिछले सात वर्षों से अपने आपको नियमित कराने हेतु आन्दोलनरत हैं। बीकानेर में विद्यार्थी मित्रों ने लम्बा आयोजन किया। कई बार विधान सभा के सामने आन्दोलन एवं धरने-प्रदर्शन, आदि किये। पिछली सरकार द्वारा उक्त धरनों, आन्दोलनों एवं प्रदर्शनों को देखते हुए विद्यार्थी मित्रों को नियमित करने हेतु आदेश प्रदान किये गये थे लेकिन आज भी विद्यार्थी मित्र नियमित नियुक्ति पाने हेतु संघर्षरत हैं।

वर्तमान सरकार ने चुनाव से पूर्व अपने घोषणा पत्र में विद्यार्थी मित्रों को भी पैराटीचर की भांति नियमित करने का आश्वासन दिया था, परन्तु वर्तमान सरकार के सात माह के कार्यकाल के पश्चात् भी विद्यार्थी मित्र नियमित नियुक्ति पाने हेतु कतार में खड़ा है।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

माननीय उच्च न्यायालय ने भी विद्यार्थी मित्रों की मांग को जायज मानते हुए, सेवा से पृथक करने पर रोक लगाने के संदर्भ में यह निर्देश दिये थे कि सभी रिक्त पदों पर विद्यार्थी मित्रों को नियमित किया जावे।

यहां पर निम्न बातें भी उल्लेख करना चाहता हूं :-

विद्यार्थी मित्र योजना के प्रारम्भ में इन्हें 2,750 रुपये मानदेय देना तय किया था। दिनांक 13.6.2014 को बीकानेर सम्भाग में इनके महापड़ाव के समय माननीया मुख्य मंत्री ने इन्हें नियमित करने का आश्वासन दिया था, परन्तु आज दिन तक क्रियान्विति नहीं हुई। विद्यार्थी मित्र शिक्षकों को भी अन्य शिक्षाकर्मी, यथा पैरा-टीचर्स, प्रबोधक एवं मदरसा शिक्षकों की भांति नियमित करते हुए समस्त परिलाभ देने के आदेश प्रदान करने की आवश्यकता है। साथ ही, इनको कम से कम 9,100 रुपये प्रति माह मानदेय दिये जाने तथा शैक्षणिक आयोजनों में भागीदार बनाये जाने की आवश्यकता है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि विद्यार्थी मित्र शिक्षकों की जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इन्हें नियमित नियुक्ति प्रदान कर राहत प्रदान करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: मैं प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा, मेरा निवेदन आपके विधायक के प्रति है, उसकी पालना करायें। उनको अपनी सीट पर जाने के लिये आप निवेदन करें।

श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्षजी, मैं आधा मिनट कहना चाहूंगा। रामचरितमानस में लिखा हुआ है – धीरज धरम पुत्र अरु नारि, आपत काल परखिये चारि। ये अब इनका धीरज खो चुके हैं, ये अधीर हो चुके हैं। इसलिये आप शिक्षा मंत्रीजी से कहें, धीरज को धीरज बंधायें, इनके कालेज खोली जाये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) हमारे माननीय सदस्य जहाजपुर से आने वाले हैं, इन्होंने अपनी मांग रखी और मांग में इनकी तरफ से कहना बिलकुल सही था कि जहां-जहां कालेज खोला गया पूर्ववर्ती सरकार द्वारा, और एक साथ कालेज खुलें, उन दो में एडमिशन चालू करने की प्रक्रिया

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

इन्होंने चालू की और जहाजपुर के अन्दर प्रक्रिया चालू ही नहीं की। मतलब, उन्होंने एडमिशन की प्रक्रिया चालू ही नहीं की। माननीय मंत्रीजी की तरफ से यह जवाब दिया गया कि हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं, तो ये काहे की समीक्षा कर रहे हैं? माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, इन्होंने कहा, बैठ जाओ, हम स्वास्थ्य का चैक-अप करवायेंगे। इसको बिलकुल हंसी-मजाक में ले लिया।

श्री अध्यक्ष: कतई नहीं लिया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) यह सदन की मर्यादा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: सदन में कोई भी बात हंसी-मजाक में नहीं ली जाती है। सदन में जो भी माननीय सदस्य अपनी बात कहते हैं, उसको गम्भीरता से लिया जाता है, सरकार भी गम्भीरता से लेती है। लेकिन मैंने आपको अभी भाषण देने के लिए नहीं, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है, इनको अपनी सीट पर बैठायें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) आप बिराजो, तब हम बात कहें।

श्री अध्यक्ष: मैं फिर वापस कार्यवाही चालू करूंगा। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप कहें अपने विधायक को, समझाइश करके अपनी सीट पर ले जायें। भाषण देने के लिए नहीं।

श्री बाबूसिंह राठौड़।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप प्रताड़ना दें सरकार को।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष) किरोड़ी लालजी ने जो कहा है, उसमें मुख्य मंत्रीजी आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबू सिंह। (व्यवधान) आप बैठिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 9-10 विधायकों ने तो धरने दे दिये राजस्थान में।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंहजी। इनका ही अंकित हो, और किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

शेरगढ़ के ग्राम देवातु से गोगादेवजी का मंदिर, सेखाला के सड़क निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त राशि की स्वीकृति

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, ग्राम देवातु से गोगादेवजी का मंदिर, सेखाला सड़क कार्य के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने हेतु प्रक्रिया

(श्री बाबू सिंह)

के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय लेख है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति बालेसर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम देवातु से गोगादेवजी का मंदिर, सेखाला सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसकी स्वीकृत लम्बाई 12.500 कि.मी. है। यह सड़क अति-महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल गोगादेवजी के मंदिर को जोड़ती है, जो इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण लोक आस्था का स्थल है। यहां पर हर वर्ष मेले का आयोजन होता है, जिसमें विभिन्न प्रदेशों से दर्शनार्थी दर्शन हेतु आते हैं।

उक्त मंदिर मुख्य सड़क से आधा कि.मी. की दूरी व पहाड़ी पर स्थित है। जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया है कि इस सम्पर्क सड़क को सीमेंट-कंकरीट सड़क द्वारा मंदिर के मुख्य द्वार तक जोड़ा जायेगा, जो कि स्वीकृति लम्बाई व पार्किंग स्थल हेतु कम पड़ेगी।

हर वर्ष मेले के दौरान हजारों वाहनों का आवागमन रहता है एवं मंदिर प्रांगण में वाहन पार्किंग का स्थान नहीं होने के कारण मेले के दौरान अव्यवस्था रहती है। वर्ष 2015 में मंदिर स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य आयोजन किया जायेगा, जिसमें एक लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की सम्भावना है। क्षेत्रवासियों की भावना एवं सुचारु आयोजनार्थ हेतु पार्किंग स्थल का होना नितान्त आवश्यक है।

विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि इस पार्किंग स्थल व सड़क की लम्बाई बढ़ाने के अतिरिक्त कार्य हेतु स्वीकृत राशि के अतिरिक्त 55 लाख रुपये अनुमानित लागत आयेगी।

अतः ग्राम देवातु से गोगादेवजी का मंदिर, सेखाला सड़क कार्य के लिए अतिरिक्त अनुमानित राशि 55 लाख रुपये की स्वीकृति जारी करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ओटारामजी देवासी।

सिरोही में चिकित्सा सुविधाओं की असंतोषजनक स्थिति

श्री ओटाराम (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित प्रस्ताव की सूचना देता हूं।

(श्री ओटाराम)

महोदय, सिरोही विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति ठीक नहीं होने के बारे में मामला लम्बे समय से सरकार के ध्यान में लाया जा रहा है, लेकिन सिरोही विधान सभा क्षेत्र के आम जन की चिकित्सा सुविधाओं से जुडी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। सिरोही विधान सभा क्षेत्र में स्थित सरकारी अस्पतालों में विगत वर्षो से डाक्टरों की भारी कमी होने के बावजूद सिरोही से डाक्टरों को हटाते हुए, अन्य जिलों में स्थानान्तरित एवं प्रतिनियुक्त किये जाने के कारण सिरोही में आम जन को चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसमें सिरोही जिला मुख्यालय अस्पताल की स्थिति यह है, पूरे दिन आउटडोर मात्र एक डाक्टर के भरोसे रहता है, जिसके कारण अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों एवं गम्भीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को भी लम्बी लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है तथा नि:शुल्क मिलने वाली सोनोग्राफी जांच की मशीन विगत 5 माह से ताले में बंद पड़ी है।

महोदय, सिरोही विधान सभा क्षेत्र में डाक्टरों के रिक्त पदों की स्थिति यह है कि सिरोही सार्वजनिक अस्पताल में वरिष्ठ विशेषज्ञों के 6 में से 2, कनिष्ठ विशेषज्ञ में 17 में से 12, वरिष्ठ दंत चिकित्सक-1, चिकित्सा अधिकारी के 12 में से 8 पद खाली हैं एवं शिवगंज ब्लाक अस्पताल सहित ग्रामीण क्षेत्र में डाक्टरों के स्वीकृत पद आधे से ज्यादा खाली पड़े हैं तथा सहायक मेडिकल स्टाफ की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है।

सिरोही विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी के कारण क्षेत्र के लोगों को राज्य से बाहर गुजरात जाना पड़ रहा है, जिसमें क्षेत्र से प्रतिदिन मरीज 100 से 150 छोटी-बड़ी गाड़ियों से पालनपुर, मेहसाणा, डीसी एवं अहमदाबाद में इलाज हेतु जा रहे हैं, जो राज्य की चिकित्सा सुविधाओं में कमी को दर्शाता है।

महोदय, सिरोही जिला मुख्यालय पर नवनिर्मित ट्रोमा सेंटर बने 4 साल होने के उपरान्त भी आम जन के उपयोग में नहीं आने का मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया, लेकिन आज दिनांक तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई, या हो रही है, वह विभाग ही जानता है। इससे सिरोही की आम जनता जो लम्बे अर्से से चिकित्सा सुविधाओं से वंचित थी और आज भी वही स्थिति है।

महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है कि एक तरफ सिरोही की

(श्री ओटाराम)

जनता डाक्टरों की कमी के कारण गुजरात के महंगे अस्पतालों की आर्थिक समस्या को झेल रही है, वहीं राज्य सरकार द्वारा सिरोही से अन्य जिलों में डाक्टरों के स्थानान्तरण एवं प्रतिनियुक्तियां की जाकर चिकित्सा सुविधाएं छीनी जा रही हैं।

इस प्रवृत्ति को तत्काल रोका जावे तथा सिरोही से अन्य जिलों में प्रतिनियुक्त डाक्टरों की प्रतिनियुक्ति तत्काल निरस्त की जावे तथा मुख्यालय पर नवनिर्मित ट्रोमा सेंटर को जन हित में शीघ्र चालू करने की तिथि घोषित की जाकर, लोगों को नवनिर्मित ट्रोमा सेंटर की सुविधा उपलब्ध करवाई जाने एवं सिरोही में डाक्टरों के खाली पड़े पदों को प्राथमिकता से जल्दी भरने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

जयपुर के निकटवर्ती कस्बों को डी.एम.यू. ट्रेन सेवा से जोड़ा जाना

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये जयपुर जिले में डी.एम.यू. ट्रेन चलाने के संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि आज जयपुर शहर में हजारों लोग नौकरी, व्यापार, मजदूरी तथा कृषि कार्यों के लिए आसपास के गांवों तथा कस्बों से प्रतिदिन आते हैं। इन कस्बों में चौमूं, फुलेरा, चाकसू, बस्सी, आदि प्रमुख हैं। ये सभी कस्बे लाइन से जुड़े हुए कस्बे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चौमूं सब्जी तथा दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में प्रमुख स्थान रखता है। इस क्षेत्र से प्रतिदिन हजारों किसान एवं व्यापारी सब्जी एवं दूध बेचने के लिए जयपुर आते हैं। ट्रेनों के सही समय पर उपलब्ध नहीं होने तथा एक निश्चित अवधि के मध्य ही उपलब्ध होने के कारण इन किसान एवं व्यापारियों को सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ती है। इस कारण सड़क मार्ग पर यातायात का अत्यधिक दबाव होता है, जिससे कई बार सड़क दुर्घटनाओं में जन हानि भी होती है।

चौमूं, लोहरवाड़ा, गोविन्दगढ़, आदि स्थानों से प्रतिदिन अध्ययन एवं रोजगार के लिए विद्यार्थी तथा मजदूर भी अत्यधिक मात्रा में जयपुर आते हैं।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि मेट्रो की लागत से बहुत कम लागत में जयपुर से चौमूं, फुलेरा, चाकसू, बस्सी, आदि स्थानों को डी.एम.यू. ट्रेनों से

(श्री रामलाल शर्मा)

जोड़ा जाता है तो सड़कों पर यातायात का दबाव काफी कम किया जा सकता है तथा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जन हानि से भी लोगों को बचाया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डी.एम.यू. ट्रेन चलाने का कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण एवं रेल विभाग के संयुक्त प्रयासों से भी किया जा सकता है, जिससे हजारों लोगों को राहत मिल सकती है। सरकार द्वारा रेलवे विभाग से प्रयास करके उक्त योजनाओं को स्वीकृत कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अत:, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि जयपुर के आसपास के कस्बों को डी.एम.यू. ट्रेनों से अविलम्ब जोड़ा जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, आज आप मुझे बार-बार डांट कर बैठा रहे हो। इतना गम्भीर इश्यू है आर.पी.एस.सी. का, जिसमें हम कहां जाकर बोलेंगे, इस मामले पर, अगर विधान सभा में नहीं उठायेंगे?

श्री अध्यक्ष: किसी न किसी प्रक्रिया से उठाइये आप। जैसे आज आपका एक विषय था, तब ले लिया। प्रक्रिया से उठाइये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सवाल हमारे लगते नहीं हैं; सवाल हम लगाते हैं, वे आते नहीं हैं। पहले ही कह दो, भाई, इनके लगाओ ही मत; इन लोगों के सवाल लगाओ मत। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किसने कहा, नहीं लगाओ? आप बैठिये। व्यवस्था के बारे में मेरे से ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कैसे बैठें, साहब? नहीं बैठेंगे। यह जो आर.पी.एस.सी. के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने आपसे कहा है, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: एक शब्द अंकित नहीं होगा। यह क्या मतलब है? आप विधान सभा में बाधा खड़ी करना चाहते हैं। (व्यवधान) चलती विधान सभा में बार-बार बाधा खड़ी करने की आपको इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा, चलती विधान सभा में बार-बार खड़े होकर और बिना आवश्यक प्रक्रिया के आपको बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

(श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) द्वारा सदन कूप में धरना)

बाड़मेर-जैसलमेर जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों का विद्युतीकरण

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के बाड़मेर व जैसलमेर जिले पहले से ही पिछड़े एवं अभावग्रस्त रहे हैं। यहां के निवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस वैज्ञानिक युग में बिना बिजली के कुछ भी सम्भव नहीं है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से इस ओर सार्थक प्रयास किये गये हैं, मगर छितराई ढाणियों में बसी इन बस्तियों के विद्युतीकरण हेतु इन क्षेत्रों में मानदण्डों में शिथिलता प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है।

इस महती योजना से विशेष तौर से बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित किया जाना सराहनीय कार्य है। एक गरीब के घर बल्ब जलने से उसका सपना पूरा होता है। इन जिलों में एक लाख 22,300 बी.पी.एल. परिवार हैं, जो अभी भी वंचित हैं; 23,890 ऐसी ढाणियां हैं जो सौ से अधिक की आबादी की हैं। डी.एन.पी. एरिया में विद्युतीकरण हेतु विशेष छूट प्रदान करें एवं प्राथमिकता भी प्रदान करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कीम का पहले चरण का कार्य पूरा हो गया है। द्वितीय चरण में वंचित बी.पी.एल. के 60,273 परिवार एवं ए.पी.एल. के 20,250 हैं; सौ से कम की आबादी की ढाणियों के 24,736 परिवारों को जोड़ा जाना है। द्वितीय चरण में ब्लाक सिवाना, बालोतरा, बाड़मेर का सर्वे हो चुका है; चौहटन, शिव, बायतू, जैसलमेर में कार्य चल रहा है; धोरीमन्ना, शिव में अभी कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है।

मेरा सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि द्वितीय

(श्री हमीरसिंह भायल)

चरण में राजस्थान के बाड़मेर-जैसलमेर के लिए विशेष तौर पर पर्याप्त राशि का आबंटन कर उक्त अभावग्रस्त क्षेत्र का विद्युतीकरण करें, ताकि इस वैज्ञानिक एवं संचार के युग में इस क्षेत्र की जनता भी लाभान्वित हो सके एवं उनका जीवन स्तर उठ सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संजीव कुमार।

भादरा तहसील में उपनिवेशन तहसील खोल कतिपय चकों/ग्रामों का री-फिटिंग कार्य पूर्ण किया जाना

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन व प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए तहसील भादरा में राजस्व सम्बन्धी रिफिटिंग की समस्या के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राजस्व तहसील भादरा क्षेत्र में 24 चकों और ग्रामों में रिफिटिंग की समस्या है। उक्त समस्या भूमि एकीकरण की कार्यवाही 1959 से पूर्ण होने के समय से बकाया है। भूमि एकीकरण की कार्यवाही के दौरान काश्तकारों की भूमि एकीकृत कर दी गयी तथा भू-अभिलेख भूमि एकीकृत के अनुसार तैयार कर दिया गया, परन्तु तैयार अभिलेख के अनुसार काश्तकारों को कब्जा नहीं दिया गया। काश्तकार भूमि एकीकरण की कार्यवाही से पूर्व जिस कदर काबिज थे, उसी कदर से अब काबिज हैं। इस प्रकार, काश्तकारों के मौके पर कब्जे व जमाबंदी के इन्द्राज में अन्तर है। मौके के अनुसार अभिलेख नहीं हैं। अत: अभिलेख एवं मौके की स्थिति अलग-अलग है, जिससे काश्तकारों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

उक्त समस्या के समाधान बाबत काश्तकारों द्वारा राजस्व अधिकारियों को बार-बार अवगत करवाया गया, परन्तु यह समस्या आज भी ज्यों की त्यों है। इस समस्या के समाधान हेतु भू-प्रबन्ध विभाग या उपनिवेशन विभाग की टीम लगा कर ही यह कार्य किया जा सकता है, क्योंकि तहसील में कार्यरत स्टाफ उक्त कार्य के लिए दक्ष नहीं है। 24 चकों और ग्रामों की रिफिटिंग की समस्या के समाधान के लिए भादरा में एक उपनिवेशन तहसील खोलकर रिफिटिंग का कार्य पूर्ण किया जा सकता है।

(श्री संजीव कुमार)

अत: निवेदन है कि भादरा में एक उपनिवेशन तहसील खोल कर रिफिटिंग का कार्य पूर्ण किया जाए ताकि क्षेत्र के काश्तकारों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर में डोडा-पोस्त के सेवन से उत्पन्न समस्याएं

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन व प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के तहत बाड़मेर जिले में डोडा-पोस्त की समस्याओं के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): राठौड़ साहब चाहें तो दोनों उठ सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं।

श्री अध्यक्ष: किरोड़ी लालजी, स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान ऐसे मुद्दे पर ले जाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, नशा शरीर के लिए हानिकारक है, यह हम सब मानते हैं, लेकिन सरकार की नशावृत्ति को लेकर जो दोहरी नीति है, यह इससे और ज्यादा खतरनाक है।

अध्यक्ष महोदय, जहां एक तरफ सरकार राजस्व की दुहाई देकर प्रदेश के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में शराब के ठेके खोल रही है जिससे प्रदेश का सामाजिक ताना-बाना छिन्न-भिन्न हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ डोडा-पोस्त को लेकर सरकार बहुत ज्यादा सख्त है। चूंकि नशा कोई भी हो, वह खतरनाक है, लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर सहित मारवाड़ के लगभग सभी जिलों में डोडा-पोस्त सेवन करने वालों की संख्या हजारों ही नहीं, लाखों में है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले आठ महीनों से राजस्थान की सरकार ने डोडा-पोस्त की कमी बताते हुए, ठेकों पर डोडा के भावों में वृद्धि कर दी एवं बहुत ही कम मात्रा में दे रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, डोडा सेवन एक ऐसा नशा है जो कि विशेष कर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सामाजिक समारोह में भी बहुतायत मात्रा में होता है। यह सच्चाई है। चूंकि डोडा पोस्त के ऐसे बंधाणी जो कि 50 की उम्र पार कर चुके हैं और उनको डोडा सेवन करते हुए लगभग 20-25 वर्ष हो गये हैं, ऐसे लोगों के लिए डोडा सेवन छोड़ना मौत को बुलावा देना है और वे लोग छोड़ भी नहीं सकते हैं। यह हकीकत है।

(श्री मेवाराम जैन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल बाड़मेर जिले का उदाहरण देना चाहता हूं कि हालात ऐसे खराब हैं कि डोडा सेवन करने वाले बंधाणी डोडा के ठेकों पर दो से तीन किलोमीटर लम्बी लाइनों में इस तपती धूप में खड़े देखे जा सकते हैं, जो कि आए-दिन अखबारों की सुर्खियां बनते हैं। तपती धूप में घंटों खड़े करने के बाद केवल 200 ग्राम डोडा उनको दिया जाता है, जिनको देख कर ही उनकी हालत खराब हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, यह गलत है।

यह सही है कि उन्होंने नशा सीख लिया, चाहे कैसे भी हो, लेकिन हमारे बड़े-बुजुर्गों को इस प्रकार धूप में घंटों खड़ा कर उनका अपमान करना सरासर गलत है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माल भिजवाना हो तो मैं भिजवा दूं चित्तौड़ से? चित्तौड़ से भिजवा दें माल? (व्यवधान) हैं, साहब?

श्री अध्यक्ष: डोडा-पोस्त भी आपके यहीं से जाता है वहां। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): चाहिए तो मैं भिजवा दूं इनके। ये भी खाते-पीते दिखते हैं।

एक माननीय सदस्य: यह तो इनके यहां है, आप भेजो न बाड़मेर में। हमारे दिक्कत है। भेजो आप।

श्री अध्यक्ष: शांत। कृपया शांत रहिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): ऐसा नहीं है कि डोडा सेवन करने वालों की सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। उनकी भी अपनी इज्जत है। इस प्रकार उनको सरकार द्वारा मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, यह गलत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार यह कह रही है कि डोडा की कमी है। अगर ऐसा ही है तो फिर बाजार में अवैध रूप से 2,500 रुपये देकर क्विंटलों डोडा बेचा जा रहा है। ये डोडे कहां से आ रहे हैं? यह सब गलत हो रहा है। डोडा के ठेकेदार एवं आबकारी विभाग की सांठगांठ से ऐसा हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार एक ऐसी नीति बनाये जिसमें जो डोडा सेवनधारी 40 की उम्र से अधिक है और कई सालों से डोडा सेवन कर रहा है, छोड़ नहीं सकता है, ऐसे को चिह्नित कर लाइसेंस दिये जाएं एवं ठेकों पर महीने में डोडा की मात्रा फिक्स की जाए तथा जो युवाओं में नशे की लत है, उसको छुड़वाने के लिए

(श्री मेवाराम जैन)

सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बड़े स्तर पर कैम्प लगा कर नशा छुड़वाया जाए, अन्यथा स्थिति यह है कि बंधाणी आए-दिन आत्महत्या कर रहे हैं। उनकी स्थिति दयनीय है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गिर्राज सिंह।

चम्बल साबर पाड़ा के बरैठा टोल तक ओवर लोडिंग वाहनों से ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा अवैध वसूली

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि पिछले कई महीनों से धौलपुर ट्रांसपोर्ट विभाग की कारगुजारियों की कहानियां आम जन एवं ट्रांसपोर्ट के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं।

चम्बल सागर पाड़ा से बरैठा टोल तक 25 किलोमीटर के डाइमेंशन के रोड से लगभग 6 हजार वाहनों का आना-जाना रहता है। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बोर्डर पर है और एन. एच. 3 आगरा-मुम्बई हाइवे है। ओवरलोडिंग एक बड़ा कारोबार है, जिसमें प्रतिदिन लाखों रुपयों का लेन-देन और अवैध वसूली ट्रांसपोर्ट विभाग कर रहा है। ट्रांसपोर्ट विभाग के कुख्यात आर.आई., रामवीर चौधरी इस अवैध वसूली के सरगना हैं और सहायक आफिस में बैठे निहाल बाबू हैं। इन्हें कई माफियों का संरक्षण प्राप्त है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अनेकों शिकायतें मिली हैं और इस सम्बन्ध में धौलपुर कलक्टर को ज्ञापन दिया और मैंने भूख हड़ताल की। भ्रष्ट अधिकारी ट्रांसपोर्ट विभाग की अपनी पूरी नौकरी के 16 साल के कैरियर में 12 साल से अधिक धौलपुर में राज कर रहे हैं और सरकारी खजाने पर डाका डाल रहे हैं।

यह मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला है। मुझे उम्मीद है कि मुख्य मंत्री महोदया इस ओर ध्यान देंगी और गंदगी की सफाई करवाने का काम करेंगी। बदनाम रामवीर चौधरी और निहाल बाबू जैसे भ्रष्ट लोगों को धौलपुर से बाहर भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक डोगरा।

बूंदी, बिजोलिया-नैनवां-लाखेरी रोड को बूंदी शहर से दूर बाइपास बनाकर निकाला जाना

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान

(श्री अशोक डोगरा)

सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बूंदी में बूंदी-बिजोलिया-नैनवां-लाखेरी रोड, जो राजकीय राजमार्ग 29 है, वह बूंदी शहर से होकर निकलता है। वहां पर काफी भीड़-भाड़, शहरी ट्रैफिक का दबाव तथा स्कूल-कालेज के छात्रों का आवागमन रहता है, जिससे इस रूट के साधनों के कारण आये-दिन शहर में दुर्घटनाओं का अंदेशा रहता है तथा जाम के हालात रहते हैं। इस रुट पर लाखेरी में ए सी सी सीमेंट फैक्टरी के बड़े वाहन निकलते हैं, जिनके कारण जाम के हालात बनते हैं। बूंदी शहर में इस रूट पर कोई बाइपास नहीं होने के कारण बड़ी परेशानी रहती है। इस क्षेत्र में वर्तमान में बूंदी की करीब 50 प्रतिशत आबादी निवास कर रही है।

इस सम्बन्ध में तेरहवीं विधान सभा के दशम सत्र में तारांकित प्रश्न संख्या 1100, सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्रीजी के जवाब में वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर ही इस बाइपास का निर्माण कराना सम्भव होना बताया जाकर, तत्समय पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होना बताया था।

यदि इस रूट पर बूंदी में एक बाइपास इस तरह से निकाला जाता है जो कि नई कृषि मंडी, जो कि दोलाड़ा में निर्माणाधीन है, को जोड़ता हुआ सीधे राताबरड़ा में निकलता है तो शहर में ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो जायेगा तथा दुर्घटनाओं व जाम के हालात से बचा जा सकेगा। यह इस क्षेत्र की अति गम्भीर समस्या है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया, वे नियम और प्रक्रियाओं के तहत आ जायें, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। आर पी एस सी की बात इन्होंने कही।

जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने महाविद्यालय का जो सवाल उठाया, उसमें सरकार ने खुद ने कहा है कि गुणावगुण के आधार पर इस पर विचार करेंगे।

इसलिए मेरा आग्रह है कि सदन की कार्यवाही चलने दें। आपको गम्भीरता के साथ ...(व्यवधान) आप उठायें, आपकी बात का जवाब देंगे। आपसे भी मेरा आग्रह है कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अपने-अपने स्थान पर पधारिये। अपने-अपने स्थान पर पधारिये। (व्यवधान)

(श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) एवं श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) द्वारा धरना समाप्त)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): नोटिस दे देना, कल मिल जायेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप अपनी सीटों पर बैठें, आपकी बात पर सरकार विचार करेगी। सरकार विचार करेगी आपकी बात पर।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): विचार में यह तो बता दो कि आप एप्रोप्रिएशन बिल में डाल दोगे ना वह?

श्री अध्यक्ष: आप विराजो। इस तरह कहा जाता है क्या?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैं उनसे कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: समीक्षा हो रही है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सरकार विचार करेगी। निश्चित रूप से गुणावगुण के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष: समीक्षा हो रही है। विराजें आप। (व्यवधान) और मिल लेना उनसे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आर पी एस सी वाला?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप नियमों के तहत आ जाओ, जवाब दे देंगे। आप नियमों में आ जाओ।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्रीमती अनिता भदेल।

महाविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त व्याख्याताओं का राजकीय सेवा में समायोजन

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से सरकार का ध्यान महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के कई वर्षों से रिक्त पदों की ओर दिलाना

(श्रीमती अनिता भदेल)

चाहती हूं, जिसके चलते आये-दिन विद्यार्थी हड़ताल करने को आतुर होते हैं। इन हड़तालों को रोकने के लिये सरकार (उच्च शिक्षा विभाग, कालेज शिक्षा निदेशालय, राजस्थान) ने वर्ष 2008 में संविदा व्याख्याताओं का चयन सम्भाग स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा मेरिट आधार पर किया गया था। संविदा व्याख्याताओं की नियुक्ति के पश्चात् महाविद्यालय में कुछ सीमा तक व्याख्याताओं के पद भरे गये, जिससे खाली पड़े पदों के कारण होने वाली हड़तालों को विराम मिल गया।

उक्त व्याख्याताओं द्वारा वर्ष 2008 से वर्तमान शैक्षणिक वर्ष तक निरन्तर एवं निर्बाध रूप से अपनी सेवाएं मात्र 7,950/- के मासिक वेतन (यदि अवकाश नहीं लिया, तब) पर सुदूर क्षेत्रों में भी प्रदान की जा रही हैं। इन संविदा व्याख्याताओं का वेतन महाविद्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के वेतन का आधा है एवं नये नियुक्त आर पी एस सी द्वारा चयनित व्याख्याताओं के वेतन का एक चौथाई व कालेज प्राचार्य के वेतन का 10 प्रतिशत है। इसके बावजूद भी संविदा व्याख्याता कार्यरत हैं व लगातार अपनी सेवाएं महाविद्यालयों में दे रहे हैं। पिछले 6 सत्रों से यह संविदा पद्धति चली आ रही है, जिसके चलते कई संविदा व्याख्याता प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निर्धारित आयु सीमा की अधिकतम आयु पार कर चुके हैं जिससे संविदा व्याख्याताओं को अपूरणीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई धन के रूप में नहीं की जा सकती है।

इन व्याख्याताओं को दिये जाने वाले मासिक वेतन से ये केवल अपना गुजारा कर सकते हैं किन्तु बच्चों की पढ़ाई, स्कूल फीस, वृद्ध माता-पिता के भोजन, आवास, चिकित्सा जैसी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में स्वयं को सक्षम नहीं पाते हैं। इसके अतिरिक्त, इन संविदा व्याख्याताओं को इच्छानुसार, जब चाहे हटाने व जब चाहे बुलाने जैसी विषम परिस्थितियों से रूबरू होना पड़ता है। इन संविदा व्याख्याताओं का भविष्य राजकीय सेवा में समायोजित नहीं होने की स्थिति में अंधकारमय है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि पूर्व में भी, वर्ष 1995 में एक अमेंडमेंट द्वारा कालेज शिक्षा में पूर्णतया अस्थायी लगभग 500 व्याख्याताओं को नियमित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012 में भी अनुदानित महाविद्यालयों के 750 व्याख्याताओं का समायोजन राजकीय सेवा में किया जा चुका है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

अत: मेरी सरकार से मांग है कि इन संविदा व्याख्याताओं का समायोजन राजकीय सेवा में कर इनके भविष्य के साथ न्याय करें।

श्री अध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से वक्तव्य। श्री रामहेत सिंह यादव।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर चोरी पर बदलने की असंतोषप्रद व्यवस्था

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): अध्यक्ष महोदय, किसान के ट्रांसफार्मर जल जाने या चोरी हो जाने के कारण विद्युत विभाग द्वारा उनको बदला जाता है। जहां तक जल जाने के बाद जो ट्रांसफार्मर्स बदले जाते हैं, उसमें पूर्ववर्ती सरकार तो 2-2 महीने लगाती थी, अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 48 घंटे, 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल दिये जाते हैं, जो ट्रांसफार्मर चोरी हो जाते हैं, उसमें कानूनी अड़चन होने के कारण किसान आज भी परेशान है। जब ट्रांसफार्मर चोरी हो जाता है तो उसकी विद्युत विभाग द्वारा थाने में एफ आई आर दर्ज करायी जाती है। सामान्यत: 20 तारीख के बाद चोरी हुए ट्रांसफार्मर की थानों में एफ आई आर दर्ज नहीं करते हैं, या एक ट्रांसफार्मर की एफ आई आर दर्ज नहीं होती है। थाने वाले कहते हैं कि जब एक-दो और चोरी हो जायेंगे तो सामूहिक रूप से उसकी एफ आई आर दर्ज हो जायेगी। इस कारण से किसान परेशान होता है। इस प्रक्रिया में पन्द्रह से बीस दिन तो पुलिस में एफ आई आर दर्ज करने में लग जाते हैं।

उसके अलावा, वह उसकी नकल लेकर, एफ आई आर दर्ज होने के बाद, विद्युत विभाग उसको यहां जयपुर स्थित एडिशनल एस पी कार्यालय भेजते हैं। यहां से उसमें स्वीकृति होने के बाद वापस जब विभाग के पास जाती है, एस ई से एक्स ईएन, ए ईएन के पास जाती है। उसके बाद उसका तखमीना बनाकर ट्रांसफार्मर सैंक्शन के लिए वापस फाइल एस ई के पास आती है। इस प्रक्रिया में लगभग 35 से 55 दिन लग जाते हैं।

मेरे यहां विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास का जो सब-डिविजन है, एक्स ईएन आफिस है, उसके अधीन जो भी ए ईएन आफिस आते हैं, जो गांव पड़ते हैं, उनमें ट्रांसफार्मर चोरी की बहुत घटनाएं होती हैं। पिछले साल का रिकार्ड देखें तो लगभग 400 से अधिक ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं पूरे डिविजन

(श्री रामहेत सिंह यादव)

किशनगढ़ बास में और उस कारण से, चूंकि अलवर जिला एन सी आर में है और वहां पर गेहूं, सरसों, अनाज के अलावा जो कामर्शियल क्राप्स हैं, जो फल हैं, सब्जी हैं, उनका बहुत ज्यादा उत्पादन करता है किसान, उस पर निर्भर है और अप्रैल, मई, जून के महीने में अगर किसान का ट्रांसफार्मर चोरी हो जाये और उसकी फल और सब्जी, जिनमें 24 घण्टे या 36 घण्टे में पानी देना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में किसान की फसल बरबाद हो जाती है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इसमें पुलिस थाने में एफ आई आर दर्ज कराना, यह विद्युत विभाग का काम है। यह 24 घण्टे में हो, 4 घण्टे में हो, 30 दिन में हो, यह दोनों विभाग का मामला है। जब विद्युत विभाग के पास ट्रांसफार्मर चोरी की काश्तकार, किसान अपनी समस्या बता देता है, उसको लिखित में उस कार्यालय में दर्ज करने के बाद, उसका ट्रांसफार्मर तुरन्त, जैसे और जले हुए ट्रांसफार्मर चेंज होते हैं, उसी प्रक्रिया के तहत उनको सैंक्शन किया जाये।

एक बात और कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय सदन में हैं, पिछले आठ -दस दिन से मेरे क्षेत्र में, विशेषकर किशनगढ़ बास में बिजली की दुर्दशा है। दस-दस, बारह-बारह घण्टे लोड-शेडिंग के नाम से काट दिया जाता है और उस कारण से किसान की फसल भी बरबाद हो रही है और पानी पीने में भी दिक्कत आ रही है।

जो चोरी किए गए ट्रांसफार्मर हैं, वह एक कोटकासिम ए ईएन आफिस की बताता हूं, दो महीने से ज्यादा, आठ ट्रांसफार्मर अभी भी ऐसे हैं जो चोरी होने के कारण, उसमें स्वीकृति, एफ आई आर नहीं होने, देरी से होने के कारण परेशानी हुई है।

मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि किसानों की व्यावहारिक कठिनाई है और जो विशेष रूप से खेती करते हैं सब्जी का कारोबार करते हैं कृषि में, उनको ज्यादा परेशानी है, उनको दिक्कत आती है। इन बैरिकेड्स को हटाएं। आप एक सर्कुलर, आदेश जारी करें कि जिस तरह से ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, उनको बदल दिया जाता है 72 घण्टे में, उसी तरह से चोरी किए हुए ट्रांसफार्मर को भी 72 घण्टे में बदलने की व्यवस्था करें। यही कहना था। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रेस्पोंड करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: रेस्पोंड करेंगे?

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): हां।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है कि ट्रांसफार्मर चोरी होने पर दिक्कत आ रही है, मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि ट्रांसफार्मर चोरी होने के बाद में बहुत विलम्ब होता है और इससे किसान को बहुत परेशानी होती है। ट्रांसफार्मर चोरी होने के बाद में जो रिप्लेसमेंट उसको मिलता है, उसमें देरी के दो ही कारण हैं। एक तो है, एफ आई आर प्रोसेस है और एक है कि अवेलेबिलिटी आफ ट्रांसफार्मर। माननीय सदस्य ने खुद स्वीकारा है कि 72 घण्टे में ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। राजस्थान के कई ऐसे भाग हैं जहां हम 48 घण्टे में भी ट्रांसफार्मर रिप्लेस कर रहे हैं।

यह जो थाने की प्रक्रिया है, इसके अन्दर बहुत लेकुना है। सबसे भारी समस्या जो उजागर हुई है, मेरे ध्यान में आई है वह यह कि थाने, जो सिविल थाने हैं, वे केस की तुरन्त एफ आई आर दर्ज नहीं करते हैं। देरी तब होती है कि किसी का ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, उसके बाद वह ए ईएन को रिपोर्टिंग होती है, ए ईएन है, जाकर एफ आई आर दर्ज कराता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर सरकार की प्रोपर्टी होती है। थाने वाले जो मेन काज आफ डिले है एफ आई आर दर्ज करने का, वे चाहते हैं कि उसकी पेंडेंसी उस महीने में नहीं आकर, उसके अगले महीने के पहले हफ्ते में ले। इस बात में सच्चाई है, हम इसको स्वीकार करते हैं, यह जो कमी है। अध्यक्ष महोदय, थाने वाले कई प्रश्न पूछने लग जाते हैं, वे लैंड पेपर्स मांग लेते हैं, नक्शा मांगते हैं, कब यह डेट इश्यू हुई। सब चीजों के अन्दर यह डिले प्रैक्टिस करते रहते हैं।

अभी हमारी नई कृषि नीति जो बनेगी, उसके अन्दर, जैसा माननीय सदस्य ने बोला कि एक टाइमफ्रेम होना बहुत जरूरी है, यह टाइमफ्रेम के लिए नीति के अन्दर हम यह भी सोच रहे हैं, एक खाली विचार हमारा है कि एक आन-योर-ट्रांसफार्मर की भी स्कीम हो सकती है। क्योंकि जब आपके खेत के अन्दर ट्रांसफार्मर लगा है तो आपकी भी तो जिम्मेदारी है। उस खेत में कोई

(श्री गजेन्द्रसिंह)

चोर आकर ट्रांसफार्मर उठा कर ले जाये, तो कुछ तो उपभोक्ता की भी इसमें जिम्मेदारी होनी चाहिए। दूसरा, मैं माननीय ...(व्यवधान) यही कि हम कुछ ट्रांसफार्मर के पैसे दे दें और हम कहें कि आपका ट्रांसफार्मर है। हम पैसा देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। यह विचाराधीन है और इसको हम, जो आप टाइमफ्रेम कह रहे हैं, वाकई में यह एक समस्या है और इसको हम हल करेंगे, और शीघ्र करेंगे। नम्बर एक।

नम्बर दो, मैं माननीय सदस्य से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अपना कष्ट तो बता दिया लेकिन आपके विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा चोरी होती है, ट्रांसफार्मर्स की, पूरे राजस्थान में; रिकार्ड है, जलने का। पिछले साल के अन्दर 220 ट्रांसफार्मर्स चोरी हुए थ्री फेज के और 1,084 जले हैं। अब थोड़ी विधायक की भी रेस्पोंसिबिलिटी होती है, विधायक सरकार को थोड़ा सपोर्ट दे।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मैं चौकीदारी भी करूंगा लेकिन विभाग भी तो कुछ करे। आपके एक एक्स ईएन ने, ए ईएन ने कहीं एस पी को कहा कि इतने ट्रांसफार्मर में एफ आर लगा दी? 400 ट्रांसफार्मर चोरी हुए, आपके विभाग का एक भी अधिकारी एस पी से, डी जी पी से, आई जी से मिला क्या? सब में एफ आर लगा दी जाती है। तो विभाग करे। विभाग अपना सामान, 20 करोड़ का, कांग्रेस के राज में 20 करोड़ के ट्रांसफार्मर अलवर जिले में चोरी हुए थे। जब पूर्ववर्ती सरकार ने आदत डाल दी तो उसको चैक करने में कुछ समय तो लगेगा न। हमने गांव के लोगों को भी जागरूक किया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): ...और मात्र 53 ट्रांसफार्मर मेरे विधान सभा क्षेत्र में चोरी हुए हैं। (व्यवधान)

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वीकार किया है कि यह एक भारी समस्या है और मैंने सजेशन भी दिया है कि नई कृषि नीति में हम इसमें सुधार करेंगे और समय निर्धारित करेंगे।

श्री अध्यक्ष: त्वरित गति से समस्या का हल कीजिये।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): यस, सर। एब्सोल्यूटली। (व्यवधान)

दूसरा आपने मुद्दा उठाया था कि बिजली की समस्या आ रही है।

(श्री गजेन्द्रसिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब से सरकार आई है, तब से लेकर पिछले पांच दिन तक, आपके हरियाणा, यू पी, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, ये जितने भी सब आसपास के स्टेट हैं, बहुत गम्भीर समस्या यह मानसून के डिले होने से हुई है। अभी जो पिछले पांच दिन के अन्दर समस्या आई है, उसमें जो नेशनल ग्रिड है, जहां से हम दूसरे प्रदेशों से बिजली हम पहले से तय करके खरीदते हैं, वहां पर उसका ग्रिड में फेल्योर हो गया। डिमाण्ड इतनी, फ्रिक्वेंसी इतनी हाई हो गई, लोग इन्डिस्सिप्लिन में होकर इतनी विथड्रा करने लग गये कि ग्रिड ही कालेप्स हो गया था। पांच दिन प्रोब्लम थी। यह प्रोब्लम आज सुबह से मिट गई है। जो पवन ऊर्जा थी, यह मानसून का दबाव आने से वह 1,200 मेगावाट से 200 मेगावाट रह गई। अब समस्या नहीं रहेगी, आज से यह हल हो गई है। अब बरसात खूब आने वाली है, दो-तीन दिन के अन्दर, खूब बरसात आने वाली है।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं। (व्यवधान) बहुत जरूरी बात है।

श्री अध्यक्ष: नो, नो। नहीं। यह परिपाटी नहीं डालूंगा नई मैं। स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पुलिस से सम्बन्धित मामला भी है और जैसा माननीय मंत्रीजी ने कहा कि एफ आई आर ...(व्यवधान) दर्ज होने में भी विलम्ब हो रहा है, मैं आश्वस्त करता हूं कि एफ आई आर जैसे ही हमारे पास आयेगी, हर थाने में उसी समय दर्ज करेंगे। (व्यवधान) मैं, निश्चित रूप से अगर पुलिस के लेवल पर, थाने के लेवल पर एफ आई आर लिखने में किसी प्रकार की कोताही बरती जा रही है तो नहीं बरती जायेगी। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें सब्मिशन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी जवाब देना चाहते थे, इसलिए अवसर दिया। आप स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

(13.00 बजे)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): पूरे राजस्थान का मसला है।

श्री अध्यक्ष: मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मेरा निवेदन है कि डिपार्टमेंट के जो थाने हैं, वहां इसकी एफ आई आर लोज होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): गृह मंत्रालय और विद्युत विभाग के मध्य सामंजस्य बिलकुल नहीं है। लोग धक्के खा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): आपके विद्युत विभाग के थाने हैं, उनको अधिकृत कीजिए, उनमें एफ आई आर दर्ज हो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): तभी काश्तकारों का भला हो सकता है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): पुलिस विभाग के थाने अलग हैं, विद्युत विभाग के थाने अलग हैं। सरकार इसमें तय कर दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह चिट के आधार पर बोलने की व्यवस्था है, इसमें यह बहस अलाउ नहीं की जा सकती।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): इनमें आपस में सामंजस्य नहीं है, इनमें आपस में सामंजस्य बना दो। समस्या अपने आप खतम हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष महोदय, आपने टोका है, कर लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था बिलकुल ठीक है, पर्ची पर माननीय सदस्य बोलते हैं उसमें सबको भाग लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन पर्ची पर बोलने पर जब माननीय मंत्री महोदय जवाब दे देते हैं, उसके बाद में प्रश्न पूछने का अधिकार माननीय सदस्यों को हो जाता है। यह मैं आपको परम्पराएं, जो व्यवस्थाएं दी गयी हैं उनको स्मरण कराना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री राजेन्द्र यादव।

कोटपूतली शहर में नेशनल हाइवे नं. 8 पर निर्माणाधीन बाइपास का बढ़ते यातायात के दृष्टिगत पुनर्निर्धारण

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): माननीय अध्यक्षजी, कोटपूतली

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

शहर की जो बसावट है, वह एन एच 8 पर लगभग 6 किलोमीटर दोनों तरफ बसा हुआ शहर है। आये-दिन वहां दुर्घटनाएं होती हैं। विगत दिनों जो पुल का क्रैक होना, जिसकी वजह से बहुत से माननीय सदस्यों को पीड़ा रही होगी, 20-20 किलोमीटर जाम की लाइन लगी रही, पूरा शहर अस्त-व्यस्त रहा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें थीं, वे बड़े भारी वाहनों से 50 करोड़ के लगभग सड़कें क्षत-विक्षत हो गयीं।

आदरणीय मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि उस क्षेत्र में कोटपूतली का बाइपास, जिसमें लगभग आधा तो बना हुआ है, अगर उसको आगे गांवों से जोड़ा जाय और कई जगह छोटी सड़कों को मिलाकर इसको बनाया जाय तो शहर का अच्छा विकल्प रहेगा। एन एच 8 पूरे उत्तर भारत से पश्चिमी भारत को जोड़ने वाली लाइफलाइन है और कोटपूतली तक आते-आते ट्रैफिक का इतना प्रेशर हो जाता है कि जो ट्रैफिक निकलता है, उससे पूरा शहर हमेशा अस्त-व्यस्त रहता है।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसको प्राथमिकता से लेकर करें। सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व है, कोई दुर्घटना हो जाती है तो पूरा जाम शहर के बीचोंबीच लगता है। इसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री शुभकरणजी चौधरी।

आप रेस्पोंड कर रहे हैं क्या?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो समस्या उठायी है, आप अनुमति दें तो मैं इस पर विस्तार से बोल दूं?

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 खाली राजस्थान प्रदेश की नहीं, बल्कि पूरे भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत सारा हमारा ट्यूरिस्ट आ रहा है, वह भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है; गुजरात जाने वाले गुड्स व्हिकल हैं, वे भी परेशान हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 नासूर बन चुका है। इसकी जो गतिविधियां रही हैं, अखबारों के माध्यम से आप और हम सब व पूरा सदन तथा राजस्थान की जनता, सब जान रहे हैं कि किस तरीके का इसके अन्दर घालमेल हुआ। दो दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय का भी एक फैसला आया।

(श्री युनुस खान)

इन सब बातों को लेकर मैंने माननीया मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन किया। माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी से भी हमने दो बार समय मांगा और उन्होंने इसी महीने की चार तारीख का समय दिया। मैं और माननीया मुख्य मंत्रीजी स्वयं वहां पर राजस्थान की जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुडी समस्याएं हैं, उनको लेकर गये थे। उस दौरान विशेष रूप से, क्योंकि अन्य भी जो माननीय सदस्य हैं, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य की भी यह समस्या है, राजस्थान के लोग, जो जयपुर-गुडगांव के बीच में इस एन एच 8 की दशा है, उससे सब अवगत हैं। अभी पिछले माह ही जब कोटपूतली की यह समस्या पैदा हुई और 8 से 10 दिन लगातार जाम रहा, अखबारों की सुर्खियां भी बना रहा, माननीय मंत्रीजी के सामने माननीया मुख्य मंत्रीजी और हमने यह बात रखी तो उन्होंने यह कहा कि अगर राजस्थान सरकार उचित समझती है तो कोटपूतली के बाइपास पर आप अपने कमेंट्स भेजें।

मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि हम शीघ्र इस पर रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार को भेजेंगे और माननीय मंत्रीजी ने इस पर, क्योंकि सड़क की जो समस्या है, इसको लेकर भारत सरकार के जो इस विभाग के सचिव हैं, उनको; राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, उनको; और सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारी हैं, उनका दल अगले सप्ताह तक इस पूरी रोड का भ्रमण करेगा और जहां-जहां समस्याएं हैं, चाहे वह कंसेशनर की तरफ से आयी हों, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ से आयी हों, उनके समाधान के लिए ठोस नीति बनाएंगे और आपका प्रस्ताव भी राज्य सरकार शीघ्र भेज देगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्षजी, मेरा विधान सभा क्षेत्र भी वहीं है। मैं इस संदर्भ में, आपकी अनुमति हो, तो एक निवेदन मंत्रीजी से करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: निवेदन कर दीजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दो-तीन बार प्रेस में आया, एन एच के द्वारा भी और जो कम्पनी बना दी, उसके आधार पर, उसमें राजस्थान सरकार पर तीन आरोप लगे हैं, जनता पर आरोप लगे हैं। उसके लिए निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

कहा कि हमें जमीन उपलब्ध नहीं करायी। फोर लेन थी, सिक्स लेन फोर लेन पर ही बननी थी। उसके बाद जो सर्विस लेन थी, उसके लिए जमीन चाहिए थी। उस कम्पनी ने सिक्स लेन नहीं बनायी और फिर उसका जवाब नहीं दिया।

दूसरा, सबसे पहले टोल टैक्स चालू हो गया, एक साल बाद काम चालू हुआ। पूरा पैसा वसूल कर लिया, और कम्पनी कहती है, हमारे पास पैसा नहीं है।

तीसरी बात, जिस कम्पनी को बनाने का ठेका दिया, पूर्व सरकार ने उसी को ड्राइंग दे दी और बिना जन-प्रतिनिधिनियों की मांग के चेंज कर दी।

ये तीन बातें ऐसी हैं जिनमें आरोप में कम्पनी भी आती है और पूर्व सरकार भी आती है। इसके जवाब के आधार पर मंत्रीजी व्यवस्था करें। सरकार के बारे में जो आरोप लगे हैं...

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): ...जनता पर जो आरोप लगे हैं, किसानों पर आरोप लगे हैं, ये निराधार हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान आकर्षित कर लिया। इस पर भी बोलेंगे क्या?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जी, बोलेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, सदन को यह जानना जरूरी है कि वास्तव में राष्ट्रीय राजमार्ग में, नेता प्रतिपक्ष भी विराज रहे हैं, मैं कोई इस पर आरोप नहीं लगाना चाहता और न इसको विस्तार से ले जाना चाहता, पूर्ववर्ती दोनों सरकारें, चाहे वह केन्द्र में रही हो, चाहे राज्य में रही हो, एक ही दल की रही है, जिससे आप और हम सब अवगत हैं। यहां पर एक पार्टी विशेष में यहां जो मुख्य मंत्री थे, उनके और केन्द्रीय मंत्री, दोनों हैं, उनके आपस में एक दल के होते हुए भी राजनैतिक भेद रहा और उनमें इस बात की होड़ रही कि इस एन एच को और जो भूमि अधिग्रहण का मामला था, इसमें दोनों में यह था कि राज्य के मुख्य मंत्री इसकी क्रेडिट न ले लें और मुख्य मंत्री के भाव यह थे कि केन्द्रीय मंत्री इसकी क्रेडिट नहीं ले लें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये माननीय मंत्री महोदय बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री के क्या मतभेद हैं, यह सब जानते हैं। ठेली वाला जानता है, रेहड़ी वाला जानता है, साइकिल चलाने वाला जानता है। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): यह हकीकत है। आप परेशान हैं, हमारी विधान सभा परेशान है। यह सही है। आप इसको स्वीकार कीजिए। सिक्स लेन बनानी थी, क्यों नहीं बनी सिक्स लेन? जमीन चाहिए थी सिक्स लेन के लिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य अपनी बात कह रहे हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन इस विभाग को मैं पिछले छह महीने से देख रहा हूं। राजस्थान की जनता और सदन को वास्तविकता बताना भी जरूरी है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा था। वह बात मैंने बतायी है।

अब मैं उस बात पर आ रहा हूं, जो वास्तव में पेपर्स पर हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात हमारे माननीय सदस्य ने पूछी, भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित, यह बात सही है कि कंसेशनर है, रियायतगृहीता है, उसने अपनी नाकामी छुपाने के लिए और राष्ट्रीय राजमार्ग ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए भूमि अधिग्रहण के मामने को प्रमुखता से रखा। उनको सिक्स लेन में जितनी भूमि आवश्यक चाहिए थी, उतनी भूमि उनको दी गयी। लेकिन उनके कुछ छिपे हुए हित थे। क्योंकि प्रारम्भिक तौर पर जब 2008 और 2009 में यह अवार्ड हुआ, तब यह परियोजना लगभग 1,800 करोड़ की थी, लेकिन उन्होंने इस परियोजना को बढ़ाकर 3,009 करोड़ रुपये का कर दिया।

जो हमारा कंसेशनर है, उसकी गड़बड़ी की बदौलत और राष्ट्रीय राजमार्ग, जो केन्द्र सरकार डील कर रही है, उनकी गड़बड़ी की बदौलत यह सारी परियोजना डिले हुई। राजस्थान की जनता का दोष नहीं है। भूमि अधिग्रहण का इश्यू इतना नहीं है जितना प्रचारित किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, कन्क्लूड कीजिए।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। इसलिए इन सारे विषयों को लेकर माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी को, यानी भारत सरकार को हमने पत्र लिखा है और मैं उम्मीद करता हूं, इन सारे तथ्यों की जांच भारत सरकार करवायेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी।

प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को फसली ऋण आबंटन के अधिकार की प्रदायगी

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय,

(श्री शुभकरण चौधरी)

सहकारिता विभाग का जब गठन हुआ, तब यह बात तय हुई थी कि दो प्रकार के लोन किसानों को उनकी मदद के लिए दिए जाएं, एक अल्पकालिक और एक दीर्घकालिक। दोनों ऋणों में यह विचार आया कि क्या एक ही बैंक के द्वारा दोनों लोन वितरित किया जाए? तो यह तय हुआ कि दीर्घकालिक ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से बांटे जाएंगे और अल्पकालिक ऋण प्राथमिक भूमि विकास बैंक के माध्यम से बांटे जाएंगे। पर, अध्यक्ष महोदय, कैसी विडम्बना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने प्राथमिक भूमि विकास बैंकों से यह फसली ऋण बांटने का अधिकार छीन लिया।

मैं वर्तमान में माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह फसली ऋण पुन: प्राथमिक भूमि विकास बैंक के द्वारा बांटे जाएंगे? अगर बांटे जाएंगे तो उनको कितना....

श्री अध्यक्ष: आप अपना वक्तव्य दीजिये, अगर वे चाहेंगे तो रेस्पोंड करेंगे। आप अपना वक्तव्य पूरा कीजिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्राथमिक भूमि विकास बैंक को फसली ऋण बांटने का अधिकार दिया जाएगा? और दिया जाएगा तो उसकी राशि कितनी होगी? मेरा प्रश्न यह है।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़।

राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होना

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल एक राष्ट्रीय राजमार्ग की समस्या नहीं है, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनके दोनों किनारों पर इन दिनों कई होटल्स का निर्माण हो रहा है। इन होटल्स का वे लोग निर्माण कर रहे हैं जो स्थानीय नहीं हैं, बाहर के लोग आकर वहां होटल्स का निर्माण कर रहे हैं। वहां पर स्थानीय निकटतम थाने में उनका कोई इन्द्राज नहीं है। उनकी कोई एंट्री नहीं होती है। उनकी पहचान सुनिश्चित नहीं की जा रही है। हो सकता है कि ये बाहरी लोग हों। कइयों ने नाम रख रखे हैं, 'सहयोग'। 'सहयोग' नाम की जांच करवायें तो जयपुर से लेकर पिण्डवाड़ा तक लगभग 20 होटल्स होंगी जो 'सहयोग' के नाम से हैं। कहीं पर 'ए-वन' के नाम से हैं। इनके नाम भी इस तरह से हैं जैसे ग्रुप हों, और इस प्रकार की होटल्स का निर्माण कर रखा है। इनमें संदिग्ध गतिविधियां भी होती

(श्री मदन राठौड़)

हैं। कई बाहरी लोग आकर वहां पर रहने लग गये हैं, उनके शेल्टर्स बन गये हैं। हो सकता है, वे बांग्लादेश के लोग भी हो सकते हैं और कोई बाहरी हो सकते हैं।

तो एक तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गृह विभाग यह सुनिश्चित करे कि निकटतम थानों में उनकी पहचान दी जाए। किसानों से जमीन खरीद लेते हैं, जमीन खरीद कर वहां होटल्स का निर्माण करते हैं। वहां कई संदिग्ध लोग भी आकर ठहर जाते हैं। यही नहीं, यहां पर कई टैंकर्स रुकते हैं, उनमें से दूध निकाला जाता है, नकली दूध उनमें भर दिया जाता है। कई केमिकल के ड्रम्स वहां पकड़े गये हैं, जो झाड़ियों में छिपाकर रखते हैं। केमिकल के टैंकर्स आते हैं। इस प्रकार के मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। लेकिन मैं यह सुनिश्चित करवाना चाहूंगा कि इस प्रकार के होटल्स के जो निर्माता हैं, उनकी जांच, उनकी पहचान, उनमें कौन लोग आकर ठहरते हैं, उनकी पहचान सुनिश्चित की जानी चाहिए और समय-समय पर निगरानी भी की जानी चाहिए। ये जो टैंकर्स में से दूध निकालते हैं, वे उनमें केमिकल-युक्त नकली दूध भरते हैं, जिसमें डिटर्जेंट से दूध बनता है और डिटर्जेंट से दूध बनाकर उनमें भर देते हैं ताकि उसकी पूर्ति हो जाए। इस प्रकार की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अखबारों में छप रही हैं।

इसलिए मैं गृह विभाग से निश्चित रूप से चाहूंगा कि वह यह सुनिश्चित करवाये, इनकी पहचान का निकटतम थानों में निश्चित रूप से इन्द्राज होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पोंड कर रहे हों?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपकी अनुमति से, यह समस्या वास्तव में, व्यक्तिगत रूप से भी हम जब इधर से निकलते हैं तो लगता है। पुलिस विभाग ने वैसे तो अपनी व्यवस्था कर रखी है, उनकी पैट्रोलिंग गाड़ियां बराबर चलती हैं। आपके इस छोटे से एरिये में हमारी चार गाड़ियां निरन्तर रात-भर चलती हैं। बीट व्यवस्था भी है, जिस बीट व्यवस्था में उसके क्षेत्र में आने वाली जितनी होटलें हैं, उनका वे पूरा ध्यान रखते हैं, निगरानी रखते हैं।

फिर भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि नेशनल हाइवे पर इन पिछले 4-5 सालों में बनी हुई जितनी भी होटलें हैं, उनका सारे व्हेअर-अबाउट

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

का पूरा पता करके थाने में उसकी पूरी रिपोर्ट रखी जाएगी, ताकि कभी भी किसी प्रकार की कोई घटना हो तो उसकी जानकारी कम से कम पुलिस विभाग के उस थाने पर अवश्य रहे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले दो महीने में इन सब के व्हेअर-अबाउट का पूरा पता करके थाने पर उनका पूरा इन्द्राज करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंहजी। दो मिनट में अपनी बात कहेंगे।

सूचना

जैसलमेर शहर में एक बालिका का अपहरण

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। निवेदन यह है कि जैसलमेर जिले के जैसलमेर शहर में दिनांक 2 जुलाई, 2014 को एक बच्ची का अपहरण करके, कोई लेकर चला गया। बच्ची का नाम सुश्री सुनिता पुत्री भगवान दास है और उसका ही पड़ोसी बच्चा सुमेरदान पुत्र ईश्वरदान स्वामी है। निवेदन है कि इस बच्ची का 2 तारीख को प्रात: 3 से 4 बजे के बीच में अपहरण करके लेकर गया है। 2 तारीख को इस परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया, जिसका मुकदमा नम्बर 53/2014 है। निवेदन यह है कि 2 तारीख को इस बच्ची का अपहरण हुआ है और आज 16 तारीख हो गयी, पर आज तक उस बच्ची का कोई पता-ठिकाना नहीं है। उस परिवार का हाल बेहाल हो रखा है। आज पूरा जैसलमेर शहर आक्रोशित है और वह परिवार अनशन पर बैठ सकता है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, क्योंकि हमारे जिले में इस प्रकार का मामला बहुत कम होता है, इसलिए आम जनता में यह भय पैदा हो गया। बच्ची को इस प्रकार से कोई पड़ोसी बच्चा लेकर चला जाए और आज 14-15 दिन होने वाले हैं, बच्ची का पता-ठिकाना नहीं है। पुलिस की लापरवाही है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष: विराजिये। गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर दिया है।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): ... कि जल्दी से जल्दी पुलिस इस परिवार को, अपनी बच्ची को किसी भी प्रकार से सुपुर्द कराने की व्यवस्था करे।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखता हूं:-

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (वर्ष 2012-13)

1- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 की धारा-12(3) (एफ) के अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2012-13;

राजस्थान लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (संख्या 62) (वर्ष 2011-12)

2- भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 62वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12; एवं

राजस्थान आवासन मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण लेखे (वर्ष 2012-13)

3- राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1971 की धारा-47 के अन्तर्गत राजस्थान आवासन मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षण लेखे वर्ष 2012-13.

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखता हूं:-

आउटपुट बजट वर्ष 2012-13 एवं आउटकम बजट वर्ष 2013-14

1- आउटपुट बजट वर्ष 2012-13 एवं आउटकम बजट वर्ष 2013-14;

सांभर साल्ट्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन (सं. 48) (वर्ष 2012-13)

2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 48वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13;

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन (सं. 65) (वर्ष 2011-12)

3- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 65वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12; एवं

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन (सं. 2) (वर्ष 2012-13)

4- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619(ए) के अन्तर्गत राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13.

श्री अध्यक्ष: श्री प्रभू लाल सैनी।

व्यवस्था का प्रश्न

सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिवेदनों की प्रस्तुति में निदेश पश्चात भी जारी विलम्ब

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था का प्रश्न।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आसन के बहुत से ऐसे आदेश हुए हैं कि जितने भी हमारे उपक्रम हैं, निगम हैं, जो कम्पनी ला 1956 के तहत जिनका सालाना आडिट होता है, उनकी समय पर आडिट रिपोर्ट यहां पेश होनी चाहिए। आज हमारे एक उपक्रम की 2011-12 की आडिट पेश हो रही है। 2011-12 की आडिट रिपोर्ट के बाद में 2013 का और आडिट हो गया होगा। इस प्रकार के निगम और उनके अधिकारी बार-बार राज्य की जनता के निवेश किये हुए पैसे का आडिट न करवाकर, राज्य हित में काम नहीं कर रहे और इस सदन के सर्वाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं और आसन के दिये हुए निर्देशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं।

मैं सम्माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से यह निवेदन करना

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

चाहूंगा कि इस प्रकार की कोई भी अगर गलतियां हुई हुई हैं तो सुधार के साथ-साथ प्रताड़ना भी दी जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्वीकार करता हूं कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइंस एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का प्रतिवेदन विलम्ब से आया है। मैं अधिकारियों से कहूंगा कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं हो और आपके माध्यम से क्षमा चाहूंगा कि इसमें विलम्ब हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आपका औचित्य प्रश्न ठीक था, मंत्रीजी ने नोट कर लिया है। आपको धन्यवाद।

श्री गजेन्द्र सिंह।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, ऊर्जा विभाग के निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2011-12)

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 12वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2011-12;

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2012-13)

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2012-13; एवं

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2011-12 के लेखों की आडिट रिपोर्ट

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104(4) के अन्तर्गत राजस्थान

(श्री गजेन्द्र सिंह)

विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2011-12 के लेखों की आडिट रिपोर्ट।

श्री अध्यक्ष: आज आपने साफा नहीं पहन रखा था, इसलिए चूक हो गई। श्री प्रभू लाल सैनी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन (सं. 35) (वर्ष 2012-13)

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13;

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2012-13)

(2) महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा 42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13; एवं

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2012-13)

(3) स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 की धारा 32(4) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13.

श्री अध्यक्ष: श्री सांवर लाल।

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन (सं. 29) (वर्ष 2012-13)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, मेमोरण्डम आफ आर्टिकल्स के नियम 114 के अन्तर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 29वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी संवैधानिकता पर तो सवाल उठाये हुए हैं। जब संविधान के हिसाब से ये मंत्री ही नहीं हैं तो काहे के लिए इनसे पढ़वाते हो? यह हमारा एतराज है। यह हमारा एतराज है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री युनुस खानजी।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): यह बीमारी हो रही है कोई। बिना मतलब की बातें उठाने का, यही काम है क्या? (व्यवधान) कई बार जवाब दिया जा चुका है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसे धमका रहे हैं, साहब। बिना मंत्री होते हुए भी धमका रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक विषय तय हो जाने के बाद भी बार-बार बोलते हैं, यह इनकी मानसिकता है। इनको माफ किया जा सकता है।

श्री युनुस खानजी।

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2012-13

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2012-13 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री बाबूसिंह राठौड़।

याचिका

बालेसर एवं शेरगढ़ में नाकारा नलकूप एवं नाकारा ओपनवेल के स्थान पर गुणवत्ता वाले नलकूप खुदवाना

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, पंचायत समिति बालेसर एवं शेरगढ़ में नाकारा नलकूप एवं नाकारा ओपनवेल के स्थान पर गुणवत्ता वाले भूजल स्थल पर नवीन नलकूप खुदवाकर पेयजल से लाभान्वित करवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

पाटन (किशनगढ़) में 132 केवीए जी एस एस की स्थापना

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, किशनगढ़ (अजमेर) विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नेशनल हाइवे-8 पर स्थित ग्राम पंचायत मुख्यालय पाटन में नवीन 132 केवी जी एस एस की स्थापना की सक्षम स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2014-15 में जारी कराने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-15 पर बहस चालू होगी। आज की बहस श्रीमती किरण माहेश्वरी प्रारम्भ करेगी।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा वर्ष 2014-2015 के परिवर्तित बजट के सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहूंगी कि यह बजट एक बहुत ही साहसिक, ऐतिहासिक और चुनौतीपूर्ण बजट है। इस बजट के अन्दर पूरे राजस्थान की जनता और उसकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, इस बजट को जिस तरीके से, ऐसे चुनौतीपूर्ण तरीके से बनाया गया है, जो हम राजस्थान को एक ऐसे विकास की पटरी के ऊपर, जहां पर यह पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी कांग्रेस के राज में, पुन: इस गाड़ी को पटरी पर लाकर और बुलेट ट्रेन के माफिक इसकी दौड़ को सुनिश्चित करने का यह बजट है। इस बजट में सारे ही पहलुओं को, जो सुराज संकल्प घोषणा पत्र के अन्दर लिये गये थे, उनको पूरा करने के लिए; यह बजट वास्तव में इस तरीके का यह बजट है, जहां पर हमने इस संकल्प को आगे बढ़ाना, यह अर्थ संकल्प, यह सभी क्षेत्रों में संरचना विकास कार्यों को पूर्ण करने का यह संकल्प है। मैं यह कहूंगी कि मुख्य मंत्रीजी की यह व्यापक दृष्टि एवं सुराज संकल्प के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, इस बजट के अन्दर वह झलक रही है।

हमने देखा कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट में विकास की व्यापक दृष्टि दिखाई है। पूर्ववर्ती सरकार थी, जो प्रतिपक्ष के यहां पर बैठे हुए और पूर्व में सरकार में बैठे हुए नेता थे, उन सबने जिस तरीके से पांच साल में मात्र चरित्र हनन का काम किया, उन्होंने मात्र जनता को गुमराह करने का काम किया, लेकिन विकास के अन्दर कोई काम उन्होंने करके नहीं दिखाया।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आज जब विकास की पटरी पर यह गाड़ी दौड़ने के लिए तैयार हुई है तो हमारे साथी, विपक्ष के अन्दर बैठे हुए, बजट की तारीफ करना या कुछ अच्छा काम हुआ है, वह कहना तो कहीं दूर की बात है, लेकिन मैंने सुना, कल से ही, कि इन्होंने हर समय बजट के अन्दर कोई न कोई कमी निकालने की कोशिश की। लेकिन... (व्यवधान) मन से तो करेंगे ही, क्योंकि आने वाला समय है, अभी तो शुरुआत है हमारी। हमने जो बजट के अन्दर जिस तरीके से, माननीया मुख्य मंत्रीजी के लिए यही कहूंगी कि उन्होंने इस बजट को 'सुशासन से विकास' का यह मंत्र जो उन्होंने दिया है इस बजट के अन्दर, यह जनता का जीवन स्तर इससे सुधरेगा और जनता का कल्याण आने वाले समय में राजस्थान के अन्दर होगा। इसमें कतई कहीं संशय की बात नहीं है।

यह सुराज संकल्प घोषणा पत्र के वादों को पूरा करना, यह अभी प्रारम्भ है और लक्ष्यों के प्रति हम समर्पित हैं। यह हमारा पहला कदम है और इसलिए अभी हम इसकी जब बात करते हैं तो मैं यह कहूंगी कि ''लड़ते-लड़ते इन अंधेरों में आप कहीं खो जायेंगे, पीढ़ियों के वास्ते हम रोशनी दे जायेंगे'', यह इस बजट के अन्दर झलकता है, क्योंकि इसमें आधारभूत संरचना, इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हर तरीके से इस बजट के अन्दर यह बात कही गई है।

जब यहां पर बहस शुरू हुई थी और आपने प्रतिपक्ष के, विपक्ष के हमारे साथियों को जब यहां पर बुलवाया था तो उन्होंने कहा था कि महिला मुख्य मंत्री हैं और महिला मुख्य मंत्री होते हुए भी इन्होंने बजट के अन्दर महिलाओं के सन्दर्भ में क्या बात रखी? शायद उन्होंने पढ़े बिना ही, क्योंकि कुछ कमियां निकालना ही शेष है, इसलिए कुछ न कुछ कहना है, इसलिए कहना था, बाकी उन्होंने अगर पढ़ा होता तो वे यह देखते कि पेज नम्बर 58 के ऊपर बिन्दु संख्या 163 से 169 तक उन्होंने वे सारी बातें कहीं कि हम लोग महिलाओं का किस तरीके से आर्थिक उत्थान करेंगे।

भामाशाह योजना, हमारी सरकार जब 2003 से 2008 तक थी, उस समय हमने शुरू की थी और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, उसने यह भामाशाह योजना बंद की। यानी, महिलाओं पर कुठाराघात करने का अगर कोई काम किया तो वह कांग्रेस की सरकार ने किया। ये लोग क्यों नहीं अपने अन्दर झांकते हैं कि इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया? हमने भामाशाह योजना शुरू की थी, पैसा बैंक में जमा कराना शुरू कर दिया था लेकिन इन्होंने

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आते ही उस पर रोक लगा दी और रोक ही नहीं लगाई, बल्कि वह जो पैसा, जो महिलाओं के खाते में जमा होना था, उस पैसे का दुरुपयोग करके, उस पैसे को कहीं, कहां, किस तरीके से इन्होंने किया, उसका जवाब तक इन्होंने नहीं दिया। हम पांच साल तक पूछते रहे, लेकिन जवाब नहीं दिया।

मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगी इस बजट के माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी को, जिन्होंने आते से ही सबसे पहला ध्यान इस ओर रखा कि वह जो भामाशाह योजना, जो बहनों के लिए शुरू की गई थी, बी पी एल परिवार की मुखिया बहन के लिए शुरू की गई थी, उसे पुन: शुरू किया और 2,000 रुपये उसके खाते में डालना, यह सुनिश्चित किया गया।

यही नहीं, माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं उन्हें यह भी बताना चाहूंगी कि उन्होंने, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 678 स्कूलों के अन्दर, बालिकाओं के जो विद्यालय हैं, उनमें शौचालय बनाना, यह भी सुनिश्चित किया, जो उन बालिकाओं के लिए सुविधा होगी। इसके बारे में कभी नहीं सोचा इन्होंने। हम बार-बार कहते रहे पांच साल तक, इन्होंने कभी नहीं सोचा।

आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हमारी बहनें, जो अच्छा काम करती हैं, उन्हें 'मां यशोदा' का अवार्ड देना, यह हमारी वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने सुनिश्चित किया है और कहा है कि हमारी बहनें जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं, जो आंगनबाड़ी में सहयोगिनी और आशा के रूप में काम कर रही हैं, वे अच्छा काम करें, तो उन्हें प्रोत्साहन राशि 5,100 रुपये, 2,100 रुपये देना, यह उन्होंने तय किया। मैं उसका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं। यह महिलाओं के बहुत बड़ी बात होगी कि आज महिलाओं के द्वारा जो काम किया जा रहा है, उस काम का, कहीं-न-कहीं उसके ऊपर स्थापित करने का, उस काम को कहीं इनाम देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने किया है।

इसलिए आज यह कहना चाहूंगी, यह जब मैं कहती हूं कि यह जो हमारा बजट है वह एक साहसिक और चुनौतीपूर्ण बजट है, वह इसलिए कहती हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान के ऊपर 1 लाख 30 हजार 640 करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर छोड़ा था। इन सबके बावजूद, वर्ष 2014-15 का यह बजट, हमारी वार्षिक योजना 69 हजार 820 करोड़ रुपये की प्रस्तावित की गई है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

पिछली बार का हमारा योजना का आकर था, वह केवल 40 हजार करोड़ था और इस बार यह जो योजना में 72 परसेंट वृद्धि हुई है, यह पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान योजना का आकार 72 प्रतिशत बढ़ा तो इसमें बढ़ा। इसलिए मैं कहती हूं कि यह एक बहुत साहसिक कदम है कि इतना बड़ा कर्जा होने के बावजूद भी योजना का आकार जो इतना बढ़ा है, यह विकास के प्रति हमारी निष्ठा है, हमारा समर्पित प्रयास है। हमारी सरकार योजना को लागू करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, इस बात का यह सूचक है।

हमने संरचना विकास के लिए 20 हजार किलोमीटर की सड़कें बनाना तय किया। हम पांच साल में कांग्रेस की सरकार में सड़क के ऊपर पैचवर्क करने के लिए तरसते थे, बार-बार यहां पर चिल्लाते थे, कहते थे कि हमारी सड़कें टूट रही हैं, खड्डे हो रहे हैं उनके अन्दर, कम से कम पैचवर्क करा दो, लेकिन इन पैचवर्क करने का भी इनके पास में पैसा नहीं था। आज इस बजट के अन्दर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि 20 हजार किलोमीटर की सड़कें जब बन जाएंगी तो गांव का विकास होगा और वह गांव के विकास के लिए उन्होंने कहा, वह 'ग्रामीण गौरव पथ' बनाने की बात की, जब घोषणा की तो पूरे ग्रामीण लोगों के अन्दर यह खुशी की लहर छा गई। आधा किलोमीटर से दो किलोमीटर तक की सी सी रोड बनाना, नालियों का काम करना, जो गांव के लिए मूलभूत उनकी सुविधा है, उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐसा डवलप होगा कि गांव-गांव के अन्दर विकास होगा।

इसके बारे में इन्होंने नहीं सोचा। केवल यहां भाषण में कहते हैं कि इतनी जनता, 70 प्रतिशत जनता गांव में रहती है, लेकिन आज तक, मैं यह पूछना चाहती हूं, यहां जो हमारे प्रतिपक्ष में बैठे हुए हमारे साथी हैं, इनकी जब सरकारें हुआ करती थीं, कब इन्होंने गांव के विकास के बारे में सोचा? लेकिन माननीया मुख्य मंत्रीजी ने आते ही सबसे पहले कहा कि कर्जा है, सब कुछ है, लेकिन इन सबके बाद में हमारे को सबसे पहला विकास अगर कहीं करना होगा तो गांव का विकास करना होगा, गरीब का विकास करना होगा। इसलिए उन्होंने गांव के विकास के लिए ये 20 हजार किलोमीटर की इतनी बड़ी सड़कें देने का तय किया और कहा कि 'ग्रामीण गौरव पथ' बनाए जाएंगे। हम शहरों में सुनते थे यह 'गौरव पथ', कभी हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि गांव में भी ऐसा 'गौरव पथ' बन सकता है, लेकिन आज इस बजट के माध्यम से हम यह देख रहे हैं कि 'ग्रामीण गौरव पथ' के माध्यम से यह विकास का काम

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

होगा।

प्रत्येक पंचायत पर सूचना प्रौद्योगिक सेवा केन्द्र का निर्माण होगा; प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाए जाएंगे। इस बात की घोषणा ही अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा है। हर पंचायत मुख्यालय पर हम उच्च माध्यमिक विद्यालय दे रहे हैं, जहां हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां पढ़ सकेंगी। उन्हें कहीं पर यह नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहां उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है, इसलिए हमें दूसरे गांव जाना पड़ता है, जाने का कोई साधन नहीं है। इसलिए कहीं-न-कहीं पढ़ाई में पीछे न रह जाएं, इस बारे में ध्यान दिया गया है और यह मूल संरचना है कि अगर हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिया, अच्छी उन्हें पढ़ाई दे दी, तो आगे चलकर वे एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। इस बारे में उन्होंने सोचा। मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूं कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय की, यह एक बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण घोषणा उन्होंने की है।

उन्होंने कहा, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अन्दर गोदामों का निर्माण होगा। हम हमेशा यह कहते रहे कि हमारे यहां पर गोदाम का अभाव है, इसलिए अनाज हमारा भीग रहा है; ग्राम सेवा सहकारी समिति के अन्दर अनाज तो पड़ा है लेकिन वह अनाज सड़ जाता है। वह गोदाम बनाने की यह एक ऐसी संरचना होगी, जिसके माध्यम से आज गांव के अन्दर वह अनाज जो उपलब्ध होना चाहिए, गांव के लोगों को, वह अच्छा अनाज उन्हें मिल सकेगा, अन्यथा तो उन्हें सड़ा हुआ अनाज कांग्रेस शासन में मिलता रहा।

रोजगार के अन्दर यह भी उन्होंने कहा कि पंचायत मुख्यालय के ऊपर जिस तरीके से रोजगार योजना में नरेगा के तहत काम शुरू होंगे, उन कामों के अन्दर ऐसे ठोस काम शुरू होंगे जिनके अन्दर रोजगार के अवसर और ज्यादा बढ़ेंगे।

यह ग्रामीण विकास की संरचना जो उनके द्वारा इस बजट के अन्दर रखी गई है, यह वास्तव में एक बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर बजट है। जिस बजट को, हम कह सकते हैं कि उन्होंने गांव की चिंता की, उन्होंने किसान की चिंता की, उन्होंने गरीब की चिंता की, ऐसा यह बजट आया है।

आज इस बजट के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी कि उन्होंने पूरे

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

प्रदेश के अन्दर 7 मेडिकल कालेज खोलने की बात कही, उन्होंने कहा कि 3 हमारे इंजीनियरिंग कालेज खोले जाएंगे; हमारे यहां पर स्मार्ट सिटीज बनेगीं।

हमारे युवाओं के लिए स्किल डवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात कही है, यह मैं सोचती हूं कि पूरे देश भर में पहला उदाहरण ऐसा होगा, जहां पर हम कौशल विकास का ऐसा विश्वविद्यालय हमारे यहां पर देखेंगे, जहां पर 45 लाख युवकों हेतु कौशल प्रशिक्षण से रोजगार के अवसर बनेंगे। इसका यह पहला उदाहरण होगा। राजस्थान के लोगों को तो अपने आप में बहुत गौरवान्वित होना चाहिए कि ऐसे कौशल प्रशिक्षण के लिए यह विश्वविद्यालय बनाने का यह जो विजन है, यह विजन केवल हमारी मुख्य मंत्रीजी के अन्दर आ सकता है। उन्होंने यह विजन देखा कि आज हमारे बेरोजगार जो हैं वे पढ़े-लिखे बेरोजगार भटक रहे हैं, उन्हें कहीं रोजगार नहीं मिल रहा। अगर उनमें स्किल डवलप होगी, अगर वास्तव में कहीं-न-कहीं शिक्षा के साथ-साथ वह हुनर उनके अन्दर आएगा तो उनको नौकरियों के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, नौकरियां उनके पीछे आएंगी और लोग कहेंगे कि नहीं, तुम्हें हमारे यहां नौकरी के लिए आना होगा। यह बात जब उन्होंने देखी, यह भी एक ऐसा विजन है, इस विजन को समझने की जरूरत है। आने वाले समय में बेरोजगारी को खतम करने के लिए, यह जो यूनिवर्सिटी होगी, इस यूनिवर्सिटी से जो बच्चे निकलेंगे, वह अपने आप में हमें इस बात की, जो हमारी ज्वलंत समस्या है बेरोजगारी की, उसको समाप्त करने का जो उन्होंने यह साहसिक कदम उठाया है, हम सब लोग इसकी सराहना करते हैं। यह पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर ऐसा पहला केन्द्र होगा, ऐसी पहली यूनिवर्सिटी होगी, जिस यूनिवर्सिटी के अन्दर, इस तरीके से स्किल डवपल करने की यूनिवर्सिटी होगी।

मैं आज आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगी कि यह जो सुपर-स्पेशलिटी हास्पिटल की जो बात कही है इस बजट के अन्दर, वास्तव में हमें जरूरत है इसकी। आज प्राइवेट हास्पिटल इतने आ गये और प्राइवेट हास्पिटल में सारी सुविधाएं हैं लेकिन गरीब की जेब उसे अलाउ नहीं करती कि वह उन हास्पिटल में जा सके। इसलिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस पर विचार किया और कहा कि हर जिला मुख्यालय पर एक सुपर-स्पेशलिटी हास्पिटल होगा और उसकी शुरुआत उन्होंने की तीन जिलों से, जहां पर उदयपुर जिला भी आया, जहां कोटा भी आया और बीकानेर भी आया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीया मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने इसमें उदयपुर जो एक

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आदिवासी क्षेत्र के पूरा संभाग का मुख्यालय है, वहां पर यह सुपर-स्पेशलिटी हास्पिटल देकर वहां के आदिवासी और वहां के जनजाति के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को वह सारी सुविधाएं देने का जो उन्होंने प्रारम्भ किया है, इसके लिए मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूं।

राज्य के अन्दर 67 परसेंट लोगों का बीमा करना, यह जो उन्होंने एक लाभ देने का एक बड़ा कदम उठाया है, यह भी बहुत साहसिक कदम है। इसको अगर देखेंगे तो आज तक कोई यह नहीं सोचता था कि मेरा भी कोई बीमा कराएगा, बिना मुझे पूछे, लेकिन यहां पर हमारे बी पी एल परिवार के लोगों को, उनका बीमा होना, यह जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने गरीब के बारे में सोचा है कि उनका बीमा होगा तीस हजार रुपये तक और अगर गम्भीर बीमार है तो तीन लाख रुपये तक भी, अगर कहीं उन्हें सहायता की जरूरत है तो वह भी दी जाएगी, यह एक ऐसा साहसिक कदम है, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है।

मैं आज आपको इस माध्यम से कहना चाहूंगी, यहां पर कह रहे थे बार-बार कि हम लोग परीक्षाएं जो हैं, हमने नौकरियां क्या दीं? मैं कांग्रेस के उन साथी भाइयों से पूछना चाहती हूं कि आपकी सरकार थी पांच साल, केन्द्र में भी आपकी सरकार थी, कितने नए-नए नियम आपने लगाये। कभी टैट की परीक्षा देनी होगी, कभी कुछ देना होगा। यहां तक कि आर पी एस सी के अध्यक्ष बैठे हैं, आर पी एस सी के अन्दर कितने बड़े सवाल उठे थे। लेकिन उन सवालों का जवाब ये नहीं दे पायें। किस तरीके से, पक्षपातपूर्ण तरीके से वे सारे पेपर्स हुए। जो सारा आज तक हम देखते हैं, कहां-कहां न्यूजपेपर्स के अन्दर हम लोग न्यूज देखते हैं कि इतनी सारी नौकरियां अटकीं, उसका कारण क्या था? डेढ़ लाख नौकरियों के अटकने का कारण क्या है? उसके पेपर्स खुल गए, कहीं पर कोई प्रक्रिया पूरी नहीं की गई...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यूजपेपर को नहीं पढ़ा जाता।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): न्यूजपेपर को नहीं पढ़ रही हूं, मैं तो सिर्फ उसका हवाला दे रही हूं कि आपने हमेशा कभी कोई प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो कभी कहीं दोष रखा। बेरोजगार युवकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और उन्हें जिस तरीके से प्रताड़ित किया, आये दिन परीक्षा के

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

लिए उन्हें जाना पड़ता था। पच्चीस साल का युवक आज पैंतीस साल का बन गया, लेकिन तब तक भी कांग्रेस का शासन उन्हें नौकरी नहीं दे सका।

माननीय, मुख्य मंत्रीजी ने यह कितना बड़ा कदम उठाया, उन्होंने कहा कि ये सारी एक के बाद एक परीक्षाएं बंद होंगी; एक ही परीक्षा रहेगी टैट की। अगर वह परीक्षा दी तो सारे तरीके से उस परीक्षा में पास होने पर वे नौकरियां उसे मिल सकती हैं, उसे बारम्बार परीक्षा नहीं देना। यह कितना बड़ा कदम है, इसके बारे में सोचो और मन में विचार करो।

मुझे तो लगता है, कहीं न कहीं, ये जो बार-बार कहते हैं, बार-बार टोकते हैं, इसलिए कि ये हम क्यों नहीं कर पाएं? इनके मन में कहीं न कहीं यह भी है कि ये सारा, सब कुछ माननीया वसुन्धरा राजेजी, मुख्य मंत्रीजी ही क्यों कर रही हैं? ये हम क्यों नहीं कर पाए? ये इनके लोग इसलिए नहीं कर पाए कि जब ये कुर्सी पर बैठ गये, तो इन्होंने देखा कि अब हम कुर्सी पर आ गये हैं, तो सब कुछ, हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा हमारा प्रतिपक्ष था पिछली बार, इतनी बार हम आवाज उठाते थे, कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसी का नतीजा रहा कि आज ये वहां पर इतनी कम संख्या में बैठे हैं।

आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अन्दर बनी है, माननीया वसुन्धरा राजेजी मुख्य मंत्री बनी हैं और तब से हमने देखा कि एक पल भी उन्होंने कहीं विश्राम नहीं लिया, बराबर से इस ओर गतिशील हैं कि कैसे राजस्थान को आगे बढ़ाया जाए, और राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए ये जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जो ग्रामीण विकास होना चाहिए, जो हमारी महिलाओं को सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको स्वावलम्बी बनना चाहिए, जो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, जो हमारे पढ़े-लिखे युवा जो बेरोजगार हो रहे हैं, उनको किसी तरीके से रोजगार मिलकर वे आगे चल सकें और अपने आपको स्थापित कर सकें, इस ओर उन्होंने ध्यान दिया है। इस बजट में हम इसी बात को बारम्बार देखते हैं कि किस तरीके से उन्होंने, हर दृष्टि से चाहे वह हमारा पर्यटन का ही क्यों न हो, उन्होंने हमारे यहां पर मावली से मारवाड़ जो मीटरगेज लाइन है, उसे हेरिटेज करने की बात कही। आप सोचिये कि वह मारवाड़, वह हमारा मेवाड़, इस मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ना, क्योंकि यहां की ऐतिहासिक जो धरोहर है, जो महाराणा प्रताप की यह भूमि है, वह महाराणा

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

प्रताप की भूमि के ऊपर, वह जो यहां पर सारा हेरिटेज के रूप में यहां पर लाइन डलेगी, उससे कितना लाभ होगा। वे सारे लोग जब यहां पर पर्यटन की दृष्टि से आएंगे तो उन्हें कितना अच्छा महसूस होगा कि वास्तव में यह राजस्थान है, जिस राजस्थान ने अपनी धरोहर को, उन्होंने उसे बचा कर रखा और इस तरीके से उन्होंने यह हेरिटेज लाइन दी।

मैं आज इस बजट पर अपने इस वक्तव्य के माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद एक चीज के लिए और देना चाहूंगी पहले कि नेशनल हाइवेज को उन्होंने डि-नोटिफाई किया। आज यह कितनी बड़ी बात है कि हमारे जो नेशनल हाइवेज के ऊपर बस रहे गांव-शहर, वहां पर प्राइवेट बसेज की कोई सुविधाएं नहीं हुआ करती थीं, लोग कहते थे कि हम जीपों के अन्दर जा रहे हैं, जीप के अन्दर, पूरी जीप ऊपर-नीचे से भर कर, पता नहीं कब कोई एक्सिडेंट हो जाए। ऐसी स्थिति को उन्होंने देखा कि इसे अगर हमने डि-नोटिफाई किया, तब जाकर हम लोग यहां पर प्राइवेट बसेज को दे सकेंगे। तो यह भी मैं कहूंगी, एक बहुत साहसपूर्ण निर्णय उन्होंने किया है।

मैं आज इसी के साथ में माननीया मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगी कि मावली से मारवाड़ की जो हेरिटेज लाइन है, उसके साथ में ही जो ब्राडगेज की बड़े लम्बे समय से डिमांड है, उसके लिए भी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को यह कहा जाए, मावली से मारवाड़ ब्राडगेज हमें दिया जाए, और यह हेरिटेज लाइन जो आपके द्वारा दी जा रही है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

साथ-साथ, देवास परियोजना का जो सेकंड फेज है, उसको कम्प्लीट करने के लिए उन्होंने यहां पर 379 करोड़ रुपये देने की जो घोषणा की है, मैं उसका बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही, यह भी कहना चाहूंगी कि तीसरा और चौथा फेज जो देवास परियोजना का है, जिसमें उदयपुर को लिया गया है, उसी के साथ में राजसमन्द को भी जोड़ा जाए, क्योंकि राजसमन्द की झील में पानी आने का यही एक मात्र स्रोत है। अगर इसे जोड़ा जाएगा तो उदयपुर के साथ-साथ राजसमन्द की जनता को भी इस पानी से पीने के पानी की बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

मैं यहां पर राजसमन्द में एक कन्या महाविद्यालय खोलने की भी, अपने-आप में, इस बजट के माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

साथ-साथ, वहां पर राजसमन्द में जो हमारे यहां पर एक तरह से कहना चाहिए, जो मार्बल के व्यवसायी हैं, उनके लिए जो बात कही गयी है, उसका भी मैं बहुत सम्मान करते हुए आदर के साथ में स्वागत करते हुए केवल जो छोटी-सी त्रुटि रह गयी है, जहां पर 6.75 किलो के स्थान पर जो 5 किलो कर दिया है, उसे पुन: 6.75 किलो व वैट जो लेना है, उसे लेने की कृपा करें।

आज मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि उन्होंने जो रिवाइज्ड माइनिंग पालिसी की बात इस बजट में कही है, यह वास्तव में जरूरत है। जनजाति क्षेत्र में माइनिंग की जो पालिसी है, उसमें जब रिविजन होगा तो उन सारे लोगों को उससे बहुत फायदा होगा।

मैं इस बजट को इस ओर देखती हूं कि यह अपने आप में इतना परिपूर्ण बजट है, इस बजट में जिस तरीके से माननीया मुख्य मंत्रीजी ने हर वर्ग का, हर क्षेत्र का जो ध्यान रखा है और जो शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की बात कही है, यह भी एक बहुत बड़ी दूरदृष्टि है उनकी। मैं यह कहना चाहूंगी कि आठ सौ से अधिक जनसंख्या के गांवों में, एक हजार गांवों के अन्दर आर ओ प्लांट लगाने की बात कही है, हम लोग एक-एक गांव में आर ओ प्लांट लगाने के लिए तड़पते थे, कहीं-कहीं सी एस आर के पैसे में किसी-किसी बड़ी कम्पनी को कहते थे कि आप आर ओ प्लांट लगा दीजिये; यहां सरकार कह रही है कि हम एक हजार गांवों में आर ओ प्लांट लगा रहे हैं। यह कितनी बड़ी बात है कि आठ सौ से अधिक की जनसंख्या के जो गांव हैं, उन सब में आर ओ प्लांट लगेगा। तो गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल देने की जो योजना उन्होंने बनाई है, मैं उसका बहुत स्वागत करती हूं।

जनता जल योजना को पी एच ई डी विभाग को देने के संदर्भ में जो उन्होंने कहा कि उस पर विचार चल रहा है, इसके लिए भी मैं उनकी बहुत सराहना करती हूं। वास्तव में, यह जनता जल योजना जो गांव के अन्दर है, वह योजना आज किसी न किसी अभाव से बंद पड़ी है। कहीं तो गांव के लोगों को लाइट के बिल चुकाने का पैसा नहीं, तो उन्होंने कहा कि टी एफ सी का पैसा इस ओर रखा जाएगा कि वे लाइट का बिल चुका सकें; कहीं कुआं गहरा कराना है तो गहरा करा सकें। यह जो उन्होंने बात कही है, इसकी भी मैं सराहना करती हूं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

उन्होंने जो इतने कारपोरेशंस बनाये हैं, राजस्थान अरबन ड्रिंकिंग वाटर, सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन; राजस्थान रिवर बेसिन प्राधिकरण का जो गठन किया जा रहा है; राजस्थान की सीमाओं पर उपलब्ध पानी को जोड़ने के लिए राजस्थान ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड जो बनाये जाने की बात कही है; बस स्टेशंस जो राजस्थान के हैं, उन सब के लिए, वे बस स्टेशंस और अच्छी तरीके से डवलप हों, उसके लिए बस पोर्ट सर्विस कारपोरेशन का जो गठन किया गया है, उसकी तो पूरे राजस्थान में सब तरफ से सराहना हो रही है कि हमारे जो बस स्टेशंस हैं, बस स्टाप्स हैं, उनकी बहुत दुर्दशा हो रही है, यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है कि जहां पर हमारे सारे बस स्टाप्स हैं उनका अच्छा डवलपमेंट होना शुरू होगा।

मैं आज इस बजट के माध्यम से राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देते हुए यही कहना चाहूंगी कि यह जो संकल्प उन्होंने किया है, सुराज का, देश एवं प्रदेश में अच्छे दिनों के नये युग को लाने का, यह सबका साथ-सबका-विकास, यह जो अन्त:प्रेरणा उनकी है यह हम सब के लिए इस राजस्थान के लिए बहुत ही ऐतिहासिक होगा। आने वाले समय में, आज तो यह शुरुआत है, यह पहला बजट है, इस पूरे, अभी के पांच साल के कार्यकाल का और इस पहले बजट में जो उन्होंने मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखते हुए जो संरचना, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के ऊपर इस बजट में विशेष तौर से ध्यान दिया है, उसको हम आने वाले समय में देखेंगे। जो पांच साल जब होंगे, तब इसका आपको अहसास होगा कि वास्तव में यह जो सरकार है, यह सरकार गरीब की, यह सरकार किसान की, यह सरकार युवा की, यह सरकार महिला की, यह सरकार हर वर्ग के बारे में ध्यान रखते हुए, अच्छे तरीके से, यह सरकार केवल घोषणा नहीं करती जैसे कांग्रेस ने किया, लेकिन यह सरकार काम करके दिखाना चाहती है और इसलिए इसकी शुरुआत इस बजट में हुई है। आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि किस तरीके से यह बजट एक ऐसा ऐतिहासिक बजट साबित होगा।

इसलिए कहती हूं कि ''कौन कहता है कि राहें बंद हैं? हर कदम पर एक नयी शुरुआत है।'' यह शुरुआत राजस्थान में हो चुकी है। अब इस शुरुआत में देखना यह है, यह शुरुआत इतनी अच्छी कि इस शुरुआत के अन्दर ऐसी गाड़ी दौडेगी कि जैसे बुलेट ट्रेन दौड़ती है, और तब हम सब लोग यह कहेंगे कि राजस्थान, यह राजस्थान विकासशील नहीं, यह राजस्थान विकसित राजस्थान की श्रेणी में आ गया। ऐसा राजस्थान बनेगा।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

यही बात कहते हुए, मैं इस बजट की बहुत-बहुत सराहना करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूं। मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश मीणा।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बजट पर चर्चा चल रही है। हमारी सदन की नेता ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए परिवर्तित बजट भाषण में जो असत्यों का वाचन किया है, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश में सबसे बड़ा, मान-मर्यादा के लिहाजा से सूरवीरों का प्रांत रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने सम्माननीय प्रांत की मुख्य मंत्री और सदन की नेता ने जो भाषण पढ़ा वह दिशाविहीन और समाज के किसी भी वर्ग को न सुनने वाला कहा जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

मैं बिना किसी भूमिका के, सीधे अपनी बात पर आता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि सदन की नेता के भाषण में असत्यता कूट-कूटकर भरी हुई है। बजट भाषण के पेज संख्या दो पर बिंदु पांच में सदन की नेता ने बताया है कि 2013-14 के दौरान राज्य सरकार का राजस्व घाटा 2,500 करोड़ रुपये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के लेखा-महानियंत्रक की रिपोर्ट है, सी ए जी की, उसमें वर्णित आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष, वर्ष के दौरान 73.67 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस रहा और इसी तरह माह नवम्बर, 2013 तक रेवेन्यू सरप्लस 1,690.18 करोड़ रहा।

जहां तक बात वित्तीय प्रबंधन की आती है तो हमारी सदन की नेता के नेतृत्व में सरकार ने दिसम्बर मध्य में शासन भार सम्भाला था और उनके वित्तीय प्रबंधन की बानगी आप देख लीजिए कि नवम्बर, 2013 तक राज्य सरकार का वित्तीय घाटा केवल 6,500 करोड़ रुपये था और इनके शासनकाल आने के बाद, चार माह में 18,301 करोड़ रुपये पहुंच गया है। अर्थात, चार माह की अवधि में 11,800 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा और हमारे शासन के आठ माह के कार्यकाल में घाटा 6,500 करोड़ रुपये। तो यह कैसा वित्तीय प्रबंधन है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह वित्तीय प्रबंधन नहीं है, यह कुप्रबंधन है और एक वोकल बजट है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट भाषण के पेज संख्या 3 पर बिंदु संख्या 8 में सदन की नेता ने आंकड़ों की दिलचस्प लफ्फाजी करते हुए आरोप

(श्री रमेश)

लगाया कि हमारा पूंजीगत व्यय बहुत कम रहा है, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सदन की नेता ने जो बताया, उसके अनुसार विगत कार्यकाल के दौरान आयोजना मद में पूंजीगत व्यय मात्र 20 हजार करोड़ रहा, जबकि हमारी सरकार के समय पूंजीगत व्यय आयोजना मद में 42,300 करोड़ रुपये का दर्ज किया गया। विगत कार्यकाल की तुलना में यह दुगना है। यह बात आर्थिक समीक्षा, बजट व्यय मद में पेज संख्या 22 पर वर्णित है।

तो आपका जो बजट है, हमें भी एक अचम्भे सी बात लगती है कि आपका जो लेखानुदान था 2014-15 का 46,990 करोड़ रुपये और फिर उसका परिवर्तित बजट 69,820; इतना बड़ा मेजर डिफरेंस पहली बार। हमारे माननीय सदस्य ने कहा है कि बहुत बड़ा, 72 परसेंट इसको बढ़ाया है, तो यह बड़े वित्तीय विशेषज्ञों के हाथ या पी पी पी माडल के आधार पर बना दिखता है और वित्तीय वर्ष में जो विकास दर 4.5 औसत रही, अब इस दर को ये 12 से 13 परसेंट विकास दर पर हासिल करना चाहते हैं, तो हमें तो यह सब असत्य सा लग रहा है।

अब मैं आपको, दूसरी बात है, बजट भाषण में पैरा संख्या 9 पर जो उल्लेख किया गया है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय बिजली कम्पनियों का घाटा 15 हजार करोड़ से बढ़कर 75 हजार करोड़ रुपये हो गया; माननीय अध्यक्ष महोदय, घाटा एक दिन में नहीं बढ़ता है, घाटे की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में, वहीं से शुरुआत हुई है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार कभी हमारी रही, कभी सरकार इनकी रही, लेकिन जो दोषपूर्ण, सबसे रिजल्टेंट बात कहें, तो सभी ने, अवेयरनेस कहें या लापरवाही कहें, अधिकारियों पर लगाम कसने की कोशिश नहीं की, इसलिए यह घाटा 15 हजार से 75 हजार करोड़ तक पहुंचा।

मैं बताना चाहूंगा इनके शासनकाल की बात कि इनका मिस्मैनेजमेंट और कोई प्लानिंग नहीं होने की वजह से 2007-08 और 2009 तक कोटा थर्मल पावर स्टेशन से जो पावर जनरेशन होना था, वह 200 मेगावाट, सूरतगढ़ से होना था 250 मेगावाट और छबड़ा की यूनिट थीं, उनसे 200,250 दोनों से होना था, टोटल 950 मेगावाट इनसे जनरेट, उत्पादन होना था, ये समय पर उत्पादन को नहीं ला पाए। इनका कोई प्लान नहीं था, न इनका कोई विजन था। इसलिए इनकी गलतियों से, समय पर जब जनरेशन नहीं आया तो इन्होंने

(श्री रमेश)

बिजली हाई रेट पर खरीदी और वह भी शार्ट टेण्डर टर्म से खरीदी। यदि बिजली खरीदनी भी थी तो लोंग टर्म प्रोसीजर पर खरीदते। बिजली की रेट है, उस समय खरीदी, 4 रुपये से 19 रुपये प्रति यूनिट पर खरीदी और उस समय अन्य राज्यों में सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध थी। यह सिलसिला 2009-10 तक भी चला है और 10 के बाद में फिर बिजली में कमी आई, 3 रुपये से 4 रुपये प्रति यूनिट तक।

तो बिजली खरीद के लिए सरकार जो पैसा देती है, हमारी सरकार ने पैसा दिया और यह सिलसिला कहां से शुरू होता है, कि जब पावर में पालिटिक्स इन्वाल्व हो जाती है तो सरकारें यह समझने लग जाती हैं कि चुनाव आ रहे हैं, बिजली मुफ्त में दे दो; सब्सिडी दे दो या रेट कम कर दो; टैरिफ का ध्यान मत रखो। उसमें इन्वाल्व हो जाती हैं तो घाटा क्यों नहीं बढ़ेगा? यदि आप घोषणाएं करते हों, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, हमारे समय में कि योजना के माध्यम से हम इतनी दरों पर बिजली देंगे, तो हमने पैसा दिया, और आपकी सरकार के समय आपके मुख्य मंत्रीजी ने जो लोक लुभावन भाषण दिया और जो योजना बनाई, उनको कनेक्शन दिये, वह आपको जो बिजली बोर्ड को पैसा देना था, सब्सिडी का, आपने नहीं दिया। इसी तरह यह गैप बढ़ता गया।

बिजली के लिए आप लोन लेते रहे, यहां तक कि ब्याज चुकाने के लिए शार्ट टर्म लोन लेना पड़ा और हाई रेट पर आप बिजली खरीदते रहे। आपकी सरकार ने घाटे को, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं...

श्री अध्यक्ष: आपके 13 मिनट बचे थे, आपकी पार्टी के। अब आप बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं। बचेगा ही नहीं समय।

श्री रमेश (सपोटरा): पहले मेरी बात सुन लीजिए। मेरे जो चार सदस्य हैं, वे नहीं बोलेंगे। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूं, क्योंकि जो भी...

श्री अध्यक्ष: जल्दी खतम कीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): जो भी माननीय सदस्य बैठे हैं, जो बैठे हैं, वे पक्ष के लोग हैं, वे अपनी बात नहीं कह सकते, जो हम उनकी बात को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: जल्दी समाप्त कीजिए। मैं चाहता हूं, जल्दी समाप्त करें।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घाटा बढ़ता गया।

(श्री रमेश)

आपने सब्सिडी का पैसा नहीं दिया और दिया तो बहुत कम दिया, नगण्य है। हमारे समय में बिजली पैदा हुई, उसकी क्षमता 7,223 एम बी ए और आपके समय में बिजली पैदा हुई 1,556.1 एम बी ए। तो हमने जो बिजली पैदा की, आपसे पांच गुना क्षमता अर्जित की।

इसी प्रकार का घाटे का एक कारण है, 2006 से 2010 के बीच में जो एफ आर पी 4 हजार करोड़ रुपये खर्च किये वह भी 4 हजार करोड़ आपने लोन लिया। उसमें भी घोटाला हुआ। जो सी ए जी की रिपोर्ट है 2011 की, उसमें साफ है कि एफ आर पी के माध्यम से कितनी फैक्टरियां चलीं, केबल खरीदी

(14.00 बजे)

गई, पोल खरीदे गये, आइसोलेटर खरीदे गये, मनमाने मीटर खरीदे गये, ब्रेकर खरीदे गये। तो इस तरह से जहां पर जरूरत नहीं थी, उसके बाद भी खरीदा गया।

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आप बिजली 24 घंटे देने की बात कर रहे हैं, उस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब क्राइसिस दुबारा से शुरू हो गया है और आप थ्री फेज भी पांच घंटे नहीं दे पा रहे हैं, 24 घंटे भी बिजली नहीं दे पा रहे हैं; मात्र 16 और 17, और रूरल में देखा जाए तो 14 घंटे तक ही बिजली मिल रही है। तो इससे अच्छी बिजली तो हम दे रहे थे आपको।

फिर उसके बाद आती है अभी आपकी बात कि हम 1,500 करोड़ के माध्यम से एफ.आर.पी., सुधार कार्यक्रम करेंगे और 24 घंटे बिजली देंगे, यही घोटाले का कार्यक्रम है, और सेकण्ड आता है आपका कि जयपुर शहर में हम 72 नए जी.एस.एस. बनाएंगे। 72 नए जी.एस.एस. में 60 तो 33 के.वी. के और उसके अलावा, 10 के करीब 132 के और 220 के.वी. के । तो ये सब चीजें बनाकर, इतना पैसा लगाकर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करूंगा कि अपने वक्तव्यों को, जो माननीय विधायक हैं, वे सीमित करें, क्योंकि आपका समय, आपको मालूम है,...

श्री रमेश (सपोटरा): मैंने कह दिया न, माननीय अध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 15 मिनट ले चुके हैं ये, 15 मिनट। 13 मिनट ही बाकी हैं और 15 मिनट ये ले चुके हैं। आप उनको निवेदन करें, मैंने तो निवेदन कर दिया। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सुनने की बात है। मैं अच्छी बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुनने की बात तो सब है लेकिन समय की सीमा के अन्दर आपको बोलना पड़ेगा। तीन बार आप कह चुके कि सुनने की बात, सुनने की बात; वह सुन ली लेकिन कितना सुनाएंगे आप?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपके पास सुनाने की बात ही नहीं है। जबरदस्ती।

श्री अध्यक्ष: 13 मिनट बचे थे और आप 15 मिनट बोल चुके हैं। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): मैं कह रहा हूं कि मेरी जगह और नहीं बोलेंगे। कह रहा हूं न, नहीं बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: इनके पास 13 मिनट ही बचे हैं। इनका नहीं है, इनका समय नहीं है, समय आपकी पार्टी का है और समय आपकी पार्टी का केवल 13 मिनट ही बचे हैं। (व्यवधान) अब आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): दो मिनट। दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट।

श्री रमेश (सपोटरा): तो मैं आपसे जो अहम बात कहना चाहता था कि बिजली कम्पनियों को प्राइवेट में, पी.पी.पी. माडल में हमारी सरकार देना चाहती है, तो क्यों देना चाहती है? यदि हमें अच्छा लगता कि रूरल में, इंटिरियर में, पी.पी.पी. माडल में, उन क्षेत्रों को पी.पी.पी. माडल में दें, लेकिन हमने जो सुना है कि पी.पी.पी. माडल पर जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, इन पांच शहरों को पी.पी.पी. माडल पर देना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले जयपुर की बात बताना चाहता हूं आपको कि जयपुर शहर में आज के टाइम जो छीजत है, वह 9.7 परसेंट छीजत है और यहां पर जो बिजली की सप्लाई होती है, हमारी कम्पनी के माध्यम से, तो 5 रुपए से साढ़े पांच रुपए प्रति यूनिट हमें उपलब्ध करवाती है, तो एक अच्छी जगह पर, जहां पर अच्छा हमें रेवेन्यू मिल रहा है, पी.पी.पी. माडल देने से क्या फायदा होगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल। अब आप स्थान ग्रहण कीजिए, दो मिनट हो गये आपके।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई बात ही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। आपकी पार्टी के केवल 13 मिनट ही थे, आप 15 मिनट बोल चुके हैं।

श्री रमेश (सपोटरा): डोटासराजी, उनको बोलें कि मुझे बोलना है। बहुत सारा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री जोगाराम पटेल।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपकी पार्टी का पूरा समय ले चुके हैं। अब आप विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, एक-एक मिनट करते-करते 15 मिनट तक पहुंच गये। आपकी पार्टी के हैं ही 13 मिनट, आप खुद काउंट कीजिए न, आप सचेतक हैं। आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रमेश (सपोटरा): दो मिनट बोलेंगे। दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं। दो-दो मिनट में तो ...(व्यवधान) माननीय सदस्य का एक शब्द भी अंकित नहीं होगा। एक शब्द भी अंकित नहीं होगा।

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मैं निवेदन करूं। रुकिये एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप विराजिए। मैंने आपसे निवेदन किया कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात तो सुन लो हमारी।

श्री अध्यक्ष: नहीं, विराजिए आप। आप अपने विधायक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): दस बार सुन चुके और एक मिनट, और एक मिनट। (व्यवधान) 15 मिनट ले लिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब आप विराजिए। जोगाराम पटेल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, बात तो सुन लीजिए। दो आगे के माननीय सदस्य हमारे नहीं बोलेंगे। इनको दो मिनट और दे दो। लास्ट के दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: 15 मिनट में बचेगा क्या? क्या बोलेंगे आप? मैं टाइम दूंगा, तब बोलोगे। केवल 13 मिनट बचे हैं, 15 मिनट तो इन्होंने ले लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उदार मना:।

श्री अध्यक्ष: इतना समय बरबाद कर रहे हैं। नहीं। आप बोलिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवर्तित बजट वर्ष 2014-15 पर अपना वक्तव्य देने ...(व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री अध्यक्ष: आपके प्रतिपक्ष के नेता से पूछिये कि कितना समय है आपका?

श्री रमेश (सपोटरा): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सीधा-सीधा आसन पर आरोप है कि अन्याय है। आसन ने व्यवस्था दी है और आसन के खिलाफ ही आप कह रहे हों कि अन्याय है। आसन के आदेश को आप अन्याय मानते हों?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आसन का सम्मान है। आसन का सम्मान है। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देंगे तो ठीक है, और नहीं देंगे तो, पर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं देंगे तो नहीं देंगे। हमारे अध्यक्ष हैं। कोई दिक्कत नहीं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। जोगारामजी, एक मिनट विराजिए आप। एक मिनट आप भी विराजिए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री, परिवर्तित बजट 2014-2015 के सम्बन्ध में शुद्धि-पत्र प्रस्तुत करेंगी।

परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-15 में भाषण में पढ़ते समय रही त्रुटियों का संशोधन

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा परिवर्तित बजट वर्ष 2014-15 का सदन में उपस्थापन कर बोलते समय कुछ आकड़ों, आदि में कहीं त्रुटियां रह गई थीं, जिनका विवरण मैंने सदन के

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पटल पर रख दिया है। कृपया परिवर्तित बजट बोलते समय रही त्रुटियों को मुद्रित बजट के अनुरूप संशोधित करने की कृपा करें।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: मुद्रण में जो जाए, तो आपने जो रखा है, उसके हिसाब से आप उसमें शुद्धि कर लें।

हां, जोगारामजी।

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे परिवर्तित बजट 2014-2015 पर अपना वक्तव्य देने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से इस बजट पर पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी बात कही जा रही है और वह बात अपने-अपने ढंग से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप दस मिनट में अपनी बात को खतम करेंगे। अपने भी बहुत वक्ता बोलने वाले हैं। इसलिए सबको एकोमोडेट करना है। दस मिनट।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 15 मिनट कर दें।

श्री अध्यक्ष: दस मिनट तो बोलो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वह मेरा पांच-सात मिनट तो यूं ही चला गया। कुछ आवश्यक बातें ही कहेंगे, बाकी नहीं कहेंगे।

तो मेरा निवेदन यह था कि इस सदन के माननीय सदस्यों ने अपने हिसाब से, अपने मतानुसार इस बजट के बारे में ये सब बातें कहीं। हम सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य जो हैं, वे अपनी बात कहेंगे, बजट के समर्थन में कहेंगे, अपने सुझाव भी रखेंगे और हो सकता है कि हमें कोई सुझाव देना है तो वह भी देंगे। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य हैं, उन्होंने अपने अनुसार बजट की समालोचना हो, आलोचना हो, टीका हो, टिप्पणी हो, वह सब की। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब के बीच में आखिर एम्पायर कौन? ऐसा तो नहीं है कि हमने कहा, वह ही सही है; ऐसा तो नहीं है कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो कहा, वह सही है, लेकिन इन सबके बीच में भी एक

(श्री जोगाराम पटेल)

एम्पायर और है। वह हमारी बात को और उनकी बात को तौलता है, पब्लिक के सामने रखता है और जगजाहिर करता है। यह कहा जाता है हिन्दुस्तान में कि प्रजातंत्र के तीन स्तम्भ हैं। दो स्तम्भ यहां पर हैं, पर एक तीसरा स्तम्भ है, वह हम दोनों पक्षों की बात को पब्लिक के सामने रखता है। वह तीसरा पक्ष है, चाहे हम उसको इलेक्ट्रोनिक मीडिया कहें, चाहे प्रिंट मीडिया कहें, उनके साथ एक पक्ष है जो इस सारे बजट का विश्लेषण करता है, जो विशेषज्ञ है। इस बजट के प्रस्तुत होने के उपरांत ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवधान डाला जा रहा है। इस बजट के पेश होने के बाद में राजस्थान के जो दो बड़े-बड़े प्रचलित अख़बार हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपस के विवाद को यहां पर मत करो। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): घर बैठकर निपट लेना।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 'राजस्थान पत्रिका' और 'दैनिक भास्कर' और अन्य जो प्रचलित अख़बार हैं, उन्होंने अपने-अपने हिसाब से विश्लेषण किया व उन सब विशेषज्ञों के कोटेशन भी कोट किए जिन्होंने इस बजट के बारे में अपने-अपने मत रखे। मैं आपके सामने उन विशेषज्ञों के मत, जो इस बजट के बारे में निष्पक्ष हैं, उनको किसी पक्ष या विपक्ष का लेना-देना नहीं है, उन्होंने जो कोट किये और उसमें सबसे पहले प्रोफेसर लक्ष्मीनारायण नाथूरामका, जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं उन्होंने इस बजट के बारे में क्या कहा है- 'राजस्थान के बजट के इतिहास में इस तरह का साहसी और चुनौतीपूर्ण बजट पहले कभी पेश नहीं हुआ। इस बजट की घोषणाएं अगर धरातल पर उतारी गईं तो यह राज्य के विकास का इंजन साबित होगा। भाजपा सरकार ने किसी घोषणा के जरिये लोक-लुभावनी सौगात बांटने के बजाए, रोजगार और निवेश बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया है।' यह प्रोफेसर लक्ष्मीनारायण नाथूरामका का मत है। उन्होंने यह भी कहा है कि 20 हजार किलोमीटर की लम्बी सड़कें बनाना, वार्षिक योजना का आकार 46 हजार करोड़ से बढ़ाकर 1 वर्ष में 69 हजार करोड़ रुपए करना, सात जिला मुख्यालयों पर मेडिकल कालेज खोलना, स्मार्ट सिटी, स्किल डवलपमेंट

(श्री जोगाराम पटेल)

यूनिवर्सिटी खोलना, कुछ ऐसे कदम हैं जो राज्य के विकास के लिए मील के पत्थर साबित होंगे।

इतना ही नहीं, बजट के जो विशेषज्ञ हैं, पंकज दहिया, जो वरिष्ठ सलाहकार भी हैं आयकर के, उन्होंने कहा है कि बजट में करदाताओं की उलझन को दूर करने का जहां सरकार ने भरपूर प्रयास किया है वहीं कुछ प्रस्तावों का दायरा बढ़ाया जाता है तो इन्हें राहत अधिक मिल जाती। वाणिज्य कर विभाग से कारोबारियों को व्यक्तिगत सम्पर्क करने के लिये, आनलाइन कर, करदाताओं को निश्चित राहत पहुंचायेगी।

माननीय महोदय, इतना ही नहीं, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जो पूर्व में भी आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रहे हैं, उन्होंने जो अपनी टिप्पणी की है, प्रो. वी.एस. व्यास, उन्होंने कहा है, राज्य में बजट तो इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने वाला दिख रहा है, लेकिन पहले पी पी पी के इंजन पर, पी पी पी माडल के इंजन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा जताया है, जो राज्य की तरक्की के लिये काफी हो सकता है।

इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब आर्थिक विशेषज्ञों के अलावा, अखबारों ने भी अपने-अपने तरीके से इसका विश्लेषण किया है। 'राजस्थान पत्रिका' ने अपने तरीके से किया, 'दैनिक भास्कर' ने अपने तरह से किया और अन्य अखबारों ने अपने-अपने तरह से किया है। लेकिन जो 'दैनिक भास्कर' ने अपनी तरफ से विश्लेषण किया है, उसे मैं कोट करना चाहूंगा- 'लेट मानसून और राजकोषीय घाटा, यानी, राहत भरा बजट आसान नहीं, लेकिन फिर भी सोमवार को मुख्य मंत्री, वसुन्धरा राजे ने सारा बोझ समझकर अच्छे दिनों का खाका खींचने की पूरी कोशिश की। हां, मुफ्त में कुछ नहीं दिया। कुछ नये कर लगाये, कुछ पुराने बढ़ाये ताकि खजाना भरा रहे।'

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये अख़बार पढ़ रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं किसी अख़बार को नहीं पढ़ रहा हूं, मैं उनके कोटेशन को कोट कर रहा हूं। I know very well each and everything. You please hear me. You have some trouble because you do not know, what is the analysis by the Experts. You do not know.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सबने पढ़ रखा है वह।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय महोदय, इतना ही नहीं.......

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): You do not know very well.

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ...बरतन भोटो है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। डिस्टर्ब मत कीजिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अखबारों ने अपने-अपने तरीके से अपने-अपने विश्लेषण किये हैं, ...(व्यवधान) अपने-अपने तरीके से जो घोषणाएं की हैं, उसके सम्बन्ध में भी टीका-टिप्पणी की है; अपने एडिटोरियल लिखे हैं और उन्होंने यह भी लिखा है कि इस तरह से बजट पेश किया गया है... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, अख़बार पढ़ रहे हैं! बताइये। परमिशन ही नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कौन पढ़ रहा है अख़बार?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अख़बार यह रहे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अख़बार पढ़ कौन रहा है? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, टेबल कराइये; जो पढ़ रहे हैं, वह टेबल कराइये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कोई नहीं पढ़ रहा है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अख़बार दिख रहा है, सदन के कैमरे में आ रहा है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): और तारे दिखेंगे दिन में।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अख़बार नहीं पढ़ सकते आप। (व्यवधान) इनके अपने विचार सुनने थे। (व्यवधान) इसकी जरूरत नहीं है। व्यवस्था दीजिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): कल आपने ही कहा था कि सदन में अख़बार नहीं पढ़ेंगे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कौन पढ़ रहा है? (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप पढ़ रहे हों। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, टेबल कराओ।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): टेबल करो कागज को।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं बोल रहा हूं, आप सुनो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): कागज को टेबल करो। आपके हाथ में अख़बार दिख रहा है, अन्धे को भी दिख रहा है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप होते कौन हो कहने वाले? Who are you?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हाउस की प्रोपर्टी है। जो आप बोल रहे हैं, हाउस की प्रोपर्टी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दीजिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): सदन में अख़बार को पढ़ने को लेकर पूरी चर्चा हो चुकी है। उसके बावजूद माननीय सदस्य अख़बार पढ़ रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कोई अख़बार नहीं पढ़ रहा हूं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप टेबल कर दो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): तकलीफ होगी, भारी तकलीफ होगी। विशेषज्ञों के विश्लेषण आयेंगे, तथ्य आयेंगे। 'राजस्थान में पहली बार', अभी यह भी आयेगा। अभी सुनो तो सही। अभी तो शुरुआत हुई है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप अख़बार मत पढ़ो, बाकी तो कुछ भी बोलो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय कोट किया गया है, वह विभिन्न विशेषज्ञों ने अलग-अलग तय किये। उन विषयों का अखबारों ने ही एनालाइसिस नहीं किया, विशेषज्ञों ने भी एनालाइसिस किया और एनालाइसिस करने के उपरान्त उन्होंने जो अपनी टीकाएं कीं, अपने जो एडिटोरियल नोट लिखे, विशेषज्ञों के जो मत लिये, उनके अनुसार एक भी ऐसा तथ्य, एक भी ऐसी टीका-टिप्पणी, पिछले दो दिन से हो रही टीका-टिप्पणी में एक भी एक ऐसा तथ्य बता देते, जो आलोचना का आधार बनता, जो टीका-टिप्पणी का आधार बनता, जो आलोचना-समालोचना का आधार बनता। सिर्फ यह कह देना कि साहब, यह ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, एक भी तथ्य ये नहीं बता पाये।

इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज के विभिन्न वर्ग, व्यापारी वर्ग, दूसरे सारे वर्ग, जिनमें मुख्य रूप से व्यापार और उद्योग वर्ग हैं, उन सबने भी अपनी-अपनी टीकाएं-टिप्पणी की हैं और उन्होंने अपना-अपना नोट दिया है, अपने-अपने मत व्यक्त किये। उन मत व्यक्त करने वालों में जो मुख्य रूप से हैं, वह फेडरेशन आफ राजस्थान ट्रेड और इंडस्ट्री के अध्यक्ष हैं,

(श्री जोगाराम पटेल)

उन्होंने यह कहा है कि इससे बढ़िया बजट आज दिन तक हमने नहीं देखा। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे इन ट्रेड और इंडस्ट्री के लिये सबसे महत्वपूर्ण बजट है। वह उनका जो नोट था, उनके जो मत थे, वे इसमें कोट हुए हैं।

इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात माडल के नोट को माना गया है और 'फोर्टी' के संरक्षक सूरजाराम मील, उन्होंने भी अपना नोट दिया है कि इससे बढ़िया बजट हमने आज दिन तक नहीं देखा। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, और भी हैं। 'फोर्टी' के महामंत्री महोदय ने भी अपना मत व्यक्त किया है और उन्होंने भी यह कहा है कि इससे बढ़िया बजट हमने आज दिन तक नहीं देखा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं ...

श्री अध्यक्ष: आप समाप्ति की ओर चलिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जी, माई लार्ड।

श्री अध्यक्ष: दस मिनट हो गये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन सब विशेषज्ञों के मत के आधार पर देखा जावे तो बजट उस तबके के निगाह में है जो निष्पक्ष है, स्वतन्त्र है, अपनी टीका-टिप्पणी करने के लिये स्वतन्त्र है। उन्होंने सबने इस बजट को पूरी तरह से सराहा है। एक तो मेरा निवेदन यह है।

दूसरा, निवेदन यह है कि अखबारों ने दूसरे दिन....

श्री अध्यक्ष: अब आगे कहां पढ़ रहे हैं? दस मिनट हो गये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अभी तो शुरू हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बीच में बार-बार व्यवधान हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अखबारों में बजट पेश होने के दूसरे दिन दो आलोचनाएं आई, एक तो माननीय पूर्व मुख्य मंत्री की आई, दूसरी कांग्रेस पार्टी के माननीय प्रदेशाध्यक्ष की आई। दोनों की टिप्पणियों को आप ध्यान लगाकर पढ़ें, एक भी तथ्य यह नहीं कि उस पर कोई टीका करे कि रिफाइनरी को ऐसे डार्क बस्ते में डाल दिया, इसलिये यह गलत है; और दूसरी माननीय प्रदेशाध्यक्षजी की जो टिप्पणी आई, उसमें आलोचना का एक बिन्दु नहीं। आप आलोचना कीजिये, आप बिन्दु बताइये। उस पर यह कहिये कि यह गलत है, राजस्थान के भविष्य के लिये गलत है, राजस्थान के आने वाले वित्तीय वर्ष के लिये गलत है, राजस्थान की जनता के लिये गलत है। एक भी ऐसा आधार

(श्री जोगाराम पटेल)

आपने नहीं बताया, जिसकी वजह से उस बजट की आलोचना की जा सके। कल से लगाकर आज दिन तक, जैसा अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, सिर्फ यह गलत है, पहले उन्होंने यह किया, साहब, लेकिन तथ्यात्मक कोई भी, एक बात भी सामने नहीं रखी।

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरू हुई है। हमारे दूसरे सदस्यों का समय काट लीजिये। हम तैयार होकर आये हैं।

श्री अध्यक्ष: काटना नहीं, किसी दूसरे सदस्य का यहां टाइम नहीं है। पार्टी के हिसाब से मैंने आपको दस मिनट दिये, और चूंकि यह ग्यारहवां मिनट चल रहा है...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरे पांच-सात मिनट तो यूं ही, बातों में ही जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: पार्टी का टाइम है और सबको बुलाना है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी समाप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष: अब विराजिये आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ बजट पर।

श्री अध्यक्ष: हां, इसीलिए तो विराज जाइये आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): शार्ट में बोल देता हूं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट और बोल लो आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक यह भी निवेदन है कि आपने एक नारा दिया था पिछली बार, 'राजस्थान में पहली बार', और 'राजस्थान में पहली बार' वाला बहुत जोरदार, एक-एक खुलकर विज्ञापन, इनके खुद की सरकार की ओर से विभिन्न अखबारों में छपाये गये और इन्होंने प्रेस में बांटा और हमको भी दिया गया। उस सब में यह कहा था कि 'राजस्थान में पहली बार', और उसमें पूर्व मुख्य मंत्रीजी का एक कोटेशन था, जो मैं पढ़ रहा हूं, उनके हस्ताक्षर से था – ''खुशी और गम की बात है कि आज राजस्थान कई प्रदेशों के लिये रोल माडल बन गया है। हमारी योजनाओं

(श्री जोगाराम पटेल)

को दूसरे प्रदेशों में भी लागू करके देख रहे हैं।'' इसका जनता ने जवाब दिया। राजस्थान रोल माडल कैसा बना, 200 में से 163 एक पार्टी की आ गयीं; रोल माडल कैसा बनाया, 25 में से 25 सीटें एक पार्टी की आ गयीं। रोल माडल कैसा बना, जो मत प्रतिशत था, वह कहां से कहां चला गया, और रोल माडल कैसा बना कि इनका एक भी ...(व्यवधान)

(14.20 बजे)

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदया, यह रोल माडल राजस्थान के सामने रखा गया, जिसका जनता ने जवाब दे दिया।

इन सबके बाद में जो तीसरा विषय है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यह रोल माडल क्या बना, हमारे सामने देखिये, प्रतिपक्ष के नेता, जो पहली बार हमारे इस सदन के सदस्य बने, वे प्रतिपक्ष के नेता बन गये। चाहे आठ बार, चाहे नौ बार और उससे कम या ज्यादा बार जीत कर आये हैं, वरिष्ठ हैं, वे नहीं बने। यह भी है। और जो पहले बजट का जवाब देने खड़े हुए, वह भी हमारे प्रतिपक्ष के नेता खड़े नहीं हुए। यह भी रोल माडल है। और रोल माडल आपके सामने रखूं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आप, पता नहीं, कितने पूर्व मंत्री रहे, फिर भी मंत्री नहीं बन रहे हैं। इस पर भी बोलो दो मिनट।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इतना भी देखें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, बीच में न टोकें। आप अपनी बात को अब जरा जल्दी से सम अप करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जी, कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदया, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बिन्दु है तो वह बिन्दु है ऊर्जा का। ऊर्जा का बिन्दु है, वह इतना महत्वपूर्ण है कि उसके आधार पर ही अर्थव्यवस्था को देखा और महता जाता है। देश में बिजली सर्व-प्रथम 1920 में आयी और तत्कालीन राजा-महाराजाओं ने अपने-अपने हिसाब से छोटे-मोटे यंत्र लगा कर बिजली की व्यवस्था की। आजादी के बाद सब बिजली देने के प्रयत्न करने लगे। मुख्य रूप से भाखड़ा,

(श्री जोगाराम पटेल)

एन.टी.पी.सी., कोयला आधारित संयंत्र, चम्बल, माही परियोजना, न्यूक्लीयर बिजलीघर, गैस आधारित संयंत्र और 1980 तक और उसके बाद, 79 तक स्थिति ठीक थी, उसके बाद धीरे-धीरे इस बिजली की स्थिति बिगड़ने लगी लेकिन मैं आपके सामने जो महत्वपूर्ण बिन्दु रखना चाहता हूं, वह यह है कि हम कहां खड़े हैं, राजस्थान कहां खड़ा है, इसको जज करना जरूरी होगा। अगर इसका कम्पेरिजन हम अन्य देशों से, अन्य कम्पनियों से करें तो हम देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति बहुत भयंकर है। आप छीजत के लिहाज से लेवें, आप अन्य लिहाज से लेवें, विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न देशों में इसकी जो स्थिति है, वह स्थिति अपने से बिलकुल भिन्न है। एक तरफ आप देखें कि दूसरे देशों में हमारे से छीजत बहुत कम है और हमारे देश में सबसे अधिक छीजत है और धीरे-धीरे छीजत बढ़ती जा रही है। हालांकि हमारी उत्पादन क्षमता वर्तमान में तापीय से, जल विद्युत से, गैस से 5,405 मेगावाट हो गयी है लेकिन फिर भी कम है और केन्द्रीय परियोजना से जो हमारी क्षमता बढ़ गयी है, वह 2,796 हो गयी, फिर भी कम है। इनके सबके बावजूद भी, आज भी विश्व में सबसे कम स्तर पर है। दूसरे, चाहे अमेरिका है, चाहे जापान है, चाहे इंग्लैण्ड है, उनकी छीजत हमारे से बहुत कम है, परन्तु हमारी छीजत सबसे ज्यादा है। इतना ही, माननीय सभापति महोदया, जो बिजली की खपत है, वह भी हमारे यहां कम है, अन्य देशों में इससे ज्यादा है।

इसलिए मेरे इस सम्बन्ध में दो सुझाव हैं, एक तो यह कि हम छीजत कम करें। इसके लिए जितना सरकारी स्तर पर प्रयास हो सकता है, माननीय सदस्यों के स्तर पर प्रयास हो सकता है, आम जनता के स्तर पर प्रयास हो सकता है, हम जितना छीजत को कम करेंगे और उत्पादन को बढ़ायेंगे, वह हमारे देश के लिए बहुत जरूरी होगा।

इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदया, जो कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु हैं उन बिन्दुओं की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। वर्तमान सरकार की इस बजट में जो प्राथमिकताएं हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका समय पूरा हुआ है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): दो मिनट। वर्तमान सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं को देखें तो लगता है कि यह एक जोरदार विजन का बजट है और यह जो विजन का बजट है, सबको साथ लेकर चला है। तो इसीलिए कहा है –

(श्री जोगाराम पटेल)

'ऊपर जिसका अंत नहीं, उसे आसमां कहते हैं;

जहान में जिसका अंत नहीं, उसे मां कहते हैं;

जहान में जिसका अंत नहीं, उसे वसुन्धरा कहते हैं।'

इस विजन के साथ यह बजट आपके सामने रखा गया है।

मैं यह कहना भी चाहता हूं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कृपया ध्यान लगा कर सुनें, वक्त भी सिखाता है और टीचर भी सिखाता है, पर दोनों के सिखाने में फर्क है, टीचर सिखा कर इम्तहान लेता है और वक्त इम्तहान लेकर सिखाता है। सीख जाओ नहीं तो दो लाइनों से भी और संख्या कम हो सकती है।

मैं इतना भी निवेदन करना चाहूंगा...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, सोना देवी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरी एक लाइन है, एक मिनट में।

मैं निवेदन भी करना चाहूंगा, निवेदन यह करना चाहूंगा, मेरे कुछ महत्वपूर्ण निवेदन हैं और वह निवेदन यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में बिजली उपलब्ध करवायी जावे। वह महत्वपूर्ण यों है कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है...

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): आपका टाइम पूरा हुआ, माननीय सदस्य, कृपया किसी और को भी बोलने दीजिएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: बस अंतिम लाइन। अंतिम लाइन। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक सेकण्ड। वह लाइन पूरी नहीं हुई। एक मिनट। मेरा निवेदन दो लाइनों में है। (व्यवधान)

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदया, आपने हमें बोलने का टाइम दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं, उसके बाद बंद।

श्री सभापति: नहीं, विषय नहीं। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक लाइन का। (व्यवधान)

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): नहीं, आपको टाइम नहीं दिया जायेगा। यह क्या मतलब हुआ? आपका, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक मिनट। एक मिनट। (व्यवधान)

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): एक मिनट बिलकुल नहीं मिलेगा। कृपा कर के हमारी बात सुनी जाए। (व्यवधान) आपसे निवेदन है, आपको अब एक मिनट नहीं मिलेगा। आपको एक मिनट करते-करते पन्द्रह मिनट हो चुके हैं।

श्री सभापति: आप बैठिये, माननीय सदस्या। माननीय सदस्या, सोनादेवी जी, एक मिनट आप बैठो। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा टाइम तो वे ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): एक मिनट क्या? आपकी पार्टी को 12 घंटे मिल गये तो भी आपको संतुष्टि नहीं मिली क्या? आपकी पार्टी को 12 घंटे मिल गये, तब भी आप संतुष्ट नहीं हुए। अब एक मिनट से आप क्या कहना चाह रहे हैं?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप हो कौन?

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): एक मिनट में क्या बताना चाह रहे हैं आप?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक मिनट। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठ जाइये। बैठ जाइये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): एक मिनट में बजट में क्या विकास कर पायेंगे आप?

श्री सभापति: अच्छा, आप बोलें अपनी बात। कहिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा निवेदन यह था...

श्री सभापति: हो गयी, हो गयी बात।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक मिनट मेरा हुआ ही नहीं पूरा। एक मिनट में तो वे बीच में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: हो गया पूरा आपका। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक मिनट ही।

श्री सभापति: एक-एक मिनट करते हुए आपने कितने, 20 मिनट हुए हैं आपको बोलते हुए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा निवेदन यह था कि अभी जो हमारे राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है जोधपुर की जीरा मंडी...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप बैठ जाइये, आपका हो गया। अब आप बैठ जाइये। मैंने माननीय सदस्या, सोनादेवी का नाम पुकारा है, अब वे बोलेंगी। आप बैठ जाएं। आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

अंकित नहीं होगा यहां पर इनका, जोगारामजी का। अब माननीया सोनादेवीजी बोलेंगी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): धन्यवाद, सभापति महोदयाजी। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री सभापति: बोलें आप। अपनी बात बोलिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदया, सरकार ने बजट की घोषणा नम्बर 153 में घोषणा की कि राज्य भर की प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करवा दी जायेगी, लेकिन रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र की स्थिति मैं अवगत करवाना चाह रही हूं कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में 20 है व राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की संख्या लगभग 83 है और इन विद्यालयों में लगभग 5 प्रिंसिपल हैं, 50 हैडमास्टर हैं, 53 लेक्चरार, 190 सेकण्ड ग्रेड व तीन थर्ड ग्रेड; इनके अलावा, फोर ग्रेड के भी बहुत से पद रिक्त पड़े हैं, जिस कारण से शिक्षण व्यवस्था में हालात बेहद ही खराब हैं और लोगों को मजबूरन अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजना पड़ रहा है।

मतलब, मैं यह कहना चाह रही हूं कि विद्यालयों की व्यवस्था, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था के लिए बजट में घोषणा कर दी गयी है परन्तु जिन विद्यालयों में, वर्तमान में जो विद्यालय हैं, जिनमें शिक्षकों की कमी है, वहां पर उनके लिए सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। पूरे जयपुर की सड़कों पर विद्यार्थी मित्र धरने पर बैठे हैं, उनके लिए कोई भी आश्वासन वर्तमान सरकार ने नहीं दिया है। तो कृपया इसकी ओर ध्यान आकर्षण करना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदयाजी, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाह रही हूं कि सरकार ने एल.डी.सी. भर्ती परीक्षा को रद्द कर के हजारों परिवारों के सामने रोजगार का संकट पैदा किया। इसके साथ खान विभाग है, हजार पदों की भर्ती पर रिजल्ट आने के बाद रद्द कर दिया, और नरेगा और

(श्रीमती सोना देवी)

एन.आर.एच.एम. संविदा-कर्मियों की भर्ती तथा स्थायी करने की बात भी नहीं की गयी और न ही बजट में बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, जो कि भा.ज.पा. ने घोषणा पत्र में लिखा था।

प्रदेश में एक के बाद एक परीक्षाएं अनियमितताओं के चलते रद्द हो रही हैं और आर.पी.एस.सी. सब्जी मण्डी की तरह हो गयी है। चाहे जो जाता है, सेटिंग कर के अधिकारी बन जाता है। विगत छह दिन पहले आर.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित दो परीक्षाएं, आर.ए.एस.-प्री और प्राध्यापक की कामर्स की परीक्षाएं रद्द कर दी गयीं तथा सेकण्ड ग्रेड की अध्यापक की भर्ती में अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही हैं। अभी हाल ही में पकड़े गये अमृत लाल मीणा को पूर्व में आर पी एस सी का पेपर बेचते पकड़ा गया था, लेकिन पुलिस ने कमजोर केस बना दिया और उसकी जमानत कर दी गयी। इस पूरे मामले की सी आई डी से जांच करवाकर आर पी एस सी की विश्वसनीयता को कायम रखें।

सभापति महोदया, प्रदेश के विधायकों को अपनी मांग मनवाने के लिए जगह-जगह धरना, आमरण अनशन करना पड़ रहा है। जैसे कि नागौर के कलेक्ट्रेट पर किसानों की बिजली की मांग को लेकर के खींवसर के विधायक ने 41 दिन का धरना दिया; सांचौर विधायक ने उद्योग मैदान पर 7 दिन का धरना दिया; और जहाजपुर विधायक ने 3 दिन धरना दिया। रायसिंहनगर विधायक, मैंने खुद ने विजयनगर, शहर के वार्ड नंबर 3 और 4 के गंदे पानी की निकासी के लिए 7 दिन का धरना दिया और जल समाधि तक की घोषणा की। आज तक उसका कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ।

सभापति महोदया, मैं सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहती हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि बताया गया कि जो कमजोर वर्ग हैं, उनकी प्राथमिक शिक्षा पर 1 करोड़ 50 लाख का खर्च होगा, यह बजट दिया है। शिक्षा को महत्व देते-देते, दूसरी तरफ जो शिक्षित बच्चे हैं, विद्यार्थी मित्र आज सड़क पर उतर गये हैं। शिक्षा को अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो क्या उनको सड़क पर बैठने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं? मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि जो सड़क पर बैठे विद्यार्थी मित्र हैं, उनकी तरफ भी अपना ध्यानाकर्षित करें और गम्भीरता से इस स्थिति का निपटारा करें।

सभापति महोदया, मैं इसके साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगी कि बजट

(श्रीमती सोना देवी)

में आपने बीकानेर में कैंसर के इलाज के लिए जो मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगी कि कैंसर की बीमारी का इलाज करने का प्रावधान तो सरकार ने किया है, लेकिन यह कैंसर की बीमारी कहां से होती है, इसका स्थायी समाधान किया है? कैंसर की बीमारी क्यों हो रही है, इसकी मूल जड़ क्या है, इसको सरकार ने नहीं देखा है। पंजाब से नहर में जो केमिकल्स और गंदगी आ रही है, वह इस कैंसर का मुख्य कारण है। इसको खतम करने के लिए सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। बार-बार यह बताया जाता है कि सरकार कर्ज में है, कर्ज में होकर के भी सरकार कैंसर की बीमारी के लिए मेडिकल कालेज का पैसा तो दे रही है, लेकिन यह जो कैंसर बन रहा है, इसकी मूल जड़ की तरफ अपना ध्यानाकर्षित नहीं कर रही है।

सभापति महोदया, इसके साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगी, गंगानगर जिला, जो कि सीमावर्ती एरिया है, उसके अन्दर माननीय बी.डी. अग्रवालजी ने 250 करोड़ रुपये मेडिकल कालेज बनाने के लिए दान में दिये। उस सीमावर्ती एरिये की जनता चाहती है कि मेडिकल कालेज के लिए जो 250 करोड़ रुपये सरकार को फ्री में मिल रहे हैं, तो उसमें क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं? वह कर्ज में कम ही होंगे ना। यह वहां की जनता की सुविधा के लिए है? वह 250 करोड़ रुपए दान में दिये जा रहे हैं तो उसकी तरफ सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है? इसके लिए भी हमने आमरण अनशन तक की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ।

सभापति महोदया, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि पूरे राज्य भर में से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की जनता को जो डीजल मिल रहा है, वह 2 रुपये प्रति लीटर महंगा मिल रहा है। यह उन जिलों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अलका सिंह।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): सभापति महोदया, पहली बार बजट पर बोल रही हूं, इसलिए पक्ष और विपक्ष, अगर कोई त्रुटि रह जाये तो माफ करेंगे, यह मैं उम्मीद करती हूं।

सबसे पहले मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को इस शानदार बजट के लिए बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने इस बजट में राज्य के विकास का विजन

(श्रीमती अलका सिंह)

लिया है और राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का संकल्प अपना दुबारा प्रस्तुत किया है।

यह बजट किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए और हर तरह के विकास के लिए कटिबद्ध है। जब यह बजट प्रस्तुत हुआ था, उसके पश्चात् जब मैं मीडिया के जो चैनल्स हैं, उनमें देख रही थी, सब जगह एक्सपर्टस की यह राय आ रही थी कि यह बजट इस तरह का है, जैसा कि चुनावी वर्ष में कोई सरकार अपना बजट रखती है। यह बात यह शो करती है कि किस तरह का विजन लेकर हमारी यह सरकार इस बार जनता के बीच में आयी है।

सभापति महोदया, कुछ आंकड़े इस बारे में देना चाहूंगी, जी एस डी पी में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री व अन्य का जो प्रतिशत शेयर था, उसका तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करना चाहूंगी। 2008-09 में जब हमारी सरकार ने राजस्थान का राज छोड़ा था, उस वक्त तक एग्रीकल्चर का जी एस डी पी में शेयर था, 21.41 परसेंट; 2013-14 में कांग्रेस ने इसको 21.27 परसेंट कर दिया। एग्रीकल्चर का कम शेयर होने का मतलब होता है कि किसानों की जो परचेजिंग पावर है, वह कम हो जायेगी। लेकिन उस सरकार ने किसानों के हित के लिए कुछ भी नहीं किया।

सभापति महोदया, सर्विसेज की मैं बात करूंगी, इंडस्ट्री का 2008-09 में जी एस डी पी में शेयर था, 31.40 परसेंट; 2013-14 में कांग्रेस की सरकार ने इसको छोड़ा 28.54 परसेंट पर। मतलब, एग्रीकल्चर का शेयर भी कम हुआ और जब एग्रीकल्चर का शेयर कम होगा तो रोजगार की संभावनाएं भी कम हो जायेंगी।

वैसे भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के नाम पर एक भद्दा मजाक किया था, रोजगारों का कोई सृजन नहीं किया था। विज्ञप्ति निकालते थे और जो बेरोजगार युवा होते थे, वे फार्म भरते थे, उनका पैसा भी उसमें लग जाता था और फिर कुछ अपने ही लोगों द्वारा कोर्ट में ले जाकर उन पर रोक लगा दी जाती थी। यह तो इतिहास है राजस्थान की पुरानी 5 साल की सरकार का। हमारी सरकार ने 15 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है और यह लक्ष्य इस बजट में अच्छी तरह परिलक्षित होता है।

सभापति महोदया, एक और चीज हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया

(श्रीमती अलका सिंह)

ने कही है, कौशल विकास पर जोर दिया है। कौशल विकास होगा तो हमारे जो युवा हैं, वे सरकारी नौकरियों की तरफ नहीं देखेंगे, वे स्व-रोजगार की तरफ भी जायेंगे। जब स्व-रोजगार की तरफ जायेंगे तो निश्चित रुप से समाज का विकास होगा।

सभापति महोदया, अब मैं प्रतिवर्ष ग्रोथ रेट बताना चाहूंगी। 2008-09 में हमने जब सरकार छोड़ी थी, तब एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट थी, 4.93 परसेंट; और 2013-14 में जब कांग्रेस की सरकार गयी है, तब एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है, 2.22 परसेंट। मतलब, एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी किसानों के लिए इन्होंने कोई हितकर कार्य नहीं किये हैं। हमारे कृषकों का भी इन्होंने भट्ठा बैठा दिया है।

सभापति महोदया, इसी तरह सर्विस सेक्टर में, जिसमें शिक्षा, अस्पताल, बैंक, होटल सभी आते हैं, उसकी ग्रोथ रेट बताना चाहूंगी। 2008-09 में जब हमने सरकार छोड़ी थी तो उसकी ग्रोथ रेट, 12.89 परसेंट; और 2013-14 में कांग्रेस ने जब सरकार छोड़ी है तो वह ग्रोथ रेट रह गयी, 8.50 परसेंट। मतलब, इन्होंने कोई-सा भी सेक्टर नहीं छोड़ा है जहां कि गिरावट नहीं आयी है। जी एस डी पी की पर ईयर ग्रोथ रेट 2008-09 में थी, 9.09 परसेंट; और 2013-14 में जब कांग्रेस ने सरकार छोड़ी तो उसकी ग्रोथ रेट हो गयी, 5.31 परसेंट।

ये कुछ प्रमुख सेक्टर्स के आंकड़े मैंने प्रस्तुत किये हैं जो कि इकोनोमी में बूस्ट लाते हैं। इन्होंने इकोनोमी में बूस्ट लाने के बजाय, इकोनोमी को बिलकुल डाउन कर दिया है।

सभापति महोदया, जी एस डी पी में कर्जे के आंकड़े मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। 2007-08 में जब हम छोड़कर गये थे तो 1.28 परसेंट था और फिस्कल डेफिसिट हमारा था, 1.75 परसेंट। वित्तीय प्रबंधन में, हमें बेस्ट वित्तीय प्रबंधन के लिए माननीया मुख्य मंत्री महोदया को बताया गया था। इसी वजह से, उस समय जो केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार ने हर वर्ष राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इंसेंटिव दिया था। लेकिन अभी 2013-14 में कांग्रेस छोड़कर गयी है, 3.47 परसेंट जी एस डी पी में कर्जा हो गया। इन्होंने चार्वाक सिद्धांत का पालन किया है, 'ऋण लेवेत घृत पीवेत'; यानी घी तो बीच के लोग खा गये और जनता को इन्होंने छाछ पिलायी है। अब जो फिस्कल डेफिसिट हो गया है, वह 3.56 परसेंट है। टेंथ फाइनेंस

(श्रीमती अलका सिंह)

कमीशन ने कहा था कि 2.9 परसेंट से अगर फिस्कल डेफिसिट अधिक होता है तो स्टेट में इकोनोमिक क्राइसिस हो जाता है। फाइनेंस कमीशन का कहना 3 परसेंट से कम ही होना चाहिये। अब यह 3.5 परसेंट है तो निश्चित रूप से राज्य में आर्थिक संकट की स्थिति है।

सभापति महोदया, पूर्ववर्ती सरकार का जो बजट था, वह वोट-आकर्षित-गवर्नेंस का बजट और हमारा गुड-गवर्नेंस का बजट है। पूर्ववर्ती सरकार ने जनता को कम्बल बांटें, साड़िया बांटी, लैपटाप बांटें, यहां तक कि नकदी बांटी। राजस्थान के इतिहास में यह पहली सरकार है कांग्रेस की, जिन्होंने कि जनता को नकद पैसा बांटा। और यह बांटने की जो प्रवृत्ति है, वह धीरे-धीरे तेज होती गई, जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते गये। बजट के समय इन्होंने जो लाभार्थियों की संख्या बताई थी, वह थी 14.40 लाख और बजट में प्रावधान किया था 880 करोड़ रुपये का, लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते गये, वैसे-वैसे यह संख्या भी बढ़ती गई और अंत में यह संख्या हो गई 57.15 लाख। बजट में अब हमारी सरकार पर जो भार आया है, वह आया है 3,383 करोड़ रुपये का। बजट में प्रावधान नहीं किया गया था लेकिन फिर भी यह अनुदान, ये योजनाएं, यह पैसा, यह कम्बल, यह साड़ी, सब बांटी गईं। इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य, माननीय राव राजेन्द्र सिंहजी ने प्रिविलेज मोशन भी मूव किया था।

मैंने कुछ तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जिनसे पता चलता है कि उनके और हमारे वित्तीय प्रबन्धन में कितना अंतर है और किस तरह विकास का विजन लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है।

मैं अब माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देते हुए बताना चाहूंगी कि हमने इस बजट में 20 हजार किलोमीटर सड़कों का प्रावधान किया है और इसके अतिरिक्त, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने स्टेट हाइवे अथोरिटी गठन करने का भी इस बजट में प्रावधान किया है, जिससे कि न केवल सड़कें बनेंगी, बल्कि उनके रखरखाव के लिए और वे अच्छी क्वालिटी की बनें, उसके लिए भी मानिटरिंग की व्यवस्था होगी।

एनर्जी के क्षेत्र में 25 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है और यह लक्ष्य जो हमारी चुनावी घोषणा पत्र में था, 24 घण्टे बिजली देने

(श्रीमती अलका सिंह)

का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने में सफल हो जायेगा। पानी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर प्राधिकरण बनाने की घोषणा की है ताकि साफ और स्वच्छ पानी ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध हो।

एक और बात आती है कि पी पी पी मोड, इसकी बहुत आलोचना सामने बैठे हुए सदस्य करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पी पी पी मोड वास्तव में परफेक्ट-प्रोग्रेस-फोर-पब्लिक होगा, जब इसका परिणाम सामने आयेगा। क्योंकि जनता का जुड़ाव जब जनता के साथ हो जायेगा तो निश्चित रूप से वे योजनाएं सफल होंगी।

माननीया मुख्य मंत्री महोदया को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी देवनारायण योजना में 500 करोड़ की व्यवस्था करने के लिए। पिछली बार भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 283 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी देवनारायण योजना के लिए, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसका पैसा कम कर दिया था। उसे 500 करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई है; इन्फ्रास्ट्रक्चर के डवलपमेंट पर ध्यान दिया जायेगा, यह और बताया गया, इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्री महोदया को साधुवाद देना चाहूंगी।

एक और चीज इस बजट में कही गई है, ट्यूरिज्म। हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्य कहते हैं, नाच-गाने से क्या फायदा है, तो मैं बताना चाहूंगी कि हमारे यहां रिच हेरिटेज कल्चर की है, यहां की कला और संस्कृति पर हमें गर्व है और इस कला और संस्कृति के लिए डेजर्ट सर्किट बनाने की घोषणा माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने की है, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देती हूं।

मैं दौसा जिले के बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र से आती हूं और मेरे एरिये में भी एक आभानेरी, पुरा-महत्व की बावड़ियां हैं, जो कि यूनेस्को की साइट पर हैं। वर्ल्ड हेरिटेज उनको डिक्लेयर किया गया है और डेली वहां दो से पांच हजार के बीच में पर्यटक आते हैं। अभी यूनेस्को की तरफ से वहां बजट आया है, 48 लाख का डवलपमेंट उस जगह का किया जा रहा है। मैं माननीया मुख्य मंत्री महोदया का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने जो राज्य का पर्यटन मैप है, उस पर आभानेरी को सम्मिलित किया है और 26 से 28 सितम्बर तक आभानेरी उत्सव मनाने की घोषणा हुई। एक चीज और मैं मांग करना चाहूंगी इस क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि यहां पर पर्यटक आते हैं और

(श्रीमती अलका सिंह)

पर्यटन और जो ट्यूरिज्म है, it is a business; it is very serious business. बहुत अच्छा रेवेन्यू यह हमको दे सकता है। इसलिए आभानेरी के विकास के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया जाये, यह मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीया मुख्य मंत्री महोदया से।

अब मैं विपक्ष के सदस्यों को, सदन को यह बताना चाहूंगी कि हम लोग पक्ष में रहते हैं, विपक्ष में रहते हैं, योजनाएं हमारी आती हैं, बहुत अच्छी योजनाएं होती हैं कई, लेकिन प्रोब्लम आती है क्रियान्विति में, उनकी डिलीवरी में और जब डिलीवरी में कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है तो जो वास्तविक लाभ उन योजनाओं का बनता है, होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। हम लोग एक दूसरे की आलोचना में ही अपना समय व्यतीत कर देते हैं।

हमारी माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने ई-गवर्नेंस और गुड-गवर्नेंस का नारा दिया है। तो विपक्षी सदस्यों से मैं कहना चाहूंगी कि आप हमारी इस मुहिम में शामिल होइये और प्रदेश के विकास के लिए गुड-गवर्नेंस का साथ दीजिये; नहीं तो, आप देखते हैं कि सर्विस इण्डस्ट्री, पी एच ई डी देख लीजिये, पी डब्ल्यू डी देख लीजिये, सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। आपका आबकारी विभाग, खनन विभाग, ट्रांसपोर्ट, कहीं भी चले जाइये, इनके कर्मचारियों को देखिये, इनके पास करोड़ों की सम्पत्ति होती है। फोरेस्ट की जहां तक बात करना चाहें, पौधारोपण का इनका रिकार्ड अगर आजादी के बाद का देख लिया जाये, तो आज तक जो रिकार्ड में पौधे हो रहे हैं अगर उनको सही मान लिया जाये, तो एक इंच भी जमीन राजस्थान में ऐसी नहीं बचेगी, जहां पौधा नहीं हो। लेकिन क्या है वास्तविक स्थिति? वास्तविक स्थिति बिलकुल इसके विपरीत है। ये चीजें अनवरत जारी रहेगी, अगर पक्ष और विपक्ष हम लोग बैठकर एक साथ गुड-गवर्नेंस पर विचार नहीं करेंगे। इसलिए मैं विपक्ष के सदस्यों का भी आह्वान करना चाहूंगी कि गुड-गवर्नेंस पर हमारा साथ दीजिये, ताकि प्रदेश का विकास हो सके और राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में आ सके।

माननीय सभापति महोदया, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप उस सीट पर बैठी हुई वास्तव में बहुत सुन्दर लगती हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती द्रोपती मेघवाल।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदया, सबसे पहले मैं

(श्रीमती द्रोपती)

आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रथम बजट पर बोलने का अवसर दिया। जनता का आशीर्वाद, माननीया वसुन्धराजी का करिश्मा है कि मेरी जैसी साधारण गृहिणी को आज प्रदेश के सर्वोच्च सदन में बोलने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदया, विधान सभा में मेरा पहला भाषण है, मैं विधान सभा में पहली बार चुनकर आई हूं। इससे पहले मैं ग्राम पंचायत खोड़ा की सरपंच थी। मेरे मन में एक आशंका थी कि विधान सभा में, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष, मिल-बैठकर राजस्थान की जनता का, जनता के बारे में चिंता करते होंगे; सही को सही, गलत को गलत कहते होंगे; बड़ी उच्च स्तरीय और सारगर्भित बहस होती होगी, परन्तु मुझे अफसोस है, मैं कल से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के भाषण सुन रही हूं, मैंने जितने प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के भाषण सुने, उनको सुनकर कह सकती हूं कि अभी प्रतिपक्ष विधान सभा और लोक सभा की करारी हार से उबरा नहीं है। अपने खीज मिटाने के लिए इस जन-कल्याणकारी बजट का बिना आधार के विरोध किया जा रहा है।

सभापति महोदया, मैंने 105 पृष्ठीय बजट को पढ़ने की कोशिश की, मेरा ज्ञान कम हो सकता है परन्तु मैं दावे के साथ यह कह सकती हूं कि यह बजट राजस्थान के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस के शासन में लूटा, पिटा, फिसलता हुआ राजस्थान अब वसुन्धराजी के शासन में खुशहाल शासन बनेगा और इसी बजट में माननीया वसुन्धराजी ने गुड- गवर्नेंस एक्ट लाने की बात कही है। वास्तव में, इस पहले बजट को देखकर मैं यह कह सकती हूं कि वसुन्धराजी के नेतृत्व में हर वर्ग खुशहाल होगा, क्योंकि यह बजट राजस्थान की आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाला होगा, समस्याओं के निदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

सभापति महोदया, राजस्थान में 'गौरव पथ' बनें, यह कल्पना गांव की बदहाली समझने वाली नेता ही कर सकती है। एक लाख किलोमीटर की सड़कों का पुन: निर्माण हो, बीस हजार किलोमीटर नई सड़कें बनें, यह राजस्थान की कायाकल्प करने वाला बजट नहीं है तो और क्या है?

सभापति महोदया, मैं उस क्षेत्र से आती हूं जहां इन्दिरा गांधी नहर परियोजना है। जर्जर इन्दिरा नहर की सफाई, मरम्मत करने की घोषणा, सेम समस्या के समाधान के लिए विशेष टीम, भाखड़ा नहर प्रणाली की 374

(श्रीमती द्रोपती)

किलोमीटर सड़क को पक्का करना, यह ऐसी बातों की घोषणा है जिन्हें मेरे इलाके का किसान बरसों तक नहीं भूलेगा।

सभापति महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र पीलीबंगा का मास्टर-प्लान बरसों से नहीं बना। सुराज संकल्प यात्रा में माननीया वसुन्धराजी मेरे क्षेत्र में गईं, मैंने प्रार्थना की, उन्होंने स्वीकार किया और बजट में घोषणा की1 इसके लिए मैं मेरे क्षेत्र की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करती हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कालीबंगा का वह क्षेत्र भी आता है जहां मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अवशेष छिपे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसी बजट में हेरिटेज के संरक्षण के लिए जो बिल लाया जा रहा है, मेरे वहां की लुप्त होती, कालीबंगा के गर्भ में छिपी मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी सुरक्षित होगी।

सभापति महोदया, जिप्सम के खनन की किसान को अनुमति देकर, जिप्सम माफिया के मुंह पर तमाचा मारकर, जो किसान कल्याण का काम किया, वह किसान कभी नहीं भूलेगा।

रोजगार व कौशल विकास के लिए रोजगार योजनाएं इस बजट के माध्यम से नौजवानों के लिए प्रस्तुत हैं। मुझे उम्मीद है कि 15 लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का वादा पूरा होगा।

4,900 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलना, वह भी ग्रामीण क्षेत्र में खोलना, क्या गांव का व्यक्ति इसे भूल पायेगा? सभापति महोदया, माननीया वसुन्धराजी ने राजस्थान में सात नये मेडिकल कालेज, तीन नये इंजीनियरिंग कालेज खोलने की घोषणा की। इससे विद्यार्थी वर्ग में उत्साह की लहर दौड़ने लगी। आज हर विद्यार्थी की जुबान पर 'हमारी नेता कैसी हो, वसुन्धराजी जैसी हो' है।

माननीया वसुन्धराजी के लिए मैं एक शेर पेश करती हूं-

कुछ लोग समय के साथ ढल जाते हैं,
कुछ लोग समय के ढांचे को बदल जाते हैं।

सभापति महोदया, पिछली सरकार द्वारा 12 किलोमीटर तक मेट्रो रेल बनाने का कार्य शुरू किया, जिसकी जयपुर को अभी आवश्यकता नहीं थी। माननीया वसुन्धराजी ने बजट भाषण में बताया, इसकी लागत 3 हजार 400 करोड़ रुपये बतायी गयी, इससे 110 रोड ओवरब्रिज अथवा 5 हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कें पूरे प्रदेश में बन सकती थीं। यह विश्लेषण करने के लिए मैं इनके दिमाग को सलाम करती हूं।

(श्रीमती द्रोपती)

इसलिए माननीया वसुन्धराजी के नेतृत्व को जनता ने विधान सभा व लोक सभा में अपार बहुमत देकर स्वीकारा है। मेरा जनता जनार्दन को भी इस सदन के माध्यम से सलाम करते हुए आभार व्यक्त करती हूं। मैं शेर बोल रही हूं-

दीया जलाने वाला चाहिए,

लोग रोशनी में आने को तैयार हैं।

सभापति जी, आज गरीब को सामान्य बीमारी के लिए 30 हजार व गम्भीर बीमारी के लिए तीन लाख रुपये इंश्योरेंस स्कीम में देना, यह उदारता का परिचय वसुन्धराजी ने दिया है।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने मेरे क्षेत्र की जनता को 50 वर्षों से अटकी रेल योजना से जोड़ने, धार्मिक स्थान सालासर बाबा, खाटूश्याम बाबा के स्थान को जोड़ने के लिए, हनुमानगढ़ से रावतसर-पल्लू-सरदारशहर-रतनगढ़ तक रेल लाइन है। रतनगढ़ से सालासर, सालासर से खाटूश्याम जी, रींगस रेल से जुड़ने से हनुमानगढ़ से जयपुर मात्र 4 घण्टे का सफर हो सकता है। पल्लू-रावतसर के बीच ब्रह्मसर में जिप्सम का खनिज व्यापार भी रेल को मिलेगा। हजारों छोटे -बड़े वाहन रोजाना जयपुर से रतनगढ़, रावतसर होते हुए, हनुमानगढ़ आते-जाते हैं। जिसका सर्वे करवाकर प्रस्ताव राजस्थान सरकार से केन्द्र सरकार को भिजवा कर विशेष पैकेज से रेल सेवा से जोड़ने का प्रयास करें। यह मेरी व क्षेत्र की जनता की मांग है।

अंत में यह कहना चाहूंगी, वर्ष 2014-15 का घोषित बजट, विशेषताओं भरा, राजस्थान के विकास के लिए व विकास पथ पर चलने की प्रेरणा से प्रेरित होकर पेश किया। 6 लाख 98 हजार 270 करोड़ के बजट ने हर वर्ग व क्षेत्र को छुआ है।

अंत में, मेरा सदन से अनुरोध है कि मेरे शब्दों से किसी को कोई ठेस पहुंची हो, तो मैं पहली बार बोल रही हूं, माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: देखिए, दोनों ही महिला सदस्यों ने 10-10 मिनट की बात कही थी, 10 मिनट से कम समय में अपना भाषण दिया। इसलिए विशेष तौर से हम लोग उनका स्वागत करते हैं।

श्री वासुदेवजी देवनानी। (व्यवधान) इसीलिए पहले कहा है। सब ध्यान रखिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदया, परसों सदन में प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री, माननीय वसुन्धरा राजे ने 2014-15 का बजट प्रस्तुत किया। वैसे बजट प्रति वर्ष प्रस्तुत होता है, आय-व्यय का लेखा-जोखा उसमें दिया जाता है, कुछ घोषणाएं होती हैं, कुछ कर प्रस्ताव लिये जाते हैं, सत्ता पक्ष के लोग समर्थन करते हैं, विपक्ष के लोग उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन यह बजट इन साधारण बजटों से अलग, एक विशिष्टता लिये हुए है, लीक से हटकर है और यह बजट राजस्थान का, 2020 तक समृद्ध व विकसित राजस्थान का एक विजन डाक्यूमेंट है। इससे प्रतीत होगा कि राजस्थान को भारत के नक्शे पर विश्व के हालैण्ड जैसा बनाने का हमारा लक्ष्य है। जो इस प्रकार का हालैण्ड बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो बजट बनेगा, तो उस बजट का केवल कुछ अफसर या कमरे में बैठकर नहीं बनता। यह माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने सारे राजस्थान में सुराज संकल्प यात्रा, उसके बाद बीकानेर और भरतपुर संभागों की ढाणी-ढाणी, गांव-गांव जाकर जो धरातल की वस्तुस्थिति देखी, उसके आधार पर यह बजट बना और इस बजट ने हर वर्ग को छुआ है।

कल से सदन में बहस भी चल रही है। मेरे कांग्रेस के मित्रों को शायद इसमें कोई भी बात अच्छी नहीं लगी, आलोचना कर रहे हैं; आलोचना करना उनका कर्तव्य भी है, लेकिन कुछ रचनात्मक सुझाव देते तो अच्छा होता।

मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या यह सत्य नहीं है कि राज्य पर कर्जा इनके शासनकाल में 70 हजार करोड़ से बढ़कर 1 लाख 30 हजार करोड़ हो गया? क्या विकास की दर 8 प्रतिशत से 4 प्रतिशत नहीं हो गयी? अभी मेरे मित्र कह रहे थे, बिजली कंपनियों का कर्जा 15 हजार से 75 हजार करोड़ तो हुआ, लेकिन वह इनके राज में हुआ। शायद वे भूल रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में ही बढ़ा है, 15 हजार से 75 हजार करोड़। पहले केवल 15 हजार करोड़ था। तो क्या यह सही नहीं है? क्या स्कूलों की हालत खराब नहीं है? क्या आपने किसी को रोजगार दिया? लेकिन इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यदि बजट को ढंग से पढ़ा होता तो वे देखते कि जो नि:शुल्क जांचों की इन्होंने घोषणा की थी, वह ढंग से लोगों की जांचें नहीं हो रही थीं, उसका बजट भी 12 करोड़ बढ़ाया गया है, 107 करोड़ से 119 करोड़ किया है। मुफ्त दवा वितरण योजना का बजट आपने रखा था 191 करोड़, उसको बढ़ाकर 299 करोड़ रखा है। आम व्यक्ति के लिए, केवल घोषणा नहीं, वास्तव में उसको सस्ती, अस्पताल में मिले, मरीज का इलाज हो। घोषणाओं से काम नहीं चलता।

(श्री वासुदेव देवनानी)

ग्रामीण विकास के बड़े ढोल पीटते थे, ग्रामीण विकास का बजट तिगना बढ़ाया गया है; आपकी सरकार के समय 3,885 करोड़ था, अब बढ़कर 12,091 करोड़ हो गया है। पंचायत राज का बजट 90 परसेंट बढ़ा है। और तो और, चिकित्सा व स्वास्थ्य का बजट दुगने के बराबर किया है; 797 करोड़ था, अब बढ़कर 1397.55 करोड़ हुआ है। पी डब्ल्यू डी का बजट बढ़ा है; पी एच ई डी का बजट बढ़ा है। बजट केवल 5 परसेंट, 10 परसेंट नहीं बढ़ा, यह 50 परसेंट से लेकर 100 परसेंट तक बढ़ा है। जब इतना बजट बढ़ा है, इसकी योजनाएं बनी हैं और इसका दृश्य साफ-साफ है, जब प्लान में बजट बढ़ता है तो इसका मतलब है, विकास की इच्छा है और विकास होगा; और नान-प्लान में बढ़ता है तो इसका मतलब है, केवल वह वेतन, इत्यादि में बढ़ा है। आपने यदि बजट का अध्ययन किया हो तो प्लान एक्सपेंडिचर 2013-14 में था 28,244 करोड़, हमने 2014-15 में रखा है 57,115 करोड़; लगभग दुगने से ज्यादा। जब प्लान में इतना बजट रखा है तो निश्चित रूप से उससे विकास के काम होंगे।

(15.00 बजे)

अब कौन से विकास के काम होंगे? यदि आपको हालैण्ड की तरह राजस्थान का विकास करना है तो आपको यहां पर अच्छी सड़कें भी चाहिए, अच्छी कनेक्टिविटी भी चाहिए, बस स्टैण्ड भी अच्छे चाहिए, हवाई यात्राओं की भी सुविधाएं चाहिए, नौजवानों को रोजगार भी चाहिए, आधुनिक तकनीकी से ओत-प्रोत शिक्षा भी चाहिए और निवेशकों के लिए और उद्योगों के लिए एक अच्छे वातावरण की भी आवश्यकता होती है। उसके लिए ही लक्ष्य रखा है कि हम विकास दर को 12 प्रतिशत तक ले जाएंगे और व्यक्ति की आय को 10 प्रतिशत तक बढ़ायेंगे। जब यह सारा लक्ष्य रखा है तो उसके लिए अच्छी सड़कें चाहिए। अच्छी सड़कें आपने भी बनाई होंगी, हमने भी बनाई हैं, लेकिन 20 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण, निश्चित रूप से 15 किलोमीटर प्रतिदिन की हैं और आपके राज में शायद 3 किलोमीटर सड़क भी प्रतिदिन की नहीं बनी होगी।

इसके साथ मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन भी करना चाहूंगा कि सड़कों की गुणवत्ता की ओर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। सड़कें बनाना तो सरल है लेकिन यदि गुणवत्ता नहीं हुई तो अगले पांच साल के दौरान ही आपने उस ठेकेदार को तो कहा है कि 8 वर्ष तक आपको इसको

(श्री वासुदेव देवनानी)

मेंटेन रखना है, लेकिन फिर भी आज हो क्या रहा है, दो डिपार्टमेंट तक में समन्वय नहीं है। पी.डब्ल्यू.डी. तो सड़क बनायेगा और पी.एच.ई.डी. उसको अगले दो-चार दिन में ही खोद देगा, फिर बी.एस.एन.एल. आयेगा वह उसको खोद देगा। तो फिर अपने पैसे का हाल तो बेकार हो जाएगा। इसलिए डिपार्टमेंट्स में समन्वय बिठाने की आवश्यकता है।

दूसरा मेरा एक सुझाव है, माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी यहां नहीं हैं, बाकी लोग नोट करेंगे, सड़क पर ओवरलोड वाहन चलाने पर कहीं न कहीं नियंत्रण बनाना होगा। नहीं तो, सड़कें तो, आप बना लोगे, सड़क आपने 8 टन के हिसाब से बनाई और यदि उस पर आप 16 टन का ट्रक ले जाओगे या लोडर ले जाओगे तो सड़क तो कोई भी बनाओ, लेकिन वह सड़क तो टूटेगी ही। इसलिए 20 हजार किलोमीटर सड़क बनाना अच्छी बात है लेकिन उसकी गुणवत्ता और ओवरलोड को, मेरे ध्यान में, रोकने की आवश्यकता है। इसके लिए यदि कोई कानून में भी संशोधन करना पड़े तो करना चाहिए और इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ प्रांतों में इसको बनाया गया है और उस प्रांत के हिसाब से यहां राजस्थान में बनाने की और नियम लाने की आवश्यकता है।

अपने यहां विकास की गति को बढ़ाने के लिए हवाई परिवहन की भी आवश्यकता है, कि उसकी सुविधा बढ़े। 16 पट्टियों के विकास की बात हुई है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। उसके साथ में जो धार्मिक स्थलों को जोड़ने की बात कही है और जो कुछ मेन शहर हैं, उनको हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी। मैं समझता हूं कि यह जितनी जल्दी हो सके, और उसमें भी यदि सस्ती मिलेगी, तो उसका लाभ होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो कि केवल बड़े कारपोरेट्स के लिए ही यदि हो गई, तो शायद आमजन उसका लाभ नहीं ले पायेगा। इसलिए उसकी भी इसमें व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

आज बस अड्डों की हालत खराब है, बस अड्डों में कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है। होटल, इत्यादि तो दूर रहा, लेकिन बसों की पार्किंग की, भीड़ की, जनता के बैठने की, सारी अव्यवस्थाएं हैं। इसलिए बस अड्डों के जो आधुनिकीकरण की बात की गई है, उसके लिए मैं समझता हूं कि वह आज की आवश्यकता है। बस अच्छी होंगी, रेल्वे कनेक्टिविटी अच्छी होगी, हवाई कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो निवेश करने वाले भी आयेंगे, उद्योग वाले भी आयेंगे, और चीजें आगे बढ़ेंगी।

(श्री वासुदेव देवनानी)

इस सारे विकास के साथ सड़कें तो अच्छी बन गईं लेकिन यदि बिजली नहीं हुई तो उद्योग भी नहीं पनपेंगे और कोई निवेश भी नहीं करेगा। इसलिए उसके लिए मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है और सरकार से निवेदन है कि उत्पादन, प्रसारण और वितरण निगमों में आपस में समन्वय की आवश्यकता है। इनके राज में तो बिजली चली जाती थी, अभी हमारे वक्ता मित्र कह रहे थे कि हमारे राज में 22 घंटे बिजली मिलती थी, आपके राज में यदि 22 घंटे बिजली मिलती रहती होती तो आपके ये हाल नहीं होते और जनता आपको आंखों पर बिठाती। उस समय तो जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी। इसलिए आज हम इस स्थिति में पहुंचे। यदि बिजली अच्छी चाहिए तो निश्चित रूप से उसके लिए उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, वितरण व्यवस्था भी ठीक करनी पड़ेगी और साथ में प्रसारण व्यवस्था भी ठीक होगी। बिजली चली जाती है, हम एक्स.ईएन. को टेलीफोन करते हैं तो वे कहते हैं कि हमारा नहीं है, प्रसारण डिपार्टमेंट की ओर से गड़बड़ है। इसलिए इस प्रसारण व्यवस्था को भी ठीक करने की आवश्यकता है।

इसमें अच्छा है कि बजट के अन्दर 400 केवी, 200 केवी, 132 केवी, 33 केवी के कई जी एस एस बनने वाले हैं, सोलर के लिए भी 25 हजार मेगावाट की व्यवस्था रखी है लेकिन बिजली विभाग में भी सुधार की आवश्यकता है। हम बार-बार शट-डाउन लेते हैं, जनता घंटों उसके लिए परेशान होती है। मैं तो शहर में सारी जगह घूमता हूं, लोग कहते हैं, मेंटीनेंस के लिए आज दिन-भर बंद रहेगी, लेकिन पांच-छह दिन बाद, यदि बरसात आई या थोड़ी-सी भी हवा तेज चली, आंधी चली तो बिजली गायब। इसलिए इसकी व्यवस्था क्यों नहीं होती? हमारे पोल्स और तार इतनी मजबूती के साथ क्यों नहीं लगाये जाते? थोड़ी-सी हवा आते ही या झोंका आते ही बिजली गायब हो जाती है। उसको ठीक करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि कई बड़े शहरों के अन्दर तो अण्डरग्राउण्ड केबलिंग की जाएगी तो शायद अच्छा होगा और सारे बड़े शहरों में रिंग सिस्टम बनाया जाए कि एक सर्किट से बिजली चली जाए तो आप उसको दूसरे सर्किट से दे दें। तो रिंग सिस्टम के आधार पर कम से कम बड़े उद्योगों में, बड़े शहरों के अन्दर और कस्बों के अन्दर बिजली को निर्बाध रूप से दे सकते हैं।

इसके साथ ही मैं एक बिन्दु की ओर और ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि कई जगह आज भी बिजली के खम्भे लोहे के लगे हुए हैं और उनके कारण

(श्री वासुदेव देवनानी)

से कई बार जानवर टच होकर मर जाते हैं। कई बार बात आती है कि गाय मर गई, कई बार दूसरा जानवर मर गया। इसलिए हम इन सबको आर सी सी पोल के द्वारा कन्वर्ट करने का क्यों नहीं एक प्लान बनाते हैं ताकि ये सारी चीजें समाप्त हो जाएं?

बिजली भी आ जाएगी और सड़कें भी बन गईं, लेकिन यदि आपके नवयुवकों को रोजगार नहीं मिला, आज राजस्थान इस समस्या से जूझ रहा है। इस समय इसमें 33 लाख युवक बेरोजगार हैं और यदि यही क्रम रहा तो 2019-20 तक ये 46 लाख तक बढ़ जायेंगे। लेकिन बच्चों को रोजगार मिले, इसके लिए बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, उनमें स्किल डवलप करनी पड़ेगी। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि बजट के अन्दर प्रत्येक पंचायत तक आई.टी.आई. खोलने की बात हुई है और दूसरी भी कई योजनाएं इसके अन्दर बनी हैं। यहां तक कि इस बार स्किल यूनिवर्सिटी बनाने की जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं, अभिनन्दन करता हूं और साथ में, शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि स्किल यूनिवर्सिटी अजमेर में खोली जाए। उसका कारण भी है कि आज जितने सम्भाग केन्द्र हैं, उन सब सम्भाग केन्द्रों पर दो या तीन यूनिवर्सिटी हैं और अजमेर ही एक मात्र ऐसा सम्भाग केन्द्र है जिसमें केवल महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी है। इसलिए वह यूनिवर्सिटी यदि अजमेर में खुलेगी, अजमेर केन्द्र में है, तो उसका स्किल डवलपमेंट के आधार पर, स्किल यूनिवर्सिटी का जो परपज है वह भी पूरा होगा और आज का नवयुवक यदि स्किल्ड, प्रोफेशनल होगा तो उसको रोजगार हर प्राइवेट इण्डस्ट्री देगी। साथ ही मैं आग्रह करूंगा कि आई.टी. के आज बैंगलोर में हैं, हैदराबाद में हैं, अहमदाबाद में हैं, तो राजस्थान के अन्दर भी आई.टी. इण्डस्ट्री होनी चाहिए। आज लोग गुड़गांव और नोएडा क्यों जाते हैं? आज जयपुर में हो, चाहे अजमेर में हो, आई.टी. इण्डस्ट्रीज को यहां पर इन्वाइट किया जाए, उनको लगाया जाए तो हमारे हजारों लोगों को वहां पर रोजगार आराम से मिल सकता है, जो कि राजस्थान की आवश्यकता है। इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री और माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने यू.जी. और पी.जी. में कौशल विकास की बात भी कही है। यह कौशल विकास होगा तो सब ठीक होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपको 13-14 मिनट हो गये हैं। जल्दी सम-अप करें आप।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं जल्दी करता हूं।

दूसरा, मैं सरकार का ध्यान संक्षेप में आकर्षित करना चाहूंगा आर.पी.एस.सी. के बारे में। आज आर.पी.एस.सी. अपनी विश्वसनीयता समाप्त कर चुकी है। यह संवैधानिक पद है, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत कुछ सदन में इस मुद्दे पर नहीं कहूंगा, लेकिन वहां पर निश्चित रूप से आर.पी.एस.सी. के चेयरमैन और आर.पी.एस.सी. की जो बाकी स्थिति है, उसने सारे राजस्थान में सरकार का भी और वहां नवयुवकों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है कि आज पता नहीं, कौनसी कुंजी आ रही है, उस कुंजी में आंसर्स गलत आ जाते हैं। इसलिए उस आर.पी.एस.सी. के बारे में गम्भीरता से विचार करके, उसको ठीक करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि उसको ठीक किया जाए।

मैं सरकार को यह निवेदन करूंगा और बधाई दूंगा कि इनकी सरकार ने जो तीन विश्वविद्यालय खोले थे, उनके लिए इन्होंने एक भी रुपया भी नहीं रखा था लेकिन आपने भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, पण्डित दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय और महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त बजट रखा।

एक-आध बिन्दु और कहूंगा। चौथा आ जाता है चिकित्सा का। डाक्टरों की कमी के लिए, सुपर-स्पेशलिटी के बारे में तीन, बीकानेर, उदयपुर और कोटा का तो चयन किया है पर मेरा सरकार से निवेदन है कि उसमें अजमेर के लिए भी सोचें, क्योंकि अजमेर में कई जिलों के लोग आते हैं और उन सब लोगों को भी इसकी आवश्यकता रहती है। इसलिए इसके लिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस ओर बढ़ें।

साथ में एक निवेदन करूंगा और सरकार को एक बिन्दु पर और बधाई देना चाहूंगा कि आपने गोपालन विभाग का गठन किया है। गौ हमारी माता है। गौ का केवल धार्मिक ही नहीं, आर्थिक रूप से भी गौ को रखना एक अच्छा रहता है। इसलिए गोपालन विभाग में जो इनकी सरकार ने केवल 50 लाख का बजट रखा था, उस बजट को हमारी सरकार ने 100 करोड़ बढ़ाकर, एक अलग विभाग बनाया है। निश्चित रूप से इसमें पंचगव्य का भी उपयोग होगा, अनुसंधान भी होगा, गउओं की भी रक्षा होगी, गौशालाओं को भी अनुदान मिलेगा। यह एक सराहनीय काम किया है। इसलिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

साथ में एक बिन्दु उद्योग का और है। आज उद्योग के लिए वातावरण

(श्री वासुदेव देवनानी)

बने, उसके लिए अजमेर में आपने सिरेमिक हब खोला है। उसके लिए मैं हमारी पूरी जनता की ओर से आपका बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूं, लेकिन साथ में एक आग्रह करता हूं कि अजमेर से जिंक निकलता है, वह जिंक बाहर जा रहा है। उदयपुर में तो जिंक स्मेल्टर है पर अजमेर में भी एक जिंक स्मेल्टर की स्थापना की जा सकती है। क्योंकि अरबों रुपयों की जमीन हमने उनको दी है, वेदांता ग्रुप को, इसलिए उनको आग्रह करें कि वे भी इसमें कुछ करें।

पेयजल के लिए एक बात कहता हुआ पूरा करूंगा किआपने नदियों को जोड़ने का जो प्रारम्भ किया है जिसमें ब्राह्मणी नदी पर बांध बनाकर बीसलपुर बांध में पानी डाला है, पिछली सरकार यदि चाहती तो बीसलपुर के बांध के अन्दर यदि चम्बल का पानी डालती और फिर बीसलपुर का पानी भीलवाड़ा जाता। आप सीधा चम्बल का पानी भीलवाड़ा ले गये। उसके कारण से भला होने वाला नहीं है। इसलिए आज बीसलपुर बांध से अजमेर के अलावा जयपुर को मिलता; आज नागौर को मिल रहा है, बाकी कई जिलों को मिल रहा है। तो बीसलपुर बांध में पानी आये, उसके लिए आवश्यक है कि नदियों को जोड़ने का काम किया जाये।

साथ में सरकार से एक निवेदन करूंगा, पानी डार्क जोन में जा रहा है, पानी की कमी है। तो क्यों नहीं जो हमारे परम्परागत जल स्रोत हैं, कुएं और बावड़ियां हैं, इनका जीर्णोद्धार करके हम पानी की कमी को दूर कर सकते हैं। यदि सरकार इस ओर ध्यान देगी तो मैं समझता हूं, आज प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक गांव में कुएं भी हैं, बावड़ियां भी हैं, उनमें पानी भी है, लेकिन धीरे-धीरे हम परम्परागत स्रोतों से दूर जाते हुए, केवल बीसलपुर की पाइप-लाइन पर डिपेंड होते जा रहे हैं। क्यों नहीं, उस आधार पर हम विचार करेंगे तो आगे बढ़ेंगे।

ग्रामीण विकास यदि आगे बढ़ाना है तो उसमें हमारी सरकार ने गुरु गोलवलकर जन सहभागिता विकास योजना को वापस प्रारम्भ किया है। इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का अभिनन्दन करूंगा। पिछली सरकार को तो शायद गुरु गोलवलकर के नाम से बड़ी घृणा होगी या नाराजगी होगी, इन्होंने उस योजना को बंद कर दिया, लेकिन गांव का विकास करना है तो 30 परसेंट गांव का, 70 परसेंट सरकार देती है। गांव के विकास की जब भागीदारी होगी तो गांव का भी विकास होगा। उस ओर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आगे होंगे।

(श्री वासुदेव देवनानी)

इसके साथ ही, भामाशाह, इत्यादि योजनाएं हैं, जो सरकार ने चालू की हैं, उसके लिए मैं अभिनन्दन करता हूं।

अंत में एक बात कहता हुआ, सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार आज एन सी आर (नेशनल कैपिटल रीजन) बना हुआ है, जिसको अलवर तक लेकर आये हैं, राजस्थान के अन्दर भी स्टेट कैपिटल रीजन (एस सी आर) बनाया जाये और उसको जयपुर से अजमेर तक लाया जाये तो अजमेर, जो राजधानी तो नहीं बन पाया, लेकिन अजमेर के आसपास और अजमेर का सम्पूर्ण विकास उसके साथ होगा। एस सी आर की एक नई कल्पना है जिसको प्रारम्भ किया जा सकता है, क्योंकि एन सी आर के बाद राजधानी के चारों ओर जो क्षेत्र है, उनका बहुत बड़ा विकास हुआ है। इसलिए राज्य में एस सी आर बनाया जाये।

हमारे अजमेर में ए डी एम को क्रमोन्नत किया गया था, उसमें पदों का सृजन किया जाये।

साथ में, आर पी एस सी की तो मैंने बात कह दी, पेरिफेरी में जो गांव हैं, उनको बीसलपुर के साथ किया जाये। अजमेर में पर्यटन की दृष्टि से आनासागर झील है, उसके चारों ओर फतहसागर की तरह, या अहमदाबाद में वह जो तालाब है, उसकी तरह पाथ-वे बनाया जाये।

यह निवेदन करता हुआ, निश्चित रूप से इस बजट की मैं सराहना करता हूं...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अजमेर के लिए एक बात छोड़ दी। मंत्री परिषद के विस्तार की भी मांग कर डालो।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह इन बातों की ओर, निश्चित रूप से, मुझे लगता है, मैंने सरकार को कुछ मुद्दों पर सुझाव दिये हैं। यह बजट सराहनीय है, इस बजट का अभिनन्दन करता हूं और यह बजट, यह पहले वर्ष का बजट है, अगले चार वर्षों में आप पायेंगे कि जो हमने कहा था, अच्छे दिन आयेंगे। अच्छे दिन आ रहे हैं, शुरुआत हुई है और चार साल के बाद जब आप और हम चुनावी मैदान में होंगे, जनता कहेगी कि अच्छे दिन तो ये ही लाये हैं, इनको ही दुबारा सत्ता में ले आओ और आप 20 के 20 ही वहां पर रहेंगे।

इस बात को कहता हुआ, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, डाक्टर राजकुमारजी शर्मा।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सभापति महोदया, माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने 14वीं विधान सभा का अपना पहला बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूं।

सभापति महोदया, इस बजट में कुछ विषय रखे गये हैं, वे स्वागत योग्य हैं। इनके लिए मैं राजस्थान की माननीया यशस्वी मुख्य मंत्री... अब तो ताली बजा दो, यशस्वी बोल रहा हूं। डोटासरा जी टेढ़े-टेढ़े देख रहे हैं। हम तो पिछली सरकार में जो मुख्य मंत्री थे, उनको भी यशस्वी कहते थे और इनको भी कह रहे हैं। सब यशस्वी हैं हमारी तरफ से। यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष तौर से...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): राजकुमारजी, आप भी यशस्वी बने रहो।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): जय हो लंकेश की।

राज्य में नया गोपालन विभाग प्रारम्भ करना, गौ-वंश संरक्षण, पशुपालन एवं किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। गौ-माता की रक्षा के लिए जो प्रावधान रखा गया है, एक बोर्ड बनाया है, मैं उसके लिए व्यक्तिश: धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्री महोदया को।

सात नये मेडिकल कालेज खोलने की गत सरकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, क्योंकि, सभापति महोदया, चिकित्सा मंत्री के रूप में काम किया है, इसलिए मैं समझ सकता हूं। विशेष तौर से जब माननीय ओटारामजी साहब देवासी, गुरुजी जो बोल रहे थे, पूरे पांच साल सिरोही जिले में डाक्टर लगाने की गुरुजी मांग करते रहे और छह महीने से यही काम कर रहे हैं और अगले साढ़े चार साल भी यही करेंगे। मैंने पूरा साथ दिया आपका, गुरुजी, लेकिन सच्चाई यह है कि डाक्टर्स हैं ही नहीं। उसके लिए सात मेडिकल कालेज खोलने का जो हमारा सपना था, उसको आपने आगे बढ़ाया है। उसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।

4,900 ग्राम पंचायतों में माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करना, शिक्षा को बढ़ावा देना है। 67 अंग्रेजी माध्यम के माडल स्कूल खोलना, गरीब बच्चों के लिए एक सपना साकार होने जैसी बात है। वह भी स्वागत-योग्य कदम है।

राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन करना, सड़कों की दशा सुधारना, आज की आवश्यकता है। देखना यह है कि परिणाम कैसे आते हैं। यह आने वाला वक्त बतायेगा।

(डा. राजकुमार शर्मा)

गांवों में आर.ओ. लगाना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मेरे पास था, हमने 50 आर.ओ. लगाने का लक्ष्य रखा था, दुर्भाग्य यह है कि वह अभी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन आप लोगों ने 1,000 आर.ओ. सिस्टम लगाने की जो घोषणा की है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो लोग खारा पानी पीने को मजबूर हैं, आजादी के 66 साल बाद में भी, उनको वह खुशी नसीब हो, जो हमने देखी है।

टैट को खतम किया है। आपने घोषणा की थी, आपका उसके लिए स्वागत है।

मैं, सभापति महोदया, जो अच्छी चीज की हैं, उनका धन्यवाद दे रहा हूं, जनता भी धन्यवाद दे रही है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि झुंझुनूं जिले को जिस तरीके से मंत्रिमण्डल में आप लोगों ने अलग रखा है, इस बजट से भी अलग कर दिया। हम तो पूरी की पूरी बजट की पत्रिका पढ़ बैठे, कहीं पर भी झुंझुनूं जिले का नाम नहीं आया। एक जगह पर आया है जो पहले से वह योजना पुरानी सरकार की स्वीकृत है। जिस प्रकार से इस बजट के अन्दर झुंझुनूं जिले को दरकिनार किया गया, यहां तक कि स्पोटर्स यूनिवर्सिटी, उसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया है, क्या वह बनेगी कि नहीं बनेगी।

यहां एक माननीय मंत्री महोदय हैं, उनके माध्यम से एक समाचार पत्र में छपा था कि वह कहीं दूसरे सम्भाग में उसको ले जाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं, यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। आप तो हमारा सपना पूरा कर दो और उस यूनिवर्सिटी के अन्दर जान डाल दो। जिस तरह से माननीय देवनानीजी कह रहे थे कि तीन यूनिवर्सिटी के लिए तीन-तीन, चार-चार करोड़ रुपये का बड़ा बजट रखा है, चार करोड़ रुपये के अन्दर एक स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनती, आप चार करोड़ रुपये के अन्दर यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देख रहे हों। पांच साल आप लोगों ने देख लिया, पांच साल हमने देख लिया, पांच साल और हम दोनों देख रहे हैं क्योंकि, भई, हम तो इधर भी नहीं हैं, उधर भी नहीं हैं, हम तो बीच में खड़े हैं।

मैं तो यह कह सकता हूं कि हमारे झुंझुनूं जिले के अन्दर बी जे पी के तीन सदस्य आये हैं और आजादी के बाद पहली बार मेम्बर आफ पार्लियामेंट भी ढाई लाख वोटों से जीता है। वहां के लाखों लोग, करोड़ों लोग

(डा. राजकुमार शर्मा)

देख रहे थे कि कैसे भी करके झुंझुनूं जिले को मंत्रिमण्डल में स्थान मिले, वहां नहीं मिला; बजट में स्थान मिले, वहां नहीं मिला।

हमारे विधायक महोदय से किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि विधायकजी, कैसा रहा बजट? बोला, आत्मा तो गवाही नहीं देती लेकिन, भइया, मंत्रिमण्डल का विस्तार होना है, इसलिए मेरी तो बड़ाई छाप देना, कहीं चिमनी मत चेप देना मेरी, क्योंकि अगर मैं बुराई कर दूंगा, अगर सरकार के खिलाफ बोल दूंगा तो मेरा नम्बर कट जायेगा। (व्यवधान) मैं तो सिफारिश कर रहा हूं कि झुंझुनूं जिले के अन्दर पहले तीन-चार मंत्री हुआ करते थे, कम से कम एक तो दे दो। मैं तो सिफारिश कर रहा हूं। हमारे जिले से...

श्री सभापति: आपस में चर्चा नहीं करें। अपनी बात रखें। बजट के जो पाइंट्स हैं, वह बजट के पाइंट्स रखिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैम, मैं वही बोल रहा हूं, सभापति महोदया।

पी पी पी मोड, अब गांव के अन्दर गांव वाले पूछते हैं कि भाई साहब, यह पी पी पी क्या होती है? हमने भी कहा कि पी पी पी मोड होती है, जिन सड़कों पर तुम चलते हो, तुम्हारा टैक्स लेते हैं, पैसे लेते हैं, वहां पर हाथ रोक लेते हैं और अगर गलती से कह दो कि पैसे नहीं लाया, तो तुम्हारे टायर की हवा निकाल देते हैं। वह पी पी पी मोड है।

मैं तो कह रहा हूं, आप सड़कों को दे दो सबको और जो आप सात सरकारी मेडिकल कालेज खोल रहे हैं, आप इनको भी पी पी पी मोड में दे दीजिये, वरना तीन मेडिकल कालेज आपके बंद होने के कगार पर आज खड़े हैं, जिनमें बीकानेर मेडिकल कालेज, कोटा मेडिकल कालेज और झालावाड़ मेडिकल कालेज, ये तीनों मेडिकल कालेज बंद होने के कगार पर हैं। मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं, मैं इन तीन कालेजों का नाम इसलिए बोलना चाहता हूं कि जब एम सी आई के लोग आते हैं यहां पर निरीक्षण के लिए, उस समय जयपुर के डाक्टरों को हाथ जोड़कर के उन कालेजों के अन्दर शिफ्ट किया जाता है ताकि एम सी आई आगे की मान्यता को रेगुलर कर दे। यह सच्चाई है। जब तीन कालेज आपके जो चल रहे हैं, वे आपकी अगर कालेज बंद होने के कगार पर हैं, तो 7 मेडिकल कालेज आगे चला पाएगी सरकार, मेरे मन में तो प्रश्नचिह्न

(डा. राजकुमार शर्मा)

हैं। मैं तो दुआ करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेडिकल कालेज या तो जल्दी से जल्दी चालू हों ताकि हमारे पास डाक्टर आयें और डाक्टर आकर, हम गांव के अन्दर चिकित्सा व्यवस्था को सुचारु रूप से शुरू कर सकें।

पिछली सरकार के अन्दर ग़रीबों के लिए एक बहुत अच्छी योजना हमने लागू की, मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना। बड़ा ताज्जुब हुआ, जब इस बजट के अन्दर उसको सिर्फ भार समझा गया, वजन समझा गया कि यह तो भार है। मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, इसको भार मत समझो। यह योजना गरीब लोगों के लिए संजीवनी बनकर के उभरी है। जो लोग पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते थे, इस योजना के लागू होने के बाद में लोगों ने इलाज कराना शुरू कर दिया। एक माता-पिता के अगर बेटा और बेटी हैं और बेटे का इलाज वह पहले कराता बीमार होने पर, इस योजना शुरू होने के बाद में बेटी का इलाज भी कराना शुरू कर दिया। मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि माननीय चिकित्सा मंत्रीजी भी आ गए हैं, बड़े भाई हैं, मैं तो आपसे यही अर्ज करना चाहता हूं कि इस योजना के अन्दर जो कमियां हैं, क्योंकि कोई भी योजना जब शुरू करते हैं तो उसमें कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को आप लोग दूर कर दो। फार्मेसिस्ट नहीं हैं हमारे पास राजस्थान के अन्दर। मैं तो यह सोच रहा था कि इस बजट में फार्मेसिस्ट के लिए आप लोग कोई न कोई प्रावधान रखेंगे, कोई न कोई वैकेंसीज निकालोगे, लेकिन दुर्भाग्य से वह चीज भी नहीं हो पायी। आप फार्मेसिस्ट की भर्ती कर लीजिए। यह योजना गरीबों के लिए इतनी अच्छी योजना है कि आपको दुआ देगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

आज गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, एक्ट भी लाने की बात कह रहे हैं, मैं तो यह कह रहा हूं कि गुड गवर्नेंस होना भी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से समाचार पत्र में एक खबर छपी कि विधायकों से पूछ कर के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बी डी ओ लगाये जाएंगे, उसके बाद से बेचारे इन तीनों कैडर के जो अधिकारी हैं, उनका जीना हराम हो चुका है। वहां के जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वे उनको कहते हैं कि मेरे यहां रहना है तो यह गलत काम भी तू कर दे। अगर काम नहीं करेगा तो मेरी एक चिट्ठी जाएगी और मुख्य मंत्रीजी तेरे को हटा देंगे। उसमें लिख भी दिया कि सत्ता पक्ष के विधायकों की सुनी जाएगी, तो हम तो गए काम से।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): राजकुमारजी, आपने कैसे लगवाए थे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपका पक्ष कौनसा है, पहले यह बता दो। आज फैसला हो ही जाए इस बात पर।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): बीच में खड़े हैं हम तो आपके सामने। आप देख लो। हम तो उम्मीद करते हैं कि करो।

सभापति महोदय, मैं एक बहुत गम्भीर विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। आज बिजली के मामले के अन्दर पूरे राजस्थान के अन्दर हाहाकार मचा हुआ है। गांव-गांव के अन्दर बिजली नहीं आती है। लोग परेशान है। सावन का महीना है, रमजान का महीना है, लोग-बाग़ तकलीफ के अन्दर हैं। सैकड़ों फोन आते हैं बिजली के लिए, मैं यह कहना चाहता हूं। आपके तो अच्छे दिन आ गए, जैसे देवनानीजी कह रहे हैं, जनता के भी अच्छे ला दो। नहीं, आपके तो आएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, मंत्री बनेंगे ये। ब्राह्मण हैं तो थोड़ी-सी तो भविष्यवाणी कर देते हैं।

सभापति महोदया, आज मैं कहना चाहता हूं कि बिजली सेक्टर को पी पी पी मोड़ में देना जन हित के खिलाफ है। आपने पहले, जिस भी सरकार ने दिया, मैं नहीं जाना चाहता हूं उस मामले पर, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों की बात होती है। पांच से पहले आप पूर्ववर्ती सरकार में थे, पिछली बार वह पूर्ववर्ती हो गया; अगली बार कौन पूर्ववर्ती होगा, यह भविष्य की बातें हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ठेकेदार के बीच में और अधिकारी के बीच में सामंजस्य नहीं है। अधिकारी की ठेकेदार नहीं सुनता, ठेकेदार की अधिकारी नहीं सुनता और वह कनेक्शन लेने के लिए जब-जब वहां पर जाता है, उसको वहां पर बहुत ज्यादा जलील होना पड़ता है।

मैं आपसे हाथ जोड़कर के विनती करता हूं, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि मैं 3 लाख 11 हजार कनेक्शन दूंगी, हर वर्ष 40 हजार कृषि कनेक्शन दूंगी। मैं यह कह रहा हूं कि एक बेरिकेड है इसमें, वह आप हटवा दीजिए। हाथ जोड़कर के विनती है कि 'गैर-आबादी' लिखा हुआ एक शब्द है, उस 'गैर-आबादी' शब्द के बेरिकेड को आप हटा दो, करोड़ों लोग आपको दुआ देंगे। दुआ इसलिए देंगे कि आजकल गांव छोड़कर लोग खेतों के अन्दर जाकर बस गए और खेतों में जाकर बस गए तो उनको घरेलू कनेक्शन चाहिए बिजली का, अगर उनके यहां पर कृषि कनेक्शन है और उसने एक लट्टू अगर तार लेकर जला लिया तो आपका वी सी आर भरने वाला अधिकारी पहुंच

(डा. राजकुमार शर्मा)

जाएगा, उसका वी सी आर भर देगा, हजारों रुपये का उस पर चार्ज करेगा और वह किसान अपने आपको ठगा महसूस करता है। मैं कहता हूं कि जब भी रिप्लाई दें, माननीया मुख्य मंत्री महोदया एक एहसान कर दें राजस्थान की जनता पर और यह जो 'गैर-आबादी' वाला जो एक बेरिकेड है उसको हटा दें, ताकि करोड़ों को घरेलू कनेक्शन भी मिल सके और वे लोग आपको दुआ दे सकें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें आप।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने, जो विद्वान हैं, उन्होंने कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार ने काफी योजनाएं बंद कीं। भामाशाह योजना का मैंने भी विरोध किया था सत्ता में रहते हुए। मैंने कहा था, भामाशाह योजना गरीब आदमियों के लिए बनी योजना है, इसको बंद मत कीजिए लेकिन उस समय जिस भी अधिकारी की चली, उसने बंद करवा दिया। मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जो भी जन हित में काम किए, उनको आप लोग बंद मत करो, उन योजनाओं को बंद मत करो। सात सड़कें मेरे नवलगढ़ में स्वीकृति कराई थीं बड़े हाथ जोड़कर के, सरकार आते ही सातों सड़कें ही रद्द कर दी गईं। अब मैं तो नहीं चलता हूं सड़क पर, जनता ही चलेगी। आपको 163 का बहुमत दिया है, बड़ा दिल रखकर के और जो पुराने कार्यकाल की जो सड़कें थीं, स्वीकृत की गईं, उनको आप वापस लेकर आ जाओ ताकि गरीब आदमी आपको दुआ देगा, जनता दुआ देगी। मैं कहना चाहता हूं, 20 करोड़ की पीने के पानी की योजना स्वीकृत कराई थी नवलगढ़ के लिए, कहीं कोई पता नहीं कि वह स्वीकृत कराई गई योजना कब पूरी होगी। सीवरेज की योजना नवलगढ़ सहित सात शहरों के अन्दर शुरू की गई थी, वहां पर जो सत्ता में आ गये, वे लोग कहते हैं, सपना लो सीवरेज का, हम नहीं आने देंगे।

मैं कहना चाहता हूं, सभापति महोदया, हमारे अधिकारों की रक्षा आपको करनी पड़ेगी, इस चेयर को करनी पड़ेगी। अगर हम लोग निर्दलीय जीत कर आये हैं तो हमारा दोष नहीं है। ऐसी हवा के अन्दर जब बड़े-बड़े धुरंधर उड़ गए और हम लोगों को साढ़े तैंतीस हजार वोटों से जीता करके भेज दिया, तो हमारा कोई गुनाह नहीं है। जनता की सेवा की थी, जनता का काम किया, इसलिए जनता ने हमें जीता करके भेजा है।

(डा. राजकुमार शर्मा)

मैं तो कहना चाहता हूं कि जो काम पिछली सरकार ने शुरू किए, उनको आप लोग जीवित रखें; आपकी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आप अच्छी तरह से चलाएं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह कर, अंतिम बात यही कहना चाहूंगा कि टैक्स के मामले में एक व्यापारी से मैंने पूछा कि आप फोन पर तो कह रहे थे कि मरवा दिया इस बार, हमारा तो बिजनस चौपट हो जाएगा और टेलीविजन के ऊपर आप बहुत जोर-जोर से सरकार की बड़ाइयां कर रहे हो। यह क्या मतलब है? उन्होंने कहा, डाक्टर साहब, मरना है क्या? अभी पांच साल सरकार रहेगी, रगड़ के रख देंगे हमको। इसलिए हम तो, टीवी के अन्दर तो हम तारीफ करेंगे और अन्दर ही अन्दर हमारी आत्मा जानती है।

मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि-

कुदरत भी टैक्स लेती पर,
शोषण के लिए नहीं, पोषण के लिए।
सूरज धरती से पानी लेता है,
खुद पीने के लिए नहीं, सौ गुणा धरती को देने के लिए।

आप पोषक हैं और निश्चित रूप से पोषक बनेंगे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। बजट में जो अच्छे काम किए, आपको साधुवाद और प्रार्थना करूंगा कि आपको ताकत दें, हिम्मत दें; आपके पास खूब पैसा आये ताकि आप जनता के लिए खर्च कर सको।

लेकिन टोल टैक्स वाले मामले में हाथ जोड़कर के विनती है, उदयपुरवाटी के पास नांगल में लोग धरने पर बैठे हुए हैं। 50 किलोमीटर का प्रावधान है नियमों के अन्दर कि 50 किलोमीटर के अन्दर दूसरा टोल नहीं लगेगा, 25-25 किलोमीटर के ऊपर अवैध टोल वसूली की जा रही है। उनकी सुनिये। आपसे लोग उम्मीद रखते हैं। क्योंकि आपको 25 सीट भी मिली हैं, 163 भी मिली हैं, तो उनके भी अधिकारों की रक्षा और संरक्षण आप करें।

मैं अंतिम चार लाइन बोलकर, क्योंकि आप लोग शासक हैं और निश्चित रूप से आप जनता के प्रति अच्छा सोचेंगे, यही निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि-

प्रजा सुखे सुखम् राज्य:, प्रजा सुखे सुखम् राज्य:

(डा. राजकुमार शर्मा)

प्रजानाम च हिते हितम्

नात्मम् प्रियम् हितं राज्य:

प्रजानाम् तु प्रिय हितं।

अर्थात, जनता की खुशियों में ही शासक की खुशी निहित होती है। आदरणीय सभापति महोदया, जनता खुश है तो शासक खुश। प्रजा का कल्याण ही उसका कल्याण होता है। जिस बात से शासक की खुशी होती है, वह उसे ठीक नहीं समझेगा। किसी बात से जनता खुश होती है, शासक उसी बात को अच्छा समझेगा। जो भी चीजें पुरानी सरकार की दी हुई हैं, वे वापस यथावत आप कर देना, और प्लस आगे कुछ दे सकते हो, तो आपका और-और धन्यवाद। बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती अनीता सिंह।

श्रीमती अनीता (नगर): सभापति महोदया, मुझे तो अभी पता ही नहीं था कि मेरा नम्बर इतनी जल्दी आ जाएगा। आपको धन्यवाद देना चाहती हूं और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री, वसुंधराजी ने जो बजट रखा है, उस बजट के समर्थन के लिए खड़ी हुई हूं। यह बजट राजस्थान प्रदेश को दिशा देने के लिए और पटरी से उतर गई आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

आलोचना-समालोचना तो बहुत सारी हो रही है लेकिन सवा सात करोड़ राजस्थान की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की जो चुनौती दी गई है, वह एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस विधान सभा में 163 सीटें और 25 सीटें लोक सभा की जिताकर जनता ने जो विश्वास, आशा और उत्साह से भर दिया है, वह अपने आप में एक बहुत काम और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। बहुत सारी आलोचनाएं यहां पर कल से हो रही हैं, लगातार, बहुत सारी तर्कसंगत भी हो सकती हैं लेकिन यह भी एक सोचने वाली बात है कि यह राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही आलोचना हो रही है या सच में ही बजट में कोई परेशानी का अनुभव किया जा रहा है। हम बहुत सारी इस बजट में उपलब्धियां को देख सकते हैं।

एक चीज, सभापति महोदया, जो हम सबने और पूरे राजस्थान ने महसूस की है कि जिस क्षण से हमारी मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री पद की

(श्रीमती अनीता)

शपथ ली है, उसी क्षण से उन्होंने जिस प्रकार से बिना रुके, लगातार एक-एक क्षण जो अपने काम के लिए लगाया है, हर क्षण उन्होंने काम के लिए लगाया है, राजस्थान के हित के लिए समर्पित होकर किया है। कभी भी कोई समय हो, उन्होंने पूरे 365 दिन का अपना एक काम बना लिया कि इस साल में इन 365 दिनों के अन्दर मैं लगातार इन कामों को करूंगी और वे सब चीजें जनता के सामने भी आ रही हैं। चाहे भरतपुर का हो या बीकानेर का हो, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, एक-एक में जाना और बीकानेर जब वे गई थीं अभी, तो उस समय टेम्प्रेचर भी 47 और पचास का था, जब लोग घर से बाहर निकलते नहीं थे। उस समय में हमारा पूरा मंत्रिमण्डल, हमारी मुख्य मंत्री गांव-गांव में पसीनों में एक-एक गांव के लोगों से उनके हालचाल पूछ रही थीं, उनकी परेशानियों का अनुभव कर रही थीं कि कैसे परेशानी है, किस तरीके का उनको करेंगे।

ये सारी चीजें उन्होंने बनते ही तय कर लीं, जो लोग अभी सोच ही रहे थे कि अभी मुख्य मंत्री बनेंगी और सारे काम करेंगी, लेकिन उन्होंने पूरा एक फिक्स एजेंडा एक रणनीति बना कर, अपने आपको इस प्रकार से जनता में सरकार ने यह पेश किया है कि पूरे क्षेत्र की जनता ने यह महसूस किया कि यह जो सरकार आयी है, यह आशावादी सरकार है, यह सरकार हमारे लिए काम करेगी और जो बिगड़ी हुई हमारी स्थिति है, उन सब बिगड़ी हुई स्थितियों को अच्छी तरीके से आगे ले जाएगी। राजस्थानियों के मन में आशा हुई और इसी आशा के अनुरूप जब लोक सभा के रिजल्ट आये, तो पच्चीस की पच्चीस सीटें लोक सभा की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आयीं, वसुन्धराजी की झोली में आयीं, उसमें यही था कि सब लोगों ने देखा कि काम होगा, हमारे क्षेत्र में विकास होगा, उसी के हिसाब से आयीं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से कि इतना अच्छा बजट, अभी पिछले पांच साल भी हम विपक्ष में बैठते थे यहां पर और बजट जब भी उठा कर देखते थे, जब भी बजट पढ़ा जाता था और उसको समझने की कोशिश करते थे तो जो बजट का मेन भाग होता था, वह मुख्य मंत्री जो थे, वे अपने सम्भाग में जोधपुर में ले जाते थे। आई आई टी आयी तो वहीं, आई आई एम आया तो वहीं। बड़ी-बड़ी योजनाएं सब अपने सम्भाग में ले जाते थे। लेकिन इस बजट में अगर आप देखेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि सातों सम्भागों में बराबर से सब कुछ दिया गया है। कोई भी

(श्रीमती अनीता)

सम्भाग ऐसा नहीं है जिसमें यह हो कि इस सम्भाग में यह काम नहीं रहा, यह काम नहीं रहा। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं लेकिन सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुईं, एक बजट में पहला बजट है लेकिन इस बजट के अन्दर सातों सम्भागों के लोग इस बात को कह सकते हैं कि मुख्य मंत्रीजी हम सब को समभाव से, समदृष्टि से देखते हुए, हम सबको साथ लेकर विकास करने का जो उनका मन है, उस हिसाब से चल रही हैं।

मैं तो भरतपुर के लिए कहना चाहूंगी क्योंकि हमारा भरतपुर डिविजन है, भरतपुर सम्भाग में जब हमारी मुख्य मंत्री महोदया आईं और उन्होंने ये सब दौरे किये, गांवों की बहुत सारी समस्याओं को देखा, बहुत सारी समस्याएं तो ऐसी थीं कि उनके आने से ही उनका निदान हो गया; बहुत सारे हमारे काम थे जो हमने उनसे कहे और उन्होंने वहीं पर उनका सैंक्शन कर दिया, और बहुत सारी चीजें जो हमारी लम्बित पड़ी थीं, पांच साल से लगातार, वे सारी चीजें इस बजट में भी दीं। हमारी जो ब्रज यूनिवर्सिटी थी, उसके लिए हम लगातार कहते रहे पांच साल लेकिन वह सिर्फ लास्ट बजट था, उसके अन्दर उसकी बात कही गयी, लेकिन उसके लिए बजट का कोई अलोकेशन नहीं किया। मेडिकल कालेज था भरतपुर का, उसके बारे में चर्चा करते रहे कि देंगे, देंगे, लेकिन उसके लिए बजट अलोकेशन अब किया है। निश्चित रूप से भरतपुर सम्भाग के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसके लिए सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी बनी, वहां मेडिकल कालेज बना, भरतपुर में नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला बनी, कीटनाशक परीक्षण की प्रयोगशाला बनी, क्योंकि यह क्षेत्र ऐसा है जहां किसानों का ज्यादा काम है, यहां ज्यादातर लोग किसान हैं। तो यह एक अच्छी शुरुआत सम्भाग में हुई है।

मैं तो इस बात का भी मुख्य मंत्री को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में जो मेवात क्षेत्र है, नगर, उसके अन्दर पांच साल में, मेरे ख्याल से, पहले कभी किसी ने कुछ नहीं किया। जो कांग्रेस के थे, उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि यह भी कोई चीज है यहां भी कुछ देना चाहिए। लेकिन उन्होंने पहले बजट में ही बहुत सारे सब-सेन्टर्स, पी एच सी, नर्सिंग कालेज और बहुत सारी बिल्डिंग्स के लिए जो उन्होंने भवन मंजूर किये हैं; आंगनबाड़ी सेन्टर्स, प्राइमरी, सेकण्डरी, सीनियर सेकण्डरी स्कूल्स भी उन्होंने स्पेशल मांग करके जो इसमें किये हैं, उसके लिए भी बहुत उनको धन्यवाद देना चाहती हूं।

शिक्षा के विषय में हम इस बात को करते थे कि बहुत सारे कालेजेज

(श्रीमती अनीता)

ऐसे थे, जहां संकाय किसी के यहां कामर्स है, तो किसी के यहां साइंस है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थीं। बच्चों को उनमें पढ़ने में परेशानी आती थी कि वहां जाएं या वहां जाएं। उनके भी पुनर्गठन की जो बात इस बजट में कही गई है, शिक्षा के लिए आगे एक बहुत अच्छा रहेगा। हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य बनेंगे आगे, उनके लिए इसका पुनर्गठन, और पन्द्रह नये महाविद्यालय खोलने की जो उन्होंने घोषणा की है, वह भी एक बहुत बड़ी घोषणा हमारी शिक्षा के क्षेत्र में बनेगी।

एक बहुत अच्छी बात, जिसको मैं सुन रही हूं, पक्ष हो या विपक्ष हो, सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वह है गोपालन विभाग। निश्चित रूप से इस विभाग की इतनी ज्यादा आवश्यकता थी कि इस विभाग के बिना हमारी जो गौमाताएं थीं, उनकी जो हालत हो रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी। हम जिस क्षेत्र से आते हैं, सभापति महोदया, वहां गौ-तस्करी बहुत होती है। वहां इतनी ज्यादा परेशानी रहती है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता है, जिस दिन गौ-तस्करी की गाड़ी पुलिस नहीं पकड़ती हो। गौ-तस्कर फायरिंग भी करते हैं। इतने लोडेड होते हैं आर्म्स से कि वे किसी को भी नहीं देखते, न पुलिस को देखते हैं। आम जनता भी उनको रोकती है तो फायरिंग करते हैं और इस प्रकार से निकलने की कोशिश करते हैं। तो एक जब यह विभाग बनेगा तो निश्चित रूप से मैं समझती हूं कि कड़े कानून भी बनेंगे, जो गौ-तस्करी को रोकेंगे। जिस प्रकार का, क्योंकि हमारा जो जिला है भरतपुर, उस जिले में यू.पी. और हरियाणा, दोनों साथ में लगते हैं, तो उनके लगने की वजह से ही वहां पर उनकी जो सरकारें हैं, उन्होंने वहां बहुत सारे बना रखे हैं, जिसकी वजह से गौ-तस्करों को लगता है कि अगर हम थोड़ा सा इलाका यह पार कर जाएंगे तो उनको बहुत कीमत वहां पर मिल जाती है। इसलिए वह ज्यादा करते थे। लेकिन मैं समझती हूं कि गोपालन विभाग जो बनेगा, उसमें इस तरह के सारे कानून बनेंगे, उनके संवर्द्धन के लिए, गौमाताओं को आगे करने के लिए बहुत सारी चीजें उस विभाग में होंगी। इस विभाग के बिना इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था। इसके लिए भी आपके माध्यम से मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

हमारे भरतपुर में जो डीग किला था, उसकी दुर्गति इतनी ज्यादा हो रही थी, उसके आसपास इतनी गन्दगी थी। अभी जब सरकार गई तो उसको देखकर आये और उसके लिए बहुत अच्छा, 4 करोड़ 81 लाख उसके काम के

(श्रीमती अनीता)

लिए दिये कि उसमें जो टूट-फूट हो रही है, उसका रखरखाव अच्छे से मेंटीनेंस हो जाए।

इसके साथ ही, एक खानवा गांव में बहुत बड़ा एक, जब हमारी पिछली सरकार थी, उस समय राणा सांगा, एक बहुत अच्छा स्मारक बनाया, लेकिन इन पांच वर्षों में, बिना देखरेख की वजह से, उसकी इतनी परेशानी हुई कि उसमें टूटफूट हो गई, बहुत सारी। मुझे बहुत खुशी है कि दुबारा से उसका पुनर्निर्माण करने की बात कही है।

एक बहुत अच्छी बात यह रही, उन्होंने यह तय किया कि मंदिरों को, जो अच्छे मंदिर हैं, सम्भागवाइज, उन सब मंदिरों का हम दुबारा से अच्छे से सुधार करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे, जो हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अपने धर्म और संस्कृति के प्रति आशावान हों और जो मंदिर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में जा रहे हैं, पुराने मंदिर हैं, उन मंदिरों में भी थोड़ी-सी जान आ जाएगी और उनमें भी सब लोगों का जाना-आना बहुत अच्छा रहेगा।

मैं एक अपनी मांग जरूर रखना चाहती हूं आपके द्वारा कि हमारे क्षेत्र के आसपास बहुत सारे शिल्पकार रहते हैं, मूर्तिकार जिनको कहते हैं, उन मूर्तिकारों के लिए एक योजना है कि शिल्पकार रहे का एक ग्राम उनका बन सकता है। उसकी योजनाएं भी हमारे आयुक्त के पास यहां आकर पड़ी हुई हैं। तो निश्चित रूप से, सभापति महोदया, मैं यह आपके द्वारा चाहूंगी कि मुख्य मंत्री महोदया जब अपना रिप्लाई दें तो उसमें एक शिल्पग्राम की जरूर वहां पर घोषणा करें, जिससे बहुत अच्छा एक हमारे यहां शिल्पग्राम बन सके।

निश्चित रूप से यह जो बजट है, पैंसठ साल में हम लगातार चलते-चलते आ गये, इन पैंसठ सालों में आज तक जितने भी चुनाव लड़े जा रहे हैं, वे पानी पर, बिजली पर, सड़क पर और डाक्टर पर और शिक्षा पर ही हम लोग लड़ते आ रहे हैं; हमारी आज तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को भी हम आज तक प्राप्त नहीं कर सके; यह बजट एक इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाला बजट है। यह बजट इस प्रकार का है कि इसमें इन चीजों को, जो आम आदमी की जरूरत है रोज की जरूरत हैं, उन जरूरतों को पूरा करे, उन सब चीजों को करे। इस प्रकार का बजट है।

इस बजट में बहुत अच्छी चीज जो हमने हमारे जिले में महसूस की

(श्रीमती अनीता)

है, दो चीजों की। पिछले पांच साल जो कांग्रेस के थे, निश्चित रूप से हम इसको देखते थे कि हर आदमी बिजली के लिए बहुत परेशान था। गांव का हो, शहर का हो, वह हमेशा इस बात को कहता था कि बिजली नहीं आती है, और बिजली के बिना घर के कोई काम नहीं होते, पानी का कोई काम नहीं होता, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है, बिजली की बहुत अच्छी व्यवस्था बनी है। हम जब भी गांव में जाते हैं तो गांव वाले कहते हैं कि अब तो 20-21 घण्टे बिजली आ रही है और बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ। बिजली का बहुत बड़ा फेरबदल ग्रामीण एरिया में सबने महसूस किया। वह सब आपके सामने हैं।

दूसरा, ला एंड आर्डर। मैं, सभापति महोदया, आपसे कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के राज में ऐसा कोई दिन हमारे मेवात एरिया में नहीं जाता था जिस दिन किसी की मोटर साइकिल चोरी नहीं होती हो, जिस दिन किसी के घर में से ट्रैक्टर नहीं निकाला जाता हो, किसी के साथ लूट नहीं होती हो। हर रोज 2-3 मुकदमे होते थे। लोग डर गए थे कि यदि प्रशासन के पास जाकर हमने मुकदमे दर्ज कराए तो हो सकता है कि हमारी मोटर साइकिल, हमारा ट्रैक्टर, हमारी बोलेरो गाड़ी वापस आएगी कि नहीं आएगी। इस प्रकार का भय लोगों के मन के अन्दर आ गया था। केवल पांच मिनट, सभापति महोदया।

श्री सभापति: पांच मिनट नहीं, दस मिनट में सभी को अपनी-अपनी बात कहनी है। अब दस मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। बहुत संक्षिप्त करें।

श्रीमती अनीता (नगर): बस, संक्षिप्त करती हूं।

श्री सभापति: बिलकुल।

श्रीमती अनीता (नगर): निश्चित रूप से। मैं समझती हूं कि रोजाना की घटनाएं ऐसी होती थीं। जिससे यह था, लोग डरते थे, फिरौती के मार्फत अपनी मोटर साइकिल और ट्रैक्टर को मंगाया करते थे। लेकिन आज, इन 7 महीनों के अन्दर, एक-एक व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि हमारे यहां पर बहुत अच्छा ला एंड आर्डर है, हमारे यहां चोरी, लूट इस तरीके से बंद हो गई। कोई एकाध घटना कभी हो जाए तो हो जाए, लेकिन बहुत सख्ती से ये सब चीजें बंद हुई हैं। बहुत अच्छी चीजें हुई हैं।

मैं तो सिर्फ आपसे यह कहना चाहती हूं, एक योजना, श्री योजना जो गांव के लिए हुई है, हम सब गांव के लोग हैं, यह योजना बहुत अच्छी है।

(श्रीमती अनीता)

इससे गांव का डवलपमेंट, मूलभूत, हमारी स्वच्छता की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की बात है, वे सारी होंगी।

दो लाइनों में मैं अपनी बात खतम करती हूं-

हो के सूरज हम दिशाओं के रहे मोहताज,

तो हम जिधर को चल पड़ेंगे, पूरब उधर आ जाएगा।

इस प्रकार की भावना से यह बजट पेश किया गया है। इसका मैं बहुत समर्थन और बधाई देना चाहती हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री हीरालालजी नागर। आप अपनी बात कहें, मैं उससे पहले कहूंगी कि अपनी जो बात है बजट के सन्दर्भ में, उसमें बजट के ऊपर ही कहें, ज्यादा ठीक होगा, और दस मिनट में अपनी बात को रखना है।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय सभापति महोदया, जिस तरह से प्रदेश की जनता ने हमारी माननीया यशस्वी मुख्य मंत्री पर विश्वास करके 163 सीटें, उनकी सुराज संकल्प यात्रा, जिस तरह से उनको समर्थन मिला और उसके बाद लोक सभा में भी हमें 25 सीटें मिलीं, निश्चित रूप से उसी अपेक्षा के साथ आज यह बजट, हमारी सरकार का पहला बजट इस सत्र में आया है। इस बजट में जनता की अपेक्षाओं पर जो सुराज संकल्प यात्रा के दौरान हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणाएं की थीं, वादे किए थे और जो विजन उनका था, हमारा यह बजट आने वाले समय में राजस्थान को पटरी पर लाने वाला और विजनरी बजट होगा। निश्चित रूप से यह मील का पत्थर साबित होगा। इसमें परम्परागत रूप से जो बजट आते हैं, पहला बजट ऐसा मैं देख रहा हूं, आजादी के बाद इतना अच्छा बजट कभी आया है तो यह पहली बार आया है। निश्चित रूप से इसमें प्रयास किये गये हैं।

इस प्रयास के साथ, जिस तरह से कांग्रेस के भाई कह रहे हैं, ऊर्जा का मामला लीजिए आप, ऊर्जा में कांग्रेस ने किस तरह से इस प्रदेश का भट्ठा बिठाया। इन्होंने कहा, हम टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, और उसके बाद टैरिफ भी बढ़ाया और लोगों की वी सी आर भी भरीं। इन्होंने पूरे कार्यकाल में 700 मेगावाट बिजली का, सौर ऊर्जा का लक्ष्य था, वह 700 मेगावाट किया। इसके इतने बड़े-बड़े इन्होंने ढिंढोरे पीटे कि ऊर्जा के क्षेत्र में हम इतने बड़े, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, काफी घपले किये और इस सौर ऊर्जा के नाम पर इनके दामाद ने कितने तरह के भ्रष्टाचार किये, किसी से छिपा हुआ नहीं है।

(श्री हीरालाल नागर)

सौर ऊर्जा के मामले में, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने 25 हजार मेगावाट का विजन रखा है। निश्चित रूप से यह आगे जाकर इस प्रदेश के विकास में काफी सहयोगी होगा।

आज ये कहते हैं, इन्होंने सौर ऊर्जा के लिए एक सांभर जैसा पर्यटन स्थल था, वहां पर सौर ऊर्जा को लाकर निश्चित रूप से उस पर्यटन स्थल पर वातावरण खराब किया है, पर्यावरण को खराब किया है। इस पावर के लिए पर्यटन स्थल की जरूरत नहीं है। पूरा राजस्थान इसके लिए पड़ा है और वहां पर हमें उस पावर को ले जाना चाहिए, सौर ऊर्जा को ले जाना चाहिए।

सौर ऊर्जा के अलावा, जिस तरह से हमारी कम्पनियों को घाटा हुआ और इन पांच साल में हमारी ऊर्जा की कम्पनियां थीं वे किस तरह से नकारा हो गईं, किस तरह से उनकी स्थिति हो गई, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है; जहां 15 हजार करोड़ का घाटा 75 हजार पर पहुंच गया। यही हमारे भाई बोल रहे थे, प्रतिपक्ष के विधायक। उनको जानकारी नहीं थी कि 15 हजार करोड़ का, पूरे इस घाटे का, पूरे कार्यकाल का था और 75 हजार करोड़, जो 60 हजार करोड़ का घाटा केवल इन पांच साल के अन्दर हुआ, इस विद्युत के काम में, निश्चित रूप से यह विद्युत की कम्पनियों को ही नहीं, पूरे प्रदेश को गर्त में ले गया। आने वाले समय में हमारी कम्पनियां मुख्य मंत्रीजी के विजन के साथ आगे बढ़ेंगी।

अभी राजकुमारजी बोल रहे थे कि बिजली के लिए टेलीफोन आते हैं, निश्चित रूप से फोन आते हैं, लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने 24 घण्टे बिजली, 8 घण्टे थ्री-फेज देने का जो वादा किया, वह पूरा होगा लेकिन कम्पनियों की स्थिति खराब है, उसको सुधारने में थोड़ा समय लगेगा। आज की स्थिति है कि एक घण्टा क्या, आधा घण्टा भी ट्रिपिंग होती है, बिजली जाती है तो गांव से फोन आ जाता है, लेकिन जब कांग्रेस का राज था, उस समय स्थिति क्या थी, यह भी राजकुमारजी को पता है और पूरे प्रतिपक्ष के बैठे हुए सदस्यों को भी कि उस समय पूरे पूरे दिन, चार-चार दिन तक भी बिजली गायब रहती थी। 4 से 6 घण्टे तक का वादा था, 8 घण्टे का वादा था, वह तो कभी इन्होंने पूरा नहीं किया, 24 घण्टे का वादा पूरा नहीं किया और कभी भी 4-5 घण्टे से ज्यादा थ्री फेज बिजली किसानों को नहीं मिली। उसी का कारण रहा कि हमारे किसान तबाह हो गये। हमारे किसान भाइयों का उत्पादन भी घटा और उनको

(श्री हीरालाल नागर)

आर्थिक रूप से नुकसान भी हुआ। उसके साथ-साथ, ऐसी वी सी आरें भरकर, अनधिकृत रूप से यह पैसे की वसूली की गई और टैरिफ नहीं बढ़ाने का नाम लेकर गलत वी सी आर भरी गई। उसमें भी निश्चित रूप से किसानों को काफी नुकसान हुआ है।

इसके साथ-साथ मैं पानी पर आऊंगा। सिंचाई का हमारा क्षेत्र है उस सिंचाई के क्षेत्र में कांग्रेस पूरे पांच साल में कोई काम नहीं कर पाई। हमारी हाड़ौती की सबसे बड़ी परियोजना थी, परवन वृहद सिंचाई परियोजना, उस परवन सिंचाई परियोजना के नाम पर राजनीति की गई। उसका विजन वसुन्धराजी का था और वसुन्धराजी ने उस योजना को तैयार करवाकर, उस समय यहां की राज्य सरकार से केन्द्र में भेजा। लेकिन केन्द्र ने उसमें रोड़े अटकाने के अलावा कोई काम नहीं किया और उसको उस समय स्वीकृति इसलिए नहीं दी क्योंकि उसका श्रेय हमारा यशस्वी मुख्य मंत्री को नहीं मिल जाए। उसके बाद में, पूरे पांच साल इन्होंने वादा किया, सम्माननीय गहलोतजी ने भी हमारे बारां में और कोटा में जाकर, कि परवन परियोजना को हम पूरा करेंगे, पांच साल में पूरा नहीं कर पाए और जब चुनाव आ गए, तब इनके होश उड़े। तो इन्होंने उस परियोजना की, आनन-फानन में उसकी एक स्वीकृति जारी करवा दी, लोगों में ऐसा भ्रम फैलाया कि यह परियोजना स्वीकृत हो गई है और सोनियाजी को बुलाकर इन्होंने वहां एक पत्थर लगवा दिया। वह परियोजना, आज भी उसमें केन्द्र से कई स्वीकृतियां बाकी हैं। उसके टेण्डर निकाल दिए, टेण्डर निकालने के बाद, टेण्डर को ये बढ़ाते रहे, आगे खिसकाते रहे और चुनाव आ गए, लेकिन उसमें आज भी कई तरह की, आठ से दस तरह की, केन्द्र सरकार की स्वीकृतियां बाकी हैं। निश्चित रूप से, ऐसी परियोजना जिसमें स्वीकृतियां बाकी हैं, इस शासन में, हमारा शासन आया है तो अब वह परवन सिंचाई परियोजना है वह भी पूरी होगी और हाड़ौती के लिए ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी परियोजना होगी।

कालीसिंध परियोजना थी, कालीसिंध सिंचाई परियोजना, 263 करोड़ का पूर्व के बजट में इन्होंने प्रावधान किया लेकिन उस पर पांच साल में कभी कोई काम नहीं किया। ये चाहते तो उस कालीसिंध परियोजना को स्वीकृत कराकर उसे भी लागू कर सकते थे, लेकिन पांच साल में इन्होंने केवल बजट में वादे किये, उस पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया, न उस पर कोई काम आगे बढ़ाया। इस तरह का काम इन्होंने अपने कार्यकाल में किया।

(श्री हीरालाल नागर)

आप पेयजल को लीजिए। पेयजल के मामले में जो योजनाएं, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने उस समय बड़ी-बड़ी योजनाएं पेयजल की चलाई थीं, इन्होंने सरकार में आने के बाद उन पेयजल योजनाओं पर कोई काम नहीं किया। मैं कहना चाहूंगा, तीन साल तक इस कांग्रेस के शासन में उन परियोजनाओं को बिलकुल बंद कर दिया गया, उन पर कोई काम नहीं हुआ। जब चुनाव आ गए, फिर इनके होश उड़े और इनको लगा कि अब हमें कुछ करना चाहिए, तो आनन-फानन में इन्होंने डी पी आर बनवाईं, योजनाएं स्वीकृत करने की कोशिश की गई। लेकिन परिणाम जनता ने इनको जिस तरह से, भ्रम फैलाया वही परिणाम जनता ने दिया और उसका नतीजा है कि आज कांग्रेस के हमारे भाई गिनती के यहां पर दिख रहे हैं।

निश्चित रूप से राजनीति विकास के काम में नहीं होनी चाहिए। जब हम विकास का विजन लेकर चलते हैं तो विकास को बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अगर अच्छी योजनाएं हैं, जनता के लाभ की योजनाएं हैं तो उनको, सरकारें बदलती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन उन पर इस तरह से राजनीतिक रूप से कभी रोक नहीं लगानी चाहिए। ऐसी मेरी सोच है।

आज सड़क पर भी यही है, सड़कों के मामले में भी पूरे कांग्रेस के शासन में कोई काम नहीं हुआ। अभी पिछला जो बजट इनका आया था, वह 1,800 करोड़ का इनका सड़कों का प्रावधान था, सड़कों पर, और जब चुनाव आ गये तो 4,400 करोड़ की स्वीकृतियां इन्होंने जारी कर दीं। आज उसी का नतीजा है कि उन ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं। जिन ठेकेदारों ने काम किये हैं, उनके वे मजदूर सब परेशान हो रहे हैं और उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो यह कांग्रेस शासन में जिस तरह से इन्होंने उन योजनाओं को बिना बजट के, बिना किसी प्रावधान के जारी किया, वे जिम्मेदार हैं। हमें चाहिए कि राज्य में, अभी जिस तरह से मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि सड़क के लिए एक अलग से, एन.एच.ए.आई. की तरह, एक यहां का जो राजस्थान में भी हम बनाने जा रहे हैं, उसी तरह से प्रावधान हो। प्रावधान के साथ एक एक्ट बन जाए कि बिना एक्ट के ये सड़कें नहीं बनें और इस तरह की परियोजनाएं नहीं बनें और वह एक्ट के बाद, जब बजट का प्रावधान हो, तब ही उन परियोजनाओं पर काम हो। तो निश्चित रूप से बजट के अभाव में जो ये

(श्री हीरालाल नागर)

योजनाएं आज हमारी रुक जाती हैं, उन पर लगाम लगेगी और सरकार और राजनीतिक रूप से जो भेदभाव के साथ काम होता है, वह काम नहीं होगा, भेदभावपूर्ण काम नहीं होगा।

आज जो हमारी मुख्य मंत्रीजी ने, जिस तरह से हमारे राशन कार्ड में हमारे साथ जो स्थितियां हुईं, जिस तरह से इन्होंने आनन-फानन में वे राशन-कार्ड बनाये, लोगों को नहीं मिले और खाद्य सुरक्षा में आनन-फानन में इन्होंने जो जारी किये, निश्चित रूप से उस पर एक टास्क फोर्स बनाकर जो हमारी सरकार काम कर रही है, उसका निश्चित रूप से काफी लाभ पुन: ऐसे उपभोक्ताओं को मिलेगा जो जरूरतमंद हैं और जिन्होंने उस समय राजनीतिक दबाव में जो गलत तरीके से स्वीकृतियां जारी की थीं, ऐसे पर लगाम लगेगी। खाद्य सुरक्षा का, जो जरूरतमंद है, जो अंतिम व्यक्ति बैठा हुआ है, उसी को लाभ मिलना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। इस पर मैं खाद्य मंत्रीजी से भी कहूंगा कि एक टास्क फोर्स बने और उस पर तुरन्त काम चालू हो। आज गांव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जरूरतमंदों को वहां पर अनाज नहीं मिल रहा है और जिनके काफी मकान हैं, काफी जमीनें हैं, काफी तरह की उनकी सम्पत्तियां हैं, वे उस पर अपात्र हैं, ऐसे अपात्र व्यक्तियों को चिह्नित करके उनको हटाया जाना चाहिए। पात्र व्यक्ति को सम्मिलित करके और एक टास्क फोर्स बनाने की जो योजना है, इसकी भी मैं बहुत-बहुत तारीफ करता हूं।

आज जो यह हमारा, इसके साथ ही जिस तरह से ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): शिक्षा के मामले में लीजिए आप, शिक्षा में अभी तक जो भी सरकारें आईं, केवल बात करते थे, लेकिन पहली बार एकीकरण करके और जिस तरह से शिक्षा की स्थिति हमारी गर्त में गई हुई है, उस पर एक चरणबद्ध तरीके से काम चल रहा है। इस एकीकरण के बाद में जिस तरह की मानिटरिंग होगी और एक ही छत के नीचे, क्लास एक से लगाकर बारह तक के विद्यार्थी पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें शिक्षा में हमारे सुधार होगा। उसके साथ-साथ, जिस तरह से हमारे टीचर की कमियां हैं, एक ही छत के नीचे हमारे सारे टीचर आएंगे और एकीकरण के साथ-साथ समानीकरण होगा, तो निश्चित रूप से इसका लाभ आने वाले समय में, जो

(श्री हीरालाल नागर)

आज स्कूलों में, हमारे सरकारी स्कूलों में, जहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं, बच्चे नहीं आते हैं, वहां पर एक छत के नीचे आने से मानिटरिंग अच्छी होगी और उसका लाभ उन गरीब बच्चों को, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, उनको काफी लाभ मिलेगा। यह लाभ, निश्चित रूप से इस बार शिक्षा में जो परिवर्तन का विजन हमारी मुख्य मंत्रीजी लेकर आई हैं, उसका लाभ हमें मिलेगा।

इतनी ही बात कहकर मैं धन्यवाद देता हूं सभापति महोदया।

श्री सभापति: ऐसे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का 1 घंटा 43 का समय पूरा हो चुका है, लेकिन विशेष आग्रह पर मैं बुलवा रही हूं श्री बृजेन्द्र सिंहजी ओला साहब को। आप अपनी बात संक्षिप्त में कहें। पांच-सात मिनट में इसको पूरा करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्ताव पेश किया है, उस पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा।

बजट में और बातें तो हैं, पर सबसे अधिक बात जो हम देख पाये हैं, या तो पी.पी.पी. पर जोर है या गुजरात माडल पर जोर है। चाहे आप सड़क का ले लें, बीस हजार किलोमीटर स्टेट हाई-वे, ओ.डी.आर., एम.डी.आर., सब पी.पी.पी. माडल से बनाएंगे। उसमें आपने पांच हजार करोड़ से ज्यादा का प्रोविजन किया है इस साल के बजट में, जिसमें सेंट्रल स्पोंस्र्ड स्कीम्स भी हैं, पी.एम.जी.एस.वाई. भी है और इस पांच हजार करोड़ के बजट में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बजट भी शामिल है। इन सड़कों पर आप 70 हजार करोड़ रुपए की लागत बता रहे हैं। तो इस हिसाब से तो ये दस साल में आपकी पूरी होंगी।

पी.पी.पी. के लिए, मेट्रो के लिए भी कोशिश की गई है, कोई पी.पी.पी. में आया नहीं।

सड़कों में, एक लाख किलोमीटर सड़कें आपने ठीक करने की बात कही है और उसमें यह नहीं कहा है कि सम्भागवाइज आप उन पर टेंडर करेंगे और यह आपने स्पष्ट नहीं किया है कि यह स्टेट फंडिंग से होंगी या जिस ठेकेदार को आप टेंडर देंगे, उससे होंगी?

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

एक तरफ तो आपकी पार्टी, महाराष्ट्र में आपकी पार्टी और आपकी पार्टी को सहयोग देने वाला दल इस बात का आंदोलन कर रहे हैं कि टोल हटाये जाएं और यहां पर आप गांव तक टोल ला रहे हैं। अगर आप सम्भागवाइज एक ठेकेदार को आठ साल का रख-रखाव का काम देंगे, तो निश्चित रूप से जो उसकी यह छुपी हुई भावना इस बजट में है, वह यह है कि उस पर टोल लगेगा। इसके अलावा, वर्तमान में जो टोल रोड्स हैं, उनकी स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। किसी भी टोल रोड पर यह नहीं लगा हुआ है कि कितने पीरियड तक इस पर टोल वसूल होगा; इसका कितना टोल वसूल हो गया। कर्मचारी उनके कोई ड्रेस में होते नहीं हैं। आप स्वयं विधायक हैं, आपको भी शायद बताना होगा कि मैं विधायक हूं। नहीं तो, उनका क्या आम जन के प्रति व्यवहार रहता है! इस तरह की व्यवस्था आप पूरी सड़कों के लिए करने जा रहे हैं, यह राजस्थान की जनता के साथ कुठाराघात है।

बिजली के मामले में भी, 1998 में जब कांग्रेस सरकार थी और फंडिंग एजेंसीज की शर्त के कारण बिजली बोर्ड को तोड़कर कम्पनियां बनानी पड़ी थीं, तो आपकी पार्टी उस समय विपक्ष में थी, बहुत आलोचना की थी। वे कम्पनियां तो पूरी तरह से स्टेट-आन्ड कम्पनियां थीं, पर अब आपने उनका पूरी तरह से निजीकरण शुरू कर दिया है, और वह भी उन शहरों से शुरू किया है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी लास सबसे कम हैं। आप करते तो गांवों में जिन फीडरों पर ज्यादा लास है, उन पर करते। पर आपने उसकी शुरुआत कर दी है, उनको आप प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं। उसके अलावा, उसमें भी आप पी.पी.पी. और डिस्इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि बिजली की कम्पनियां, अमरीका में भी अगर उनके शेयर अलाट किये जाते हैं तो सबसे कम डिमांड वाले वे शेयर होते हैं, क्योंकि बिजली एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लास जरूर होता है, चाहे वे विकसित देश हों या विकासशील देश हों, पर उसमें भी आपने पी.पी.पी. माडल की बात की है। आपने सब जगह पर पी.पी.पी. माडल की बात की है। (व्यवधान)

आपने कहा है कि हम गुजरात माडल पर, गुजरात ने 15 कम्पनियों का डिस्इंवेस्टमेंट किया है, हम भी तीन कम्पनियों का डिस्इन्वेस्टमेंट करेंगे, आर.एस.एम.एम. का, आर.एस.एम.डी.सी. का और रीको का। पहली बात तो

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

आपको 'सिडबी' ने कई बार लिखा है कि रीको है, उसके कार्य दो तरह के हैं, एक तो वह जमीन बेचता है और दूसरा वह इंडस्ट्रियल प्रमोशन का काम करता है, तो इनको आप अलग-अलग करो। अगर आप इनको एक कम्पनी में रखते हैं तो आप उसको लिस्टेड नहीं कर पाएंगे, और लिस्टेड आप फिर कहां पर करेंगे, जयपुर एक्सचेंज तो खुद ही मरणासन्न अवस्था में है। वह कोई ठीक से काम ही नहीं कर रहा है अभी, बिलकुल बंद होने के कगार पर है। तो यह भी आपने बजट में फरमाया है।

इसके अलावा, इस बजट में, अगर सात दिन तक बारिश नहीं आई तो हम बहुत भयंकर अकाल की स्थिति पर, मुंह पर हम खड़े हुए हैं, कोई भी कंटिंजेंसी प्लान उसके लिए नहीं बनाया गया है। आपको रोजगार के लिए तो ठीक है कि आपके पास नरेगा है, आपके पास मानव के लिए फूड-ग्रेंस की भी व्यवस्था हो सकती है, या नहीं है तो बाहर से आ जाएगा, नहीं तो फूड एक्ट पास है; आप देने के लिए बाध्य हैं, पर पशुओं की जो स्थिति होने वाली है, उनको ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके लिये चारे की व्यवस्था

(16.00 बजे)

करनी पड़ेगी। उसके लिये इस बजट में कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया है। आपको कंटिंजेंसी प्लान बनाना चाहिये था, पर वह नहीं बनाया गया है। उसके बारे में भी जब सदन की नेता जवाब दें, तो कुछ अपने विचार प्रकट करें।

आपने यह कहा कि 26 प्रतिशत शेयर गवर्नमेंट ने रखे और रिफाइनरी में सब कुछ एच.पी.सी.एल. को दे दिया। एच.पी.सी.एल. तो भारत सरकार का उपक्रम है, पी.एस.यू. और भारत सरकार, दोनों की मिली-जुली वह कम्पनी थी, पर इस बजट भाषण में आपने कहा है कि हम सोलर ऊर्जा के लिये पी पी पी मोड पर जायेंगे और 26 प्रतिशत तक शेयर हम स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। प्राइवेट आदमी के साथ आप जायेंगे, उसमें 26 प्रतिशत शेयर लेंगे, वह ठीक है और गवर्नमेंट की कम्पनी के साथ 26 प्रतिशत का जो अनुबन्ध किया गया, उसको आप गलत मानते हैं।

इसी तरह से, भारत के माननीय वित्त मंत्रीजी कहते हैं कि हम उस शहर में मेट्रो लाने की या उसको प्रोत्साहन करने की कोशिश करेंगे, जिसकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। जब जयपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू किया तो

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

जयपुर की आबादी 20 लाख से ज्यादा थी और 20 लाख की आबादी को देखते हुए, हालांकि अहमदाबाद की आबादी हमसे ज्यादा है, पर लखनऊ और अहमदाबाद को केन्द्रीय बजट में 100-100 करोड़ रुपये दिये गये हैं। अब हमारे समझ से परे की बात है कि भारत सरकार सही है या आप सही हैं? आप इसको फीजिबल नहीं मान रहे हैं, भारत सरकार कह रही है कि हम उस शहर में मेट्रो को लाने में सहायता करेंगे, जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है।

इसी तरह से, मैं जिस जिले से आता हूं, उसका कहीं इस बजट में नाम नहीं है। एक जगह नाम है, 58 नम्बर पर, कि पानी के रि-स्ट्रक्चर के लिये जिन छह शहरों को चुना गया है, 2,160 करोड़ रुपये की लागत से एशियन डवलपमेंट बैंक से लोन लेने के लिए, वह तो हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने ही कर दिया था। तो वह तो कमिटमेंट था, अब उसको हटा नहीं सकते हो। और कहीं उसका नाम नहीं है। पिलानी से आपके विधायक चुनकर आते हैं और पिलानी विधान सभा क्षेत्र में कस्बा चिड़ावा, उसमें पूर्ववर्ती सरकार ने सीवरेज की योजना शुरू की थी, उसका भी कहीं इस बजट में कोई नामो-निशान नहीं है।

सात मेडिकल कालेजों की यहां बहुत चर्चा हो रही है। ये सात मेडिकल कालेज पूर्ववर्ती यू पी ए की सरकार ने, जब कांग्रेस सरकार थी, उसी समय मंजूरी कर दी थी। आपने उसमें से यह किया है कि एकाध जगह का स्थान बदल दिया। उसका भी आप बहुत श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वे कालेज पिछले बजट में ही भारत सरकार ने राज्य सरकार को दे दिये थे।

आपने बजट भाषण में कहा है कि हमने 1995 से, जब हमारी सरकार थी, चैक-पोस्ट हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी। बीच में कांग्रेस ने लगा दी, फिर हम आये, हटा दी। पर आप 16 मार्गों, अब सरकारी पैसा है, वे निजी क्षेत्र के लोग उगायेंगे। यह कहां तक उचित है? सरकार का जो रेवेन्यू है, उसको प्राइवेट लोग कलेक्ट करेंगे। यह भी समझ में आने से परे वाली बात है।

इस बजट में कहीं भी महंगाई को घटाने की ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है। भारत के वित्त मंत्रीजी कहते हैं कि महंगाई बढ़ाने में राज्यों का सबसे बड़ा हाथ है; राज्य सरकारें कीमत घटे, इस बारे में कोई कदम नहीं उठातीं; फिर भी इस बजट में कोई ऐसे कदम नहीं उठाये गये हैं कि महंगाई कम हो। अलबत्ता यह जरूर किया गया है, महंगाई बढ़ाने के लिये जरूर कुछ न कुछ कदम उठाये गये हैं।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

आपने कहा है कि हम टाउन प्लानिंग का गुजरात पैटर्न पर एक्ट लायेंगे।

श्री सभापति: माननीय ओलाजी, संक्षिप्त करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं।

गुजरात में नगरीय कर सबसे अधिक है। बजट में कहा गया है कि हमको जे.एन.यू.आर.एम. में पैसे लेने हैं, इसलिये पानी की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, नगरीय विकास कर बढ़ाना पड़ेगा। आपने रेडीमेड वस्त्रों, टैक्सटाइल पर कर बढ़ाया है, आप पानी पर बढ़ाने जा रहे हों, आप सड़कों पर टोल लगाने जा रहे हों, तो इन सब बातों से महंगाई बढ़ेगी।

किसान है, वह असंगठित है, इसलिये उसका कोई कहने वाला नहीं है। उस पर जरूर भारत सरकार और राज्य सरकार, दोनों कैंची चला देती हैं। जब प्याज के पैसे बढ़ते हैं, टमाटर के बढ़ते हैं, तो कहते हैं, निर्यात रोक दो। जहां जिस देश को आप निर्यात करते हों, वे आपका इन्तजार नहीं करेंगे, वे तो लेंगे, किसी दूसरे देश से लेंगे। तो आपका मार्केट वहां तो कैप्चर हो जाता है और यहां फिर वह पैसे गिरने शुरू हो जाते हैं। तो किसान की हालत खराब हो जाती है।

मैं जिस जिले से आता हूं, उसमें इसी हाउस में खेल यूनिवर्सिटी का बिल पास किया। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी हैं, वे उस समय विपक्ष के मुख्य सचेतक होते थे, आप भी सदन में थीं, उसके लिये एक पैसे का भी प्रोविजन इस बजट में नहीं किया गया है। एक्ट पास कर दिया, वाइस चांसलर लगा दिया, ओ.एस.डी. लगा दिया, जमीन गवर्नमेंट ने अलाट कर दी, उसके लिये एक पैसे का प्रोविजन नहीं किया है। यह सरकार क्या इंगित करना चाहती है, यह हमारी समझ से परे है।

यहां जी.एस.टी. की बात आई। सबसे बड़ी रुकावट जी.एस.टी. के मामले में बी जे पी शासित राज्य ही थे, पर चूंकि अब आपकी दिल्ली में सरकार आ गयी, यहां आ गयी, आप उसके लिये एग्री हो गये। जी.एस.टी. जब लागू हो जायेगी तब तो शायद यह स्थिति रहे कि नहीं रहे, पर अब हनुमानगढ़ से लेकर भरतपुर तक जितने सीमावर्ती रूट हैं, उन पर सारे पर पेट्रोल पम्प हरियाणा के लोगों ने राजस्थान की सीमा से 500 मीटर दूर खोल रखे हैं, 10-10, 20-20 खोल रखे हैं। वह इसलिये है कि 4-5 रुपये डीजल और पैट्रोल में

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

कीमत का फर्क है। लोग पैरेलल पैट्रोल पम्प चलाते हैं। ड्रमों में भरकर लाते हैं, अवैध तरीके से भरकर लाते हैं। उससे संगठित अपराध भी होते हैं। अगर आप अपनी ड्यूटी, जो स्टेट का टैक्स है, उसको कम करके और एट-पार हरियाणा के ले आयें, तो स्टेट की तो आमदनी बढ़ेगी और लोगों को, जो दो नम्बर का काम करते हैं, उस पर रोक लगेगी।

आपने बहुत सारी बातें इस बजट में कही हैं, 24 घंटे बिजली देंगे; हमने 7 महीने में 900 मेगावाट बिजली जोड़ दी, 7 महीने में कोई एक पावर हाउस बन सकता है क्या? और कह रहे हैं कि 850 मेगावाट और इस बजट में जोड़ देंगे। आप कह रहे हैं कि हमने 69,820 करोड़ का प्लान आउट-ले बना दिया, पर इस प्लान आउट-ले की तो समीक्षा तब होगी, जब 31 मार्च को इसका पूरा हो जायेगा।

आप, सभापतिजी, बार-बार मेरी तरफ देख रही हैं।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, क्योंकि मैं घड़ी की तरफ देख रही हूं, आपकी तरफ देख रही हूं।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): मैं अनुशासित सदस्य हूं, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री सभापति: सदन का समय है यह और सभी माननीय सदस्य अगर समय से चलें, क्योंकि बहुत बड़ी सूची है...

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कृपा करके जो जन हितकारी काम दें, उनके ऊपर ध्यान दें और जो सरकार जिन बातों से वाहवाही लूटना चाहती है, उनके साथ-साथ जो जन हित की बात है, उन पर भी ध्यान दें।

आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामलालजी शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट की चर्चा में मुझे भाग लेने के लिये अनुमति प्रदान की।

सभापति महोदया, प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्री, वसुन्धराजी ने जो परिवर्तित बजट 2014-15 पेश किया है, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आशा व उम्मीद भी करता हूं कि जो भी इस बजट के विरुद्ध में अपना वक्तव्य जारी कर रहे हैं, वह सिर्फ विपरीत विचारधारा के लोग होने के नाते जारी कर रहे हैं, मन से तो वे भी इस बजट की प्रशंसा ही कर रहे हैं।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदया, यह बजट बंद कमरों में बनाया हुआ नहीं है। लोगों की भावनाएं और लोगों से चर्चा-परिचर्चा करने के बाद, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह विद्यार्थी हो, उन सबसे चर्चा करने के बाद, उन सबके सुझावों को शामिल करके राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने यह बजट पेश किया है।

दो-तीन बात इस संदर्भ में मैं निवेदन करूंगा। सभापति महोदया, इस बजट के अन्दर आपने यह देखा होगा कि मुख्य मंत्रीजी ने, जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारें सरकार के खजाने को लुटाने का जो प्रयास करती रही हैं, वैसा प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी ने नहीं किया। उन्होंने डेढ़ सौ करोड़ रुपये करों में राहत दी, तो साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये करों से अर्जित करने की व्यवस्था भी दी है।

सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं दो-तीन बातें निवेदन करना चाहूंगा। सड़कें बनाने का या चिकित्सा की समुचित व्यवस्थाओं को सुधारने का जिक्र भी इस बजट के माध्यम से किया गया है, लेकिन कई विकास के काम ऐसे हैं जो विकास के काम सरकार बनने के बाद में शुरू हुए थे, उनका जिक्र इस बजट के अन्दर नहीं आया। सभापति महोदया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा, मुख्य मंत्रीजी का एक विजन है कि इस शहर के अन्दर बढ़ती हुई आबादी को या बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रेशर को कैसे कम करें और उनके उस विजन के माध्यम से जयपुर शहर के आसपास के जो कस्बे हैं, उन कस्बों को विकसित करने का काम शुरू हुआ। मैं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र का जिक्र करना चाहूंगा, सभापति महोदया, मेरे चौमूं विधान सभा क्षेत्र में बहुत कम क्षेत्र जयपुर विकास प्राधिकरण का आता है लेकिन फिर भी उसके अन्दर सात करोड़ रुपये के टेण्डर लग चुके हैं, करीबन 42 करोड़ रुपये जे.डी.ए. की पी.डब्ल्यू.सी. की मीटिंग के अन्दर स्वीकृत हो चुके हैं।

ऐसे ही, सभापति महोदया, मेरा विधान सभा क्षेत्र ही नहीं है, जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में आने वाले सभी विधान सभा क्षेत्रों की यही स्थिति है। बगरू विधान सभा क्षेत्र के अन्दर भी जे.डी.सी. ने दौरा करके 50 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा वहां की है, उनका जिक्र इस बजट के अन्दर नहीं हुआ।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार बनने के बाद में मुख्य मंत्री

(श्री रामलाल शर्मा)

ने पूरे प्रदेश का विकास करने की दृष्टि से अनेकों योजनाओं की शुरुआत की है।

सभापति महोदया, मैं एक और बात का जिक्र करना चाहूंगा। अभी विपक्ष के कई माननीय सदस्य कह रहे थे, जनसंख्या के पलायन को रोकने के लिए अगर 2003 से लेकर 2008 तक की जो वसुन्धराजी की सरकार थी, अगर वह सरकार फीडर सुधार कार्यक्रम नहीं चलाती, अगर गांवों के, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर फीडर सुधार कार्यक्रम के माध्यम से बिजली मिलना शुरू नहीं होती, तो आज शहरों की जनसंख्या और भी तीव्र गति से बढ़ती। वहां पर उनकी जो माकूल व्यवस्था करनी चाहिए, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे आवास की व्यवस्था हो, उनके अन्दर भी संकट खड़ा होता। जब से यह फीडर सुधार कार्यक्रम हुआ है, तब से ही ग्रामीण क्षेत्र का शहरों की ओर जो पलायन होता था, उस पलायन पर ब्रेक लगे हैं। लोगों ने छोटे-छोटे कुटीर उद्योग भी वहां लगाना शुरू किया है।

तो आने वाले समय में भी, इस तरीके से जो योजनाएं मुख्य मंत्रीजी ने घोषित की हैं, वह मात्र यह दस्तावेज बन कर नहीं रहेगा, यह धरातल के ऊपर क्रियान्वित होने वाला बजट है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बजट के अलावा और भी अन्य योजनाओं के तहत प्रदेश का विकास होगा।

सभापति महोदया, मैं तो आपके माध्यम से इतनी ही बात इस बजट के लिए कहना चाहूंगा कि हमने चादर उतनी ही फैलायी है, जितने हमारे पैर थे; बड़ी चादर फैलाने का काम नहीं किया है।

विपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं, वे बार-बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं और वे जिक्र कर रहे हैं मेट्रो का। सभापति महोदया, मेट्रो की आवश्यकता, मुझे नहीं लगता कि आने वाले पांच-सात साल तक भी रहती। जितना पैसा इन्होंने मेट्रो पर खर्च किया, अगर इसकी बीस परसेंट राशि भी ब्रिज बनाने के लिए, सड़कों को चौड़ा करने के लिए, ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए खर्च करते तो मैं समझता हूं कि पांच-सात साल का समय जयपुर शहर में और भी चल सकता था। अगर इनको खर्च ही करना होता तो, सभापति महोदया, जैसा मैंने 295 के तहत कहा, डी.एम.यू. ट्रेन चलाने का अगर ये काम करते, रेलवे की लाइनें बिछी हुई हैं, मीटर गेज से अधिकांश लाइनें ब्राड गेज में परिवर्तित हो चुकी हैं, रेलवे की जमीन इनके पास उपलब्ध है और मैं तो आपके

(श्री रामलाल शर्मा)

माध्यम से मांग भी करना चाहूंगा, केन्द्र के अन्दर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ देने की आवश्यकता है तो ग्रामीण क्षेत्रों को डी.एम.यू. ट्रेन से जोड़ना नितान्त आवश्यक है, ताकि उन लोगों को लाभ मिल सके।

सभापति महोदया, एक दूसरी बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा कि बिजली के क्षेत्र में जितना विकास 2003 से लेकर 2008 तक हुआ और अब की बार भी इस बजट में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि किसानों को बिजली अच्छी मिले, समय पर मिले, वोल्टेज सही मिले, इसके लिए उन्होंने ग्रिड बनाने की घोषणा भी की है और निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रदेश की जनता इस बिजली का उपयोग ठीक तरीके से कर पायेगी।

सभापति महोदया, एक बात मैं आपके माध्यम से जरूर कहूंगा, पूर्ववर्ती सरकार ने एक नहीं, अनेकों पाप ऐसे किये हैं जिनकी वजह से आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग दुःखी हैं। सभापति महोदया, एक नीतिगत निर्णय इन्होंने किया, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर कृषि उपज मण्डी का जो गठन था वह गठन इसलिए किया गया था कि किसानों को लाभ दे सकें और किसानों को लाभ तभी मिल पाता है जब स्थानीय स्तर के ऊपर निर्णय होते हों, पिछली गवर्नमेंट ने एक नीतिगत निर्णय यह किया कि कृषि उपज मण्डी के अन्दर चाहे कितना भी पैसा उपलब्ध हो, लेकिन कृषि उपज मण्डी सड़क बनाने का काम नहीं करेगी। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार के एक निर्णय की वजह से, सिर्फ उन्होंने यह कहा कि कृषि उपज मण्डी का जो शुल्क के रूप में पैसा आता है, उस पैसे का उपयोग सिर्फ इन्टरनल डवलपमेंट के अन्दर होगा। सभापति महोदया, इन्टरनल डवलपमेंट के नाम पर, मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं, मेरी कृषि उपज मण्डी के प्रांगण के अन्दर इन्टरनल डवलपमेंट की आवश्यकता नहीं, पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सेक्रेटरी ने और बोर्ड ने मिल कर, मैंने पूछा कि सड़क बनाने की आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी ड्रेन बनाने की, उसके बावजूद भी आपने पैसा खर्च क्यों किया? तो उनका एक ही उत्तर था कि यह पैसा सड़कों में तो खर्च कर नहीं सकते; यह पैसा पड़ा है, इसको कहीं न कहीं तो खर्च करना होता था। सभापति महोदया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चार करोड़ रुपये बिना किसी उपयोगिता के इन्टरनल डवलपमेंट के नाम पर उन्होंने खर्च किये।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदया, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि स्थानीय स्तर पर जो कृषि उपज मण्डी है, जो ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर पी.डब्ल्यू.डी. जो सड़कें बनाती है वह नोर्म्स के आधार पर बनाती है, 500 से अधिक आबादी का गांव है वह जुड़ने का काम पी.डब्ल्यू.डी. से होगा, या 10 हजार से अधिक आबादी की कोई ग्राम पंचायत है वह पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से जुड़ने का काम होगा; मिसिंग सड़कें हैं, जो छूटी हुई हैं, जिनकी दूरी आधा किलोमीटर है, एक किलोमीटर है, तीन किलोमीटर है, ऐसे मिसिंग सड़कें बनाने का काम मण्डी के द्वारा होता था। इसलिए, सभापति महोदया, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि जब बजट की रिप्लाई माननीया मुख्य मंत्रीजी दें, तो कम से कम पूर्ववर्ती सरकार के इस निर्णय को चेंज करने की बात वे जरूर कहें।

सभापति महोदया, एक और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वर्षों पहले एक बात किसी कवि ने कही थी कि 'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून; बिन पानी न ऊबरे, मोती, मानस, चून।' सभापति महोदया, अनाज का विकल्प है, जब किसी को गेहूं खाने को नहीं मिलता था तो बाजरा मिलता था; बाजरा खाने को नहीं मिलता था तो मक्का मिलती थी; मक्का किसी को नहीं मिलती थी तो चावल मिलता था, अनाज का विकल्प है लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं है। पानी किसी फैक्टरी के अन्दर भी पैदा नहीं होता। वैसे प्रदेश की मुख्य मंत्रीजी ने इस पानी को बचाने के लिए इस बजट के अन्दर प्रावधान किया है लेकिन हम सब की जिम्मेदारी भी बनती है। आने वाले समय के अन्दर यह प्राकृतिक स्रोत समाप्त होने की कगार के ऊपर है, वाटर रिचार्ज को हम कैसे कर सकते हैं।

एक सुझाव जो मेरे ध्यान में आता है, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यहां रखना चाहूंगा। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 500 से लेकर एक हजार ट्यूबवैल, जिनको हम हैण्डपम्प कहते हैं, सभापति महोदया, आज वे खराब पड़े हैं। क्यों नहीं, इन एक हजार हैण्डपम्पों को हम नरेगा से जोड़ कर इनको वाटर रिचार्ज के रूप में काम में ले सकें? सभापति महोदया, पानी रहेगा। क्योंकि पहले तो नारा चलता था कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में; अब तो, सभापति महोदया, आवश्यकता इस बात की है कि 'गांव का पानी गांव में', 'खेत का पानी खेत में' और 'मकान का पानी मकान में'। क्यों नहीं हम राजस्थान में एक ऐसा कानून लेकर आयें ताकि मकान का निर्माण करने वाले व्यक्ति को एक शपथ पत्र लेकर बाध्य किया जाए? ग्रामीण

(श्री रामलाल शर्मा)

क्षेत्र में पंचायत उसको बाध्य करे कि मकान बनाने से पहले वह एक शपथ पत्र दे कि मैं 20 लाख का मकान बनाऊंगा तो 20 हजार रुपये वाटर रिचार्ज के ऊपर भी खर्च करूंगा; शहरी क्षेत्र के अन्दर नगरपालिका क्षेत्रों में भी वह एक शपथ पत्र यह दे कि मैं 50 लाख का मकान बनाऊंगा तो 50 हजार रुपये वाटर रिचार्ज के लिए भी खर्च करूंगा।

सभापति महोदया, अगर ऐसा अभी नहीं सोचा गया, अभी ऐसा नहीं किया गया, तो आने वाले समय के अन्दर इस जल का दोहन और भी तीव्र गति से होगा और इसका विकल्प हम सब को नजर भी नहीं आता है। तो प्राकृतिक रूप से जो बरसात का पानी है, इसको हम कैसे इकट्ठा कर पायें और कैसे इससे वाटर रिचार्ज कर पायें और जल को हम कैसे बचा पायें।

वैसे तो प्रदेश की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जो अपने बजट भाषण के अन्दर कहा है कि हम ड्रिप इर्रिगेशन को बढ़ावा देंगे और इसके ऊपर अनुदान की भी घोषणा की है, निश्चित रूप से यह एक सकारात्मक पहल है और इससे कम पानी से अधिक पैदावार हो सकती है।

सभापति महोदया, आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा। इस बजट में किसानों के बारे में बहुत गम्भीरतापूर्वक चिंता की गयी है और किसानों के हितों को ध्यान में रखा गया है। पहली बार बजट के अन्दर यह घोषणा की गयी है कि हम किसानों के लिए खाद और बीज का भण्डारण करने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि समय आने पर न तो किसान को बीज उपलब्ध हो पाता है और न उसको खाद उपलब्ध हो पाती है। मुख्य मंत्रीजी ने जो बात इस बजट के माध्यम से कही है, निश्चित रूप से यह किसानों के लिए लाभदायक होगी।

सभापति महोदया, मेरा एक निवेदन और है। वर्षों पहले अग्नि-पीड़ित परिवारों को जो सहायता दी जाती थी, उनके नोर्म्स बने हुए हैं। सभापति महोदया, आग उस व्यक्ति के घर में लगती है जिसके कच्चा छप्पर हो। इस नियम में भी संशोधन की आवश्यकता है। आज महंगाई जिस गति से बढ़ी है, बाजार के अन्दर भी जिस तीव्र गति से महंगाई बढ़ी है, उसी के अनुसार उस गरीब आदमी के ऊपर भी है। अगर उस गरीब आदमी के छप्पर जलता है या उसके पशुधन का नुकसान होता है तो उस अग्नि-पीड़ित परिवार को लाभ देने के लिए भी जो नोर्म्स हैं, उनके अन्दर संशोधन की आवश्यकता है।

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदया, मेरा एक और सुझाव आपके माध्यम से है कि राजस्थान की जनता सम्मान और सुरक्षा चाहती है और राजस्थान की जनता को आपने सम्मान और सुरक्षा दे दी। निश्चित रूप से अगर करों की थोड़ी-सी वृद्धि भी अगर हो गयी तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसा ही मुख्य मंत्रीजी ने किया है।

सभापति महोदया, यह पहला बजट है, जिस बजट के ऊपर जनता की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आयी हैं, नकारात्मक प्रतिक्रिया एक भी नहीं आयी। सभापति महोदया, पहले भी मैंने बजट देखे हैं, कई बार जब बजट पेश होते हैं तो व्यापारिक संगठनों द्वारा या उद्योगपतियों के द्वारा इस बजट का विरोध किया जाता है, लेकिन पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने ऐसा बजट पेश किया है कि एक भी व्यापारी ने इस बजट का विरोध नहीं किया, एक भी उद्योगपति ने इस बजट का विरोध नहीं किया। सबने सराहना की है इस बजट की।

इसलिए मैं भी इस बजट के अन्दर अपना पूरा मत और समर्थन देता हूं और आशा व उम्मीद करता हूं कि यह बजट राजस्थान को एक नई दिशा देने वाला होगा, राजस्थान की अवाम को सुरक्षा और अवाम को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने वाला होगा।

श्री सभापति: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं आज राजस्थान के परिवर्तित बजट 2014-15 पर बोल रहा हूं। माननीय सभापति महोदया, आपने मौका दिया, उसके लिए पहले ही धन्यवाद देता हूं। बाद में बोलते-बोलते कहीं ध्यान नहीं रहे।

सभापति महोदया, यह बजट is not only a vision; it is a divine mission, divine vision. दिव्य संदेश है यह बजट। माननीया वसुंधराजी को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं और इसके साथ में भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं कि यह 2014-15 का बजट वास्तव में अब तक के मेरे सार्वजनिक जीवन में, मैं विद्यार्थी नेता रहा हूं, मजदूर नेता रहा हूं लगभग 2 दशक और पिछले 2 दशक से, 21 वर्ष से मैं राजनीति में हूं, बहुत सारे बजट देखे हैं, जब मैं मजदूर नेता था तब भी, 5 साल में यह पहला ही बजट इतना दिव्य और सुंदर, सुंदर, सुंदर। भाई, उत्तम। उत्तम, भाई।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अंकल, एक मिनट। सभापति महोदया, आप तो सबसे पहले बधाई इस बात की स्वीकार करो कि चार बार विधायक रह गये, पहली बार समर्थन में बोलने का मौका मिला है। वरना आप जब-जब जीते हैं, पार्टी को हराकर आप अकेले आये हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): भतीजे, मैंने तो तुम्हें यशस्वी होने के लिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बीच में टोका-टोकी ना करें। अपनी बात को कंटिन्यू रखें। आपस में बात ना करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदया, मैं बजट के बारे में निवेदन करूंगा कि पिछली सरकार, जिसने मुफ्त की खैरात बांटना पसंद किया, मुफ्त की साड़ियां, उसके नकद पैसे दिये, साइकिल के नकद पैसे दिये, सी एफ एल बांटीं, लेकिन जनता ने क्यों ठुकरा दिया, क्योंकि यह देश, यह प्रदेश और यहां की जनता स्वाभिमानी है। यहां समाजवाद और साम्यवाद भी इसलिए फेल हुआ कि उन्होंने नारा लगाया 'रोटी, कपड़ा और मकान', लेकिन हमारे मनीषियों ने और वर्तमान युग के मनीषी, पहले मनीषी संतों और ऋषियों ने और वर्तमान युग के मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, रोटी, कपड़ा और मकान लेकिन उसके ऊपर स्वाभिमान।

सभापति महोदया, मैं सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई सुबह उठकर के हमको चार जूते मारे और चार गालियां दे और फिर उसके बाद कहे कि रसगुल्ले खा लो, गुलाब जामुन खा लो और यह जलेबी खा लो; नहीं खायेंगे और उसको ठुकरायेंगे, क्योंकि हम लोग स्वाभिमानी हैं। यह स्वाभिमानी देश है। 5 साल तो काम किया नहीं आप लोगों ने, कांग्रेस सरकार ने और आखिरी 4 महीनों में 'राजस्थान में पहली बार,' 'राजस्थान में बड़ा फैसला', 'राजस्थान में पहली बार', जैसे कांग्रेस के भी पूर्व मुख्य मंत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं सदन में, स्वर्गीय हो गये, कुछ वर्तमान में हैं, उन्होंने जैसे काम किया ही नहीं, बस इन्होंने ही किया हो।

सभापति महोदया, मैं बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूं। कुछ लोग इस समय दर्जी, धोबी, नाई, मोची और पत्रकारों के भरोसे राजनीति करना चाहते हैं। बड़े-बड़े होर्डिंग्स पूर्व मुख्य मंत्रीजी के लगे, बड़े-बड़े विज्ञापन, पूरे-पूरे पेज के। करोड़ों-अरबों रुपया विज्ञापनों में खर्च कर दिया। लेकिन जनता का उससे भला नहीं हुआ। जनता को चूंकि मुफ्त खाने की आदत नहीं है, यह देश स्वाभिमानी है, स्वाभिमान के भरोसे जिया।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

सभापति महोदया, वर्तमान बजट पर मैं बोलूं, उससे पहले आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश के सम्मान को, स्वाभिमान को, जमीर को, इज्जत को कायम रखते हुए कोई भी सरकार पूरे 5 साल काम करे। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री, वसुंधराजी ने पहले भी 5 साल काम किया। आप कहेंगे कि फिर सरकार क्यों गयी? सरकार आप लोगों के कारण से नहीं गयी, कांग्रेस के कारण से नहीं गयी, हमारे बीच में ही कुछ ऐसे बंधु थे जिन्होंने माननीया मुख्य मंत्रीजी को सहयोग नहीं किया। यह मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए सरकार नहीं बन पायी। लेकिन सरकार तब भी हमारी थी, क्योंकि अपोजिशन में रहकर के भी हम 78-79 लोग थे, अब फिर भारी बहुमत से जनता ने हमको जितवाया है।

मैं आपके बीच में कहूंगा, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, कैफी आजमी ने जो शेर लिखा है उसको मैंने मोडिफाई किया है, 'प्रदेश और देश में कांग्रेस की इस सरकार के इस जुल्म को देखा है तवारीख की नजरों से, तवारीख मतलब इतिहास। '...शहजादे और पूर्व मुख्य मंत्री ने खता की थी, पूरी कांग्रेस ने सज़ा पाई है'। खैर, हम लोगों को तो फायदा हुआ, जनता ने इन्हें पूरी तरह से ठुकरा दिया। मैं इस बात को यही इतिश्री देता हूं।

सभापति महोदया, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट रखा है, उस सम्बन्ध में मैं आगे बात को कहना चाहता हूं, सिचुएशन आफ फिस्कल डेफिसिट, एफ वाई 2003-04 में 6 प्रतिशत; एफ वाई 2007-08 में 1.75 प्रतिशत और एफ वाई 2013 में 3 प्रतिशत। लोन और लाइबिलिटी आन दी स्टेट, 2008 में हम लोगों ने जो छोड़ा था, वह था 77 हजार 138 करोड़ रुपये का कर्जा, लेकिन बढ़ाते-बढ़ाते आप लोगों ने उसको 31.08.2014 तक 1 लाख 30 हजार 640 रुपये का कर्जा किया। बहुत लंबा मैं नहीं जाऊं, तो हम लोगों ने अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू सरप्लस, यह जो आप लोगों ने छोड़ा माइनस में 505, यह नुकसानदेह है और हमने आगे जो बढ़ाया है, वह 737 करोड़।

सभापति महोदया, इसी प्रकार से, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल सरप्लस/डेफिसिट, माइनस में 2034 आप लोगों ने और हमारा जो होने वाला पूंजी निवेश है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यह 3,888 रुपये। इसी प्रकार से, टोटल रिसीप्ट्स, आप लोगों ने 99 हजार 877 और हम लोगों का जो आयेगा, 1

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

लाख 28 हजार 275 करोड़; टोटल एक्सपेंडिचर 1 करोड़ 349 रुपये और हमारा आपसे 31 प्रतिशत बढ़कर के आयेगा; 31 प्रतिशत बढ़कर के बजट आया है, 1 करोड़ 31 लाख 427 रुपये।

सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सपेंसेज आन रोड डवलपमेंट, टार्गेट डवलपमेंट आफ 20,000 किलोमीटर रोड पी पी पी माडल; अब इस पी पी पी माडल में से कमियां निकाल रहे हैं। वास्तव में पब्लिक पार्टिसिपेशन की यह जो योजना है, यह पूरे यूरोप में सफल है और यहां पर भी सफल होगी। आखिर किसी जगह तो हम करेक्टर को मेनटेन करेंगे। इस नाते यह होने वाला है।

सभापति महोदया, ईस्ट-वेस्ट कारिडोर मोर दैन एक हजार किलोमीटर। इसी तरह से, कांस्टिट्यूशन आफ राजस्थान स्टेट हाइवे आथोरिटी, यानी हाइवे आथोरिटी जो सेंटर की बनी हुई है, उसी तर्ज पर कांस्टिट्यूट करके राजस्थान की हाइवे अथोरिटी बनायेंगे। रोड मेंटीनेंस, ओ पी आर सी, आउटपुट एंड परफोर्मेंस बेस्ड रोड्स कांट्रेक्ट फार ऐट यीअर, 8 साल के लिए यह कांट्रेक्ट है।

इसी प्रकार से, आर सी सी रोड्स एट ग्राम पंचायत ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट। कुछ कहना चाह रहे हैं माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदया, मैं तो यह कह रहा था कि आप इतनी एकाग्रचित होकर इनका भाषण सुन रहे हों। मैंने कभी देखा नहीं इतना एकाग्रचित्त। इसलिए कह रहा हूं कि प्रभावित हो रहे हों।

श्री सभापति: धन्यवाद। मैं सभी का भाषण एकाग्र होकर ही सुन रही हूं।

माननीय सदस्य, आप कंटिन्यू करें और थोड़ा सम-अप करें। 10 मिनट का समय आपका हो चुका है। आप शुरू करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आर सी सी रोड्स एट ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर लेवल, more than 9,000 to be covered. यह जो सारी सड़कों की योजना है। इसी प्रकार मैं रोड से आगे बढ़ता हूं, in current F.Y. 530 village habitations of 250 to 499 यानी 250 की आबादी से 499, 500 तक की आबादी के लिए रोडों की विशेष योजना है।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

सभापति महोदया, इसी प्रकार से एम ओ यू किया गया है पवन हंस के साथ, यानी कि एयर की सुविधाएं, हवाई सुविधाएं भी दी हैं। एम ओ यू किया गया है, for helicopter services for places.., विशेष रूप से और as they will provide its 2 aeroplanes to be used air taxies., यानी, राजस्थान सरकार के, स्टेट के प्लेन हैं, उनको भी अटैची के रूप में...। इसी प्रकार से, प्लेन की सेवाओं के बारे में आगे बताया गया है।

सभापति महोदया, एनर्जी के बारे में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आर वी वी एन एल टार्गेट आफ फाइव यीअर्स 6,500 मेगा वाट्स इन न्यू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी; यानी, 6500 मेगावाट का जो पावर जनरेशन होगा, वह राजस्थान के लिए बहुत ही सुखद होगा। टार्गेट आफ वेटिंग-फ्री एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यानि 40 हजार नये कनेक्शन देंगे 2014 -15 में। Debt equity ratio of electricity companies to be improved. Gain equity from market.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदया, अब भी आप मंत्री नहीं बनाओगे तो इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। इससे बढ़िया कोई भाषण हो नहीं सकता।

श्री सभापति: प्लीज, कोई भी मेम्बर टोकेगा नहीं। आप बैठ जाएं। आप बैठ जाएं, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप विराजिये, उनको बोलने दीजिये। (व्यवधान) आप भी बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): क्यों नहीं बन सकते गृह मंत्री?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सोलर पावर का 25 हजार मेगावाट कैपेसिटी का लक्ष्य रखा गया है। (व्यवधान) हिन्दी में बोल रहा हूं। आपको कहीं दिक्कत हो रही हो सुनने में, समझने में, हनुमानजी, हनुमानजी, आपको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हिन्दी में बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें जल्दी। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): इसी प्रकार से लीगल प्रोविजन्स में, बजट प्रिपेरेशन्स में और टैक्सेज के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, जो इण्डस्ट्री के लोग हैं, फार्मर्स हैं, एन जी ओज हैं, पब्लिक के प्रोफेशनल्स हैं, जो

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

व्यावसायिक लोग हैं और साधारण लोग हैं, उन सबसे राय लेकर बनाया गया है। जी एस डी पी के बारे में बताया गया है।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, सिंगल एप्लिकेशन पर रजिस्ट्रेशन अण्डर-रेफरेंस, सिंगल फार्म और आन-लाइन, सारे आन-लाइन पर होंगे और जितने टैक्सेज से सम्बन्धित होंगे, जितनी भी समस्याएं होंगी, वे आन-लाइन होंगी। मैं हिन्दी में आपको निवेदन कर रहा हूं।

E-governance, maximum possible efforts to make human interference negligible, यानी पहले जो व्यक्ति के द्वारा काम को रोकने की और काम को टरकाने की, चलताने की पद्धति थी, उसको भी अवोइड किया जायेगा और ये सब काम आन-लाइन होंगे। यह भी आप समझ लें।

रिफण्ड, जो एक बार टैक्स किसी ने गलती से ज्यादा जमा करा दिया, उसको रिफण्ड लेने में बहुत कठिनाई होती थी, तो रिफण्ड टू बी इश्यूड आन-लाइन। यह भी आन-लाइन होगा, सो दैट करप्शन इन द रिफण्ड, यह जो करप्शन होता था रिफण्ड लेने में और देने में, इसके बारे में कोई करप्शन नहीं होगा। यह बहुत बड़ी सुविधा इस प्रदेश के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने की है।

माननीया सभापति महोदया, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने application to be made online for registration for modification and cancellation. यानी कि समझौते की जो वार्तालाप और रजिस्ट्रेशन है, वह भी आन लाइन होगा और डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हैं, वे भी आन-लाइन होंगे। सारा आन-लाइन होगा, कम्प्यूटराइज्ड होगा। इसके बारे में अब किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी। रेक्टिफिकेशन इन असेसमेंट, यह भी आन-लाइन होगा। रिओपनिंग आफ टैक्स फाइल्स एण्ड असेसमेंट, यह भी आन-लाइन होगा। एप्लिकेशन, फोर्म कम्पोजिशन स्कीम, यह भी आन-लाइन होगा। माननीय, सारा आन-लाइन होगा।

इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसी प्रकार से बहुत सारे, लम्बा मैं बहुत नहीं करना चाहता, मैं संक्षेप कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं समय बहुत कम लूं।

बिजली के बारे में मैंने आपको बताया है, सड़क के बारे में बताया है,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

शहरी विकास, सौ नये शहरों का निर्माण, देश में श्रद्धेय माननीय प्रधान मंत्रीजी ने जो कहा कि सौ शहर नये बनाये जायेंगे, पांच शहर का, स्मार्ट सिटी योजना, पांच शहर राजस्थान में से होंगे। इसमें हमारा सौभाग्य है कि एक शहर हमारे नीमराणा-शाहजहांपुर के बेल्ट में और उस बेल्ट में भी एक नया शहर बनेगा। ऐसी योजना की मुझे जानकारी मिली है, सुनाई पड़ी है।

पेयजल के बारे में हमारे डाक्टर राजकुमार जी ने कहा कि हमारे झुन्झुनूं के बारे में कुछ नहीं सोचा, झुन्झुनूं के बारे में पेयजल का नाम रखा है, पेयजल पाली, टोंक, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, गंगानगर, झुंन्झूनूं... डाक्टर राजकुमार शर्माजी, विधायक, माननीय सदस्य नवलगढ़, सुन लें, 2,160 करोड़ रुपये का प्रबन्धन किया है। 2,160 करोड़ का, यह आपके ध्यान में क्यों नहीं आया? पढ़े-लिखे समझदार हों, बहुत अच्छे विद्वान विधायक हों, हमारे साथी। (व्यवधान) नहीं, अब बोलने के लिए कुछ और गुंजाइश नहीं है। 2,160 करोड़, 2,160 करोड़ रुपये, किसको कहते हैं?

इसी प्रकार से, राजस्थान बस पोर्ट सर्विसेज कारपोरेशन के लिए 360 करोड़ रुपये, रोडवेज के 80 स्टैण्डों का सुधार किया जायेगा, व्यवस्था की जायेगी, आपको सुविधाएं दी जायेंगी। आपके टायलेट, लैट्रिन, बाथरूम से लेकर आराम से ए सी कमरे आपको वहां मिलेंगे, 80 बस स्टैण्डों पर।

इसी प्रकार से, फ्लैट्स की रजिस्ट्री की रेट्स में तीन साल में पुन: विक्रय पर और उस पर भी छूट दी गई है; पावर आफ एटार्नी पर भारी छूट दी गई है।

इसी प्रकार से, जहां विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं थी, महिला बंदी सुधार गृह और जोधपुर, जयपुर जेलों को वीडियो कांफ्रेंसिंग से जोड़ेंगे। जोधपुर और जयपुर का विशेष महत्व है, इसको आप लोग समझ लें।

ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास के नाते से मैं, माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं, माननीया मुख्य मंत्रीजी की बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूं, मृदा परीक्षण, मिट्टी के परीक्षण की लैब खुलेंगी; 18 करोड़ का बजट पुरानी लैब्स को विकसित करने के लिए होगा।

इसी प्रकार से, चार प्रतिशत दर लघु अवधि फसली ऋण के लिए

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

पचास करोड़ रुपये; ग्रामीण सहकारी समितियों को दस-दस लाख रुपये गोदाम निर्माण हेतु; मनरेगा से रेलवे के अण्डरब्रिज, बहुत जगह रेलवे लाइन के फाटक पर, बिना आदमी के, कई बार एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो अण्डरब्रिज बनेंगे और यह खाले-नालों पर भी पैसा लगेगा।

1,079 गांवों में दो सौ अड़तालीस करोड़ सत्रह लाख का उप-स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण पर व्यय होगा। महिला सुरक्षा सलाह केन्द्र के लिए तीस से पैंतालीस का सहयोग मिलेगा। आंगनबाड़ी 100 केन्द्रों को शिशु पालन गृह के रूप में विकसित किया जायेगा। कहीं नेचर पार्क, तो कहीं औषधि उद्यान का निर्माण भी इस बजट में है।

यह भी हमारे सबके ध्यान में आना चाहिए और कई कल्याणकारी योजनाएं हमारे दिमाग में से बजट पढ़ते-पढ़ते भी निकल गई होंगी।

एक सौ पचास करोड़ से तीन लाख दस हजार मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण; 30.18 करोड़ से 18 साल तक के बच्चों की विभिन्न जांचें फ्री में; 140.72 करोड़ रुपये बेघर बच्चों, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, गरीबों के लिए। इसी प्रकार से, 26.66 करोड़ एस सी, एस टी छात्रावासों के निर्माण; पत्रकारों को, पत्रकार बंधु जो यहां बैठे हैं, बैठे होंगे, पत्रकारों को पांच से दस लाख रुपये की मेडिक्लेम पालिसी, 4,850 में आंगनबाड़ी भवन, अन्य की मरम्मत के लिए 276.42 करोड़ रुपये; अल्पसंख्यकों के मदरसों के लिए, अल्पसंख्यकों के मदरसे, उनके लिए भी दिया गया है, सामग्री के लिए 58 करोड़ रुपये, मदरसों में शिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री के लिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आपका आलरैडी 20 मिनट होने आया है। सम-अप करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ग्राम विकास के लिए नई योजनाएं। ग्राम स्वच्छता, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सड़कों का सर्वांगीण विकास, शिक्षा का विस्तार, विद्युत परियोजनाएं, और इसी प्रकार से, गौ-वंश, गौ माता में 33 करोड़ देवी-देवता होते हैं, गोपालन विभाग होगा और गौ-वंश के बचाव के लिए, उसके संवर्द्धन और संरक्षण के लिए गो-शालाएं होंगी और विशेषकर हमारे एरिया से, मेवात से, मेवात के एरिये में गौ-कशी और गौ-तस्करी बहुत होती है, उसमें बहुत बड़ी रुकावट आयेगी। गौ-संवर्द्धन हमारा विभाग होगा।

डार्क जोन में भी आपने कहा है, गैर-आबादी, गैर-आबादी और डार्क जोन में भी, गैर-आबादी के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करेंगे

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

और डार्क जोन में भी कृषि के लिए बिजली कनेक्शन होंगे। दुग्ध उत्पादन के लिए दो-गुना व्यवस्था की गई है, शीतलन क्षमता को बढ़ाने के लिए। ब्याज अनुदान के चलते सहकारी और गैर-सरकारी बैंकों से ऋण लेने पर किसानों को पांच प्रतिशत की सहायता। यह सब बजट में है। इसके अलावा, पशुओं की चिकित्सा के लिए भी गुजरात के माडल पर व्यवस्था की गई है। मेडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज, यह सब सारा बजट में आया है।

मैं पुन: भूरि-भूरि प्रशंसा करूंगा माननीया मुख्य मंत्रीजी की।

मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग आप लोगों की तरह किसी तरह की भ्रांति की बात नहीं करते। कई बार लोग मिलते हैं मुझे, कांग्रेसी बंधु, कहते हैं कि अब तो देश में क्रांति आयेगी। यह देश क्रांति का नहीं है, संक्रांति का है। हर महीने संक्रांति आती है, वर्ष में एक बार मकर संक्रांति आती है। तो आप झूठी क्रांति का नारा देकर क्रांति नहीं ला सकते। यहां संक्रांति है, क्रांति के आगे 'स' लगा हुआ है।

मैंने दो-तीन बातें कही हैं, भाई राजेन्द्रजी राठौड़ ने, पहले एक शेर सुना दिया था-

जुल्म को देखा तवारीख की नजरों ने,
लमहों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई।

'हो गई है पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।' आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, कांग्रेस की दीवार। शर्त यह थी, इनकी बुनियाद भी हिलनी चाहिए, इनकी बुनियाद भी खतम होनी चाहिए। आज यह दीवार, कांग्रेस की, पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी, यह बुनियाद भी हिलनी चाहिए; हर सड़क पर, हर गली में, हर गांव में, हर नगर में हाथ लहराते हुए हर हाथ हिलना चाहिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): और आहूजा जी मंत्री बनने चाहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत भी बदलनी चाहिए, देश, प्रदेश की सूरत भी बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही; हो कहीं भी आग, लेकिन यह आग जलनी चाहिए। यह देश और प्रदेश के स्वाभिमान को बचाना चाहिए। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने देश और प्रदेश के स्वाभिमान को बचाते हुए एक अच्छा बजट दिया है।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

पर्सनली कांग्रेसी मुझे मिले, उन्होंने कहा कि बजट बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा तो धर्म है, विरोध करना। आपका धर्म है, विरोध करना, लेकिन ईमानदारी के साथ इस प्रदेश के विकास के लिए हम सब मिलकर काम करें, बी जे पी और कांग्रेस भूलकर काम करें और अच्छे विकास के लिए काम करें। आप कोई चार सुझाव देते कि हमको यह भी करना चाहिए। डोटासराजी, सिर्फ बुराई करने से काम नहीं चलेगा, इसमें कोई अच्छाई आपको नजर आयी या नहीं? कोई अच्छाई नजर आयी तो वह भी बोलिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, यह अच्छाई नहीं है कि आपको मंत्री बनाने की मांग पूरा सदन कर रहा है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): हम सब मिलकर वर्तमान 5 साल तो रहेंगे ही; 5 साल तो माननीया मुख्य मंत्री, वसुन्धराजी रहेंगी। अगली बार जनता और आदेश देगी, क्योंकि मैंने पिछली बार कहा था, आप लोगों ने सुना होगा, जो पूर्व विधायक दो-चार बैठे हैं, सिंहासन खाली करो, ज्ञानदेव आहूजा आता है''; ''सिंहासन खाली करो कि राजेन्द्र राठौड़ आता है''; सिंहासन खाली करो कि हम सब आते हैं, और भारी संख्या में आते हैं''; यह कहा था और आज फिर कह रहा हूं, हम फिर आएंगे, फिर आएंगे, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, गंगा की तरह पवित्र काम कर रहे हैं। पांच साल तो रहेंगे। पांच साल एक -दूसरे को सहयोग करें। राजस्थान को आगे बढ़ा ले जाएं, प्रदेश को आगे बढ़ा ले जाएं। प्रदेश को होलैण्ड और पोलैण्ड मैं नहीं कह रहा। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने हवाला दिया है, लेकिन यह देश, यह प्रदेश पूरे विश्व में और जैसे अलवर, हमारे पर्यटन स्थल के केन्द्र पर आए।

अंत में, माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में बहुत कुछ किया है, अलवर में मैं और चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, सदन का समय सभी का है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं दो मिनट में कह दूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि अलवर के लिए बहुत कुछ किया है मेवात के लिए बहुत किया है, मेरे रामगढ़ को भी दिया है, लेकिन अलवर में नगर निगम बने, अलवर शहर में नगर निगम बने। भरतपुर में बना है, बहुत खुशी की बात है।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

अलवर में जोनल कमिश्नर और आए क्योंकि हमारे यहां 25-30 लाख लेबर है; अलवर में जोनल रोडवेज आफिस खुले; मेरे यहां रीको का कार्यालय हो; मुबारकपुर मेरा कस्बा है, नौगांवा और बड़ौदा मेव में सी एच सी होस्पिटल हों, इसके लिए माननीय राजेन्द्रजी राठौड़ को निवेदन करना चाहता हूं; रीको का औद्योगिक क्षेत्र हो; रामगढ़ में महिला पोलीटेक्निक कालेज हो; नौगांवा में आई टी आई हो; गोविन्दगढ़ में पंचायत समिति हो। यह भी इस बजट भाषण के माध्यम से, बजट पर मेरे बोलने के माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं।

सभापतिजी, मैं ज्यादा समय ले गया हूं तो सदन व आपसे क्षमा चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री सुरेश सिंह रावत।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): सभापति महोदया, राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री, परम आदरणीया वसुन्धरा राजेजी ने राजस्थान सरकार का शानदार बजट पेश किया और योजना का आकार 69 हजार 820 करोड़ रुपये किया। यह बजट लगभग ढाई घंटे, बिना पानी पिये, लगातार माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सभी बिन्दुओं का समावेश करके राजस्थान की 7 करोड़ जनता को सौगात दी। इसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं और बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदया, राजस्थान की जनता, राजस्थान का अवाम अपने आपको भाग्यशाली महसूस करता है। राजस्थान की जनता निश्चित रूप से भाग्यशाली है। राजस्थान की जनता को एक ईमानदार, सेवाभागी, जन-जन की हृदय सम्राज्ञी, चमत्कारी व्यक्तित्व की धनी, ऐसी मुख्य मंत्री राजस्थान को मिलीं। सभापति महोदया, जिस तरह जून की तपती धूप में, बरसती बरसात में, सुराज का संदेश लेकर, सुराज का संकल्प लेकर, सुराज संकल्प यात्रा के माध्यम से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर, 14 हजार किलोमीटर का लम्बा सफर तय किया, जनता के दुःख-दर्द को समझा और महसूस किया, इसी का परिणाम रहा कि राजस्थान की जनता ने एक तिहाई से भी ज्यादा, ऐतिहासिक प्रचण्ड बहुमत के साथ माननीया वसुन्धराजी को मुख्य मंत्री बनाया।

माननीय सभापति महोदया, मैं मुख्य मंत्रीजी एवं सार्वजनिक निर्माण

(श्री सुरेश सिंह रावत)

मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने 20 हजार किलोमीटर लम्बाई की एक सड़क विकास कार्यक्रम की योजना बनायी। 20 हजार किलोमीटर की सड़कों के योजना-बद्ध विकास हेतु राजस्थान स्टेट हाइवे अथोरिटी का गठन किया व सरकार द्वारा योजना में 20 हजार करोड़ रुपये का विनियोजन करने का प्रावधान रखा।

सड़क हर राज्य के विकास के लिए एक बहुत बड़ा आधार होती है। मैं धन्यवाद दूंगा माननीया मुख्य मंत्रीजी की सोच को और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को, जिन्होंने चालू वित्त वर्ष में 250 से 499 की आबादी के 530 गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए 509 करोड़ की लागत से 1,294 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का निर्माण करने का प्रावधान किया।

सभापति महोदया, राज्य के प्रमुख बस अड्डों को आधुनिक रूप से विकसित करने तथा वहां रोडवेज व निजी बसों के सुलभ संचालन हेतु माननीया मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान स्टेट बस सर्विसेज कारपोरेशन के गठन की घोषणा के साथ ही 350 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा। इसके लिए भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदया, राजस्थान के दूरदराज के क्षेत्रों में बसे 10 हजार गांव व ढाणियों को लोकल सोलर ग्रिड और स्टेट सोलर सिस्टम के माध्यम से अगले 5 वर्षों में विद्युत आपूर्ति हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया। इसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदया, माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने अजमेर जिले के बजट में बहुआयामी सौगातें दे दीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीया मुख्य मंत्रीजी और जल संसाधन मंत्रीजी को, जिन्होंने फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना बनायी व मसूदा के लिए 74 करोड़ 65 लाख रुपये की परियोजना हेतु प्रावधान किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीया मुख्य मंत्रीजी का, जिन्होंने अजमेर जिले के अत्यन्त पिछड़े इलाके हेतु मगरा विकास बोर्ड के तहत 300 करोड़ का प्रावधान रखा।

सभापति महोदया, माननीया मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अजमेर जिले सहित अन्य 10 जिलों के

(श्री सुरेश सिंह रावत)

महाविद्यालयों में, जिनमें प्रत्येक में 5,500 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, इन महाविद्यालयों का संकायवार पुनर्गठन कर, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए संकायवार 15 नये महाविद्यालय खोलने की घोषणा की।

सभापति महोदया, अजमेर जिला खनिज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। जिले में क्वार्टज, फैल्सपार, सोडा, माइका, वेलेस्टोनेट, सोपस्टोन, आदि का भण्डार है। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इन खनिज भण्डारों को देखते हुए, अजमेर जिले को सिरेमिक हब के रूप में विकसित करने के लिए सिरेमिक प्रमोशन पालिसी लाने की घोषणा की। इसके लिए भी मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदया, तीर्थराज पुष्कर धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बूढा पुष्कर, मध्य पुष्कर और मुख्य पुष्कर, तीनों का संगम ही तीर्थराज पुष्कर है। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बूढा पुष्कर सहित नाथद्वारा, कैला देवी जैसे धार्मिक स्थलों के सुनियोजित एवं चरणबद्ध विकास हेतु 38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। इसके लिए भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदया, पुष्कर विधान सभा क्षेत्र की पीसांगन पंचायत समिति के क्षेत्र को...(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया गया।

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदया, पुष्कर विधान सभा क्षेत्र की पीसांगन पंचायत समिति के सम्पूर्ण क्षेत्र को पिछली

(श्री सुरेश सिंह रावत)

कांग्रेस की सरकार ने डार्क जोन घोषित करके किसानों के साथ कुठाराघात किया है। पीसांगन पंचायत समिति क्षेत्र का कोई भी किसान डार्क जोन घोषित होने के बाद खेतों को पानी नहीं पिला सकता, कुआं नहीं खोद सकता, पीने के लिए बोरिंग नहीं कर सकता, कृषि कनेक्शन नहीं ले सकता। अत: आपके

(16.50 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पीसांगन पंचायत समिति क्षेत्र को डार्क जोन से मुक्त किया जावे।

माननीय सभापति महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण में आने वाले पेरिफेरी के 118 गांवों में आबादी की भारी समस्या है। 1974 से इन पेरिफेरी गांवों की आबादी का विस्तार नहीं हुआ है। पिछली सरकार ने आबादी विस्तार की घोषणा की जिसके तहत ग्राम पंचायत मुख्यालय में 500 मीटर और बाकी गांवों में 200 मीटर तक की, लेकिन इसमें भी कई प्रकार की विसंगतियों के कारण आम आदमी को कोई लाभ नहीं मिल पाया है। गांवों में जहां पुरानी आबादी बसी हुई है, उस आबादी के पट्टे देने का अधिकार ग्राम पंचायतों को नहीं है। गांव में आबादी भूमि के पट्टे देने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं होगा तो किसको होगा? सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि पेरिफेरी गांवों में भूमि की आबादी का विस्तार हो तथा पट्टे देने का अधिकार ग्राम पंचायत को दें।

सभापति महोदय, अजमेर जिले में भू-संशोधन के तहत वर्किंग जमाबंदी से आधार जमाबंदी लागू होने से किसान को उसकी भूमि के मालिकाना हक से महरूम कर दिया है, जिससे हजारों काश्तकार एस.डी.एम. और तहसील कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। जिस जमीन पर काश्तकार काबिज है, वह उस भूमि का असली हकदार है। उसके स्थान पर पूर्व खातेदार के नाम भूमि दर्ज हो गई। वर्तमान आधार जमाबंदी के खसरा नम्बर, क्षेत्रफल, नक्शे के क्षेत्रफल से मेल नहीं खा रहे हैं। इसलिए निवेदन है कि गांवों में कैम्प लगाकर इन त्रुटियों को तत्काल प्रभाव से सुधारा जावे।

सभापति महोदय, एक ओर तो पेरिफेरी क्षेत्र में सभी नियम-कायदे शहरी क्षेत्र के लागू होते हैं, दूसरी ओर बिजली विभाग द्वारा सेल्फ-फाइनेंस

(श्री सुरेश सिंह रावत)

स्कीम की बाध्यता शहरी क्षेत्र के लिए तो नहीं है, लेकिन पेरिफेरी क्षेत्र के गावों के लोगों के लिए लागू है। इससे पेरिफेरी क्षेत्र के लोगों पर दोहरा भार पड़ रहा है। अत: आपसे निवेदन है कि पेरिफेरी क्षेत्रों में सेल्फ-फाइनेंस की स्कीम को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा पिछले तीन सालों की बकाया राशि के नाम पर किसानों के घरों पर हजारों रुपये के बिल भेज दिये गये हैं। इतनी राशि के मनमाने ढंग से कर्मचारियों द्वारा भेजे गये बिलों की राशि को जमा कराने में गरीब उपभोक्ता असमर्थ हैं। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इनका पुन: आकलन करके, किसानों को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दें।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों, आदि के सर्वांगीण विकास हेतु मील का पत्थर साबित होगा। आज मीडिया के माध्यम से, इस संचार क्रांति के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टी.वी. चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, सोशल साइट्स फेसबुक, वाट्सएप के माध्यम से आम गरीब, किसान, दूर-दराज की ढाणी में बैठे आम आदमी को यह मालूम हो गया है कि राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री, जो कल्याणकारी हैं, गरीबों की हितैषी हैं, युवाओं की हितैषी हैं, किसानों की हितैषी हैं, महिलाओं की हितैषी हैं, धार्मिक स्थलों की रक्षक हैं, सभी 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाली मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया, उससे आने वाले समय में राजस्थान का विकास होगा, आम गरीब का विकास होगा, किसानों का विकास होगा, राजस्थान खुशहाल बनेगा और अब सभी के अच्छे दिन शुरू हो गये हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमराराम।

श्री अमराराम (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, माननीया मुख्य मंत्री, वसुंधराजी ने बजट पेश किया है, वह एक ऐसे समय में पेश किया है, जब कांग्रेस सरकार ने पांच साल के अन्दर हमारे इस राजस्थान की स्थिति को बिगाड़ दिया था। पर एक चुनौतीपूर्ण और हिम्मत से जो बजट पेश किया गया, उसमें कई कल्याणकारी योजनाओं का वर्णन किया गया है। ऐसी कल्याणकारी योजनाओं के अलावा, यह बजट किसानों के लिए और गांवों के

(श्री अमराराम)

विकास के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीबों के लिए, हर प्रकार से, हर क्षेत्र में हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बहुत ही गहराई से यह बजट जनता की भलाई के लिए पेश किया है।

मुझे याद है कि जब हमारी सरकार 2003 से 2008 तक थी और उससे पहले 1998 से 2003 तक जो कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने इस प्रदेश की आर्थिक हालत बिगाड़ दी थी और उस बिगड़ी हुई हालत में राजस्थान में हमारी सरकार और हमारी मुख्य मंत्री ने बागडोर सम्भाली। सड़कों की हालत उस समय बहुत खराब थी, लेकिन हमारी सरकार ने सड़कों में सुधार किया और लोग यह कहने लगे कि 2003 से 2008 तक की हमारी सड़कें गुजरात से कम नहीं हैं। प्रतिदिन 12 किलोमीटर हमारे यहां सड़कें बनती थीं और कांग्रेस सरकार ने अपने समय में प्रतिदिन 8 किलोमीटर तक की सड़कें नहीं बनाईं। वे चार साल-साढ़े चार साल तक तो बैठे रहे। मेरे क्षेत्र में बालोतरा से मेरे गांव तक की 20 किलोमीटर की सड़क है, वे पांच साल तक उस सड़क को नहीं बना सके और पांच साल तक इधर से उधर मीटिंग करते रहे। आखिर हमारी यह सरकार आई और आते ही मैंने दो महीने के अन्दर पूरी 20 किलोमीटर की सड़क बनवा दी।

हमारी सरकार ने जो अभी 20 हजार किलोमीटर सड़क बनाने का जो संकल्प लिया है, इससे ग्रामीण क्षेत्र में हर व्यक्ति, हर वर्ग, सभी को आने-जाने में बहुत अच्छी सुविधा होगी।

आपको मालूम है कि हमारे यहां मेगा हाइवे का सबसे पहले निर्माण रामजी के गोल से, सांचौर के विधायक महोदय आते हैं, उनको मालूम है कि किस प्रकार की वहां सड़क है, और पेट का पानी तक नहीं हिलता है। पहले आपके समय में 1998 से 2003 तक क्या हालत थी, चार घंटे में बालोतरा आते थे, जहां अब आप दो घंटे में सांचौर से बालोतरा आते हो। इस प्रकार सड़कों का निर्माण हुआ।

अब हमारी सरकार ने बजट के अनुसार 15 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कों का निर्माण करने का संकल्प लिया है। जोधपुर से बाड़मेर तक फोर-लेन के काम का सर्वे हो रहा है और बहुत जल्दी काम शुरू होने जा रहा है। आपकी सरकार ने तो पांच साल में जोधपुर से बाड़मेर तक का रास्ता तक बन्द कर दिया था, क्योंकि जोधपुर का प्रदूषित पानी, जिसके कारण से हमारे डोली गांव,

(श्री अमराराम)

आराबा, कल्याणपुर की तरफ से सांचौर वाले घूमकर कहीं जाते थे, लेकिन हमारी सरकार आते ही वह सड़क पूरी हुई है। यह हमारी उपलब्धि है।

अध्यापकों के क्या हाल थे, आपने स्कूलें खोल दीं पर कोई हैडमास्टर नहीं। हायर सैकण्डरी भी खोल दीं लेकिन खोली कब, जाते-जाते खोलीं। चार महीने में आपकी नींद खुल गई और काम करना शुरू किया। जितना प्रतिशत आपको बजट खर्च करना था, वह नहीं किया और आपका बजट लैप्स हो गया। अगर आप सारा बजट खर्च करते तो राजस्थान में यह स्थिति देखनी नहीं पड़ती।

(17.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, रिफाइनरी का प्रश्न आया। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य कल कह रहे थे कि क्या मालूम, यह रिफाइनरी यहां लगेगी कि नहीं लगेगी? इन्होंने जिस प्रकार से रिफाइनरी के अन्दर चुनावी रिफाइनरी लगाने का प्रयास किया था और आनन-फानन के अन्दर, चुनाव की आचार-संहिता लागू होने से दो-तीन दिन पहले ही माननीया सोनिया जी को लाकर इन्होंने शिलान्यास करवाया। इनको यह मालूम नहीं था।

इन्होंने एक और फैसला किया, माननीय सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट से, हमारी खारवाल कम्यूनिटी एक ऐसी है जो साल्ट निकालने का काम करती है और यह राजकीय उपक्रम विभाग के अन्दर था, डीडवाना और यह पचपदरा नमक का काम और उन पट्टाधारियों को नमक के खोदने का अधिकार था। इन्होंने इसको राजस्व विभाग में, 2013 में कैबिनेट का फैसला आनन-फानन में किया और यहां पर रिफाइनरी के लिए इन्होंने एक्वीजिशन के लिए कार्यवाही की। उसके अन्दर हमारी 180 खानें आ रही हैं, उन किसानों की, उन खारवाल नमक निकालने वालों की। क्या आपने उनको मुआवजा दिया? बिना मुआवजा तय किये हुए, आप यह कह रहे हों, रिफाइनरी के लिए; यह रि -नेगोशिएशन क्यों हो रहा है? जमीन हमारी, पैसे हमारे और उसके बाद में आप उन खारवालों को मुआवजा नहीं दो। तो उसके लिए रि-नेगोशिएशन करना पड़ेगा दुबारा।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने जो फैसला और बजट के अन्दर जो बात कही है, यह रिफाइनरी नेगोशिएशन के बाद में पचपदरा में ही लगेगी। आप सबको मालूम है, 402 करोड़ रुपये, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने पहले

(श्री अमराराम)

ही घोषणा कर दी थी कि 402 करोड़ रुपये है, इस रिफाइनरी के काम के लिए लगेंगे। उसकी बाउंडरी बनने के लिए टेण्डर भी हुए हैं, वहां पर मिट्टी का सैम्पल भी लिया है, वहां पर सारे लोग लगे हुए हैं और आप यह डाउट करते हैं, माननीय सदस्य मेवारामजी, कि यहां रिफाइनरी लगेगी कि नहीं लगेगी! यह रिफाइनरी बाड़मेर में पचपदरा में ही लगेगी। यह काया पलट हो जायेगी। यह डिग्बोई से कम हमारा बाड़मेर नहीं है। आज जो रायल्टी हमें मिल रही है, हमारे 12 महीनों के बजट के बराबर मिल रही है। यह सोच हमारी मैडम का था, यह सोच हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी का था जिन्होंने सबसे पहले कुआं बाड़मेर के अन्दर जिसका उद्घाटन किया था, मंगला जिसका नाम है, मंगला कुएं का जो उद्घाटन किया था, आज हालत क्या है?

आज पानी के अन्दर जितनी भी योजनाएं थीं, माननीय सभापति महोदय, चुनावी हिसाब से फलौदी के अन्दर सड़ी-गली पाइपलाइन पड़ी थी, जो भंगार में थी। उन पाइपों को लाकर, हमारा जो नागाणा क्षेत्र है, वहां से करीब 50 किलोमीटर बालोतरा में पानी आया। वही आठ इंच की पाइपलाइन सड़ी हुई, तीन-तीन फुट में वह पाइप, जिनकी वेल्डिंग करने में 1.63 करोड़ रुपये इन्होंने खर्च किये, आज वह पाइपलाइन बेकार है; दो साल के अन्दर बेकार हो गई। सारी जगह जंग लगा हुआ है, पाइप टूट रहा है और उसी के कारण जगह-जगह पानी जाने से, आज घी ढुलता है, मारवाड़ी में कहावत है, घी ढुलता है तो जी दुख नहीं पाता, लेकिन पानी की एक-एक बूंद गिरती है, तब हर आदमी को दु:ख होता है, तो ऐसे कीमती पानी को बेकार पाइपलाइन लगाकर आपने नष्ट किया है। जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। इसीलिए यह सुराज संकल्प यात्रा के अन्दर जितना भारी समर्थन जनता ने दिया, आप लोगों से नाराज होकर, जिसके कारण 163 से भी ज्यादा की संख्या में आज हम मौजूद हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार से, माइनोरिटी के लिए, हमने मदरसों के लिए पहले क्या काम किया था? कभी आपने सोचा था? यह मुस्लिम जो वोट बैंक हमारा था, हमेशा आप उनको इस प्रकार से पिछड़ा हुआ रखते रहे। हमने सबसे पहले मदरसों के अन्दर टीचर लगाये और उनको हिन्दी, अंग्रेजी, गणित पढ़ाना सिखाया। आपने क्यों नहीं सिखाया? आप हमेशा उनको वोट बैंक समझते रहे और हमेशा उनको दूर करने की भावना से, कि कांग्रेस आपकी हिमायती है और बी जे पी नहीं है। बी जे पी ज्यादा हिमायती

(श्री अमराराम)

है। इसलिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 58 करोड़ रुपये उन शिक्षकों के लिए और मदरसों की सामग्री के लिए बजट के अन्दर प्रावधान किया है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा, एस.सी. के लिए ये कहते रहे कि एस.सी. हमारी है, मेरे समय में, 2003 से 2008 तक हमने एकलव्य एस.टी. का छात्रावास बनाया, जिस पर करीब 36 लाख रुपये लगे थे; हमने एस.सी. का अम्बेडकर छात्रावास बनाया, जिस पर 42 लाख रुपये लगे। हमारी मैडम ने अब छह और एस सी, एस टी के छात्रावास बनाने के लिए करोड़ों रुपये दिये हैं। अब कौन हितैषी है एस सी और एस टी का? आप हमेशा इस प्रकार से उनको खाली लालच दे-देकर के और उनका शोषण करते रहे, लेकिन यह भा ज पा सरकार ने जो बोला, जो कहा, वह किया।

किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है, सस्ते ऋण की व्यवस्था की गई है और उद्यान के लिए, माननीय सभापति महोदय, आप यह सुनकर ताज्जुब करेंगे कि मेरी तहसील के अन्दर अनार की खेती काश्तकार कर रहा है और एक-दो गांवों के अन्दर, अनार की खेती करने में, उन लोगों के एक-एक खेत में 20-20 लाख रुपये की पैदावार तीन साल के बाद हो सकेगी। हमारे इस बजट के अन्दर किसानों को अनुदान देने की बात कही गई है।

एक और बात इस बजट के अन्दर है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी मुख्य मंत्रीजी को कि इन्होंने, ड्रिप से जो खेती करेगा, उसको तुरन्त कनेक्शन मिलेगा। आज हमारे यहां जो अनार की खेती हो रही है, सब ड्रिप सिस्टम से हो रही है, बूंद-बूंद से सिंचाई हो रही है। इस प्रकार से हम खेती करेंगे तो राजस्थान को बहुत ही सुन्दर बना सकते हैं और यह अब बाड़मेर के अन्य एरिये के अन्दर भी शुरू हो रहा है, जहां अनार की खेती हो गई, खजूर की खेती हो रही है। हर प्रकार से काश्तकारों की हिमायत करने वाली यह सरकार हमेशा उनके लिए हाजिर है।

पशुओं के लिए भी मोबाइल यूनिट तैयार करके, जगह-जगह मोबाइल यूनिट के द्वारा, इन्होंने क्या किया, ये कई योजनाएं, सैकड़ों योजनाएं, जो हमेशा ये बोलते थे कि हमने यह किया, हम यह कर रहे हैं, लेकिन वे कागजों में रह गई। इसलिए आप इधर आ गये और हम इधर आ गये। अगर वास्तव में जनता के प्रति आपका दर्द होता और जनता की आप सुनते तो आज यह नौबत आपके सामने नहीं आती। आज दो आदमी अगर नहीं हों तो हमारे डूडी साहब भी नहीं बनते। यह मैं आपको अर्ज कर रहा हूं।

(श्री अमराराम)

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन यह है और मेरा सुझाव भी है कि एग्रीकल्चर के अन्दर हमको आगे बढ़ना है तो हमें किसानों के लिए, बी.एससी. (एग्री) और एम.एससी. (एग्री) जो किये हुए लड़के हैं, जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन लोगों को एम्प्लायमेंट देने का एक ही जरिया है कि 10 लाख रुपये का लोन और 10 लाख रुपये बिना ब्याज देकर के, हर खेत के अन्दर एक लाख गैलन का टांका बनाया जाये और 20 बीघा जमीन के अन्दर वहीं पर सौर ऊर्जा लगाई जाये और ड्रिप योजना से वे फल की पैदावार, सब्जी की पैदावार कर सकें और चारों तरफ खेत के, चार भुजा खेत की होती हैं, उसके चारों तरफ 50-50 पेड़, यानी 200 पेड़ लगेंगे और 200 पेड़ लगेंगे, वहां पर मिनरल वाटर मिलेगा टांके में, आपको पी एच ई डी वालों की जरूरत नहीं रहेगी। सौर ऊर्जा लगाने पर उन बिजली वालों की भी जरूरत नहीं रहेगी। दो भैंसें रखें और अपना फार्म हाउस रखें। फार्म हाउस के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, एक भैंस का दूध बेच दें, एक भैंस का दूध आपके खुद के काम में लें। प्योर आर्गेनिक खेती करें। भैंसों के गोबर से गोबर गैस तैयार करके अपना खाना आराम से पका सकें, बिजली पैदा कर सकें। सौर ऊर्जा से पांच होर्स पावर तक की मोटर चल सकती है, इस प्रकार का प्लांट लगाया जाए ताकि हम लोग आत्मनिर्भर बन सकें। इसलिए यह मेरा विशेष तौर से निवेदन है।

मैं, अंत में, यह जो कुछ ऐसी योजनाएं हैं, जो जनता जल योजना है, उस जनता जल योजनाओं को खतम करना चाहिए। क्योंकि वह दो-ढाई हजार के अन्दर आज हमारे 1,500 से ज्यादा जो लोग हैं, इस जनता जल योजना में लगे हुए हैं और जिसके कारण उनको 2,500 रुपये मिलते हैं। लेकिन 2,500 में क्या करेगा? इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं माननीया मुख्य मंत्रीजी को, उन्होंने गांवों के अन्दर आर ओ लगाने का निर्णय किया है। वे स्वच्छ पानी पियें, वह भी एक बहुत अच्छा है। यह बहुत अच्छा है कि हर गांव के अन्दर और नजदीक-नजदीक हमारी जो ढाणियां हैं, वहां पर भी आर ओ का प्लांट लगे। जिससे लोगों को शुद्ध पानी मिल सके। स्वास्थ्य के बारे में भी बहुत अच्छा काम किया है।

बिगड़ी हुई हालत को अब सुधारने में टाइम जरूर लग रहा है। इस पांच सालों के अन्दर राजस्थान की काया पलटने के लिए जो बजट लाया गया है, उसका मैं पुरज़ोर शब्दों में समर्थन करता हूं।

(श्री अमराराम)

आपने समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री झाबर सिंहजी।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश के जिस प्रकार के आर्थिक हालात थे, प्रदेश की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से चरमराई हुई थी, उन विषम परिस्थितियों में हमारी माननीया मुख्य मंत्री, वसुंधरा राजेजी ने जिस प्रकार का, सभी वर्गों के हित में एक संतुलित बजट प्रस्तुत किया है, वह आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा और प्रदेश को उन्नति और प्रगति के नये मार्ग पर ले जाते हुए, समाज के सभी वर्गों को उसका समुचित लाभ मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज से पांच साल पहले जो राज्य सरकार का कुल कर्जा और लायबिलिटीज 77 हजार 138 करोड़ रुपये थी, पांच साल में वह बढ़कर 1 लाख 30 हजार 640 करोड़ रुपये हो गई और उन सबके बावजूद, प्रदेश के विकास को जो गति मिलनी चाहिए थी, वह गति नहीं मिल पाई। नये बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने दूरगामी सोच के साथ जिस प्रकार के प्रावधान किये हैं, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों को उनका लाभ मिलेगा।

मैं बात करना चाहूंगा, वर्तमान परिस्थितियों की प्रदेश की लगभग 74 फीसदी से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है, साढ़े 24 प्रतिशत से कुछ अधिक आबादी शहरों में निवास करती है। उस सबके बावजूद, पिछले पांच साल में गांवों के साथ जिस प्रकार का सौतेला व्यवहार हुआ, उसके मैं कुछ आंकड़े आपके सामने देना चाहूंगा। प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 43 हजार 264 गांव और 2003 के हैबिटेशन सर्वे के अनुसार 77 हजार 869 ढाणियां हैं और शहरों और कस्बों की संख्या 222 है। कुल 6 करोड़ 85 लाख 48 हजार 437 की आबादी में से शहरी आबादी मात्र 1 करोड़ 70 लाख 48 हजार 85 है, जबकि ग्रामीण आबादी 5 करोड़ 15 लाख 352 है। इस सबके बावजूद, पेयजल जैसे संवेदनशील मुद्दे पर गत वर्ष शहरी क्षेत्र के लिए कुल 1,02,022.45 लाख रुपये खर्च किए गए, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुल व्यय 85,758.98 लाख रुपये रहा और इसी का कारण है कि गांवों में पेयजल

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने के कारण ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर लोगों का पलायन हो रहा है। नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन के एक सर्वे के अनुसार, आज गांवों के हालात ये हैं कि विकल्प मिलने पर 42 फीसदी किसान खेती-बाड़ी से हमेशा-हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, और अच्छे जीवन की आशा में शहरों की ओर पलायन करने का विचार रखते हैं। लेकिन अगर ये हालात नहीं बदले तो शहर के भी जिस प्रकार के हालात हैं, जिस प्रकार कच्ची बस्तियां दिन-प्रतिदिन विकसित हो रही हैं, शहरों की हालत भी बद से बदतर हो जाएगी।

देश में 60 करोड़ के लगभग किसान आबादी है। इस समुदाय के पिछले 17 सालों में करीब 3 लाख किसानों ने देश में आत्महत्या की है, लेकिन, सौभाग्य से, हमारे प्रदेश में अभी इस प्रकार के हालात उत्पन्न नहीं हुए हैं। 65 परसेंट से अधिक किसान कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं। ऐसे में मुख्य मंत्रीजी ने बजट में सहकारी और गैर-सहकारी बैंकों के माध्यम से लिये जाने वाले ऋण पर जो 5 प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है; मैं उसका तहेदिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कृषकों को कर्ज से बाहर निकालने में यह मददगार साबित होगा।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगातार गिर रहा है। फिलहाल यह आंकड़ा 13 फीसदी के आसपास है। इस पर भी अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी और रोजगार के अवसर सृजित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में इस बजट के मार्फत माननीया मुख्य मंत्रीजी ने संतुलित प्रयास किए हैं। उनका सकारात्मक प्रभाव, उनके सकारात्मक परिणाम आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से दिखाए देंगे; जो हालात हैं, उनमें निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव होगा।

मैं आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रदेश में सात मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की है। साथ ही, मैं उनका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि सीकर जिले का जिला अस्पताल आसपास के जिलों में सबसे बड़ा अस्पताल है और वहां एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित श्री कल्याण आरोग्य सदन के नाम से 60 साल पुराना 400 बेड का क्षय रोग उपचार का अस्पताल कार्यरत है,

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

जिसके पास लगभग 100 बीघा जमीन है। वह संस्था अपना भवन, पूरी जमीन और अपने पूरे संसाधन मेडिकल कालेज खोलने के लिए राज्य सरकार को देने को तैयार है। मैं उम्मीद करुंगा माननीया मुख्य मंत्रीजी निश्चित रूप से सकारात्मक रूप से इस विचार करेंगी।

मैं उनको इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने गरीबों के लिए, जो खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आ रहे हैं, उन सारे परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। साथ ही, मैं उनसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आम आदमी के लिए, जो खाद्य सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आ रहे और जिनको स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनके लिए, गांवों में जिस प्रकार की मुनाफाखोरी है, जयपुर एस.एम.एस. अस्पताल में लाइफलाइन के जरिए जिस प्रकार 20 से 80 प्रतिशत बाजार मूल्य से कम दाम पर आम मरीज को दवा उपलब्ध होती है, अगर इस प्रकार के मेडिकल लाइफलाइन स्टोर सभी रेफरेल अस्पतालों में खोल दिये जाएं, तो आम गरीब रोगी को उसका बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है।

जहां तक हम शिक्षा की बात करें, पिछले पांच वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार का कबाड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा जो आर टी ई आया है, राइट-टू-एजुकेशन, उसके बाद ना शिक्षकों में पढ़ाने की ललक रही है और न बच्चे मेहनत करके पढ़ना चाह रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में भी माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए जो भी कुछ योजनाएं बनाई हैं, उनके साथ-साथ वे कम से कम केन्द्र सरकार से बात कर कक्षा पांच और कक्षा आठ के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करवाना सुनिश्चित करवाने का प्रयास करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वह रुक सके और वे पढ़ाई में ध्यान दे सकें और सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है, उसको रोका जा सके।

साथ ही, पिछले पांच साल में जिस तेजी के साथ सेकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में विषय अध्यापकों की कमी रही, जहां छात्र थे वहां विद्यार्थी नहीं थे और जहां विद्यार्थी थे वहां अध्यापक नहीं थे, इसको राज्य सरकार एकीकरण के मार्फत दूर करने का प्रयास कर रही है।

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

मैं उम्मीद करूंगा कि इसी माह में राज्य सरकार एकीकरण के सारे प्रस्तावों का समेकित रूप से आकलन कर और ग्रामीण क्षेत्र के बालक-बालिकाओं के लिए सभी विद्यालयों में विषय अध्यापक उपलब्ध हों, उसको करने में सफलता प्राप्त करेगी।

साथ ही, उन्होंने बालिका शिक्षा पर जो फोकस किया है, वह भी काबिले तारीफ है। लेकिन साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र की बहुत सी सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में विज्ञान विषय नहीं है, विज्ञान संकाय नहीं है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को विज्ञान संकाय की पढ़ाई में काफी कठिनाई आती है और उन्हें शहरों और कस्बों की ओर रुख करना पड़ता है। अगर जहां अच्छी संख्या बालक-बालिकाओं की अध्ययनरत हो, उन सभी सीनियर सेकण्डरी स्कूलों में विज्ञान संकाय खोलने का प्रयास किया जाए और आने वाले वर्षों में वहां विज्ञान संकाय खोला जाए, तो ये ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से, चाहे राज्य बोर्ड हो, चाहे सी बी एस ई का बोर्ड हो, चाहे कालेज और विश्वविद्यालय की परीक्षाएं हों, बालिकाएं जिस प्रकार से मेरिट में स्थान प्राप्त कर रही हैं, उसको देखते हुए बालिका शिक्षा पर और उनको विज्ञान संकाय की शिक्षा उपलब्ध करवाने से, देश में उनको आगे बढ़ने का और देश को अच्छे डाक्टर और इंजीनियर मिलने का रास्ता प्रशस्त होगा, ऐसी भी मैं उम्मीद करता हूं।

जहां तक सड़कों का सवाल है, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो सड़कों को लेकर विजन प्रस्तुत किया है, पिछले पांच वर्ष में सड़कों के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हुआ, आने वाले वर्षों में माननीया मुख्य मंत्रीजी की योजना के अनुरूप, पूरे प्रदेश में सड़कों की हालत में सुधार होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

ऊर्जा के क्षेत्र में पांच साल पहले जो पन्द्रह हजार करोड़ रुपये का घाटा था, पांच साल में बढ़ कर लगभग 75 हजार करोड़ रुपये हुआ है। उसके लिए भी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट में जो विजन रखा है, मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में बिजली कम्पनियां आर्थिक रूप से सुदृढ़ होंगी और प्रदेश के किसानों के साथ-साथ, घरेलू उपभोक्ताओं को भी सस्ती और अच्छी किस्म की विद्युत उपलब्ध करवाने में वे कामयाबी हासिल करेंगी।

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

जहां तक रोजगार का सवाल है, पिछले पांच वर्षों में जिस प्रकार के हालात रहे, उनसे निपटते हुए मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार का कार्यक्रम रखा है और जिस प्रकार का विजन प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से वे अपना वादा पूरा करने में सफल होंगी और बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में निश्चित रूप से उनके लक्ष्य के मुताबिक कामयाबी हासिल करेंगी।

साथ ही, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिस प्रकार अनियमितताओं का एक बड़ा स्रोत बन गई है, उसके बारे में मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। आज जब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चालू हुई, तो गारंटी उन परिवारों को मिलनी चाहिए थी जिन परिवारों के पास स्थायी रोजगार का कोई साधन नहीं था, लेकिन सभी परिवारों के जाब कार्ड बने; जिन परिवारों में पांच-पांच सरकारी नौकर थे, बड़े ओहदों पर सरकारी अफसर थे, उन परिवारों के लिए भी जाब कार्ड बने। मैंने चार साल पहले, तत्कालीन पंचायत राज और ग्रामीण विकास मंत्रीजी ने एक समीक्षा मीटिंग ली थी, जयपुर में, उन्हें कुछ तथ्य प्रस्तुत किये थे कि गांवों में जाब कार्डस बिक रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस योजना का आम आदमी को समुचित लाभ मिले, इसके लिए पक्के निर्माण कार्यों पर ज्यादा जोर दिया जाए और जो योग्य परिवार हों, उन्हीं परिवारों को जाब कार्ड वितरित किये जाएं, ताकि आम गरीब आदमी को नरेगा के मार्फत रोजगार मिल सके। नरेगा को अगर उत्पादक कार्यों के साथ जोड़ दिया जाए तो उसका उन परिवारों को दुगना लाभ मिल सकता है।

मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का सबसे संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिए आभार प्रकट करते हुए यह उम्मीद करूंगा कि उन्होंने बजट पेश करते हुए जो इच्छाएं और इरादे जाहिर किये हैं, वे निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त करने में कामयाबी हासिल करेंगी।

इसी आशा के साथ, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री गोरधन।

श्री गोरधन (धोद): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीया वसुन्धराजी, मुख्य मंत्रीजी के द्वारा पेश बजट भाषण पर अपने

(श्री गोरधन)

विचार रखना चाहूंगा। मैं यह सोचता हूं कि जिस प्रकार से माननीया वसुन्धरा जी ने इस बजट में सभी वर्गों का, सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए इस बजट का निर्माण किया, जिसमें चाहे पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि व उद्योग-धन्धों को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में फोकस किया गया है। यह बजट ऐसी हालत में पेश किया गया है, क्योंकि पिछले पांच सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस ने यह शासन चलाया था, उससे राजस्थान को एक 'बीमारू' राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया और इस 'बीमारू' राज्य को विकासशील व विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए यह बजट जिस प्रकार रखा गया है और जिस प्रकार की इसमें व्यवस्थाएं दी गई हैं, तो मैं माननीया वसुन्धराजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और इस बजट की मैं प्रशंसा करता हूं।

जिस प्रकार से पिछले पांच वर्षों में कांग्रेस ने राज्य को निम्न स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया और एक भी कोई ऐसी योजना, जिसको धरातल पर लाकर काम में लिया हो, हो सकता है कि उन्होंने योजनाएं काफी लागू कीं लेकिन बजट के अभाव में उनकी योजनाएं फ्लाप होती चली गईं। इसी का कारण है कि उन्होंने, जिस प्रकार से कांग्रेस ने यह माना कि अल्पसंख्यक और एस सी समुदाय केवल, और केवल, कांग्रेस का वोट बैंक है, उस नशे को कम करते हुए। क्योंकि कांग्रेस का नशा तब उतरा, जब इन्होंने देखा कि एक भी विधायक एस सी का नहीं जिता पाए और एक भी विधायक अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं जिता पाए। तब इनको झटका लगा कि यह क्या हुआ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एस सी समुदाय हो, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो, चाहे एस टी समुदाय हो, चाहे राजस्थान के अन्य सभी वर्ग, उन वर्गों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ए सी, एस टी और अल्पसंख्यक समुदाय, यह कह सकते हैं कि जिनको सरकार को ऊपर उठाने की जरूरत है उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीया वसुन्धराजी ने एस सी के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बजट में विशेष प्रावधान रखा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि मैं उस जगह से जीतकर आया हूं, जहां से लगातार, लगातार क्या, 60 सालों में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है और लगातार बीस सालों से सी पी एम का

(श्री गोरधन)

जहां पर कब्जा रहा है। वैसे बजट में बहुत सारे प्रावधान किये गये हैं, हमारे सीकर जिले को भी इसमें बहुत कुछ दिया है, चाहे वह शेखावाटी विश्वविद्यालय के सवा चार करोड़ रुपये हों, चाहे संकायवार महाविद्यालय खोलने का मामला हो, चाहे लोसल नगरपालिका में मास्टर-प्लान दिया हो, लेकिन इनके साथ-साथ में, आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र धोद काफी पिछड़ा हुआ है। लगातार 20 सालों से वहां सी पी एम का राज रहा है। जनता वहां पर विकास के लिए तरस रही है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि वहां पर एक सरकारी महाविद्यालय की स्थापना हो।

माननीया वसुन्धराजी द्वारा रसीदपुरा में एक प्याज मण्डी की, अपने घोषणा पत्र में पहले भी कहा था, उसकी स्थापना करना और पूरे सीकर जिले में सभी विधान सभा क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई है, लेकिन धोद विधान सभा क्षेत्र ही ऐसा है जहां पर एक भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। इसलिए मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर रीको की स्थापना हो। विधान सभा क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र है, इसलिए वहां पर तहसील की स्थापना हो, क्योंकि तहसील के लिए तहसीलदार बैठता है।

मेरा निवेदन है कि हमारे उस क्षेत्र में सीकर और धोद, सीकर के आसपास जो पंचायतें लगती हैं, उनका हैडक्वार्टर सीकर हो और धोद के आस-पास लगने वाली पंचायतों का हैडक्वार्टर धोद हो, जिससे हमारे उस क्षेत्र की जनता को कार्य कराने में और उनको सुविधाजनक होने के कारण से, वहां पर अलग-अलग स्थापना हो, तो इसके लिए बढ़िया रहेगा और जनता के लिए भी अच्छा रहेगा।

दूसरा मेरा यह भी निवेदन है, माननीय झाबरसिंहजी ने बताया, श्री कल्याण आरोग्य सदन लगातार 60 सालों से, जिसमें यूं कह सकते हैं कि एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा सरकार के कुछ अनुदान मात्र से वह अस्पताल चलता है। उसमें बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा भी है, लगभग 100 बीघा के करीब उसके पास जमीन है और लगभग 400 बेड वहां पर संचालित हैं। यदि वहां पर मेडिकल कालेज की स्थापना हो जाए तो मैं सोचता हूं कि इस क्षेत्र के लिए और शेखावाटी बेल्ट के लिए अच्छा हो सकता है।

इस विधान सभा में पहली बार मेरे को बोलने का मौका मिला है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि

(श्री गोरधन)

जिस प्रकार से बीस हजार करोड़ रुपये माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने दिये हैं, वही योजना और वही विकास जिस प्रकार से माननीय वाजपेयीजी की की सरकार ने केन्द्र में दिये थे और उसी की तर्ज में, मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू की गई थी, उसी का एक छोटा-सा रूप माननीया वसुन्धराजी ने भी चालू किया है। 9 हजार से अधिक आबादी वाली पंचायतें, जो 0.5 से 2 किलोमीटर की सड़क, जिसमें नाली निर्माण भी होगा और राजस्थान में एक बहुत अच्छी शुरुआत करते हुए, 'ग्रामीण गौरव पथ' के रूप में जो योजना चलाई है, मैं उनकी भी बहुत भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

जिस प्रकार से धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए और पर्यटन के विकास के लिए, आज का जमाना आई टी का जमाना है और व्यक्ति यह सोचता है कि मैं जितना जल्दी, मेरा समय बचा सकूं, वह समय बचाने की कोशिश करता है और माननीय वसुन्धराजी ने उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, यहां 16 हवाई पट्टियां हैं उनका विकास किया जाएगा और दो वायुयान, जो एयर टैक्सी के रूप में हैं, वह राज्य सरकार इस विकास के लिए देगी।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए जिस प्रकार 40 हजार नये कनेक्शन देने की भी घोषणा की गई है और गांवों के समग्र विकास के लिए एक 'श्री योजना' चलाई गई है, जिसमें यूं कह सकते हैं कि गांव का शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, उसमें सभी बातों को शामिल करते हुए यह योजना लागू होगी।

युवाओं के लिए और विशेषकर, सुराज संकल्प यात्रा में माननीया वसुन्धराजी ने यह कहा था कि एक ही परीक्षा के माध्यम से अध्यापकों का चयन किया जाएगा, उसी को मध्यनजर रखते हुए जिस प्रकार से यह लागू की है, मैं सोचता हूं कि यह युवाओं के लिए बहुत अच्छा है। यूं कह सकते हैं कि माननीया वसुन्धराजी द्वारा सुराज संकल्प यात्रा में जो वादा किया गया था उसको पूरा किया गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं ।

मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की परिस्थितियों में यह बजट पेश किया गया है, उन परिस्थितियों में और पिछले पांच सालों के इस कांग्रेस के कार्यकाल को देखते हुए माननीया वसुन्धराजी ने जो बजट पेश किया है, यह बजट उन विपरीत परिस्थितियों में है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि

(श्री गोरधन)

जिनके हौसले बुलंद होते हैं, वे अपना मुकाम हासिल करते ही हैं। इसलिए मैं पुन: वसुन्धराजी को शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हुआ, बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं । जय जय राजस्थान। जय जय भारत।

श्री सभापति: श्री लादूरामजी विश्नोई।

श्री लादूराम (गुढामालानी): आदरणीय सभापति महोदय, मैं परिवर्तित बजट के बारे में, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने दीर्घकालीन प्रभाव रखते हुए जो बजट प्रस्तुत किया है, उसके बारे में कुछ बिन्दुओं पर डिटेल में आपको बताना चाहूंगा और इसके लिए हमारे कुछ इंटर-स्टेट, नर्मदा के बारे में मुझे थोड़ा लम्बा बोलना पड़ेगा। आपसे परमिशन लेना चाहता हूं।

भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री, श्रीमान् पीयूष गोयल ने एक घण्टे की एक परिचर्चा में यहां की वितरण कम्पनियों के बारे में जो पूअर रिमार्क्स दिये हैं, उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपके नोटिस में डालना चाहता हूं, सदन के कि हमारी मुख्य मंत्रीजी जो 15 हजार करोड़ का घाटा छोड़ कर गई थीं, उसका चार गुणा, 60 हजार करोड़ का घाटा कांग्रेस शासन में बढ़ गया और वह 75 हजार करोड़ हुआ। तो इसमें जो इन विद्युत वितरण कम्पनियों को मिसमैनेजमेंट से चलाया, उसके कारण यह घाटा बढ़ा है और इसका विस्तृत अध्ययन सरकार को कराना चाहिए। मैंने चूंकि विद्युत विभाग में 36 साल की सेवाएं दी हैं, इसका बहुत कुछ कारण स्पष्ट है। आगे के बिन्दुओं के समय इस पर मैं विस्तृत रूप से प्रकाश डालूंगा।

पिछली कांग्रेस सरकार ने एस.एफ.एस. स्कीम में किसानों के ऊपर ट्रांसफार्मर की कीमत का भार डाला था, जो कि उससे पहले 60 साल में कभी भी कोई भी सरकार ने इसका भार नहीं डाला। ट्रांसफार्मर की कीमत 80 हजार से लगाकर के डेढ़-डेढ़ लाख रुपए वसूल की गयी। इतना पैसा वसूल करने के बावजूद, यह जो कर्ज है, वह 75 हजार करोड़ तक बढ़ गया। तो यह बड़ा चिंता का विषय है और एक जांच का विषय भी है।

इस मौके पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस राज में कृषि उपभोक्ताओं को, जो सुराज संकल्प यात्रा के दौरान हमारी आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने भी नोटिस किया और माननीय सदन भी अच्छी तरह से जानता है कि किसानों को साढ़े चार-पांच घण्टे से ज्यादा विद्युत नहीं मिली, घरेलू उपभोक्ताओं को दस-बारह घण्टे से ज्यादा विद्युत उपलब्ध नहीं हुई। इसके कारण किसानों को नुकसान हुआ ही।

(श्री लादूराम)

साथ-साथ में, मैं आपको अभी ताजे आंकड़ों के बारे में बताना चाहता हूं कि जालौर और बाड़मेर, इन जिलों में हमारी सरकार के आते ही, मार्च से लगाकर जून तक, इन दोनों जिलों में उनालू-बाजरी बोई जाती है, तो यह जानकर इस सदन को खुशी होगी कि इन दोनों जिलों में हजारों किसानों के 50 से 100 क्विंटल बाजरा का उत्पादन हुआ है। इसमें विपक्ष के माननीय सुखरामजी विश्नोई, जो सांचौर के एम.एल.ए. बैठे हैं, इनके गांव में भी वह बाजरा हुआ है, मेरे गांव में भी वह बाजरा हुआ है और इनको अच्छी तरह से मालूम है। और, ये पूरारामजी, एम.एल.ए. भीनमाल; ये चौहटन के एम.एल.ए., हालांकि वे बाई-पास सर्जरी के कारण से इस सदन में नहीं हैं; गुढामालानी की तरफ से मैं आपको बता ही रहा हूं, इन दोनों जिलों में भरपूर बाजरा और चारा पैदा हुआ है। यह हमारी सरकार की ही देन है कि छह से सात घण्टे, साढ़े सात घण्टे रात को और साढ़े छह घण्टे दिन में बिजली जो इन्होंने उपलब्ध करवाई है, राजस्थान सरकार ने, उसके कारण ही यह बाजरे की फसल लेना किसानों के लिए, इनके हित में हुआ। वरना अप्रैल, मई और जून की जो लू चली है, उसमें अगर 24 घण्टे आप बिजली लगातार नहीं दो तो बाजरे की फसल उसी वक्त जल जाती है। मैं आदरणीया मुख्य मंत्रीजी को और हमारे ऊर्जा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि जालौर और बाड़मेर जिले में जो गुजरात पैटर्न पर बाजरे की जो पैदावार ली जाती है, उसमें बहुत भारी हमारी सरकार ने सहयोग दिया है। उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

इसके अलावा, उपभोक्ताओं को सिंगल फेज बिजली देने के लिए 400 के.वी. के तीन, 220 के.वी. के 9, 132 के.वी. के 11 ग्रिड सब-स्टेशन व 33 के.वी. के 220 सब-स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। इससे भी लगातार अन-इंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलेगी। यह आप मानकर चलिए। यह सप्लाई हमारे गुढामालानी विधान सभा क्षेत्र में और सांचौर विधान सभा क्षेत्र में आज भी, जब से हमारी सरकार आयी है, 24 घण्टे लगातार बिजली मिल रही है। यह इनके भादरना का ग्रिड है, जिसमें सांचौर एम.एल.ए. का क्षेत्र है और मैं वहां का रहने वाला हूं और साथ में गुढामालानी विधान सभा क्षेत्र की खुद की मैं गारंटी देता हूं कि 24 घण्टे बिजली उपलब्ध हो रही है। तो मैं राज्य सरकार को और हमारी यशस्वी माननीया मुख्य मंत्रीजी को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

(श्री लादूराम)

बिजली के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हमारी मुख्य मंत्रीजी ने सोलर ऊर्जा पर फोकस किया है, जिसके तहत 25 हजार मेगावाट का उत्पादन सोलर ऊर्जा नीति के तहत व एक लाख 25 हजार करोड़ रुपए का विनियोजन होगा। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में अपने पूरे राजस्थान का रबी सीजन में कंजम्प्शन 2 हजार एल.यू. है और 25 हजार मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करने पर 5 हजार एल.यू. का सोलर का उत्पादन होगा। तो अपने राजस्थान की जितनी रिक्वायरमेंट है, मैं आपको बता दूं कि 2005-2006 में एक हजार एल.यू. का अपना कंजम्प्शन था, जो अभी नौ साल में बढ़कर 2 हजार एल.यू. हुआ। इस प्रकार, नौ सालों में डबल कंजम्प्शन हुआ। तो पांच साल में ही 5 हजार एल.यू. अपने जब प्रोडक्शन होगा तो आप यह मानकर चलिए कि राजस्थान सरप्लस स्टेट होगा ऊर्जा के क्षेत्र में। अपने मुख्य मंत्रीजी के पिछले कार्य काल में अपने कांकरोली, भीनमाल, जेरड़ा, जो गुजरात में पड़ता है, इसको वेस्टर्न ग्रिड से जोड़ने के लिए एक 400 के.वी. की लाइन स्वीकृत हुई थी, उस पर हमारे बी.जे.पी. के पिछले राज में ही कार्य सम्पूर्ण कर दिया गया था और वेस्टर्न ग्रिड से उसका कनेक्शन जुड़ गया। उसका फायदा यह हुआ कि पूरे राजस्थान का नेशनल ग्रिड से कनेक्शन हो गया। तो आज हम बिजली खरीदते हैं, वह भी बहुत महंगी खरीदते हैं, जब ऊर्जा के क्षेत्र में अपन सरप्लस स्टेट होंगे तो वह पूरी इंडिया में बिजली बेचने का अपने को शुभ अवसर मिलेगा। उसमें राजस्थान को बहुत ही जबरदस्त फायदा होगा। मुख्य मंत्रीजी को मैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

कांग्रेस सरकार में 60 परसेंट बिजली बी.पी.एल. परिवारों को, ज्योति कम्पनी, दिल्ली से डायरेक्ट ठेका लेकर आई और पिछले राज में इसका कार्य, इन्होंने जगह-जगह पर अपनी मर्जी से शुरू किया। वहां जिन गली-मोहल्लों में, गांवों में जहां भी इन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन किया, वहां पर रिश्वत और भ्रष्टाचार करके लाइनें खींचीं। मैं आपको बता दूं कि इसकी आज जांच बैठाई जाए तो यह साबित हो जाएगा कि वह ज्योति कम्पनी जो है, वह बीच में ही काम छोड़कर चली गई। आज से करीबन साल, सवा साल पहले भाग गई। वह राजस्थान सरकार के अंडर में डायरेक्ट होनी चाहिए। अब जो 40 परसेंट वर्क है, बाड़मेर जिले में पी.डी.सी.एल. कम्पनी ने सर्वे किया है और वर्ल्ड-बैंक के थ्रू वह कार्य जब भी बी.पी.एल. परिवारों का शुरू हो, तो मेरा सदन से यह

(श्री लादूराम)

निवेदन है कि वह कार्य राजस्थान सरकार की देख-रेख में हो। डायरेक्ट दिल्ली की गवर्नमेंट से यह पैसा या इसका कार्य जो है, नहीं होकर, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो, ताकि स्टेट गवर्नमेंट के आफिसर्स, बिजली कम्पनियों के आफिसर्स का डायरेक्ट सुपरविजन हो।

आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने रामजी के गोल से फलौदी तक के बीच के सारे टोल नाके बंद कर दिये हैं। इसके लिये मैं आपके माध्यम से आदरणीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। 2006-07 में मुख्य मंत्रीजी ने इसकी शुरुआत की थी अमरारामजी के एरिये से। इन सात सालों में पब्लिक से बहुत पैसा वसूल कर लिया और अब टोल नाकों से वसूलना बंद किया है। उसके लिये भी आदरणीया मुख्य मंत्रीजी धन्यवाद की पात्र हैं।

कांग्रेस के राज में जले हुए ट्रांसफार्मर 5 से 10 दिन के पीरियड में दिये जाते थे, जो कि हमारी सरकार ने आते ही 72 घण्टे में ट्रांसफार्मर बदलने का निर्णय लिया है। उसमें करीब-करीब जालौर और बाड़मेर जिले की मुझे पूरी नालेज है और समय-समय पर मैं खुद रिव्यू करता हूं, बिजली के अधिकारियों से मेरी बात होती है, किसानों से मेरी बात होती रहती है, यह 72 घण्टे का समयबद्ध कार्यक्रम सुचारु रूप से चल रहा है और उसमें किसानों को बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है।

चोरी के ट्रांसफार्मरों की आज सुबह क्वेश्चन आवर में यह बात आई थी। तो चोरी के ट्रांसफार्मर के बारे में मेरा यह सुझाव है कि चोरी के ट्रांसफार्मर में एक बार एफ आई आर दर्ज होना और जांच का विषय, यह तो पुलिस का एक लम्बा-चौड़ा प्रोसीजर है, परन्तु ट्रांसफार्मर का रिप्लेसमेंट, किसान जैसे ही अपने ए.ईएन. कार्यालय में इन्फोर्मेशन देता है, वह ट्रांसफार्मर इमिजिएटली बदला जा सकता है। उसमें कोई भी चोरी के कारण डिले होने का बिजली कम्पनियों की तरफ से कोई प्रोविजन नहीं है और यह डिले होता है तो इसको भी सुपरविजन के द्वारा कम किया जा सकता है।

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, यह तो कुछ ज्यादा ही लम्बा हो रहा है।

श्री लादूराम (गुढामालानी): यह तो अभी शुरू ही किया है, साहब।

(श्री लादूराम)

गुढामालानी विधान सभा क्षेत्र से पहली बार भाजपा का उम्मीदवार जीतकर आया हूं, तो आप मुझे मौका दीजिये। गुढामालानी बहुत ही बैकवर्ड एरिया है।

श्री सभापति: आसन आपसे यह जानना चाहता है कि आप विभागवार बोलेंगे या किसी विभाग पर? विभागवार बोलेंगे, तब तो लिस्ट काफी लम्बी हो जायेगी।

श्री लादूराम (गुढामालानी): विभागवार आ रहा हूं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) माननीय सदस्य, अगर विभाग पर ही बोलना है तो फिर डिमाण्ड आ रही है, उस दिन खूब बोल लेना।

श्री लादूराम (गुढामालानी): विभागवार बोल गया, अब मैं आपके नर्मदा पर आ रहा हूं।

श्री सभापति: अच्छा, तो आप नर्मदा पर आये हैं।

श्री लादूराम (गुढामालानी): मैं नर्मदा पर बोल रहा हूं। 1979 में नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का गठन हुआ और वह चार स्टेट के बीच में था, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने 1979 में एक अवार्ड घोषित किया, जो कि राजस्थान के साथ बहुत बड़ा पक्षपात किया। वह मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके तहत आबंटित पानी की मात्रा मैं बताता हूं, मध्य प्रदेश में 18.25 मिलियन एकड़ फीट, गुजरात में 9 मिलियन एकड़ फीट, राजस्थान में पाइंट 5 मिलियन एकड़ फीट और महाराष्ट्र में पाइंट 2 मिलियन एकड़ फीट। महाराष्ट्र में तो मेधा पाटकर वैसे ही बहुत पीछे पड़ी हुई हैं इसलिए उनका इसमें शेयर बहुत कम है। इसमें चार स्टेट हैं जिनका मैंने आंकड़ा बताया और जो पानी आज की तारीख में यूज हो रहा है, वह भी मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में 18.2 मिलियन एकड़ फीट की जगह 9.44 मिलियन एकड़ फीट पानी अभी यूज़ में ले रहे हैं और वहां 8.8 मिलियन एकड़ फीट पानी की बचत है; गुजरात में 9 मिलियन एकड़ फीट पानी है, उसमें से 4.80 मिलियन एकड़ फीट पानी यूज़ हो रहा है और 4.20 मिलियन एकड़ फीट पानी की अभी बचत है; राजस्थान में पाइंट 5 मिलियन एकड़ फीट की जगह पाइंट 3 मिलियन एकड़ फीट पानी यूज हो रहा है। पाइंट 10 मिलियन एकड़ फीट की बचत कुछ भी नहीं रहेगी, क्योंकि जगह-जगह जलदाय योजनाओं और सिंचाई के लिये कार्य आन-गोइंग हैं और यह राजस्थान की सेविंग पूरी हो जायेगी।

(श्री लादूराम)

इन हालात में मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के साथ जो अलाटमेंट नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल से हुआ है, वह बहुत बड़ा भारी अन्याय हुआ है। इसमें आदरणीया मुख्य मंत्रीजी को मैंने इस बारे में विस्तृत निवेदन किया तो मुख्य मंत्रीजी ने इसका डिटेल सर्वे करवाया और सरदार सरोवर डैम से लगाकर पूरी नर्मदा कैनाल का सर्वे करवाया। सर्वे में यह बात आई कि जो पानी समुद्र में फालतू बहकर जा रहा है, वह पानी, 31.45 क्यूसेक्स उसकी सेविंग है...

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, अब आप कन्क्लूड करें। लास्ट वन मिनट। conclude your statement.

श्री लादूराम (गुढामालानी): मेरे को दो-तीन मिनट दीजिये, मैं पूरा कर रहा हूं।

श्री सभापति: चलिये, दो मिनट ले लीजिये, लेकिन अब कन्क्लूड कर दें।

श्री लादूराम (गुढामालानी): तो जो पानी की बचत हुई है, उसमें मुख्य मंत्रीजी के सामने टेक्निकल एक्सपर्ट राजस्थान के हैं, उन्होंने वह रिपोर्ट दी और मुख्य मंत्रीजी ने उसको बड़ा एप्रीशिएट किया है कि बिना नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के अपने को राजस्थान में 1,156 क्यूसेक्स पानी उपलब्ध हो सकता है, जिसमें उस अथोरिटी का कहीं इन्टरवेंशन नहीं है। इसके लिए पीपराली में 350 एकड़ बीघा जमीन उपलब्ध है। वहां नर्मदा कैनाल की तरफ से अधिकारियों ने सर्वे किया है और सांचौर के एम एल ए साहब का भी एरिया कवर होता है। आने वाले टाइम में इसका बजट प्रोविजन अगर हमारे शामिल कर लिया जाता है तो जालौर और बाड़मेर जिले के लोगों के लिये सिंचाई और पीने के पानी की जबरदस्त समस्या साल्व होगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आदरणीय प्रधान मंत्री महोदय, नरेन्द्रजी मोदी ने 17 मीटर का गेट स्वीकृत कर दिया है सरदार सरोवर में। उसके कारण वह पड़ोसी स्टेट के हिसाब से अपने राजस्थान का शेयर और मिलना चाहिये। यही मेरा निवेदन है। मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि पड़ोसी स्टेट के हिसाब, इस मांग को आगे रखें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: अब आपको 20 मिनट हो गये।

श्री लादूराम (गुढामालानी): एक मिनट। आदरणीया मुख्य मंत्रीजी जब वहां सुराज संकल्प यात्रा पर पधारी थीं तो उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि सूरत में घर-घर हीरा कटिंग उद्योग हैं, उनकी ब्रांच हेतु गुढामालानी, धोरीमन्ना, सिणधरी, इनमें 24 घण्टे की बिजली, पानी और जमीन मैं उपलब्ध कराऊंगी। तो वहां बाहर के जो प्रवासी हैं, गुढामालानी के, वे आकर के यहां कार्य कर सकते हैं। यह मेरी सरकार से मांग है।

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, अब आसन पांवों पर है।

श्री लादूराम (गुढामालानी): एक लास्ट पाइंट है।

श्री सभापति: सम्माननीय सदस्य, अब आसन पांवों पर है। जब आसन पांव पर रहता है तो कोई सदस्य अपने पांव पर नहीं रह सकता। तो विराज जायें।

श्री लादूराम (गुढामालानी): आधे मिनट का मामला है, सिर्फ आधे मिनट का।

श्री सभापति: मुख्य सचेतक महोदय, इस सदन के कुछ नियम आप अपने माननीय सदस्यों को भी बतायें।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक) विराज जाओ। आसन पैरों पर है।

श्री सभापति: श्रीमान् मानसिंह गुर्जर।

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री, माननीया वसुन्धराजी को ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले पांच वर्षों में कांग्रेस के कुशासन ने जिस प्रकार से राजस्थान की अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया और जिस मुकाम पर राजस्थान को कांग्रेस के लोग ले गये, इन विपरीत परिस्थितियों में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने, वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया है, निश्चित रूप से राजस्थान को आगे ले जाने वाला है

(18.00 बजे)

(श्री मान सिंह)

और एक विजन उसके साथ में है। इसलिए मैं आपके माध्यम से उनको बार-बार धन्यवाद देता हूं।

बजट में उन सारी चीजों का हवाला हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने हिसाब से कह दिया। बजट में जो मुख्यतया बीस हजार किलोमीटर सड़क बनाने की बात कही गयी है, निश्चित रूप से राजस्थान को एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाने का, और राजस्थान की जनता जो सपना देखती है कि हमारे प्रदेश की सड़कें और हमारा प्रदेश विकसित हो, इस बीस हजार किलोमीटर का जो संकल्प राजस्थान की सरकार ने व्यक्त किया है, पी पी पी माडल पर, उससे हमारा राजस्थान निश्चित रूप से अग्रणी प्रदेशों में शामिल होगा।

मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस के साथियों ने यहां बहुत-सी दलीलें दीं, उन्होंने कहा कि हमने बहुत बड़ी योजना पास करायी, यह किया, लेकिन जहां माननीय वसुन्धराजी ने अपने पिछले कार्यकाल में 9,904 गांवों को सड़क से जोड़ने का काम किया, वहीं कांग्रेस की सरकार ने अपने पिछले पांच साल में केवल 1,538 गांवों को सड़क से जोड़ने का काम किया। इस तुलना को जब हम देखते हैं तो किस प्रकार से गांव-विरोधी, किसान-विरोधी कांग्रेस की सरकार रही है, इस बात को हमारे माननीय साथियों को समझना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा, यहां पर माननीय डोटासरा जी नहीं हैं, बहुत किसान की बात उन्होंने कही थी, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले शासनकाल में किसान को सिंचित क्षेत्र के रूप में, जब 2003 में वसुन्धराजी ने शासन सम्भाला तो उन्होंने सिंचित क्षेत्र को 43.72 से बढ़ा कर के 64.40 किया और कांग्रेस ने अपने पांच साल के शासन में मात्र 67.40 लाख हैक्टेयर बढ़ाने का काम किया। इससे तुलना कर सकते हैं कि किस प्रकार की यह किसान-विरोधी सरकार रही, किस प्रकार का राजस्थान की जनता के साथ में कांग्रेस ने कुशासन दिया।

आज इस विपरीत परिस्थिति में माननीया वसुन्धराजी ने जो बजट पेश किया है, राजस्थान का हर वर्ग अपने आपको यह महसूस कर रहा है कि निश्चित रूप से हम राजस्थान को उस स्थान पर ले जाने का काम करेंगे, जहां राजस्थान पहुंचना चाहिए।

(श्री मान सिंह)

इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा, माननीया मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा, जो उन्होंने बजट में हमारे कृषि के कनेक्शन को बिना वेटिंग के देने का संकल्प लिया है और 2014-15 में जो 40 हजार कनेक्शन देने की घोषणा की है, उसके लिए मैं उनको बार-बार धन्यवाद देना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश का किसान, जिसको बहुत दिनों से इस बात की उम्मीद थी कि हमको कृषि का कनेक्शन मिलेगा, माननीय सदस्य जिस प्रकार से कह रहे थे कि बिजली से, जब वह 24 घण्टे बिजली से आज बाजरे की फसल हो रही है, तो निश्चित रूप से, जब उसके कनेक्शन ही नहीं होगा तो कहां से फिर उसको फसल मिलेगी? तो वह किसान जो लम्बे समय से लाइन में था उसको यह कनेक्शन मिलने पर, राजस्थान का किसान अपने आपको बहबूद महसूस करने का काम करेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए माननीया वसुन्धराजी ने पंचायती राज के माध्यम से टी.एफ.सी. और एस.एफ.सी. का जो पैसा, निश्चित अंश के रूप में, तकनीकी कर्मचारियों के साथ में, पंचायतों में जोड़ने का काम किया है, उससे हमारे गांवों के हैण्डपम्प और गांव की पेयजल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करने में मौका मिलेगा। माननीय पंचायती राज मंत्रीजी यहां मौजूद हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज गांवों के अन्दर जिस प्रकार की हमारी पेयजल व्यवस्था है, उसमें कई बार इस प्रकार की रिपोर्ट आती है कि हैण्डपम्प ठीक हो गये, यह हो गया, लेकिन अगर इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो पंचायत स्तर पर अगर उनका इस प्रकार का तकनीकी स्टाफ होगा तो हमारे गांवों को और हमारे किसान को इसका लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगापुर सिटी के बारे में कांग्रेस की पिछली सरकार ने बहुत घोषणाएं कीं, इनके जो पांच साल के बजट हैं वे बजट मैं पिछले पांच साल से पढ़ रहा हूं और उनको मैंने इसलिए रखा कि जब आखिरी साल में जिस प्रकार से इन्होंने जो घोषणाएं कीं, वह एक भी घोषणा वहां पर मौके पर पूरी नहीं हो पायी। चाहे वह सीवरेज की घोषणा थी, चाहे हमारे यहां पर वजीरपुर जो उप-खण्ड है उसमें एस.डी.एम. की घोषणा कर दी, लेकिन आज तक वहां एस.डी.एम. का न कार्यालय है, न एस.डी.एम. बैठता है। गंगापुर में पी.एच.ई.डी. के एक्स.ईएन. के आफिस घोषित कर दिया, ना वहां आफिस है, न वहां कर्मचारी बैठा, न उसकी कोई गाड़ी है, न उसका कोई साधन है। इसी

(श्री मान सिंह)

प्रकार उन्होंने 23 हायर सेकण्डरी स्कूल खोले, केवल बोर्ड लगा दिये और बोर्ड लगाने के बाद में वहां पर न प्रिंसिपल पहुंचा, न सब्जेक्ट की फैकल्टी पहुंची।

गांव के किसान ने जब यह देखने का काम किया कि यह कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी नहीं होकर के, ट्रेड यूनियन बन गयी है, जिस प्रकार से ट्रेड यूनियन पीछे से सौदा करने का काम करती है और पीछे से सौदा कर के, जिस प्रकार से प्रदेश की जनता को ठगने का काम पांच साल में कांग्रेस ने किया, उस राजस्थान की जनता ने कहा कि ट्रेड यूनियन वालों, तुम को हम राजस्थान को बरबाद नहीं करने देंगे और उन्होंने आपको बहुत बड़ा सबक सिखाने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे यहां पर एक बहुत लम्बी घोषणा इन्होंने की। एक आर.यू.बी. बनना था, रेलवे का अण्डरब्रिज, उसके लिए साढ़े छह करोड़ रुपये की घोषणा कर दी और कांग्रेस के लोगों ने उसका पत्थर लगा दिया। जब पत्थर लगा दिया तो रेलवे का जी.एम. आया, उसने पत्थर को हटा दिया कि हमारे पास में ऐसी कोई स्वीकृति नहीं है, आप इस प्रकार से बिना स्वीकृति के नहीं लगा सकते।

इस प्रकार के जब वहां हालात हुए, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं जहां से चुनाव जीत कर आया हूं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, कि पांच साल तक उस शहर में पानी भरा रहा। दो बार वहां से पूर्व मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब निकले। जब सरकार को यह पता लगा कि मुख्य मंत्री होने के बावजूद पानी नहीं सूख सकता, तो मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहूंगा कि सुराज संकल्प यात्रा में वसुन्धरा जी एक बार उस पानी में होकर गयी थीं, लेकिन जब भरतपुर सम्भाग में सरकार गयी तो माननीय पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे गंगापुर शहर की सड़कों को इस प्रकार से कर दिया जैसे हालैण्ड की सड़कें हों। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसलिए विजन के साथ में काम करना पड़ेगा, जनता को साथ में, विश्वास में लेकर चलना पड़ेगा और इस बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार से सब वर्गों को छूने का काम किया है, मैं उनको बार-बार धन्यवाद देते हुए, माननीय सभापति महोदय, यह कहना चाहूंगा कि देवनारायण योजना,

(श्री मान सिंह)

जिसको एस.बी.सी. वर्ग के लिए घोषित किया गया था, पांच साल में कांग्रेस ने उसमें 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, माननीयस वसुन्धराजी ने इस वित्त वर्ष के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा की है। उसके लिए मैं उनको बार-बार धन्यवाद देना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आपने जिस योजना में देवनारायण बोर्ड को सशक्त करने की बात कही है, वह निश्चित रूप से उस वर्ग को मजबूती देने का काम करेगी।

इसी के साथ में, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस वर्ग की बालिकाएं जो 60 प्रतिशत अंकों से पास होती हैं, उन्हें स्कूटी देने का काम न केवल सरकारी स्कूल में करें, जो निजी कालेजों में एडमिशन लेती हैं, उनको भी देने का काम करें। यह मेरी सरकार से विनती है कि इस एस.बी.सी. की छात्राएं जो 60 प्रतिशत अंकों से पास होती हैं, उनके लिए करें। कांग्रेस ने अपने शासन में कंजूसी बरती और केवल एक हजार बालिकाओं को स्कूटी देने का काम किया, दो हजार बालिकाएं वंचित रह गयीं। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इसकी संख्या को बढ़ा कर कम से कम तीन हजार किया जाए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह मेरी आपसे विनती है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे गंगापुर में एक रेल का कारखाना हुआ करता था, राजस्थान में गंगापुर एक मात्र शहर है जहां रेल का इंजन बनता था और गंगापुर की जनता को उससे बड़ा भारी रोजगार मिलता था। आज वह कारखाना बंद हो गया, वहां की मिलें बंद हो गयीं। केवल गंगापुर में आज अगर कोई व्यापारिक या गंगापुर को बिजनेस देने का कोई साधन रहा है तो वह हमारा एजुकेशन हब है। कोटा के बाद में, चालीस से पचास हजार बच्चे गंगापुर से बाहर के यहां आकर पढ़ते हैं। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी से यह मांग करना चाहूंगा कि हमारे यहां जो राजस्थान में केन्द्र सरकार ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की घोषणा की है, भरतपुर संभाग में सवाई माधोपुर जिला और उसमें गंगापुर कृषि के मामले में प्रथम है, 'ए' श्रेणी की कृषि मण्डी है और पूरी तरह वहां का किसान सरसब्ज है, इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को हमारे सवाई माधोपुर-भरतपुर सम्भाग में आप खोलने का काम करें। सरकार से हम इसकी मांग करते हैं।

विशेषकर जो सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात कही है, वह

(श्री मान सिंह)

निश्चित रूप से इंग्लिश मीडियम स्कूलों के माध्यम से गांव का जो बच्चा है उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल का लाभ मिलेगा। प्रथम आपके जो 66 स्कूल खोलने की बात है, उसमें भी हम मांग करते हैं कि हमारा आई.टी.आई. का तो आपने इसमें ले लिया, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी इसमें लेने का काम करें।

सभापति महोदय, यहां पर शिक्षा मंत्रीजी नहीं हैं, आपके माध्यम से उनसे एक विशेष अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में निचले स्तर पर जिस प्रकार का इन्होंने बंटाढार किया है, उस पर सोचने की इस पूरे सदन को आवश्यकता है। हर साथी को इस बात को समझना होगा कि एजुकेशन का जो हाल हुआ है, अगर इसको हमने सम्भालने का काम नहीं किया तो हमको कभी माफ नहीं किया जायेगा।

सभापति महोदय, सदन के माध्यम से मैं शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में, अगर सम्भव हो, तो हाई स्कूल दो तरह के करने का काम करें, एक नार्मल हाई स्कूल हो, एक टेक्निकल हाई स्कूल हो। टेक्निकल हाई स्कूल में जाने वाला बच्चा, उसको ना आई टी आई करने की जरूरत होगी, ना पोलीटेक्निक डिप्लोमा करने की जरूरत होगी। नवीं क्लास से जब वह टेक्निकल हाई स्कूल में होगा, तो रोजगार से जुड़ने का काम करेगा। रोजगार सृजन का इससे बड़ा कोई साधन नहीं हो सकता है। टेक्निकल हाई स्कूल और नार्मल हाई स्कूल, इसमें दो तरह के हाई स्कूल अगर राजस्थान में कर दिये जायें तो पूरे हिन्दुस्तान में सबसे पहला उदाहरण राजस्थान के अन्दर होगा। यह मेरी पुरजोर अपील है और पुरजोर निवेदन है कि सरकार इस पर विचार करे और आमूलचूल परिवर्तन, जिस प्रकार से एकीकरण करने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार हाई स्कूल लेवल पर भी करने का काम करें।

सभापति महोदय, शंका जिस प्रकार की हो रही है कि कल को सैकण्डरी और हाई स्कूल में भी अगर बच्चे नहीं आयें तो हमारी स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं होगी। इसलिए हम उन स्कूलों को एक तरफ तो इंग्लिश मीडियम करें और दूसरी तरफ एकीकरण करके सुधारने का काम करें। दूसरी तरफ, हाई स्कूल को दो तरह का पैटर्न देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की जो गरीब जनता है और राजस्थान का जो आने वाला नौजवान है, उसको शिक्षा का एक नया आयाम मिलेगा।

(श्री मान सिंह)

सभापति महोदय, मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि आपने घोषणा की थी नैनो सेंटर की। कहां है आपका नैनो सेंटर, यूनिवर्सिटीज में, स्टडीज का? कहीं पता ही नहीं है। आप अपने बजट को कभी पढ़ना कि कितनी-कितनी घोषणाएं की थीं। मैं सदन में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप और हम जो बात रखें वह इस अवाम के हित की होनी चाहिए।

मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को बारम्बार धन्यवाद देता हूं इस विकासशील बजट के लिए।

आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री जगदीश नारायण।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके बाद मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं राजस्थान की यशस्वी माननीया मुख्य मंत्री, वसुंधरा राजेजी का, जिन्होंने 14 तारीख को ओजस्वी भाषण के रूप में राजस्थान के बजट को पढ़ा।

सभापति महोदय, यह जो बजट पेश किया गया, इस बजट को अगर गहराई से देखा जाये तो राजस्थान का चमकता हुआ विकास इस बजट में नजर आ रहा है। यह बजट राजस्थान की तरक्की का बजट है। इस बजट को जिसने भी गहराई से पढ़ने का प्रयास किया है, वह व्यक्ति सच्चे अर्थों में इस बात को समझ पाया है कि वर्षों से जिस बजट का इंतजार था, वह बजट अब की बार मिला है।

सभापति महोदय, बजट में अगले 5 वर्षों में सोलर ऊर्जा से 25 हजार मेगावाट की क्षमता स्थापित करना, मैं कहता हूं कि एक स्वर्णिम युग की शुरुआत करने के बराबर है। आज बिजली क्षेत्र में हम बहुत कमजोर हो चले हैं, बहुत पिछड़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में अगर राजस्थान को बचाया जा सकता है तो सोलर ऊर्जा का विकास करके, सोलर ऊर्जा की इकाइयां स्थापित करके इस काम को सफल बनाया जा सकता है।

सभापति महोदय, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने समय रहते इस क्षेत्र में अगर काम किया होता तो बिजली क्षेत्र की आज जो समस्या है, वह हमारे सामने

(श्री जगदीश नारायण)

नहीं होती। चूंकि उस सरकार का एक नारा था, 'पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सबको पढ़ाओ', पानी बचाने और बिजली बचाने की हालत यह हुई कि बचाते-बचाते उनकी वह बिजली आज बिलकुल गायब हो चली है। पानी बचाने की बात इन्द्र ने उनकी सुनी और इन्द्र ने पानी को बचाने के लिए बरसाना बंद कर दिया।

सभापति महोदय, 'सबको पढ़ाओ', मैं कहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में हमारी वह हालत हुई कि उन स्कूलों से बच्चों को छोड़-छोड़कर के प्राइवेट स्कूलों में जाना पड़ा। आज 5-6 महीने सरकार को बने हुए हैं और कांग्रेस के भाई चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि स्कूलों में मास्टर नहीं हैं। आप कौनसा समानीकरण कर रहे हैं, आप कौनसा एकीकरण कर रहे हैं। भले आदमियों, वही समानीकरण कर रहे हैं, वही एकीकरण कर रहे हैं। जो अपराध आपने किया है, उस अपराध को आखिर ढकना तो पड़ेगा, उस अपराध से आखिर उबरना तो पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि राज्य में वर्ष 2014-15 में 400 के वी के 3, 220 के वी के 9, 132 के वी के 11 नये सब-स्टेशन तथा 23 के वी के 220 सब-स्टेशन की स्थापना करना किसान जगत के लिए सूर्य उदय करवाना है। कांग्रेस ने बिजली बचाने का काम तो किया लेकिन कभी बिजली बनाने का काम नहीं किया। अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो आज बिजली क्षेत्र में ये हालात पैदा नहीं हुए होते।

सभापति महोदय, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का पुरजोर शब्दों में आभार व्यक्त करना चाहता हूं और मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, आज राजस्थान का किसान वर्ग कर रहा है। किसान वर्ग में बजट को पढ़ते ही एक खुशी की लहर चल पड़ी है। ज्यों ही किसानों ने यह सुना कि किसानों को आवेदन करते ही कनेक्शंस दे दिये जायेंगे, तो मैं कहता हूं कि किसान का रोम-रोम खुश हो चला और किसान ने अपनी आत्मा से ढेर सारी दुआएं मुख्य मंत्रीजी को भेजने की कोशिश की है।

सभापति महोदय, आज क्षेत्र में अगर किसान से जाकर के बात करें तो किसान प्रफुल्लित हैं। किसान इस बात के लिए खुशी जाहिर कर रहा है कि अगर बिजली क्षेत्र में हमारी किसी ने सुनी है तो वसुंधरा राजेजी की अब की बार की सरकार ने सुनी है, अब हमें चिंता नहीं है।

(श्री जगदीश नारायण)

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं बात करूं जल प्रबंधन की, तो नदी-नालों को पुनर्जीवित करना तथा नदियों को जोड़ना, यह राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीजी के सपने को साकार करना है। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने यह तय किया है कि माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी ने जो सपना संजोया था, उस सपने को साकार करना है और उस सपने के माध्यम से इस राजस्थान की जनता के लिए पेयजल की व्यवस्था करनी है।

सभापति महोदय, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि ग्रामीण आधारभूत संरचना के अन्तर्गत ग्राम के समग्र विकास को, इस दृष्टिकोण से माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 'श्री योजना' बनाकर के और इस योजना के तहत 5 योजनाएं बनाकर, जिनमें ग्राम स्वच्छता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और विद्युत को आधार बनाकर के विकास करना अपना एक लक्ष्य बनाया है। यह अनूठा लक्ष्य है। मैं समझता हूं कि ऐसे लक्ष्य से ही सही मायने में ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो सकता है। ग्रामीण विकास को नजदीकी से अगर किसी ने समझने का प्रयास किया है तो माननीया मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी ने किया है। आज तक ग्रामीण क्षेत्र के विकास को समझने का प्रयास करने की कोशिश किसी ने नहीं की है।

सभापति महोदय, यह बजट इतना प्रशंसनीय बजट है, इस बजट के पक्ष में जितनी प्रशंसा की जाये, उतनी मैं कम समझता हूं।

इसके साथ ही, राज्य में मेडिकल कालेजों और अस्पतालों की स्थापना करना, राजस्थान को निरोगी बनाने के लिए एक सुंदर कदम उठाने का प्रयास किया गया है। इससे राजस्थान निरोगी बनेगा और राजस्थान निरोगी बनकर विकास की गति को पकड़ेगा।

इसके साथ ही, कृषि क्षेत्र में किसानों के माध्यम से उपज बढ़ाने के लिए अगर किसानों को राहत देने का काम किसी ने किया है तो माननीय माननीय मुख्य मंत्रीजी वसुन्धरा राजेजी ने इस बजट के माध्यम से किया है। गत वर्षों में हम देखते आए हैं, किसान बीज लेकर फसल बोने के लिए तैयार रहता है लेकिन खाद की जहां चर्चा आती है, किसान खामोश हो जाता है, किसान को बाजार में चक्कर काटने पड़ते हैं, ब्लैक के दामों में किसान को खाद नहीं मिल पाता। माननीया वसुन्धराजी ने एडवांस में किसान के लिए

(श्री जगदीश नारायण)

उर्वरक का भण्डारण करके किसान की व्यवस्था करने की पहल की है। यह भी माननीय वसुन्धरा जी की बहुत बड़ी पहल है।

इसके साथ ही, माननीय सभापति जी, मैं निवेदन करूं सड़कों के बारे में, तो सड़क क्षेत्र में 20 हजार किलोमीटर सड़कें तो बनाई ही बनाई जाएंगी लेकिन 20 हजार किलोमीटर के साथ में वह सड़क, जिस सड़क पर हमारे गांव का विकास निर्भर है, उसमें आधा किलोमीटर से लेकर और दो किलोमीटर तक की 'गौरव पथ' के नाम से सड़क बनाई जाएगी, उसके साथ नाली का निर्माण होगा और सही मायने में अगर देखा जाये तो गांव का असली विकास भी वही होगा। जिसको माननीया मुख्य मंत्रीजी ने नजदीक से देखने का काम किया है, उसको इस बजट में जगह प्रदान की है।

माननीय सभापति जी, पूर्ववर्ती सरकार के समय में हमने देखा है, सड़क बनाने का शौक इनको खूब रहा है, लेकिन सड़क नहीं बनाई, केवल पत्थर लगाने का काम किया है; जगह-जगह पत्थर लगाने का काम किया है। आज वह पत्थर, मैं आपको गिनवा सकता हूं, जहां सड़क नाम की कोई चीज नहीं है पर सड़क का शिलान्यास और सड़क के उद्‌घाटन का लेख जरूर उस पत्थर पर अंकित है।

इसलिए, माननीय सभापतिजी, इन लोगों को विकास की जरूरत नहीं है, इन लोगों को शासन की जरूरत है, कुर्सी की जरूरत है। कुर्सी आनी चाहिए, शासन मिलना चाहिए। अबकी बार जनता ने इनके काले कारनामों को देखकर ऐसा सबक सिखाया है, ऐसा सबक सिखाया है कि आज भी वह सबक के मारे इनका पेट दर्द चल रहा है, उस पेट में आज भी शांति नहीं है।

मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ये लोग समझदार होते, इन लोगों ने राजस्थान से प्यार किया होता, इन लोगों को राजस्थान के विकास की चिंता हुई होती तो मैं कहता हूं, माननीय सभापतिजी, पिछले 65 वर्षों में कुछ वर्षों को छोड़कर राज इनके हाथों में रहा है और उस राज का अगर यह सही ढंग से विकास के रूप में इस्तेमाल करते तो मैं समझता हूं कि आज पीने के पानी की जगह-जगह समस्या नहीं मिलती, आज स्कूलों में अध्यापकों की कमी नहीं होती। आखिर इन लोगों ने किया क्या? जब आज हमारी सरकार कुछ करना चाहती है, कुछ करने की सोचती है, विकास के लिए कुछ मुद्दे तैयार करती है और पेट में दर्द चलता है, यह बजट बेकार है, यह बजट

(श्री जगदीश नारायण)

निराधार है, यह बजट नाकारा है। मैं कहता हूं, माननीय सभापतिजी, अगर यह बजट ही बेकार हुआ होता, तो राजस्थान की जनता ने 163 की तादाद में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहां नहीं भेजा होता। मैं कहता हूं कि इन्होंने अच्छे बजट बनाये होते तो आज इनकी वह दुर्दशा नहीं होती। लेकिन यह मैं जरूर इनको सांत्वना देना चाहता हूं, इनको तसल्ली बंधाना चाहता हूं कि आप चिंता न करें, आपके इस हालात से हम भी सबक लेना चाहते हैं, हम भी सीख लेना चाहते हैं, आपकी तरह हम नहीं करेंगे। हम राजस्थान में दुबारा आयेंगे। पीने के पानी की व्यवस्था भी करेंगे, किसान की व्यवस्था भी करेंगे, स्कूलों में अध्यापकों की व्यवस्था भी करेंगे और इस राजस्थान को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। इस राजस्थान को विकास के पथ पर साथ लेकर चलने का काम करेंगे।

माननीय सभापतिजी, बजट के संदर्भ में 2008-09 तक बिजली कम्पनियों का जो घाटा 15 हजार करोड़ रुपये का दिखाया था, कांग्रेस की सरकार में वह घाटा 15 हजार से बढ़कर 75 हजार करोड़ तक पहुंच गया।

शुरू-शुरू में जब माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 2003 में सरकार सम्भाली थी, उस समय राजस्व घाटा 3,424 करोड़ रुपये का था और माननीया मुख्य मंत्री, वसुन्धरा राजेजी ने अपने अथक प्रयासों से, अपनी सोच से, जिसको पूरा करने के बाद, 1,653 करोड़ रुपये का सरप्लस छोड़ा था। घाटे को पूरा करना और सरप्लस में राजस्थान को लाना और उसके बाद 2008 से 2013 तक फिर राजस्व घाटा 2,500 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। इसका मतलब, शासन व्यवस्था में प्रबन्धन व्यवस्था कतई इनके पास नहीं थी। यह चीजें इनकी अकुशल प्रबन्धन को दर्शाती हैं। आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, यह मैं तो समझ नहीं पाता। जब आये सरकार में, तब घाटा देकर गये।

एक बार तो, माननीय सभापतिजी, पूर्ववर्ती माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात का रोना रोते थे कि खजाना खाली है, खजाना खाली है। जगह-जगह इस बात का प्रचार करते थे। जबकि हमारी माननीया मुख्य मंत्री, वसुन्धरा राजेजी ने अगर घाटा भी खजाने में मिला तो कभी खजाना खाली होने का रोना नहीं रोया और उस खजाने को भरने के लिए, निवेश को बढ़ाने के लिए बढ़- चढ़कर काम किया।

(श्री जगदीश नारायण)

इसलिए, माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि यह कुशल प्रबन्धन अबकी बार माननीया वसुन्धराजेजी के हाथों में आया है; राजस्थान विकास करेगा, राजस्थान विकास की गति में आगे बढ़ेगा, दौड़ेगा, ऐसी कामना करता हूं। माननीया वसुन्धरा राजेजी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हुआ और आपका आभार प्रकट करता हुआ मेरी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पब्बाराम।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, दो दिवस पूर्व सम्मानित सदन में राजस्थान की लोकप्रिय और यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया की ओर से 2014-15 का बजट प्रस्तुत किया गया। यह बजट बड़ा ही स्वागत योग्य, श्लाघनीय है। मैं आपके माध्यम से सरकार को और माननीया वसुन्धराजी का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन विषम परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में माननीया वसुन्धरा जी और भारतीय जनता पार्टी को शासन की बागडोर मिली, जिस प्रकार से पूर्व की सरकार ने कंगाली के स्तर पर लाकर इस राजस्थान के प्रदेश को छोड़ दिया था, ऐसी परिस्थिति में इससे बढ़िया बजट और कोई प्रस्तुत नहीं कर सकता था। वर्ष 2014-15 के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान में अंतिम छोर पर बैठे हुए उस आम आदमी की चिंता माननीया वसुन्धराजी ने की है। बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, आदि की समस्याओं के निराकरण हेतु भरसक प्रयास इस बजट में देखने को मिले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक बहुत बड़े परिवार की मुखिया होने की भावना के साथ, जिम्मेदारी के लिए, माननीय मुख्य मंत्री महोदया के नेतृत्व में प्रदेश अपनी उन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा 2014-15 का यह जो बजट पेश किया गया, इसे राज्य की जनता के समक्ष पेश करने से पूर्व माननीया वसुन्धराजी सुराज संकल्प यात्रा के दौरान सम्पूर्ण राजस्थान में हर गांव तक पहुंचीं और वहां की समस्याओं को अनुभूत किया और उसके बाद में भी, सत्ता में आने के बाद में वे बैठी नहीं रहीं, पांच महीने प्रशासन करने की नहीं सोची, पांच वर्ष तक लगातार काम करने की सोच के साथ में, आगे बढ़ते हुए, सबसे पहले संभागवार दौरा करना शुरू किया और वहां पर सरकार को आम आदमी के दर पर ले जाकर, उनकी समस्याओं को

(श्री पब्बाराम)

जानने का जो विशेष प्रयोग किया, वह सम्पूर्ण भारत के अन्दर श्लाघनीय है। सभी लोग इसकी प्रशंसा करते हैं।

भरतपुर में जाने के बाद में, उसके बाद में लोक सभा के चुनाव आ गये और लोक सभा के चुनाव में मिशन 25 को पूरा करने के बाद में, एक व्यक्ति जब, एक छात्र जब परीक्षा देता है और मेहनत के बाद में फिर वह चाहता है कि मैं अपनी नींद को निकालूं, आराम करूं, परन्तु आपने आराम नहीं किया और दबी-कुचली जनता, गरीब जनता के द्वार पर जाने का जो संकल्प लिया और निकल पड़े।

कुछ मेरे विपक्ष के साथियों ने बार-बार जो सम्भागीय दौरे हैं, उनकी आलोचना की है। परन्तु आपको मैं आगाह करता हूं कि कोई भी मुख्य मंत्री 52 डिग्री सेल्सियस गर्मी के अन्दर और जहां पर रिकार्ड गर्मी पड़ती हो, फलौदी और चूरू, चूरू उस सम्भाग में, सबसे पूरे हिन्दुस्तान में, सबसे अधिक गर्मी वाला स्थान है और उन स्थानों का दौरा करना, जिसके पांव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिसको आम जनता का दर्द है, वह उस जनता के दर्द तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को अनुभूत किया और अनुभूत समस्याओं को इस बजट के अन्दर प्रस्तुत करने का प्रयास किया, परिलक्षित किया।

मैंने भी कुछ प्रश्न पूछे थे, तारांकित और अतारांकित, परन्तु उन प्रश्नों का जवाब माननीया वसुन्धराजी ने इस बजट के अन्दर दे दिया।

क्योंकि उन्होंने उन समस्याओं को वहां पर जाकर अनुभूत किया और उन्होंने विभिन्न संगठनों से, गांव-ढाणी जाकर, उसके बाद में, कई प्रकार के विशेषज्ञों, औद्योगिक और व्यापारिक संगठनों, किसानों, स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संगठनों, सामाजिक संगठनों, इन सबसे विचार-विमर्श किया। राज्य की आम जनता से विचार-विमर्श करने के बाद जो बिन्दु निकलकर आये, वे इस बजट में रखे। इस बजट के अन्दर गांव, गरीब, किसान, कर्मचारी, स्टूडेंट, युवा, व्यापारी, मजदूर, महिला, उद्योग जगत, सभी का पूरा ध्यान रखा गया है। सभी वर्ग ऐसे समझते हैं कि यह बजट शायद मेरे लिए ही प्रस्तुत किया गया है।

हर दृष्टि से देखा जाय तो यह अच्छा बजट है और सब जगह से प्रशंसा हो रही है। मात्र कुछ विपक्षी सदस्यों के द्वारा आलोचना हो रही है। समालोचना होनी चाहिए, परन्तु आलोचनात्मक स्वर हमेशा, नकारात्मक स्वर, उनकी तरफ से सुनायी देते हैं। यह अच्छी बात नहीं है।

(श्री पब्बाराम)

पिछले पांच वर्ष के वित्तीय कुप्रबंधन ने प्रदेश को हर दिशा से कमजोर किया था। राज्य की हर क्षेत्र में हालत खस्ता हो गई थी। दिसम्बर, 2013 में जनता के ऐतिहासिक समर्थन के बाद सरकार ने एक नई ऊर्जा के साथ अपना कार्य प्रारम्भ किया और जिसके परिणाम शीघ्र ही देखने को मिलेंगे। मुझे व प्रदेश की जनता को यह विश्वास है कि 2020 तक राजस्थान शक्तिशाली, विकसित और समृद्ध राज्यों के अन्दर शुमार हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, अगले 5 वर्ष में, माननीय वसुन्धराजी ने यह संकल्प लिया है कि राज्य के 15 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस बात से खिल्ली विपक्ष के बंधु उड़ाते हैं कि 15 लाख नौकरियां हैं। नौकरियों का अर्थ सरकारी नौकरी से नहीं है विभिन्न प्रकार की स्किल डवलपमेंट की, जो आपके पंचायत समिति स्तर त।क आई टी आई खोलना और इसी प्रकार से स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना, इस प्रकार से युवाओं को इस योग्य बनाया जाएगा कि रोजगार स्वत: उन तक पहुंच जाएं। इस प्रकार का प्रयास माननीया वसुन्धरा जी ने किया है।

राज्य में प्रतिदिन 15 किलोमीटर लम्बाई की सड़क का निर्माण करके और 20 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण करने का संकल्प जो माननीया वसुन्धरा जी, हमारी नेता ने लिया है, वह निश्चित तौर से श्लाघनीय और प्रशंसनीय है।

पिछली सरकार ने राज्य के संसाधनों का दोहन जिस प्रकार से किया, कुप्रबंधन के मार्फत से, उन्होंने संस्कृत की इस उक्ति को चरितार्थ कर दिया कि ''यावत जीवेत सुखम् जीवेत, ऋणम् कृत्वा घृतम पीवेत'', यानी कि ऋण लिये जाओ और घी पीते रहो और आनन्द करो। तो वे ए सी के अन्दर बैठे रहे और धीरे-धीरे फ्रिज के अन्दर समा गये और जम गये व बहुत कम मात्रा में हो गये। यह परिस्थिति उनकी इसी दृष्टिकोण के कारण हुई है।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए, हम गौरव पथ की सुना करते थे कि शहरों के अन्दर होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समिति से जो बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों तक जोड़ने का 'गौरव पथ' के माध्यम से संकल्प है, वह भी प्रशंसनीय है। इसी प्रकार से, गांवों के अन्दर आधा किलोमीटर से लेकर दो किलोमीटर सी सी रोड का निर्माण करवाना व किसानों को उनके आवेदन करते ही कृषि कनेक्शन की एक अभूतपूर्व योजना माननीया वसुन्धराजी ने प्रदान की है।

(श्री पब्बाराम)

इससे कृषक समाज में हर्ष की लहर दौड़ चली है। राज्य के सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत उपभोक्ताओं को पूर्ण गुणवत्तापूर्ण बिजली प्रदान करने का जो संकल्प किया है, वह भी श्लाघनीय और प्रशंसनीय है। 2014-15 में 40 हजार कृषकों को कृषि कनेक्शन देने का बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसके लिए राज्य के कृषक माननीया वसुन्धराजी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

बूंद-बूंद सिंचाई योजना के तहत डार्क जोन में भी आन-डिमाण्ड कनेक्शन देने का जो फैसला किया है, यह बहुत ही साहसिक फैसला है। राज्य की 'जनता जल योजना' नासूर बनी हुई थी। न तो सरपंच के पास में ऐसी कोई व्यवस्था थी कि वह उसको ठीक करके जनता को पानी पिला सके। एक साहसपूर्ण निर्णय लेते हुए माननीय वसुन्धराजी ने एक बार समस्त स्कीमों को पी एच ई डी के मार्फत ठीक करवाकर, उनके लिए बजट निर्धारण करके, बजट का कुछ प्रतिशत भाग उन्हीं पर खर्च किया जाएगा, यह निर्धारित कर दिया और उसके बाद पंचायतों को हैण्ड-ओवर करने का संकल्प लिया है। निश्चित तौर से ये ट्यूबवैल्स जनता को पानी पिलाने का काम करेंगे।

इंदिरा गांधी नहर, प्रथम व द्वितीय चरण, जिसके अन्दर नहरें अटी पड़ी थीं, उनको 50 साल हो चुके थे, सफाई और पुनरुद्धार का कार्य भी हाथ में लिया है और बूंद-बूंद व फव्वारा पद्धति से सिंचाई करने का संकल्प लिया है। अगले तीन वर्षों में इंदिरा गांधी नहर की प्रथम चरण की नहरों की सफाई, मरम्मत, विस्तार, पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण का कार्य होगा।

एक बहुत बड़ा विषय है, वसुन्धराजी अगर बीकानेर नहीं जातीं तो ये 500 किलोमीटर सड़कें नहीं बन पातीं। बड़ा गम्भीर विषय था। कुछ ऐसे गांव थे, जो सड़कें नहरों के पास-पास बनायी गयी थीं, वे 50 साल, 40 साल पहले बनी थीं। उनका कोई धणी-धोरी नहीं था। न पी डब्ल्यू डी उनका रखरखाव कर रही थी, न उनके पास बजट था। ऐसा लगता था कि सड़क गड्ढों में है या गड्ढे सड़क में हैं, और उन गांवों को जुड़ा हुआ बता दिया गया। उसके अन्दर दूसरी सड़कें भी नहीं जा पातीं।

राजस्थान दिवस सेलीब्रेशन को समाप्त कर दिया, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, पूर्ववर्ती सरकार ने इसको नाच-गाने का कार्यक्रम कहकर बंद कर दिया। ट्यूरिज्म पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। प्रत्येक देश व राज्य अपने

(श्री पब्बाराम)

यहां पर देश और विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, अपनी संस्कृति के दिग्दर्शन के लिए इस प्रकार के महोत्सव मनाते रहे हैं। विपक्ष के साथियों को मैं अर्ज करता हूं कि यह पूरा का पूरा राजस्थान की संस्कृति, आल्हादित करने वाले गाने, गीत पर आधारित है। किसी भी मंगल गीत के बिना कोई भी कार्यक्रम हमारे यहां पर सफल नहीं माना जाता। जन्म पर हालरिया गाते हैं और उस संस्कार देने वाले हालरिये के साथ में, ''मात सिखावे पालने हालरियो हुलराय, इला न देणी आपणी मरण बढ़ायी माय।'' सूरमा बनने की ट्रेनिंग, उसके संस्कार भी हालरिये के गीत में पड़े हुए हैं। विवाह और शादी पर मंगल गीतों के बगैर कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। मानसून आने पर मन मयूर नाचने लगता है और ''मोरिया आछो बोल्यो रे ढलती रात मां'', ये गीत गाये जाते हैं। इसी प्रकार से, खेती में हल चलाते समय किसान तेजा गाता है और हल चलाता है। इसी प्रकार से, फसल पकती है तो चिड़िया खेत खाने लगती है, तो एक किशोरी अपने घर को बसाने के लिए वह एक कालचिड़े को बोलती है, ''बैरी मत खा रै कालचिड़ा, बाबुल की ज्वार'', वह मत खा, ताकि वह मेरी अच्छी तरह से शादी कर दे और मैं आगे जाऊं। आपने इसको भी गाना-बजाना बता दिया। जो 'तेरह ताली' भक्तिमय संगीत है, 'तेरह ताली' नाच-गान के अन्दर नहीं आते, बाबा रामदेव की भक्ति का एक अनूठा तरीका है। 13 जगह मंजीरे बांधकर महिला किस प्रकार से उन 13 मंजीरों को टच करती है और भगवान रामदेवजी की आराधना करती है, उसको उस महोत्सव में शो किया जाता है। इसको भी नाच-गाना कह कर बन्द कर दिया। अग्नि नृत्य, हमारे सिद्धों द्वारा अग्नि के ऊपर चलकर अग्नि नृत्य किया जाता है, वह ईश्वर प्राप्ति की तरफ बढ़ने का एक प्रकार से तरीका है। यजमानों के ऊपर निर्भर रहने वाले कलाकारों को विदेशों तक कार्यक्रम करने का मौका इसी कार्यक्रम के द्वारा मिला। इसी कार्यक्रम के अन्दर इस प्रकार से शूरवीरों के गाने भी गाये और बजाये जाते हैं। आला और रूदल, बगड़ावत, तेजाजी, पाबूजी की फड़ और स्वतंत्रता संघर्ष के गाने भी फागुन गीतों के मार्फत यहां पर गाये जाते हैं। इसको गाने और बजाने का महोत्सव बताकर बन्द किया है। इसके लिए मैं पूर्व सरकार की निन्दा करता हूं तथा वर्तमान सरकार ने इसको किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, चूंकि मैं उस क्षेत्र से आया हूं जहां पर सोलर हब है

(श्री पब्बाराम)

25 हजार मेगावाट सोलर से बिजली उत्पन्न करेंगे। सोलर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा सोलर पार्क मेरे क्षेत्र में आता है, जहां पर राज्य सरकार ने 65 हजार बीघा एक गांव की जमीन आरक्षित कर रखी है। वहां पर एक बहुत बड़ी विद्युत कम्पनी अपना इन्वेस्टमेंट करेगी। भड़ला में सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। वहां के किसानों के एक दर्द को मैं सदन में बताना चाहता हूं कि वे पीढ़ियों से वहां पर बैठे हुए हैं और पहले तो डेजर्ट डवलपमेंट के नाम पर उनको अलाटमेंट नहीं किया, सात पीढ़ियों से वहां बैठे हुए हैं, वे कृषक हैं, वे पशुपालक हैं, वे ऊंटपालक हैं, उसके बाद वहां पर उपनिवेशन विभाग आ गया और उनको किसी प्रकार का अलाटमेंट नहीं किया। मैं इस सदन के मार्फत आग्रह करता हूं कि 65 हजार बीघा में से कम से 5 हजार बीघा उन कृषकों के लिए पशुपालन के लिए छोड़ दी जाए।

मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं माननीया वसुंधराजी का और मैं ऊंटपालक रहा हूं और ऊंट को जो राज्य पशु घोषित किया है, उसके बारे में दो शब्द कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। ऊंट ऐसा प्राणी है जिसने आप और हमको यह जीवन प्रदान किया है। ऊंट से राजस्थान की पहचान है। अगर ऊंट ना होता तो ये पीढ़ियां यहां पर आकर नहीं बैठतीं। ऊंट वह जीव है जो पांच दिन तक, सात दिन तक प्यासा रहकर, अकाल के जमाने में राजस्थान में उन पीढ़ियों को किस प्रकार से जिन्दा रखता था। आज भूजल का इतना दोहन करते हैं, उस समय भूजल प्राप्त नहीं होता था। ऐसी परिस्थिति में बरसात के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। बरसात नहीं होती थी, अकाल पड़ता था, अकाल में अनाज पैदा नहीं होता था तो सिन्ध से, ऊंटों के द्वारा लाना पड़ता था, इधर मालवा से लाना पड़ता था। यह ऊंट ही था जिसने इन पीढ़ियों को ये दिन देखने को दिये। माननीया वसुंधराजी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऊंट जैसे जानवर को आपने राज्य पशु घोषित किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: श्री रामपाल मेघवालजी।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आम बजट पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।

माननीया यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जो...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट विराजें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूरी होने तक बढ़ाया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्यसूची के सम्पूर्ण होने तक बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

आदरणीय सदस्य।

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रामपाल (बारां-अटरू): माननीया यशस्वी मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, सुराज संकल्प यात्रा के दौरान गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर, गत सरकार से पीड़ित लोगों के दु:ख दर्द जानकर, उनकी बुनियादी समस्या, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, इन सबको ध्यान में रखकर आम बजट जो पेश किया है, वह सर्वांगीण विकास और चहुंमुखी विकास वाला है, लोगों को राहत पहुंचाने वाला है और सराहनीय बजट है।

राजस्थान को देश में अग्रणी राज्य बनाने का भागीरथी प्रयास आपने किया है। गत सरकार ने राज्य को पिछड़ा राज्य बनाकर कर्ज के गर्त में धकेल दिया था। आपने उस राज्य को उबार कर अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने का जो प्रयास किया है, वह 'चलो जलायें दीप वहां, जहां अभी भी अंधेरा है', इस पंक्ति को मन में रखते हुए किया है।

माननीय सभापति महोदय, गत कांग्रेस सरकार ने बिजली के घाटे को चार गुणा बढ़ाकर, 15 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर, 75 हजार करोड़ रुपये किया और बदले में केवल चार घंटे बिजली भी नहीं दे पाई। माननीया मुख्य मंत्री जी ने सरकार संभालते ही किसानों को थ्री फेज आठ घंटे बिजली उपलब्ध कराई और 24 घंटे सिंगल फेज बिजली उपलब्ध कराई, जिससे आज आम

(श्री रामपाल)

जनता राहत महसूस कर रही है। आगामी पांच वर्षों में 6,500 मेगावाट विद्युत क्षमता स्थापित करने की घोषणा कर विद्युत क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने भरसक प्रयास किया है। साथ ही, 2014-15 में 40 हजार कृषि कनेक्शन जारी करना और आगामी समय में आवेदन के साथ ही कनेक्शन करना, एक सराहनीय कदम रहा है।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 1 लाख 21 हजार 133 गांवों की ढाणियों में बसे, राज्य में पशु-पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बड़ी चुनौती होने के बावजूद, 69,085 गांव-ढाणियों को पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु पांच लाख हैण्डपम्प व 6,523 जनता जल योजना पी.एच.ई.डी. और पंचायतों के माध्यम से करवाये। 800 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों में आर.ओ. संयंत्र लगाने और शुद्ध पेयजल देने की व्यवस्था करके इस आम जनता को राहत पहुंचाई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी ड्राई क्षेत्र घोषित कर रखा है जिससे उस अटरू की जनता ने बार-बार आंदोलन भी किये हैं। गहरे ट्यूबवेल करने के बावजूद भी वहां पानी निकालने में दिक्कत आती है। इसलिए ऐसी स्थिति में, पहले निवेदन भी किया था कि शेरगढ़ से या मायता बांध से यदि अटरू की जनता के लिए पेयजल की व्यवस्था हो जाती है तो उस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बारां जिले में बरसों से, गत चालीस वर्षों से लगातार बाढ़ नियंत्रण के लिए मांग उठती आ रही है और हर साल लाखों-लाखों रुपये की हानि होती आ रही है, उस ओर आपने ध्यान देकर 60 दिन की कार्ययोजना में बारां शहर को डायवर्जन चैनल के लिए 58 करोड़ 15 लाख रुपये की स्वीकृति जारी करके बहुत बड़ी राहत पहुंचाई है। साथ ही, अभी बारां में अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोला और 4.50 करोड़ रुपये के पक्के धोरे बनाने की भी घोषणा की। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपसे एक निवेदन और है। यदि बारां जिला केन्द्र पर मेडिकल कालेज की व्यवस्था हो जाये तो दूर-दराज से, गांव-

(श्री रामपाल)

गांव और ढाणी-ढाणी से आने वाली जनता के लिए एक सराहनीय कदम होगा और बीमारी से जूझने वाले प्रत्येक रोगी के लिए राहत महसूस होगी।

सिंचाई के लिए, माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन के माध्यम से सिंचाई परियोजना की घोषणा कर 35,000 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र को लाभान्वित किया जाना एक सराहनीय कार्य रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं, माननीय मेरे साथी हीरालालजी ने भी आपको अवगत करवाया और मैं भी चाह रहा हूं कि बारां जिले में अकावत-परवन वृहद परियोजना एक महती परियोजना है और किसानों के लिए अन्नदायी और सर्वांगीण विकास की योजना है। गत 30 सालों से इस मांग को बराबर उठाया जा रहा है। यह बारां, झालावाड़ और कोटा जिले के लगभग 313 गांवों को लाभान्वित करने वाली योजना है, लगभग 1.38 लाख हैक्टेयर जमीन सिंचित होगी और 50,000 किसान परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा, परन्तु गत कांग्रेस सरकार के शासन में इस योजना की बिना कुछ रूप दिये हुए, आनन-फानन में ही औपचारिकताएं पूरी करते हुए घोषणा कर दी गयी, जबकि इसकी कुछ शर्तें होंगी, वे पूरी नहीं हुई। तो मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करूं, इस योजना का जल्दी से जल्दी शुभारम्भ कर, इस पूरे क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए इस महती योजना का प्रयास करें।

शिक्षा के क्षेत्र में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने प्रत्येक ग्राम पंचायत पर माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर 4,900 ग्राम पंचायत केन्द्रों पर गांव के बालक-बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाने के लिए भरसक प्रयास कर इस महती योजना को लागू किया है। जिससे गांव के बालक-बालिकाएं, जो उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनके लिए एक बहुत ही लाभान्वित करने वाली योजना आपने प्रस्तुत की, इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं।

गत सरकार ने कमजोर वर्ग के 2,27,256 निजी विद्यालयों में बालकों को शिक्षा दिलाई, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 2014-15 में इसे बढ़ाकर 3.50 लाख विद्यार्थियों का भला किया है। यह एक सराहनीय कार्य आपका रहा है।

माननीया मुख्य मंत्रीजी को इस राजस्थान की यात्रा के दौरान कुछ नारे सुनने में आये होंगे, ''गौ-माता को जीने दो, दूध की नदियां बहने दो''

(श्री रामपाल)

उस नारे को अंगीकार करते हुए गोपालन विभाग की स्थापना की है। गौ-माता की करुण पुकार आपने सुनी और गौ-भक्तों के लिए, इस राजस्थानवासियों के लिए पुण्य कार्य आपने किया है। वह गौ-माता की दुर्दशा को ठीक करने का जो सराहनीय प्रयास किया है, उसके लिए मैं आपको शत-शत नमन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके द्वारा आने वाले वर्षों में 20,000 किलोमीटर की लम्बी सड़कें बनाकर गांवों का चहुंमुखी विकास करने का आपने जो लक्ष्य लिया है, उससे कृषि, उद्योग, व्यापार, सभी क्षेत्रों में तरक्की के अवसर प्रदान होंगे। 'गौरव पथ' और 250 से 499 तक की आबादी के गांव सड़कों से जोड़े जायेंगे। इससे हर गांव की तरक्की होगी, खुशहाली आयेगी और पूरा राजस्थान तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

आपने मुझे जो समय दिया, इसके लिए मैं पुन:-पुन: आप सभी का आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2014-2015 का परिवर्तित बजट जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 14 तारीख को पेश किया है, मैं इससे असहमत होते हुए, माननीय सभापति महोदय, आपकी मार्फत, सत्ता पक्ष के जो मंत्री महोदय बिराज रहे हैं, हमारे विधायक साथी बिराज रहे हैं, पहले सत्र में कांग्रेस का रोना रोया; हमने सोचा, हनीमून मना रहे हैं, इसलिए इनकी बात सुनो; आठ महीने होने जा रहे हैं, आज भी हमें गाली निकाल रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, अब कुछ करें, अब कुछ आगे बढ़ें, अब कुछ करो ताकि जिन मांगों को लेकर, जिन कामों को लेकर आपको वोट दिये थे, सुराज संकल्प यात्रा में जो वादे किये थे, उन वादों पर आगे बढ़ोगे, तब जाकर कुछ कर पाओगे।

यह जो बजट पेश किया गया है, इसका पहला ही पैरा है, उस पहले पैरा में एक विरोधाभासी बजट महसूस हो रहा है, बैलगाड़ी से मेट्रो की बात की जा रही है, दूसरी तरफ मेट्रो को नकारा जा रहा है। प्रधान मंत्री अहमदाबाद से मुम्बई तक बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं। यह जो जयपुर 40 किलोमीटर रेडियस में, लम्बाई में उत्तर-दक्षिण में 40 किलोमीटर है। आज यह बात कही जा रही है कि यह 2025 की जरूरत है। इस 2025 के विजन को

(श्री सुखराम विश्नोई)

सामने लेकर पिछली सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यह जो नेगेटिव बात कही जा रही है, एक किसान को पूछा गया कि गुलाब का फूल किस तरह से दिख रहा है? उस पोजिटिव आदमी ने बात कही कि कांटों के बीच में कितना बढ़िया गुलाब का फूल खिल रहा है; नेगेटिव वाले ने कहा कि फूल तो बढ़िया है, परन्तु कांटे बहुत हैं। इस मेट्रो में कांटे नहीं देखने हैं, कांटों के बीच में फूल देखना है।

इसके बाद में दूसरा पैरा बजट का आता है, उसमें आई आई टी, आई ए एस में राजस्थान के युवा सलेक्ट हुए हैं, उनको बधाई दी गई है, परन्तु मेरा यह मानना है कि जिस तरह से घोटाला हुआ है और उस घोटाले में, पिछले दो-तीन साल से चल रहा है, कई लोग जो गरीब किसान परिवार के बच्चे, जिन्होंने मेहनत करके परीक्षाएं दीं और परीक्षा के बाद इसलिए वंचित रह गये कि पैसों के बल पर उन लोगों ने जोइन कर लिया और आज कुछ वे जानते ही नहीं हैं। न जानते हुए आई ए एस, आर ए एस बनकर, डकैतों की तरह बैठकर, जो 20-20, 30-30 लाख रुपये उस अमृत लाल को दिये थे, वह वसूल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उसकी निंदा करता हूं। इसकी जांच सी बी आई से की जाये ताकि इस भर्ती घोटाले का मामला सामने आये।

इसके बाद में, यह जो दो कार्यकाल की बात की जा रही है, पिछले कार्यकाल में काम सही नहीं हुआ, हमने काम सही किया, मेरा माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि दोनों कार्यकाल का एक श्वेत पत्र जारी किया जाये ताकि पता चले कि किस तरह का कार्य 2007-2008 में हुआ और 2013-2014 में हुआ, ताकि सभी लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट हो जाये। मेरे सभी विधायक साथी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, वे आंकड़े कहीं मेल नहीं खा रहे हैं। हमने इस तरह से कर दिया, हमने इस तरह से कर दिया; कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया। इस बात को लेकर श्वेत पत्र जारी किया जाये ताकि सही स्थिति सामने आ जाये।

(19.00 बजे)

इसके बाद में, घाटे की जहां तक बात आ रही है, पहले घाटा कम था, उसके बाद में 15 से 27 हजार करोड़ के आसपास कर दिया; आज जो प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं, गुजरात के, मेरे पड़ोस में है और मार्च में उन्होंने, जो मोदीजी ने बजट पेश किया, उस गुजरात सरकार का जो घाटा था, वह 175 करोड़ का घाटा था। राजस्थान के बजट से भी ज्यादा घाटा था।

(श्री सुखराम विश्नोई)

आप गुजरात माडल की बात कर रहे हैं, राजस्थान से साढ़े तीन रुपये लीटर डीज़ल महंगा है, राजस्थान से यूरिया महंगी है, राजस्थान से बिजली महंगी है और जो गुजरात की सड़कों की बात कर रहे हों, हाइवेज से हटकर के आप गुजरात के गांवों में जाओ, गांवों की सड़क जाकर के देखो, राजस्थान से भी घटिया हालत में गुजरात की सड़कें हैं। जब आप गए नहीं हैं, तब गुजरात माडल की बात कर रहे हैं।

जहां तक वित्तीय प्रबंधन की बात है, वित्तीय प्रबंधन में आपने सभी पी पी पी मोड़ पर देने की बात कही है। सड़क परिवहन, जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसे डि-नेशनलाज किया जा रहा है और प्राइवेट बसों को, जो सरकारी डिपो है, उनकी अनुमति दी जा रही है। आज जो सरकारी बसें चल रही हैं, अगर आपने प्राइवेट कम्पनियों को, प्राइवेट ठेकेदारों को, उन लोगों को बसों के अन्दर, जहां पर भी जिला मुख्यालय पर परिवहन डिपो बना हुआ है, प्राइवेट लोगों को उस डिपो के अन्दर अनुमति दी गई तो सरकारी बसें फेल होंगी, परिवहन प्राइवेट लोगों के हाथों में जाएगा और वे मनमाने तरीके से पैसा वसूल करेंगे, भाड़ा वसूल करेंगे। जो एक व्यवस्था तीस से चालीस सालों से रोडवेज की बनी है, वह जान-बूझकर के फेल की जा रही है।

यह चैक-पोस्टों की जो बात की जा रही है, पिछली सरकार ने, माननीय सदस्य, हमारे सत्ता पक्ष के कह रहे थे कि हमने यह जो इंस्पेक्टर प्रणाली थी, उस इंस्पेक्टर राज को खतम करके और खतम करने के बाद में पिछली कांग्रेस सरकार ने वापस चैक पोस्टें जारी कर दीं। आपने उनसे हटकर के आगे काम किया। हमने तो कम से कम उस इंस्पेक्टर राज को वापस कायम किया था ताकि टैक्स की व्यवस्था चालू रहे, आपकी सरकार ने यह जो बजट पेश किया है, उन चैक पोस्टों पर कम्प्यूटर कौन लगाएगा? प्राइवेट आदमी कम्प्यूटर लगाएगा, वह ही पैसा वसूल करेगा। इससे दलाली होगी और भ्रष्टाचार होगा। तो मेरा, माननीय सभापति महोदय, निवेदन है, इस व्यवस्था वापस बंद किया जाए और सरकारी स्तर पर जो व्यवस्था चल रही है, उसको दुरुस्त किया जाए।

इसके अलावा, प्राइवेट हवाई चलेंगे; उसके बाद स्किल यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है। काफी सदस्यों ने बात की, स्किल्ड बनने के बाद में सब निहाल हो जाएंगे, 15 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। 15 लाख के

(श्री सुखराम विश्नोई)

रोजगार की बात करने वाली सरकार, 1 हजार रोजगार, जो माइंस डिपार्टमेंट में पुलिस भर्ती निकाली थी, वे छात्र, वे विद्यार्थी, जिन्होंने परीक्षा दी, परीक्षा पास की, रिजल्ट आ गया, उद्योग मैदान पर धरने पर बैठे हैं। केवल मात्र हजार की बात करें, बाबुओं की छह हजार की बात कर रहे हैं, उसके बाद में तृतीय शिक्षक भर्ती उनकी रोकी गई और रोकने के साथ-साथ, माननीय शिक्षा मंत्रीजी कह रहे थे कि 52 हजार शिक्षक सरप्लस हो रहे हैं। कहां तो शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हों और कहां सरप्लस बनाने की बात कर रहे हों! जब सरप्लस शिक्षक हो रहे हैं तो भर्ती का तो मामला बिलकुल बंद है। एक भी सरकारी नौकरी, आप कह सकते हों, सत्तापक्ष, कि हम इस तरह से लगाएंगे?

टीचर आप लगा नहीं सकते क्योंकि सरप्लस आपके खाते में चल रहे हैं। पुलिस का मामला है, आपने एक हजार जो माइंस में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की है, उन पर रोक लगा दी है। विद्यार्थी मित्र यह आपकी देन है, विद्यार्थी मित्र आप बी जे पी की देन है। विद्यार्थी मित्र जो चालीस हजार की तादाद में हैं, आज पूरे राजस्थान के विद्यार्थी मित्र इन सड़कों पर पड़े हैं। इस बदहाली में, इस गर्मी में, इस बरसात में इन सड़कों पर पड़े हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जो 15 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, वह नौकरी, मेरे हिसाब से, मनरेगा के अन्दर आप 15 हजार की नौकरी दे सकते हों, बाकी सरकारी स्तर पर स्किल्ड परसन को नौकरी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। केवल मात्र झूठे वादे करके, असत्य वादे करके सत्ता में आये हों।

मेरे सत्ता पक्ष के जो साथी हैं, वे साथी बड़े उतावले हो रहे हैं, जमीन से ऊपर चल रहे हैं और हमारे को गालियां दे रहे हैं कि आपने नहीं सुनी, तब आपकी यह हालत हुई है। मैं आज यह कहना चाह रहा हूं, अगर जिस तरह से आप बोल रहे हैं, जिस तरह से आप भाषण कर रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों के अन्दर व्यवहार कर रहे हैं, आज कम से कम दस तरह के धरने उद्योग मैदान में चल रहे हैं, यह जो व्यवहार आज आपका हो रहा है, यह हमारी जो हालत हुई है, आने वाले सालों में आपकी हालत होगी। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शमा परवाने को जलना सिखाती है; गिरने से या हारने से तकलीफ जरूर होती है, पर ठोकर आदमी को चलना सिखाती है। हम तो चलना सीख रहे हैं, पर आप चलना भूल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): राठौड़ साहब, सुनो तो सही। दुबारा बोलो आप यह डायलोग। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, इस बजट में कहा गया है कि हम टीम भावना से काम कर रहे हैं, कौनसी टीम भावना? आप टीम भावना से काम करने वाले जल संसाधन मंत्री को आप ढोहे चले जा रहे हों। अगर टीम भावना होती तो बहुत से होशियार मतलब बुद्धिमान लोग सत्ता पक्ष में बैठे हैं, ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य। सम्माननीय सदस्य। आखिरी कुछ पंक्तियां अंकित नहीं होंगी, जो माननीय सदस्य ने बोली हैं।

सम्माननीय अमृत लाल मीणाजी।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि हमारी यशस्वी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सदन के पटल पर 2014-15 का बजट पेश किया। हमारे इन तमाम क्षेत्रों को, प्रत्येक वर्ग को और प्रत्येक समाज के विकास की बात का, विकास के लिए बजट पेश किया।

हम उस क्षेत्र से आते हैं, पूरा क्षेत्र पहाड़ी है और पिछली सरकार के पांच वर्ष तक के कार्यकाल में सड़कों का हाल बेहाल है। लेकिन इस बजट में जो बीस हजार किलोमीटर का रोड बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उस क्षेत्र में वाकई में रोड का जाल बिछेगा। साथ में अठारह सौ करोड़ का जो प्रावधान किया है, आर सी सी रोड का और 0.5 से लेकर 2 किलोमीटर का, पहाड़ी इलाके में उबड़-खाबड़ इलाके में, यह विकास की गंगा का मार्ग आगे बढ़ेगा।

मेरा आपसे निवेदन है कि बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 80 बस अड्डों का सुधार करना, विस्तार करना और सभी प्रकार की जो व्यवस्था की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, वे धन्यवाद की पात्र हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा 'टैट' के स्थान पर 'रीट' का जो शुरू किया, हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है, शिक्षा का काफी अभाव है और एक ही परीक्षा देकर के हमारे सभी छात्रों का भविष्य काफी उज्ज्वल होगा।

जहां तक हर पंचायत समिति क्षेत्र में आई टी आई खोलने का जो बजट में सम्मिलित किया है, राज्य में तीन नये इंजीनियरिंग कालेज खोलने की बात कही है और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस सरकार में 31.3.2009 से उस

(श्री अमृतलाल)

क्षेत्र के तमाम किसानों को कनेक्शन नहीं मिला और अभी हमारी माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने 2014-15 में चालीस हजार किसानों को कनेक्शन देने का जो बजट तैयार किया है और सभी प्रकार के, 400 के, वी के, 220 के वी के, 132 के वी के, 33 के वी के जो सब-स्टेशन बनाये जाएंगे, उनसे किसानों को और सभी को अधिक फायदा मिलेगा।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पेयजल की जो व्यवस्था की है, 3,173 नये गांवों को पानी से जोड़ने की और स्वच्छ पानी, जिसमें विशेष करके अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, मेवात के लिए जो प्रावधान बजट में किया है, वह वाकई में धन्यवाद लायक है। इनको मिलना चाहिए था, उनके इन समाजों का ख्याल रखा और 23,956 गांवों को, जिनकी संख्या 800 की हो, उनमें आर ओ की व्यवस्था करना, यह बहुत सराहनीय है। हर वर्ग के लिए और ग्रामीण आधार पर मूलभूत संरचना में योजनाएं हैं, ग्रामों में स्वच्छ पानी मिले, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, विद्युत योजना की बात हो।

मेरा आपसे निवेदन है कि मैं उस क्षेत्र से आता हूं, जो महाराणा प्रताप की कर्मभूमि है, हाड़ा रानी ने अपना सिर कटवाया था। मेरा विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर है और उस विधान सभा क्षेत्र के लिए मेरी कुछ मांगें हैं। विश्व की सबसे प्रसिद्ध झील जयसमन्द झील है, मीठे पानी की, उसको हरा-भरा रखने के लिए, भरने के लिए अगर कोई व्यवस्था होती है, बजट में अगर सम्मिलित किया जाता है तो तमाम उस जनजातीय क्षेत्र में सही कार्य होगा।

दूसरा, माननीय सभापति जी, हाड़ा रानी का जो महल है, वर्षों पुराना महल है। पर्यटन की दृष्टि से उसके सारे गौरवों, महल का अगर सही जीर्णोद्धार किया जाए और महाराणा प्रताप की कर्मभूमि और स्मारक और समाधिस्थल को विकसित करके, जयसमन्द की विश्वविख्यात मीठे पानी की झील को, चारों को पर्यटन के नक्शे पर अगर लाया जाए, तो काफी विदेशी लोगों का आकर्षण होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापतिजी, समूचे क्षेत्र में शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाए।

पूर्व सरकार के शासन में राजकीय महाविद्यालय, सराड़ा खोला था; एक हायर सेकण्डरी का, जो दो कमरों में चल रहा है। इन्होंने बजट भी घोषित किया, लेकिन अभी तक वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई।

(श्री अमृतलाल)

अंत में, इन्होंने उस आदिवासी क्षेत्र को भ्रमित किया। साड़ियां बांटने का काम किया; पत्थर लगाने का काम किया; दारू बांटने का काम किया। पिछले तीस-चालीस साल से कांग्रेस का वहां का एम एल ए था, अंत में जनता ने इनको धिक्कारते हुए भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखा, वसुन्धरा जी, हमारी मुख्य मंत्रीजी में विश्वास रखा। धन्यवाद। जय हिन्द। जय राजस्थान।

श्री सभापति: श्री ललित कुमार मीणा।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में नया हूं और पहली बार बोल रहा हूं। मेरे को आपने सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

आपके माध्यम से सोमवार को माननीया हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जो 2014-15 का आम बजट, चौदहवीं विधान सभा का पहला बजट प्रस्तुत किया, वह अपने आप में एक पूरे राजस्थान को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने वाला एवं सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए, उसको विकास की गति को देते हुए, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने वाले सिद्ध होगा। इस बजट के माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कृषि क्षेत्र, विद्युत, हमारे उद्योग, शिक्षा, मेरे युवा भाइयों को और विधवाओं को, हमारे बुजुर्गों का, सबका ध्यान रखते हुए हर डिपार्टमेंट में उनका फोकस रहा। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

अब मैं सबसे पहले जो मूल बात है बजट की, उन पर आना चाहूंगा। सबसे पहले मैं सड़क, जो परिवहन का राजस्थान में एक सबसे सशक्त साधन है, उसके लिए, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो बीस हजार किलोमीटर सड़कों के लिए जो एक अथोरिटी का गठन किया है जिससे आगामी आठ वर्षों तक उनको बनाने का, उनका रिप्लेसमेंट का जो कार्य होगा, उससे पूरे तंत्र को बहुत मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा माननीया मुख्य मंत्रीजी ने हमारे एयरवेज, जो पवनहंस हमारा क्रम है, उस उपक्रम के माध्यम से एयर टैक्सी। मान लीजिए, कोई बीमार होता है, किसी को भी कोई जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए उन्होंने विशेष एम ओ यू किया है, ताकि दोनों को आगे बढ़ाया जा सके।

इसमें आर एस एच ए, राजस्थान स्टेट हाईवेज अथोरिटी का गठन

(श्री ललित कुमार)

करके माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सड़कों के रख खाव और उनकी लम्बाई के लिए, उनकी वाचिंग के लिए गठन किया है, उसके लिए मैं बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक लाख किलोमीटर की ओ डी आर और विलेज रोड्स हैं, जो कनेक्टिविटी है, उनके लिए प्रावधान किये हैं, उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

सड़क और एयरवेज के माध्यम से, एयरवेज में पूरे राजस्थान में 16 पट्टियां हैं। उनके रखरखाव के लिए और उसको आगे बढ़ाते हुए, हमारी एयर कम्पनियां हैं, उनको बाहर से यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित किया है। उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। केवल अभी जयपुर, जोधपुर और उदयपुर हमारे राष्ट्रीय लेवल पर एयरवेज से कनेक्टेड हैं। इनको इससे मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा, ऊर्जा क्षेत्र में मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो 400 केवी के तीन पूरे राजस्थान में प्रपोज किये हैं, 220 केवी के ग्रिड 9 स्वीकृत किये हैं, 132 केवी के 11 किये हैं, 33 केवी के 220 किये हैं, यह ऊर्जा के क्षेत्र में एक विशेष और अच्छी पहल है। मैं यह पिछले कार्यकाल में, माननीया मुख्य मंत्री के, पूरे राजस्थान में थर्मल पावर, अडानी पावर जो एस्टेब्लिश किये हैं उससे ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हुई है। उसी को इस बार अपग्रेड करते हुए, 900 किलोवाट और विद्युत को बढ़ाने के लिए छबड़ा थर्मल दिया है।

मेरे क्षेत्र में भूसे से जो बिजली बनती है, उसका प्लांट पिछले कार्यकाल में बना था, उससे भी मेरे क्षेत्र में मुझको फायदा हुआ है।

ऊर्जा के क्षेत्र में एन टी पी सी जो केन्द्र सरकार की एक एजेंसी है, पावर ग्रिड उसको सप्लाई करती है, उसी तरह राजस्थान जे वी एन एल, जो लाइट का काम देखती है एन टी पी सी की तरह, उत्पादन का, उसका प्रोडक्शन प्रसार, राजस्थान विद्युत प्रसारण के लिए 10 प्रतिशत प्रावधान किया है, उससे विद्युत उत्पादन और प्रसारण में आने वाले पांच साल में जो गति आएगी, वह अविश्वसनीय रहेगी।

25 हजार क्षमता स्थापित करने का, बनाने का जो प्रयास रहा है, वह वास्तव में, मुख्य मंत्रीजी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि इससे हमारा ऊर्जा क्षेत्र लाभान्वित होगा और बढ़ेगा।

(श्री ललित कुमार)

पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में 8 33 के वी, 2 132 के वी सब-स्टेशन बनें। उसके बाद, पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में कोई एक ग्रेड-अपग्रेड नहीं हुआ है, कोई उपलब्धि नहीं आई है। मेरे भाई यहां पर विपक्ष में यह कहते है कि हमने यह किया, परन्तु आप जमीनी हकीकत पर यह देखें, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र वार, प्रत्येक क्षेत्रवार कि आपने किस क्षेत्र में क्या-क्या दिया।

मैं इसी में आगे पेयजल के लिए कहना चाहूंगा, 3,173 नये गांव और ढाणियों को पेयजल की सुविधा के लिए बजट का प्रावधान किया है, उसमें 570 गांव अनुसूचित जाति और 390 गांव अनुसूचित जनजाति और इसी में 100 गांव अल्पसंख्यक बाहुल्य, इन जातियों के हैं। वहां पर पेयजल के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया है। आर ओ का अलग से प्रावधान किया है, ताकि शुद्ध पेयजल, सभी पंचायती स्तर, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक अच्छी व्यवस्था हो सके।

इसके अलावा, जल संसाधन, इर्रिगेशन में, मैं यह बता दूं कि हमारे किसान भाई, उन किसान भाइयों पर, सबसे प्रथम फसल के लिए, हमारी कन्ट्री की, हमारे देश की, हमारे राजस्थान की जो इकोनोमी है, वह 70 प्रतिशत एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। आज एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, हमको हमारी, जी बी डी पी हमारी ग्रोथ बढ़ानी है तो हमको एग्रीकल्चर पर ध्यान देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर से आप नीचे जाएंगे, तो आपको सबसे पहले आपके इर्रिगेशन, आपको अपने जल संसाधन, जो आपका तंत्र है वाटर का, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा।

हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने नदियां जोड़ने का उस समय सपना देखा था, उसको यू पी ए सरकार ने कार्यक्रम को ठण्डे बस्ते में डाल दिया। उसी को लेते हुए, हमारी माननीया यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने एक प्रयास किया है कि राजस्थान के साउथ-ईस्ट में हाड़ौती पठार में हमारी पार्वती, कालीसिंध और परवन जो कुछ नदियां पड़ती हैं, इनको इन्टर-कनेक्ट करके एक पानी का स्रोत, जो हमारा पानी बह जाता है, उसको आपस में मिलाकर नहरी तंत्र डवलप किया जाए ताकि एग्रीकल्चर का जो हमारा बेस लेवल है, उसको मजबूत करते हुए किसान को मजबूत किया जाए। इसलिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लाइट के बिना रह सकते हैं आप

(श्री ललित कुमार)

रोड के बिना रह सकते हैं, पर आप एग्रीकल्चर, खेती किससे होगी, खेती के लिए पानी, वह सबसे बड़ी हमारी आवश्यकता है।

राजस्थान आज पूरे विश्व में थार के रेगिस्तान से जाना जाता है । अगर थार के रेगिस्तान को भी, अपन को मेहनत करके यह दिखाना होगा। वह इसी प्रकार हो सकता है कि हम हमारी विश्व की सबसे बड़ी कैनाल, इंदिरा गांधी, गंग कैनाल, ये जो कैनालें हैं इनको आप जोडकर, राजस्थान के थार, हमारा रेगिस्तान है, इसको हरा-भरा कर सकते हैं। इसी में पहल करते हुए, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इंदिरा गांधी थार योजना, इंदिरा गांधी कैनाल के लिए विशेष पैकेज दिया है।

साउथ ईस्ट हमारा हाड़ौती पठार माना जाता है, राजस्थान को चार भागों में बांटने के बाद जो हमारा साउथ ईस्ट पार्ट आता है, कोटा, बूंदी, झालावाड, जहां पर खेती की सबसे बड़ी उपज, सरसों, सोयाबीन, धनिया, यह कृषि प्रधान हब माना जाता है। इसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहां पर सरकार में आते ही, उन्होंने विश्वास किया कि जो इन्टर-कनेक्टिविटी है नदियों की, जो तीन-चार नदियां इस रीजन में हैं उनको जोड़ा जाए और इस क्षेत्र का डवपलमेंट है, एग्रीकल्चर का, उसको और बढ़ाया जाए।

इसके बाद, आगे मेरे क्षेत्र की जो लंबी सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनकी ओर थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जापान इन्टरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी द्वारा घोषित राजस्थान लघु सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत माननीया मुख्य मंत्रीजी की यह बहुत बड़ी पहल है। जापान दूसरे विश्व युद्ध में खतम हो गया था। उस जापान ने 50-60 साल में आज अपने आपको एस्टेब्लिश किया है। जापान हमारे राजस्थान का एक तिहाई, मतलब, आपका जरा सा है, आज वह जापान विकसित राष्ट्रों में खड़ा है। माननीया मुख्य मंत्री जी ने जापान इन्टरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी के द्वारा जो लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं, पूरे राजस्थान की 60 योजनाएं, उप-योजनाएं, 2014-15 के इस वर्ष में करने के लिए जो प्रावधान किया है, यह एक बहुत बड़ी सराहनीय उपलब्धि है।

झालावाड़ में, मैं और धन्यवाद देना चाहूंगा माननीया मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने भीमसागर डैम पर 5 करोड़ रुपए देकर नहरी सुदृढ़ीकरण में इर्रिगेशन डिपार्टमेंट में एक अलग पहल की है।

(श्री ललित कुमार)

इसके अलावा, मेरे क्षेत्र में पिछले कार्यकाल में, बी.जे.पी. के, भारतीय जनता पार्टी के, जब मुख्य मंत्रीजी का कार्यकाल था, उस समय हमारी नारायण खेड़ा लघु सिंचाई परियोजना, जिससे चार गांव लाभान्वित हुए। हमारी सेमली फाटक सिंचाई परियोजना, हमारी हत्याधर, ये जो सिंचाई परियोजनाएं, छोटी-छोटी सिंचाई परियोजनाएं थीं, उनको विकसित करके, चार-चार, पांच-पांच गांव हुए हैं, आज उन गांवों में सिंचाई हो रही है। परन्तु उनका जो नहरी डवलपमेंट था, वह पिछली सरकार ने आते ही, उनका पैसा भी लैप्स हो गया और उनका कोई डवलपमेंट नहीं हो पाया। माननीया मुख्य मंत्रीजी को, माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी तरफ से अवगत करवाना चाहूंगा कि जो वे हमारी लघु सिंचाई परियोजनाओं के डैम, जो पिछले कार्यकाल में बने, उनको नहरी तंत्र के द्वारा मजबूत किया जाए ताकि पानी टेल तक पहुंच सके और किसान को फायदा पहुंच सके।

इसी प्रकार, मेरे क्षेत्र की अहमदी सिंचाई परियोजना जो 22 हजार करोड़ की थी परन्तु फोरेस्ट डिपार्टमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की पालिसीज के कारण वह अभी तक लम्बित है। हमारी सरकार ने पिछली बार 2008 में वन विभाग को, हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट और फोरेस्ट डिपार्टमेंट को जो कुछ पैसा देना था, 18 करोड़ रुपए, वह दे दिया। वह देने के बाद, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से और फोरेस्ट डिपार्टमेंट से, वहां से एन.ओ.सी. चाहिए थी परन्तु पिछले पांच साल में अहमदी सिंचाई परियोजना से 12 गांव लाभान्वित होते, वह सब कुछ, उस परियोजना में हमको केवल वहां से एन.ओ.सी. लानी थी; पिछले पांच साल में उस सिंचाई परियोजना में कांग्रेस सरकार ने एक कदम नहीं उठाया।

माननीय सभापति महोदय, बारां जिले से पूर्व मंत्री आते हैं, दो साल वे मंत्री रहे, कई आरोप लगे, इस कारण से शायद वे बीच में रह गये।

मैं शार्ट में अपनी बात रखूंगा। इसके अलावा, मेरा दाढ़ी, राड़ी बांध, जो 22 गांवों को सिंचित करता है और हत्याधर मेरे 32 गांवों को सिंचित करता है, यह भी मेरा फोरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से अटका हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को अवगत कराउंगा कि मेरी इन तीनों सिंचाई परियोजना को लेते हुए आगे बढ़ायें।

इसी में मैं सबसे बड़ी चीज, जो मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में दी है,

(श्री ललित कुमार)

मेरे युवा भाइयों के लिए, उसके लिए मैं सदन के सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीया मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि जो पिछला कार्यकाल मुख्य मंत्रीजी का था, उस समय 38 हजार नौकरियां माननीया मुख्य मंत्रीजी ने दी थीं। उस समय थ्रेड ग्रेड टीचर में 38 हजार नौकरियां, एक-एक परिवार से दो-दो, कोई भाई-बहन, कोई पति-पत्नी, टीचर बने थे। उसी उपलब्धि ने माननीया मुख्य मंत्रीजी को पांच साल तक, पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारी मुख्य मंत्रीजी को याद रखा कि वे होतीं तो हमको नौकरियां देतीं।

आज मैं विपक्ष में बैठे हमारे भाइयों को यह कहना चाहूंगा कि आपकी जितनी भी वैकेंसीज थीं, आपकी फर्स्ट ग्रेड की, आपकी सैकण्ड ग्रेड की, आपकी थर्ड ग्रेड की, वे कहीं न कहीं आज कोर्ट में लम्बित हैं। वे क्यों कोर्ट में लम्बित हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बताओ।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): आपकी वजह से। आपकी नर्सिंग ट्यूटर ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, सात महीने हो गये, आप बताओ। (व्यवधान)

श्री ललित कुमार (किशनगंज): मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आपके नर्सिंग ट्यूटर की जो वैकेंसी, ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, अंगुली से धमका रहे हैं, ऐसे-ऐसे। (व्यवधान)

श्री सभापति: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई 2014 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.35 बजे गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई 2014 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

पाली जिले में अन्न सुरक्षा योजना से लाभान्वित परिवार

34. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार की अन्न सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पाली जिले की किस-किस तहसील में कितने-कितने गेहूं की आवश्यकता है?

(2) उक्त योजना में लाभान्वित परिवार को प्रति माह प्रति सदस्य कितना-कितना गेहूं देने का प्रावधान है तथा वर्तमान में कितना-कितना गेहूं दिया जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रावधानानुसार प्रत्येक व्यक्ति को दिये जाने वाले गेहूं की मात्रा की अपेक्षा कम गेहूं की आपूर्ति की जा रही है, जिससे अनेकों परिवारों को गेहूं से वंचित रहना पड़ रहा है?

(4) क्या सरकार उक्त योजना में प्रति सदस्य को प्रावधानानुसार गेहूं की आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार की अन्न सुरक्षा (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा) योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों की आनलाइन सूची अनुसार पाली जिले की तहसीलों में गेहूं की आवश्यकता निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	नाम तहसील	खाद्य सुरक्षा योजना में कुल गेहूं की आवश्यकता (क्विंटल)
1	जैतारण	9081
2	सोजत	9682
3	रायपुर	8730
4	रोहट	4956
5	मारवाड़ जंक्शन	7447
6	पाली	8112
7	देसूरी	6318
8	रानी	4500
9	बाली	12474
10	सुमेरपुर	7537
	कुल योग	**78837**

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

(2) उक्त योजना के तहत अन्त्योदय परिवारों को प्रति परिवार 35 किग्रा. खाद्यान्न एवं अन्य पात्र परिवारों को प्रति व्यक्ति 05 किग्रा. प्रति माह खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रावधान है। जिले को प्राप्त प्रति माह आबंटित मात्रा का समानुपातिक रूप से सभी लाभार्थियों को वितरण करवाया जा रहा है।

(3) राज्य में 2 अक्टूबर, 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो गई है जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार ग्रामीण क्षेत्र में कुल जनसंख्या के 69.09 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र में कुल जनसंख्या के 53.00 प्रतिशत अधिकतम परिवार शामिल किये जा सकते हैं। पाली जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार शहरी क्षेत्र में 2,43,803 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 10,89,941 कुल 13,33,744 लाभार्थियों का चयन किया जाना था, जिसके अनुपात में जिले द्वारा शहरी क्षेत्र हेतु 1,99,337 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 14,36,474 कुल 16,35,811 लाभार्थियों का चयन किया गया है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पाली जिले को प्रति माह शहरी क्षेत्र हेतु 1,024 मै. टन एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 5,694 मै. टन कुल 6,718 मै. टन गेहूं का आबंटन किया जा रहा है।

(4) भारत सरकार द्वारा 446 लाख लाभार्थियों के हिसाब से गेहूं का आबंटन किया जा रहा है, जबकि राज्य में लगभग 531 लाख लाभार्थियों का चयन किया गया है। योजना की समीक्षा कर अपात्र व्यक्तियों को चयनित सूची में से कम किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विराटनगर के चिकित्सालयों में स्त्री रोग चिकित्सकों के रिक्त पद

35. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के राजकीय चिकित्सालयों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के कितने पद स्वीकृत हैं? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश के चिकित्सालयों में स्त्री रोग विशेषज्ञ के

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं अन्य के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां?

(4) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के अन्तर्गत आने वाले सिर्फ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विराट नगर में स्त्रीरोग विशेषज्ञ का 1 पद स्वीकृत है जिस पर डा. सुरेश कुमार सहरिया चिकित्सा अधिकारी, पी जी गायनी, पदस्थापित हैं।

(2) जी हां। प्रदेश के चिकित्सालयों में रिक्त स्त्री रोग विशेषज्ञ के पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबंध हटने अथवा स्त्री रोग में पी जी चिकित्सक उपलब्ध होने पर प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र विराट नगर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के 10 एवं अराजपत्रित संवर्ग के 51 पद रिक्त हैं, जिनका चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को डी ए सी पी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

महिला स्वास्थ्य दर्शिका एवं वरिष्ठ लिपिक के पद पदोन्नति के हैं, जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सूचना सहायक, लैब टेक्नीशियन, वार्ड बाय एवं सफाई कर्मचारी के रिक्त पदों को स्थानान्तरण अथवा विभागीय भर्ती के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों एवं अराजपत्रित संवर्ग के रिक्त पदों का संख्या विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थाओं का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विराटनगर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)	1
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)	1
		चिकित्सा अधिकारी	2
		सूचना सहायक	2
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पावटा	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		सूचना सहायक	2
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मैड	चिकित्सा अधिकारी	1
		नर्स श्रेणी-द्वितीय	1
		वार्ड बाय	3
		सफाई कर्मचारी	1
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलेसर	चिकित्सा अधिकारी	1
		नर्स श्रेणी द्वितीय	1
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		सूचना सहायक	1
		वार्ड बाय	1
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जयसिंहपुरा	चिकित्सा अधिकारी	1
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1
		वार्ड बाय	2
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़नगर	सूचना सहायक	1
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पांचूड़ाला	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1
		सफाई कर्मचारी	1

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थाओं का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंतेला	वरिष्ठ लिपिक	1
		वार्ड बाय	1
		सफाई कर्मचारी	1
9.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रागपुरा	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
10.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भाभरू	वार्ड बाय	1
		सफाई कर्मचारी	1
11.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागावास अहिरान	महिला दर्शिका	1
12.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तेवड़ी	नर्स श्रेणी-द्वितीय	2
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		लैब टैक्नीशियन	1
		वार्ड बाय	2
13.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लुहाकना कलां	नर्स श्रेणी-द्वितीय	2
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		लैब टैक्नीशियन	1
		सूचना सहायक	1
		वार्ड बाय	1
14.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुधीआमलोदा	नर्स श्रेणी-द्वितीय	2
		महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
		लैब टैक्नीशियन	1
		सूचना सहायक	1
		वार्ड बाय	2
15.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, साईवाड़	नर्स श्रेणी-द्वितीय	1
		वार्ड बाय	2

कोटड़ा उप खण्ड (उदयपुर) के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

36. श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री प्रताप लाल भील)

(1) उप खण्ड कोटड़ा (उदयपुर) के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उप खण्ड कोटड़ा (उदयपुर) में प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के 938 पद स्वीकृत एवं 344 पद रिक्त हैं। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 220 स्वीकृत तथा 147 पद रिक्त हैं।

(2) जी हां। रिक्त पदों को भरने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में नवीन गैस कनेक्शन के मानदण्ड

37. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में नये गैस कनेक्शन के लिए क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

(2) क्या गैस कनेक्शन के साथ गैस चूल्हा लेना जरूरी है? यदि नहीं, तो जो एजेन्सियां गैस कनेक्शन के साथ उपभोक्ता को जबरन चूल्हा बेच रही हैं, उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार ऐसी एजेन्सियों का लाइसेन्स निरस्त करने का कानून बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नये गैस कनेक्शन के लिए निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। गैस कनेक्शन के साथ जबरन गैस चूल्हा बेचे जाने पर द्रवित पैट्रोलियम गैस (वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के बिन्दु 3 (4) के अन्तर्गत पाबन्दी है। यदि कोई एजेन्सी चूल्हा खरीदने के लिए उपभोक्ता को बाध्य करती है, तो उसके विरुद्ध राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश, 1990 के बिन्दु 11 के अन्तर्गत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा तथा मार्केटिंग डिसीप्लीन गाइडलाइन्स, 2014 के

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

तहत तेल कम्पनियों द्वारा कार्यवाही की जाती है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। ऐसे प्रकरणों में कार्यवाही करने हेतु प्रावधान बिन्दु संख्या 2 में प्रदत्त विवरणानुसार पूर्व से ही विद्यमान है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में संचालित 108 एम्बुलेंस सेवा

38. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत पांच वर्षों में प्रदेश में मरीजों को आपातकालीन सेवा देने वाली एम्बुलेंस 108 सेवा कहां-कहां संचालित की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एम्बुलेंस वाहन में चिकित्सा सुविधा हेतु कौन-कौन से उपकरण/दवाइयां किस कम्पनी से खरीदी जाती हैं? उक्त कम्पनी को सरकार द्वारा गत 3 वर्षों में कुल कितना भुगतान किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक उक्त वाहनों द्वारा कुल कितने मरीज लाये गये व कितने किलोमीटर की दूरी तय की गई? उक्त एम्बुलेंस में चिकित्सा सुविधा हेतु कितना स्टाफ स्वीकृत है और उक्त स्टाफ किनके नियंत्रण में काम करता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त वाहनों हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त वाहन लक्ष्य पूर्ण कर रहे हैं?

(5) बारां जिले में उक्त वाहनों हेतु कितने डाक्टर पदस्थापित हैं तथा वाहनों की निगरानी व दवाइयां किस प्रकार उपलब्ध करवाई जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सितम्बर 2008 में 108 आपातकालीन सेवा का संचालन शुरू हुआ। विगत पांच वर्षों में प्रदेश में मरीजों को आपातकालीन सेवा देने वाली एम्बुलेंस 108 सेवा की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त एम्बुलेंस में चिकित्सा सुविधा हेतु खरीदे जाने वाले उपकरण एवं दवाओं का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा सुविधा हेतु परिशिष्ट-ब में वर्णित दवाइयां एवं उपकरण सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा ही क्रय किये जाते थे, जिनका पुनर्भरण एन आर एच एम द्वारा प्रति माह किया जाता था। उक्त उपकरण जिन कम्पनियों से क्रय किये जाते थे, उनकी सूची एवं उक्त कम्पनियों को गत दो वर्षों (जुलाई 2010 से मार्च 2012 तक) में किये गये भुगतान रुपये 3.25 करोड का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

अप्रैल, 2012 से 6 मई, 2013 तक जेड एच एल को मेडिकल एवं नान-मेडिकल कंज्यूमेबल्स के पेटे कोई भुगतान नहीं किया गया है।

इसके पश्चात् नये अनुबन्ध के तहत ई.एम.आर.आई., हैदराबाद के साथ 23 मई, 2013 को एग्रीमेन्ट साइन किया गया। ई.एम.आर.आई. को प्रति एम्बुलेंस रु. 1,12,500/- प्रति माह की दर में मेडिकल एवं नान-मेडिकल कंज्यूमेबल्स का खर्च भी सम्मिलित है, जिसकी सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक लाभार्थियों एवं ट्रिप की संख्या का विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है। इन वाहनों द्वारा वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक 4,80,90,734 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

उक्त एम्बुलेंस में सेवा प्रदाता कम्पनी के साथ हुए समझौते के अनुसार चिकित्सा सुविधा हेतु एक पायलट (वाहन चालक) तथा एक ई एम टी (जी एन एम/बी.एस.सी. नर्सिंग) 24 गुणा 7 ड्यूटी के लिये उपलब्ध रहना आवश्यक है। समस्त 108 सेवा की एम्बुलेंसों पर कार्यरत पायलट एवं ई एम टी, सेवा प्रदाता कम्पनी ई एम आर आई के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं तथा उन्हीं के अधीन कार्यरत हैं।

राज्य स्तर पर परियोजना निदेशक, एन आर एच एम एवं सलाहकार 108, एन आर एच एम तथा जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 108-एम्बुलेंस सेवा की निगरानी की जाती है।

(4) जी हां। यह सही है कि उक्त वाहनों हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आर एफ पी के तहत औसत 5 ट्रिप/प्रति एम्बुलेंस/प्रतिदिन होना अनिवार्य है। सेवाओं के नियमित संचालन एवं मानिटरिंग हेतु जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से सेवा प्रदाता कम्पनी को संचालन व्यय का भुगतान

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

प्रति माह जिले में संचालित एम्बुलेंसों के औसत संचालित ट्रिपों के आधार पर किया जाता है। जिलेवार पांच ट्रिप प्रति एम्बुलेंस प्रतिदिन प्रतिमाह पूर्ण नहीं होने की स्थिति में भुगतान में से आनुपातिक कटौती की जाती है।

(5) राज्य में तैनात सभी 649 एम्बुलेंस, बैसिक लाइफ सपोर्ट (बी एल एस) एम्बुलेंस है, जिनमें डाक्टर के पदस्थापन का प्रावधान नहीं है। प्रत्येक एम्बुलेंस में फर्स्ट एड एवं मरीजों/घायलों को निकटतम अस्पताल तक पहुंचाने के लिये एक ई एम टी (इमरजेंसी मैनेजमेंट टेक्निशियन) एवं एक पायलट (वाहन चालक) का प्रावधान है। सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा प्रत्येक एम्बुलेंस में 24 गुणा 7 सेवा के लिये ई एम टी एवं पायलट पदस्थापित हैं। ई.एम.आर.आई. को प्रति एम्बुलेंस रु. 1,12,500/- प्रति माह की दर में मेडिकल एवं नान-मेडिकल कंज्यूमेबल्स का खर्च भी सम्मिलित है। राज्य स्तर पर परियोजना निदेशक, एन आर एच एम एवं सलाहकार 108, एन आर एच एम तथा जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा 108-एम्बुलेंस सेवा की निगरानी की जाती है।

(सूचियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

राजसमन्द जिले के पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना

39. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजसमन्द जिले में विधान सभा क्षेत्रानुसार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? यदि नहीं, तो किन-किन पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं?

(2) जिन पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, वहां पर इन्हें प्रारम्भ करने की सरकार की क्या कार्य योजना है?

(3) जिले के किस-किस पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय हैं एवं किस-किस पंचायत मुख्यालय पर विज्ञान विषय नहीं है?

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(4) क्या यह सही है कि सुराज संकल्प घोषणा पत्र में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर विज्ञान विषय के साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय आरम्भ करने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी क्रियान्विति कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। जिला राजसमन्द में विधान सभा क्षेत्रानुसार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजकीय उच्च माध्यमिक अथवा राजकीय माध्यमिक स्तर का विद्यालय संचालित है। इसकी सूचना परिशिष्ट-"क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजकीय उच्च माध्यमिक अथवा राजकीय माध्यमिक स्तर का विद्यालय संचालित है।

(3) जिला राजसमन्द के 10 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर संचालित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान विषय संचालित है तथा जिले में 79 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान विषय संचालित नहीं है। विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(सूचना व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रतापगढ़ जिले में राशन डीलरों द्वारा वितरित सामग्री

40. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रतापगढ़ जिले में विगत एक वर्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जिला रसद कार्यालय को कौन-कौन सी सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में प्राप्त हुई? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत एक वर्ष में जिला प्रतापगढ़ में किस-किस राशन डीलर को कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस सामग्री का आबंटन किया गया? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में विगत एक वर्ष में किस-किस राशन डीलर द्वारा किस-किस श्रेणी के कितने राशन कार्डों पर कितनी-कितनी सामग्री का वितरण किया गया? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ जिले को माह अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 तक आबंटित सामग्री का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रतापगढ़ जिले में राशन डीलरों को माह अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 तक आबंटित खाद्यान्न, गेहूं एवं चीनी, इत्यादि सामग्री का विवरण परिशिष्ट-2 पर, आबंटित केरोसीन का विवरण परिशिष्ट-3 पर एवं माह अप्रेल, 2013 से सितम्बर, 2013 तक (आटे का आबंटन माह अक्टूबर, 2013 से बन्द होने के कारण) आबंटित ए पी एल आटे का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) प्रतापगढ़ जिले में श्रेणीवार राशनकार्डों की संख्या का राशन डीलरवार विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

माह अप्रैल, 2013 से मार्च, 2014 तक राशन डीलरों द्वारा खाद्यान्न गेहूं, आटा, लेवी चीनी व केरोसीन, इत्यादि के वितरण का विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में डोडा पोस्त सेवन पर रोक हेतु कार्य योजना

41. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान में अफीम व डोडापोस्त का सेवन करने से नशा करने की प्रवृत्ति बढ़ी है? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने एवं नशा-मुक्ति हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नशा-मुक्ति के लिए केन्द्र सरकार भी राज्य सरकार का सहयोग कर रही है? यदि हां, तो किस प्रकार तथा क्या नशा-मुक्ति हेतु अन्य संस्थाओं को भी कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पश्चिमी राजस्थान में अफीम व डोडापोस्त व्यसनियों की संख्या अधिक है।

राज्य में अफीम व डोडापोस्त के रोगियों को नशा-मुक्त करने के

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

लिए राज्य सरकार द्वारा कार्य योजना बनाई जा रही है, जिसके अन्तर्गत अधिक प्रभावित जिलों के जिला अस्पताल एवं मेडिकल कालेजों में डोडापोस्त व्यसनियों को शिविर लगाकर नशा-मुक्त करने का प्रयास किया जायेगा।

(2) नशामुक्ति कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा ही संचालित किया जाता है। योजना के अन्तर्गत एन.जी.ओ. एवं सभी का सहयोग लिया जाना प्रस्तावित है।

परबतसर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

42. श्री मानसिंह किनसरीया (परबतसर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि परबतसर कस्बे में कोई राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है? यदि हां, तो कस्बे से कितनी दूरी पर राजकीय महाविद्यालय है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार परबतसर कस्बे व आस-पास के क्षेत्रों के छात्र/छात्राओं की संख्या को देखते हुए उक्त कस्बे में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। परबतसर से राजकीय महाविद्यालयों की दूरी निम्नानुसार है :-

क्र.स.	महाविद्यालय का नाम	परबतसर से दूरी
1	राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़ (अजमेर)	40 किमी
2	राजकीय महाविद्यालय, अजमेर	66 किमी
3	राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना	75 किमी

(2) परबतसर में दो निजी महाविद्यालय, सीमा मेमोरियल महाविद्यालय एवं मारवाड़ महाविद्यालय स्थित हैं, जिनकी छात्र संख्या क्रमश: लगभग 220 एवं 265, कुल 485 ही है। परबतसर में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना चालू वित्तीय वर्ष में विचाराधीन नहीं है।

निवाई में नवीन राशन कार्डों का वितरण

43. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हीरालाल)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र निवाई में नये राशन कार्ड बनाने हेतु आवेदन मांगे गये थे? यदि हां, तो वर्ष 2011 व 2012 में कितने व्यक्तियों/परिवारों से राशन कार्ड बनाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए? ग्रामवार/शहरवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र हेतु बनाये गये राशन कार्डों में गलत नाम व लिंग अंकित हो गये हैं? यदि हां, तो इन्हें कब तक ठीक करवा कर पुन: संबंधितों को वितरित करवा दिया जावेगा?

(3) जिन आवेदकों के राशन कार्ड बनाये जा चुके हैं, क्या उनके राशन कार्ड वितरित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन आवेदकों को वितरित कर दिये गये हैं और किन-किन को वितरित किया जाना शेष है? शेष आवेदकों को अब कब तक राशन कार्ड वितरित कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र निवाई में नये राशन कार्ड बनाने हेतु आवेदन मांगे गये थे। राशन कार्ड अभियान 2012 के अन्तर्गत कुल 91,679 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। ग्रामवार/शहरवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त क्षेत्र हेतु बनाये गये राशन कार्डों में कुछ त्रुटियां हुई हैं। त्रुटियुक्त राशन कार्डों का सुधार करने हेतु विभागीय निर्देश जारी किये गये हैं। जिनके अनुसार त्रुटियुक्त राशन कार्डों को दुरुस्त कराकर उपभोक्ताओं को निरन्तर वितरित किया जा रहा है।

(3) जी हां। कुल 69,862 आवेदकों के राशन कार्ड बनाये जा चुके हैं। उन्हें सम्बन्धित विकास अधिकारी/अधिशासी अधिकारी के माध्यम से वितरित करवा दिया गया है। 21,817 उपभोक्ताओं के राशन कार्ड बनाये जाने शेष हैं। शेष राशन कार्ड तैयार होते ही उपभोक्ताओं को वितरित कर दिये जायेगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में चिकित्सा कर्मियों की भर्ती हेतु कार्य योजना

44. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों व नर्सिंग

(श्री हनुमान बेनीवाल)

कर्मियों/पैरा मेडिकल स्टाफ़ व अन्य कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत है तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? संख्या विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 में किन-किन पदों को भरने की विज्ञप्तियां जारी की गयी व इनमें से कितने पदों पर भर्तियां पूरी कर ली गईं? अब तक विज्ञापित पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के क्या कारण है तथा इसे अब कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में संचालित राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों) में चिकित्सकों के स्वीकृत 6,772 पदों में से 2,089 पद तथा अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत 60,455 पदों में से 24,390 पद वर्तमान में रिक्त हैं। पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2013-14 में दिनांक 15.7.2013 को चिकित्सा अधिकारी के 1,364 पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई।

दिनांक 1.7.2013 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 30.8.2013 को सहायक रेडियोग्राफर के 1,891, लैब टेक्निशियन के 2,970 एवं प्रयोगशाला सहायक के 543 पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई।

दिनांक 1.7.2013 को समन्वयक (स्वास्थ्य) के 56, कम्प्यूटर अनुदेशक के 39, समन्वयक (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) के 34, समन्वयक (प्रोग्राम) के 662, समन्वयक (आई.ई.सी.) के 34, क्लीनिकल अभिलेख सहायक के 4,309, लेखा सहायक के 2412, ब्लाक आशा पर्यवेक्षक के 249 एवं पी.एच.सी. आशा पर्यवेक्षक के 1,612 पदों को भरने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई।

उपरोक्त में से चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। चयनित 1,239 पात्र अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश वरीयता क्रम में जारी किये गये, जिनमें से 766 चिकित्सकों ने विभाग के अधीन विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में कार्य ग्रहण किया।

माननीय खण्ड पीठ, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा याचिका संख्या 9352/2013 द्वारा श्री महेन्द्र कुमार बनाम सरकार व अन्य में

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

निर्णय दिनांक 26.09.2013 के द्वारा विभाग में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को अधिकतम 15 प्रतिशत बोनस अंक दिये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका संख्या 33653/2013 दायर की जा चुकी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। इस कारण से अन्य पदों की भर्ती प्रक्रिया में अग्रिम कार्यवाही अवरुद्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के उपरान्त ही इन भर्तियों से सम्बन्धित अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

परिशिष्ट-अ

प्रदेश में संचालित राजकीय स्वास्थ्य केन्द्रों (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों) में चिकित्सकों एवं अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का पदवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिकत पदों की संख्या
1	वरिष्ठ विशेषज्ञ	10	10
2	कनिष्ठ विशेषज्ञ	1858	982
3	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	689	247
4	चिकित्सा अधिकारी	3887	772
5	चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	328	78
6	नर्स श्रेणी प्रथम	1067	467
7	नर्स श्रेणी द्वितीय	9094	3481
8	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	2747	1268
9	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	18808	5775
10	अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	570	119
11	फार्मासिस्ट	1400	809
12	रेडियोग्राफर	259	157
13	सहायक रेडियोग्राफर	1141	932
14	वरिष्ठ लैब टेक्निशियन	58	31
15	लैब टेक्निशियन	3797	1981
16	नेत्र सहायक	232	158

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
17	दन्त टेक्निशयन	92	80
18	वरिष्ठ स्वास्थ्य कार्यकर्ता	177	112
19	स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष)	2520	873
20	वरिष्ठ लिपिक	1222	214
21	कनिष्ठ लिपिक	1287	329
22	सूचना सहायक/क्लीनिकल अभिलेख सहायक	4025	2164
23	वाहन चालक	711	123
24	वार्ड बाय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	8637	4160
25	सफाई कर्मचारी	2611	1157
	कुल योग	**67227**	**26479**

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने की कार्य योजना

45. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2010 से मई, 2014 तक सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक कितने-कितने नामांकन किये गये तथा कितने-कितने नामांकन ड्राप हुए? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा नामांकन बढ़ाने के लिये कोई उपाय किये गये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक डाइस डाटा के अनुसार सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक का नामांकन एवं ड्राप-आउट का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में नामांकन/ड्राप-आउट का विवरण परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

(2) जी हां। सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने हेतु किये जा रहे उपायों का विवरण निम्नानुसार है :-

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं के चिन्हिकरण हेतु वर्ष 2010 में चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे कर वर्ष 2011-

(शिक्षा मंत्री)

12 में नामांकन अभियान आयोजित कर लगभग 7.25 लाख तथा 2012-13 में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम से लगभग 1.12 लाख बालक-बालिकाओं को प्रवेश करवाया गया था।

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।

राज्य के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

प्रथम कक्षा से अंग्रेजी का अध्यापन।

दोपहर का भोजन।

नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें।

प्रवेशोत्सव के माध्यम से बच्चों का नामांकन।

एजुकेशन ट्यूर।

विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां, बालिकाओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण, 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में मेरिट के अनुसार प्रथम 10-10 हजार बालक-बालिकाओं को पुरस्कार के रूप में लैपटाप का वितरण, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, आदि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नामांकन बढ़ाने के प्रयास किये गये हैं।

परिशिष्ट-क

वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक डाइस डाटा के अनुसार सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक का नामांकन एवं ड्राप आउट का विवरण

नामांकन

वर्ष	कक्षा 1 से 8		
	बालक	बालिका	योग
2010-11	3570058	3563761	7133819
2011-12	3506521	3710350	7216871
2012-13	3347343	3585906	6933249
2013-14	31368238	3372278	6540516

ड्राप आउट

वर्ष	कक्षा 1 से 8		
	बालक	बालिका	योग
2010-11	ड्राप आउट विद्यार्थियों की सूचना संधारित नहीं की जाती थी।		
2011-12	75400	87057	162457
2012-13	30428	36000	66428
2013-14	28446	34184	62630

परिशिष्ट-ख

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में नामांकन/ड्राप आउट का विवरण

नामांकन

वर्ष	कक्षा 9 से 12		
	बालक	बालिका	योग
2010-11	873647	618348	1491955
2011-12	914295	697944	1612239
2012-13	891577	773934	1615511
2013-14	907461	778651	1686112

ड्राप आउट

वर्ष	कक्षा 9 से 12
	संख्या
2010-11	176831
2011-12	190188
2012-13	174375
2013-14	252019

जयपुर जिले में नवीन राशन कार्डों में अशुद्धियों में सुधार हेतु कार्य योजना

46. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षों में सरकार द्वारा प्रदेश में नवीन राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी? यदि हां, तो क्या राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(2) क्या जयपुर जिले में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है? यदि हां, तो कुल कितने राशन कार्ड बनाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वितरित किये गये नवीन राशन कार्डों में भारी अशुद्धियां पाई गई हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसमें सुधार की क्या प्रक्रिया अपनाई गई एवं संवेदक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जयपुर जिले में पुराने एवं नवीन राशन कार्डों की संख्या कितनी-कितनी है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2012 में राशन कार्ड अभियान-2012 के तहत राज्य में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को नवीन डिजिटाइज्ड एवं कम्प्यूटराइज्ड राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया दिनांक 01.06.2012 को प्रारम्भ की गई थी। विभागीय दिशा-निर्देश दिनांक 01.06.2012 के अनुसार राज्य के लिए चयनित फर्मों द्वारा नवीन डिजिटाइज्ड राशन कार्ड के उपभोक्ताओं से प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगणकों द्वारा जांच पश्चात् आवेदन पत्र में वर्णित विवरणों की कम्प्यूटर में प्रविष्टि, निर्धारित डाटाबेस में संधारण, समस्त प्रविष्टियों की चैकिंग, प्रुफ रीडिंग, डाटा में शुद्धिकरण, इत्यादि कार्य की प्रक्रिया सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी के पर्यवेक्षण में पूर्ण कर ली गई है। जिला सीकर, झुन्झुनूं, हनुमानगढ, राजसमन्द एवं सिरोही में शत-प्रतिशत राशन कार्डों का वितरण किया जा चुका है। अन्य जिलों में राशन कार्ड वितरित किये जा रहे हैं। राज्य में अब तक 70 प्रतिशत राशन कार्ड वितरित हुए हैं।

(2) जी नहीं। जयपुर शहर में 8,64,499 नवीन राशन कार्ड बनाये जाने हैं, जिनमें से 2,17,899 राशन कार्ड बनाये जा चुके हैं। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में राशन कार्ड बनाने हेतु 9,61,884 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से 7,72,843 नवीन राशन कार्डों का वितरण किया जा चुका है। शेष राशन कार्ड बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा चयनित फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे तैयार राशन कार्ड में मुख्य रूप से नाम, आयु, सम्बन्ध, श्रेणी, इत्यादि की त्रुटियां पाई गई हैं। इस त्रुटियों को सम्बन्धित फर्म से निर्धारित प्रक्रिया

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

अनुसार अविलम्ब दुरुस्त कराकर सम्बन्धित उपभोक्ता को पुन: राशन कार्ड जारी किये जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा जिला रसद अधिकारियों को दिनांक 17.09.2013, 13.01.2014 एवं 27.03.2014 को निर्देश जारी किये जा चुके हैं, जो परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

राशन कार्ड तैयार कर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया काफी वृहद् एवं विस्तृत है, जिसमें कुछ त्रुटियां होना स्वाभाविक है। निविदा की शर्तों के अनुसार त्रुटियुक्त राशन कार्डों को फर्म द्वारा दुरुस्त कर उपभोक्ता को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। यह कार्य दिनांक 30.09.2014 तक पूर्ण किया जाना है। अत: राज्य सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति एवं राशन कार्ड कार्य हेतु चयनित फर्म के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।

(4) जयपुर शहर में पुराने राशन कार्डों की संख्या 7,73,543 है एवं नवीन राशन कार्ड 8,64,449 बनाये जाने हैं तथा जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में पुराने राशन कार्डों की संख्या 8,86,034 है एवं नवीन राशन कार्डों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या 9,61,884 है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उचित मूल्यों की दुकानों पर आबंटित खाद्य सामग्री

32.श्री रमेश (सपोटरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में उचित मूल्य की दुकानों पर किस-किस सामग्री का माहवार कितना-कितना आबंटन निर्धारित था? आबंटित सामग्री में से कितनी-कितनी का वितरण किया गया? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला करौली में सरकार द्वारा गत वर्षों की तुलना में आबंटित सामग्री की मात्रा में कमी की गई है? यदि हां, तो किस-किस सामग्री की तथा क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या प्रदेश के सभी जिलों में राशन हेतु आबंटित सामग्री की मात्रा में कमी की गई है? यदि नहीं, तो केवल जिला करौली में ही कमी करने के क्या कारण हैं?

(4) क्या यह सही है कि जिला करौली हेतु आबंटित की जाने वाली राशन सामग्री को अन्य जिलों को आबंटित कर दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस जिले को तथा क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में उचित मूल्यों की दुकानों पर आबंटित/वितरित सामग्री का तहसीलवार/माहवार विवरण परिशिष्ट-'ए' पर संलग्न है।

(2) जिला करौली में सरकार द्वारा गत वर्षों की तुलना में आबंटित गेहूं एवं केरोसीन की मात्रा में कोई कमी नहीं की गई है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में राज्य को आबंटित चीनी की मात्रा में कमी किये जाने के कारण राज्य के समस्त जिलों में समानुपातिक रूप से आबंटित मात्रा में कमी की गई है।

(3) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 में राज्य को आबंटित चीनी की मात्रा में कमी किये जाने के कारण राज्य के समस्त जिलों में केवल आबंटित चीनी की मात्रा में समानुपातिक रूप से कमी की गई है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

(4) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में नये राशन कार्ड

33. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में नए राशन कार्ड बनाने की प्रकिया कब प्रारम्भ हुई थी व किस अवधि में उपभोक्ताओं से आवेदन प्राप्त किये गए थे? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज रखें।

(2) उक्त राशन कार्ड तैयार करने का कार्य किस-किस एजेंसी को कब-कब दिया गया था तथा एजेन्सियों को कब तक राशन कार्ड तैयार करके देने थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त एजेन्सियों द्वारा राशन कार्ड निर्धारित अवधि में तैयार नहीं किये गये तथा तैयार किये गये राशन कार्डो में भी भारी त्रुटियां सामने आ रही हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके लिए सम्बन्धित एजेन्सियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान में राशन कार्ड की त्रुटियों के सुधार हेतु कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो सुधार हेतु क्या प्रकिया अपनाई गई है तथा अब तक कितने उपभोक्ताओं ने राशन कार्ड में सुधार हेतु आवेदन किया है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सभी श्रेणी के नवीन डिजिटाइज्ड एवं कम्प्यूटराइज्ड राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया 1 जून, 2012 से प्रारम्भ कर दी गई थी। उपभोक्ताओं से सभी जिलों में 15 जुलाई, 2012 से 16 अगस्त, 2012 की अवधि में आवेदन फार्म प्राप्त किये गये थे।

(2) नवीन राशन कार्ड तैयार करने का कार्य ई-निविदा के माध्यम से राज्य के लिए चयनित 11 फर्मों को राशन कार्ड तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित जिला कलक्टर के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 15.10.2012 तक अनुबन्ध कर राशन कार्ड सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ करने हेतु दिनांक 26.09.2012 को निर्देश जारी किये गये, जिसकी पालना में चयनित फर्मों द्वारा

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

किये गये अनुबन्ध की दिनांक का विवरण परिशिष्ट-1 पर सलंग्न है। चयनित फर्मों को अनुबन्ध की तिथि से चार माह की अवधि में राशन कार्ड तैयार कर उपलब्ध कराये जाने थे।

(3) जी हां। तकनीकी कारणोंवश फर्मों द्वारा राशन कार्ड कार्य निर्धारित अवधि (अतिरिक्त दो माह सहित) में पूर्ण नहीं किया जा सका। राशन कार्ड कार्य की अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डलीय समिति में दिनांक 03.03.2014 को निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार राशन कार्ड कार्य की अवधि माह सितम्बर, 2014 तक बढ़ा दी गयी है। समयावधि बढाने के कारण वर्तमान में इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

फर्मों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे राशन कार्डों में पायी गयी त्रुटियों को सम्बन्धित फर्म से निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अविलम्ब दुरुस्त कराकर सम्बन्धित उपभोक्ता को पुन: राशन कार्ड जारी किये जाने के सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारियों को दिनांक 17.09.2013, 13.01.2014 एवं 27.03.2014 को निर्देश जारी किये जा चुके हैं, जिनकी प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(4) जी हां। नये राशन कार्ड वितरण पर उपभोक्ताओं द्वारा चिन्हित त्रुटि का सम्बन्धित क्षेत्र के प्रगणक द्वारा सत्यापन कर प्राधिकृत अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाता है। प्राधिकृत अधिकारी त्रुटिपूर्ण राशन कार्ड दुरुस्ती हेतु फर्म को देता है। सम्बन्धित चयनित फर्म द्वारा पायी गयी त्रुटियों को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अविलम्ब दुरुस्त कराकर सम्बन्धित उपभोक्ता को पुन: राशन कार्ड जारी किये जाने के लिए जिला रसद अधिकारी के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी को देता है। इस सम्बन्ध में जिला रसद अधिकारियों को दिनांक 17.09.2013, 13.01.2014 एवं 27.03.2014 को निर्देश जारी किये जा चुके हैं, जिनकी प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं। उपभोक्ताओं द्वारा त्रुटिपूर्ण राशन कार्डों में सुधार हेतु किए गए आवेदनों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

दौसा जिले में खाद्य सुरक्षा गारण्टी योजनान्तर्गत आबंटित गेहूं

34. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. किरोड़ी लाल)

(1) खाद्य सुरक्षा गारण्टी योजना के तहत दौसा जिले में कितने व्यक्तियों को चिन्हित कर लाभान्वित किया गया? ग्राम पंचायतवार एवं वार्डवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में लाभार्थी को चिन्हित करने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना में चिन्हित सभी योग्य व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल रहा है?

(4) जिला दौसा में उक्त योजना के तहत जून, 2014 तक कितने टन गेहूं का आबंटन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खाद्य सुरक्षा गारण्टी योजना के तहत दौसा जिले में कुल 14,55,404 (91,485 शहरी, 13,63,919 ग्रामीण) व्यक्तियों को चिन्हित कर लाभान्वित किया गया है। ग्राम पंचायतवार एवं वार्डवार संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थी को चिन्हित करने के मानदण्डों (समावेशन एवं निष्कासन) की प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(3) जी हां। उक्त योजना में चिन्हित सभी पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ मिल रहा है।

(4) उक्त योजना के तहत जून, 2014 तक दौसा जिले में 54,441.00 मै.टन गेहूं का आबंटन किया गया। माहवार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	माह	आबंटित मात्रा मै.टन
1	अक्टूबर, 2013	6340.00
2	नवम्बर, 2013	6340.00
3	दिसम्बर, 2013	6340.00
4	जनवरी, 2014	6340.00
5	फरवरी, 2014	6433.00
6	मार्च, 2014	5662.00
7	अप्रैल, 2014	5662.00

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

क्र.सं.	माह	आबंटित मात्रा मै.टन
8	मई, 2014	5662.00
9	जून, 2014	5662.00

(सूची व प्रति पुस्कालय में रखी गयीं)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कनिष्ठ लिपिकों के पद पर पदोन्नति

35. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जोन में विगत पांच वर्ष में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति की गई है? यदि हां, तो पदोन्नत कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति वरिष्ठता सूची के आधार पर की गई है? यदि हां, तो वरिष्ठता सूची की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कनिष्ठ लिपिक पद पर पदोन्नति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों एवं वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदोन्नति कोटे के कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर जोन कार्यालय के द्वारा विगत पांच वर्षो में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति कनिष्ठ लिपिक के पद पर नहीं की गई है।

(2) जयपुर जोन कार्यालय के द्वारा विगत पांच वर्षों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति कनिष्ठ लिपिक के पद पर नहीं की गई है।

(3) जी हां। राज्य सरकार चतुर्थ श्रेणी संवर्ग से कनिष्ठ लिपिक पद पर निर्धारित 15 प्रतिशत कोटे के आधार पर वरिष्ठता सूची में से वरिष्ठतम कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति देने का विचार रखती है।

जयपुर जोन कार्यालय के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के संवर्ग की अंतरिम वरिष्ठता सूची दिनांक 22.04.2013 की स्थिति में जारी की गई है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद हेतु पूर्व में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जयपुर जोन कार्यालय के अधीन वर्तमान में कनिष्ठ लिपिक के 354 पद स्वीकृत हैं एवं 15 प्रतिशत के आधार पर 53 कनिष्ठ लिपिक के पदों का पदोन्नति कोटा निर्धारित है। उक्त पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत वर्तमान में 51 पद रिक्त हैं।

बाड़मेर जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद

36. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के चिकित्सालयों में चिकित्सकों, मेल नर्स और ए.एन.एम. के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से चिकित्सालयों में कितने-कितने पद? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बाड़मेर जिले के अधीन आने वाले चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों, नर्स श्रेणी प्रथम एवं द्वितीय तथा ए.एन.एम. के रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को डी एसी पी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से एवं चिकित्सा अधिकारी तथा चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबंध हटने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी प्रथम का पद पदोन्नति का है, जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी द्वितीय एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों को स्थानान्तरण अथवा विभागीय भर्ती के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्कालय में रखा गया)

एस.एम.एस. चिकित्सालय (जयपुर) में चिकित्सक द्वारा अभद्र व्यवहार

37. श्री बंशीधर (खण्डेला) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग के रेजीडेंट द्वारा माह मई, 2014 में अभद्र व्यवहार किये जाने का प्रकरण उजागर हुआ था? यदि हां, तो किस रेजीडेंट डाक्टर द्वारा एवं उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अभद्र व्यवहार के मामले में कोई जांच हुई है? यदि हां, तो किस स्तर पर एवं उसकी रिपोर्ट कब एवं किस अधिकारी को प्रस्तुत की गई एवं उस रिपोर्ट पर किस अधिकारी को निर्णय लेना था? क्या सरकार निर्णय नहीं लेने वाले अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि एस एम एस अस्पताल, जयपुर के न्यूरोसर्जरी विभाग के डा. हेमन्त, प्रथम वर्ष रेजीडेन्ट डाक्टर द्वारा मई, 2014 में अभद्र व्यवहार किये जाने का प्रकरण उजागर हुआ था। प्रकरण की जांच हेतु तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।

(2) जी हां। प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जयपुर द्वारा तीन सदस्यीय चिकित्सकों की एक जांच समिति का गठन किया गया था, जिसमें डा. वी. आर. सरदाना, आचार्य न्यूरोसर्जरी, डा. एस.के. जैन, आचार्य न्यूरोसर्जरी एवं डा. आर.एस. राव, अति. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर सम्मिलित थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.05.2014 को प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित की है। कमेटी की रिपोर्ट पर कार्यवाही विचाराधीन है।

जोधपुर चिकित्सालय में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पद

38. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर के चिकित्सालयों में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की क्या स्थिति है और ये पद कब से रिक्त हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) जोधपुर में पदस्थापित ऐसे कुल कितने अधिकारी, चिकित्सक अथवा कार्मिक हैं, जो अपने मूल पदस्थापन से अन्य स्थान पर प्रतिनियुक्ति अथवा कार्य व्यवस्था के तहत कार्य कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसे समस्त कार्मिकों को अपने मूल पदस्थापन स्थान पर भेजने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जोधपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित राजकीय चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

मेडिकल कालेज जोधपुर से सम्बद्ध चिकित्सालयों में स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत/पदस्थापित एवं रिक्त पदों का पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

सेवानिवृति/नवीन पदसृजन/स्थानान्तरण, आदि कारण से रिक्त हुए पद भिन्न-भिन्न समय से रिक्त हैं।

(2) जी हां। पदोन्नति के रिक्त पद पदोन्नति उपरान्त/स्थानान्तरण द्वारा एवं अन्य कार्मिकों के रिक्त पद चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर/स्थानान्तरण द्वारा भरे जा सकेंगे।

(3) जिला जोधपुर में पदस्थापित 100 चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारी अपने मूल पदस्थापन स्थान से अन्यत्र कार्य व्यवस्था के तहत कार्य कर रहे हैं। पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) उपरोक्त चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों को आमजन को आवश्यकतानुसार बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु कार्य व्यवस्था के तहत लगाया हुआ है।

(विवरण पुस्कालय में रखा गया)

प्रदेश मे संचालित 108 एम्बुलेंस की सेवाएं

39. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में गत पांच वर्षों से मरीजों को आपातकालीन सेवा देने वाली एम्बुलेंस 108 सेवा कहां-कहां संचालित की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एम्बुलेंस वाहनों में चिकित्सा सुविधा हेतु कौन-कौन से उपकरण, दवाइयां किस एजेन्सी से खरीदी जाती हैं? उक्त एजेन्सी को सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त एम्बुलेंस वाहनों में चिकित्सा सुविधा हेतु कितना स्टाफ स्वीकृत है तथा यह स्टाफ किस अधिकारी के अधीन कार्य करता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त वाहनों हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित है? यदि हां, तो कितना-कितना तथा वर्ष 2011 से 2013 तक उक्त वाहनों द्वारा कितने मरीज लाये/ले जाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सितम्बर 2008 में 108 आपातकालीन सेवा का संचालन शुरू हुआ। विगत पांच वर्षों में प्रदेश में मरीजों को आपातकालीन सेवा देने वाली एम्बुलेंस 108 सेवा की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त एम्बुलेंस में चिकित्सा सुविधा हेतु खरीदे जाने वाले उपकरण एवं दवाओं का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

चिकित्सा सुविधा हेतु परिशिष्ट-ब में वर्णित दवाइयां एवं उपकरण सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा ही क्रय किये जाते थे जिनका पुनर्भरण एन आर एच एम द्वारा प्रति माह किया जाता था। उक्त उपकरण जिन कम्पनियों से क्रय किये जाते थे, उनकी सूची एवं उक्त कम्पनियों को गत दो वर्षों (जुलाई 2010 से मार्च 2012 तक) में किये गये भुगतान रुपये 3.25 करोड का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

अप्रैल 2012 से 6 मई, 2013 तक जेड एच एल को मेडिकल एवं नान-मेडिकल कंज्यूमेबल्स के पेटे कोई भुगतान नहीं किया गया है।

(चिकित्सा एवं स्वस्थ्य मंत्री)

इसके पश्चात नये अनुबन्ध के तहत ई.एम.आर.आई. हैदराबाद के साथ 23 मई, 2013 को एग्रीमेंट साइन किया गया। ई एम आर आई को प्रति एम्बुलेंस रुपये 1,12,500/- प्रति माह की दर में मेडिकल एवं नान-मेडिकल कंज्यूमेबल्स का खर्च भी सम्मिलित है, जिसकी सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) एम्बुलेंस वाहनों के लिए कोई स्टाफ स्वीकृत नहीं है, अपितु उक्त एम्बुलेंस में सेवा प्रदाता कम्पनी के साथ हुए समझौते के अनुसार चिकित्सा सुविधा हेतु एक पायलट (वाहन चालक) तथा एक ई एम टी (जी एन एम/बी.एससी नर्सिंग) सदैव ड्यूटी के लिये उपलब्ध रहना आवश्यक है। समस्त 108 सेवा की एम्बुलेंसों पर कार्यरत पायलट एवं ई एम टी, सेवा प्रदाता कम्पनी ई एम आर आई के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं तथा उन्हीं के अधीन कार्यरत हैं।

(4) जी हां। यह सही है कि उक्त वाहनों हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आर एफ पी के तहत औसत 5 ट्रिप/प्रति एम्बुलेंस/प्रतिदिन होना अनिवार्य है।

वर्ष 2011 से वर्ष 2013 तक 108 एम्बुलेंस द्वारा लाये/ले जाये गये मरीजों की संख्या निम्न प्रकार है :-

वर्ष	**लाभार्थियों की संख्या**
जनवरी 2011 से दिसम्बर 2011	7,23,125
जनवरी 2012 से दिसम्बर 2012	9,82,132
जनवरी 2013 से दिसम्बर 2013	7,09,634
कुल	**24,14,891**

(सूचियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सीवरेज के पानी से उत्पादित सब्जियों के सेवन से उत्पन्न घातक बीमारियां

40. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कैलाश भंसाली)

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर के आस-पास सीवरेज के पानी से उगने वाली सब्जियों के सेवन से लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोक-थाम का विचार रखती है यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या जोजरी नदी के किनारे बसे तनावड़ा, सांगरिया, सालावास, आदि गांवों के लोगों में औद्योगिक प्रदूषित पानी से सिंचित उपज और सब्जियों के लगातार सेवन से कैंसर, आदि घातक बीमारियों के मरीज एस.एन. मेडिकल कालेज तथा अन्य राजकीय अस्पतालों में उपचार के लिए आये हैं? यदि हां, तो विगत पांच वर्ष की अवधि में आये ऐसे मरीजों का नाम, बीमारीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर शहर के आसपास सीवरेज के पानी से उगने वाली सब्जियों के सेवन से बीमार हुआ कोई भी मरीज चिह्नित नहीं हुआ है।

(2) मेडिकल कालेज के आन्कोलोजी विभाग में इलाज/उपचार हेतु कैंसर के मरीज आते हैं। परन्तु प्रदूषित पानी से सिंचित उपज और सब्जियों के लगातार सेवन से हुए कैंसर के इलाज हेतु मरीजों का आना चिह्नित नहीं हुआ है और ऐसा कोई अध्ययन राज्य सरकार के संज्ञान में नहीं है। इसी प्रकार, जोधपुर शहर के अन्य चिकित्सा संस्थानों में भी प्रदूषित पानी से सिंचित उपज और सब्जियों के सेवन से कैंसर, आदि घातक बीमारियों के मरीजों का उपचार/इलाज हेतु आना नहीं पाया गया है।

निःशुल्क दवा/जांच योजना हेतु आबंटित राशि

41. श्री घनश्याम (टोडाभीम) व **श्री दर्शन सिंह** (करौली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना में चालू वित्त वर्ष 2014-15 के लिए मई, 2014 तक कितनी राशि मेडिकल कालजों के अधीन चिकित्सालयों को आबंटित की जा चुकी है तथा गत वित्त वर्ष में नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत आबंटित की गई राशि से इस वर्ष आबंटित की गई राशि कितनी प्रतिशत कम या अधिक है? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना को अघोषित तरीके से बंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना एवं मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना में चालू वित्त वर्ष 2014-15 के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के मेडिकल कालेजों के अधीन चिकित्सालयों को आबंटित राशि की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

गत वित्त वर्ष में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों को मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना में कोई राशि आबंटित नहीं की गई।

मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य के मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों को वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में की गयी आबंटित राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

इस प्रकार, मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों एवं झालावाड़ मेडिकल कालेज के लिये वित्तीय वर्ष 2013-14 में राशि रुपये 102.84 करोड़ एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में राशि रुपये 128.53 करोड़ आबंटित की गई है, जो कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2014-15 में 24.98 प्रतिशत अधिक है।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट-अ

राज्य में मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना एवं मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना में चालू वित्त वर्ष 2014-15 के लिए राज्य के मेडिकल कालेजों के अधीन चिकित्सालयों को आबंटित राशि की सूचना निम्न प्रकार है :-

चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि (लाखों में)	मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि (लाखों में)
अजमेर	285.00	587.45
दन्त चिकित्सालय जयपुर	कोई राशि आबंटित नहीं की गई	कोई राशि आबंटित नहीं की गई
जयपुर	660.00	1515.03
उदयपुर	285.00	807.67
कोटा	285.00	1028.03

चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि (लाखों में)	मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि (लाखों में)
बीकानेर	285.00	432.02
जयपुरिया अस्तपाल, जयपुर	8.09	20.50
जोधपुर	465.00	1300.22
कुल योग	**2273.09**	**5690.92**

नोट :- उपरोक्त वार्षिक आबंटन का एक तिहाई लेखानुदान में स्वीकृति प्रदान की गई थी।

परिशिष्ट-ब

मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजनान्तर्गत राज्य के मेडिकल कालेजों को वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में किये गये आबंटन का विवरण निम्न प्रकार है

Sr. No.	Dis-trict Name	Medical College Name	Budget Utilized during 2013-14 (In Rupees)	Budget Available 2014-15 (In Rupees)
1.	Ajmer	JLN Central Store Medical College	74021265	61186189
2.	Ajmer	Zanana Hospital Ajmer Medical College Hospital	8260090	8977227
3.	Bi-kaner	PBM Medical College And Hospital	179514920	158605622
4.	Jaipur	Dental College Jaipur	1950831	2334585
5.	Jaipur	Gangori Hospital	147847489	16659093
6.	Jaipur	JK Lone Hospital Jaipur	27738872	215.0526
7.	Jaipur	Mahila Hospital Jaipur	17445708	20946459
8.	Jaipur	PSM Department	146274	188710
9.	Jaipur	Phychiatric Centre Jaipur	2923732	3656214
10.	Jaipur	SMS Hospital	277746528	249164757
11.	Jaipur	TB Hospital Jaipur	8455410	8725263
12.	Jaipur	Zanana Hospital Jaipur	19090210	21267747

Sr. No	District Name	Medical College Name	Budget Utilized during 2013-14 (In Rupees)	Budget Available 2014-15 (In Rupees)
13.	Jaipur	Jaipuria Hospital DH	11374231	1560725
14.	Jhalawar	Jhalawar Medical College Medical College Hospital	39187064	56211304
15.	Jodhpur	Mahatma Gandhi Hospital Jodhpur	60050808	81652119
16.	Jodhpur	Mathura Das Mathur Hospital Jodhpur	59088476	74606587
17.	Jodhpur	Umiad Hospital Jodhpur Medcial College Hospital	42445940	52060473
18.	Kota	J.K Loan Hospital Kota	26397112	31996686
19.	Kota	MBS Hospital Kota	54270016	80672084
20.	Kota	New Govt. Medical College Kota	13227103	28541819
21.	Udaipur	Maharana Bhopal Govt. Hospital Medi-cal College	70249904	68412660
		Total	**1018371983**	**1057959849**

प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना

42. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) व **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में नि:शुल्क दवा और जांच योजना लागू है? यदि हां, तो कब से एवं अब तक इन योजनाओं से कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश के हर नागरिक का स्वास्थ्य बीमा कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से एवं किस प्रक्रिया के तहत?

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना दिनांक 2 अक्टूबर, 2011 से संचालित की जा रही है। उक्त योजना के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में प्रारम्भ से दिनांक 30.06.2014 तक लाभान्वित मरीजों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

प्रदेश में जांच योजना राज्य के चिकित्सा संस्थानों में निम्नानुसार चरणबद्ध तरीके से लागू की गई है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

क्र. सं.	योजना के चरण	योजना प्रारम्भ की तिथि	चिकित्सा संस्थान का नाम
1	प्रथम चरण	7 अप्रैल, 2013	मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पताल, जिला/उप जिला/सैटेलाइट अस्पताल, झालावाड़ मेडिकल कालेज
2	द्वितीय चरण	1 जुलाई, 2013	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
3	तृतीय चरण	15 अगस्त, 2013	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं डिस्पेन्सरी

प्रदेश में नि:शुल्क जांच योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिनांक 30.06.2014 तक लाभान्वित मरीजों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम विभाग द्वारा कतिपय नागरिकों के लिये चलाई जा रही है। वर्तमान में सभी नागरिकों के लिये बीमा योजना लागू करना व्यावहारिक नहीं है। प्रारम्भिक तौर पर प्रस्ताव विचारार्थ है। सभी पहलुओं का अध्ययन करवाया जा रहा है।

परिशिष्ट-अ

प्रदेश मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना एवं नि:शुल्क जांच योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ से दिनांक 30.06.2014 तक लाभान्वित मरीजों का जिलेवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है

क्रम संख्या	जिले का नाम	मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित मरीजों की संख्या	मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना के अन्तर्गत लाभान्वित मरीजों की संख्या
1	अजमेर	7970980	894297
2	अलवर	7431146	160571
3	बाड़मेर	4555630	791781
4	बांसवाड़ा	4266741	604816
5	बारां	4223645	584904
6	भरतपुर	5784190	778024

क्रम संख्या	जिले का नाम	मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित मरीजों की संख्या	मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना के अन्तर्गत लाभान्वित मरीजों की संख्या
7	भीलवाड़ा	5823959	1041531
8	बीकानेर	9313085	648671
9	बूंदी	3101174	315129
10	चित्तौड़गढ़	4282386	358030
11	चूरू	4961687	1486705
12	दौसा	3802602	519215
13	धौलपुर	3460638	436352
14	डूंगरपुर	2526476	280072
15	गंगानगर	2741165	3256392
16	हनुमानगढ़	4391630	1668331
17	जयपुर	1747059	3462533
18	जैसलमेर	2003348	154967
19	जालौर	2641966	556118
20	झालावाड़	3545993	87456
21	झुन्झुनूं	5413078	46512
22	जोधपुर	9586885	2827781
23	करौली	3538323	488753
24	कोटा	7829535	1045445
25	नागौर	5944475	980642
26	पाली	5141997	1007210
27	प्रतापगढ़	2126254	126278
28	राजसमंद	3810282	883177
29	सवाई माधोपुर	4620292	473511
30	सीकर	6540929	862905
31	सिरोही	3043812	633071
32	टोंक	3791713	601564
33	उदयपुर	8680411	2141073
	योग	**175453486**	**30603817**

प्रश्न संख्या-43

(स्थगित)

प्रदेश में एकल अध्यापकों से संचालित विद्यालय

44. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में एकल अध्यापक के कितने विद्यालय हैं और इनमें कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार विद्यालयों में समानीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार शहरों में पदस्थापित आधिक्य अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्र में लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में एकल अध्यापक विद्यालयों एवं इनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट "क'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाकर शिक्षकों के पदस्थापन की कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां। समानीकरण के सम्बन्ध में नीति निर्धारण की प्रक्रिया विचाराधीन है।

(4) प्रश्नोत्तर बिन्दु संख्या 3 के अनुसार।

परिशिष्ट-क

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग अन्तर्गत प्रदेश में एकल अध्यापक विद्यालय एवं उनमें अध्ययनरत छात्र संख्या का जिलेवार संख्या विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	एकल अध्यापक विद्यालयों की संख्या			इनमें अध्ययनरत छात्र संख्या			विशेष विवरण
		राप्रावि	राउप्रावि	योग	राप्रावि	राउप्रावि	योग	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	जोधपुर	588	10	598	24809	950	25759	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	पाली	139	2	141	4219	62	4281	-
3	सिरोही	80	0	80	2340	0	2340	-
4	जालोर	464	3	467	20953	321	21274	-
5	बाड़मेर	742	4	746	37202	402	37604	-
6	जैसलमेर	409	6	418	13154	508	13662	-
7	भरतपुर	179	5	184	11038	419	11457	-
8	करौली	148	5	153	4543	342	4885	-
9	सवाईमाधोपुर	84	0	84	2336	0	2336	-
10	धौलपुर	262	4	266	13647	335	13982	-
11	हनुमानगढ़	99	4	103	3681	271	3952	-
12	झुंझुनूं	117	1	118	2763	39	2802	-
13	श्रीगंगानगर	350	6	356	11030	421	11451	-
14	चुरू	207	2	209	8916	102	9018	-
15	बीकानेर	426	7	433	15973	177	16150	-
16	कोटा	31	0	31	468	0	468	-
17	बूंदी	200	10	210	7550	642	8192	-
18	झालावाड़	200	2	202	6710	132	6842	-
19	बारां	173	2	175	5091	167	5258	-
20	अजमेर	206	9	215	6757	517	7274	-
21	भीलवाड़ा	630	11	641	26376	983	27359	-
22	नागौर	512	26	538	17846	1812	19658	-
23	टोंक	135	3	138	4029	300	4329	-
24	जयपुर	399	10	409	12757	588	13345	-
25	अलवर	188	1	189	4945	48	4993	
26	सीकर	184	3	187	3780	132	3912	-
27	दौसा	194	9	203	8600	815	9415	-
28	उदयपुर	831	0	831	40341	0	40341	-
29	बांसवाड़ा	435	9	544	26913	340	27253	-
30	डूंगरपुर	316	0	316	19632	0	19632	-
31	चित्तौड़गढ़	471	3	474	15386	101	15487	-
32	प्रतापगढ़	315	8	323	14400	818	15218	-
33	राजसमंद	321	0	321	15447	0	15447	-
	योग	**10135**	**165**	**10300**	**413632**	**11744**	**425376**	

आरटैट परीक्षा की उपयोगिता

45. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शिक्षक नियुक्ति के लिए ली जाने वाली आरटैट परीक्षा की उपयोगिता के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश के मध्यनजर आरटैट परीक्षा के प्राप्तांकों में सभी वर्गों को छूट देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। शिक्षक नियुक्ति के लिये आरटैट के साथ अन्य और ली जाने वाली परीक्षा को समाप्त कर एक ही परीक्षा REET (Recruitment cum Eligibility Exam. for Teachers) "अध्यापकों के लिये भर्ती एवं पात्रता परीक्षा" ली जाकर नियुक्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

(2) वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय उपरान्त कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

धरियावद के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

46. श्री गोतम लाल (धरियावद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद के उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/ उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने-कितने कर्मचारी कार्यरत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद के राजकीय उच्च माध्यमिक/

(शिक्षा मंत्री)

माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का पदवार विवरण परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। रिक्त पदों पर भर्ती आवश्यकता अनुसार कार्यवाही कर की जावेगी।

परिशिष्ट-क

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धरियावद के विद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1.	प्रधानाचार्य एवं समकक्ष	9	0	9
2.	प्रधानाध्यापक एवं समकक्ष	29	23	6
3.	व्याख्याता एवं समकक्ष	54	4	50
4.	वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-II एवं समकक्ष	188	92	96
5.	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-II एवं समकक्ष	8	3	5
6.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-II	0	0	0
7.	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II एवं समकक्ष	4	3	1
8.	अध्यापाक ग्रेड-III एवं समकक्ष	19	2	17
9.	शारीरिक शिक्षक ग्रेड-III एवं समकक्ष	7	4	3
10.	पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-III एवं समकक्ष	3	2	1
11.	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III	10	2	8
12.	कार्यालय सहायक	2	1	1
13.	वरिष्ठ लिपिक	12	8	4
14.	कनिष्ठ लिपिक	40	5	35
15.	जमादार	1	1	0
16.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	53	16	37
	योग	**439**	**166**	**273**

प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धरियावद के विद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1.	अध्यापक ग्रेड-II	91	18	73
2.	अध्यापक ग्रेड-III	810	505	305
3.	शारीरिक शिक्षक	21	21	0
4.	प्रबोधक	59	58	1
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	6	5	1
	योग	**987**	**607**	**380**

प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में छात्रों का कम नामांकन

47. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश के ऐसे सरकारी विद्यालय जिनमें छात्रों का नामांकन कम है, उन विद्यालयों को बन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने विद्यालय बन्द किये जाएंगे? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालय बन्द करने से कितने अध्यापक सरप्लस होते हैं? सरप्लस अध्यापकों का समायोजन किस प्रकार से किया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपरोक्तानुसार।

नगर में शिक्षकों के रिक्त पद

48. श्रीमती अनीता (नगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद कब से रिक्त हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अनीता)

(2) क्या सरकार विद्यालयों का एकीकरण कर उक्त समस्या का समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उसके लिए क्या नियम बनाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'क-1" तथा "क-2" पर संलग्न है।

(2) राज्य में कम नामांकन वाले विद्यालयों को उसी राजस्व ग्राम में स्थित विद्यालय के साथ नि:शुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आर टी ई) के मापदण्डों के अनुरूप विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए एकीकृत करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। एकीकरण के पश्चात् विद्यालयों में समुचित छात्र एवं अध्यापक संख्या होने से अध्यापन की कार्यवाही सुचारु रूप से हो सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में संस्कृत शिक्षकों की पदोन्नतियां

49. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 में संस्कृत शिक्षा में तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में की गई पदोन्नति में कई योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी होने के बावजूद पदोन्नति से वंचित रखे गये हैं? यदि हां, तो उसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पदोन्नति से वंचित उक्त अभ्यार्थियों को पदोन्नति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। संस्कृत शिक्षा में तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी में वर्ष 2013 में विभिन्न विषयों यथा- विज्ञान, गणित अंग्रेजी, सा. विज्ञान, हिन्दी एवं संस्कृत में की गई पदोन्नतियों में सेवा नियमों के आधार पर निर्धारित योग्यता रखने वाले सभी पात्र शिक्षकों को पदोन्नति में शामिल किया गया है।

(2) उत्तर बिन्दु संख्या-1 में निहित।

प्रदेश में संविदा पर विद्यार्थी मित्रों की नियुक्तियां

50. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार संविदा पर विद्यार्थी मित्रों की नवीन नियुक्ति करने का विचार रखती है एवं वर्तमान में नियुक्त विद्यार्थी मित्रों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा रिट नं. 10339/12 त्रिलोक सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय के अनुसार विद्यार्थी मित्रों की नियुक्ति को अवैध एवं असंवैधानिक माना गया है।

आर.टी.ई. योजना के तहत छात्रों को निःशुल्क शिक्षा

51. श्री रतन लाल जलधारी (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निजी विद्यालयों में आर.टी.ई. योजना के तहत छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त करने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला सीकर में उक्त योजनान्तर्गत कितने छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयो में "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों को विद्यालय की एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेशित बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक नि:शुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश दिये जाने एवं इन प्रवेशित बालकों को नि:शुल्क प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

(2) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-

(शिक्षा मंत्री)

2009 के प्रावधानान्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के लिये प्रमुख शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. बालक राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या : F 21(19)Edu-1/ E.E/2009 दिनांक 29.3.2011 के परिभाषित "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" से सम्बन्धित होना चाहिए;
2. बालक राजस्थान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2011 के नियम 10(3) में परिभाषित कैचमेंट एरिया का निवासी होना चाहिए; व
3. विद्यालय में कैचमेंट एरिया से आवेदन करने वाले बालकों की संख्या विद्यालय द्वारा नि:शुल्क शिक्षा हेतु घोषित सीटों से अधिक होने की स्थिति में लाटरी से चयन प्रक्रिया में बालक का चयन होना आवश्यक है।

नियमों की प्रति परिशिष्ट 'क"पर संलग्न है।

(3) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानान्तर्गत जिला सीकर में "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह" के बालकों के विधान सभा क्षेत्र वार लाभान्वित संख्या विवरण परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में संचालित तकनीकी महाविद्यालय

52. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने राजकीय तकनीकी महाविद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अलवर जिला मुख्यालय पर राजकीय तकनीकी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में राज्य सरकार के अधीन 12 इंजीनियरिंग कालेज स्वायत्तशासी संस्थाओं के रूप में तथा 42 राजकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय संचालित है। सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(2) जी नहीं। वर्तमान में अलवर जिले में 09 गैर-अनुदानित निजी इंजीनियरिंग कालेज एवं 02 राजकीय पालीटेक्निक महाविद्यालय संचालित हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा विश्वविद्यालय में व्याख्याताओं का नियमितीकरण

53. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा विश्वविद्यालय में वर्ष 2008 में नियुक्त प्रोफेसर्स में से कुछ को परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही नियमित किया गया है? यदि हां, तो किन-किन को व कब-कब? आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या परिवीक्षा अवधि को कम किया जा सकता है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत एवं कितनी अवधि में? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त गम्भीर प्रकरण में लिप्त दोषी अधिकारियों को निलम्बित कर उनके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कोटा विश्वविद्यालय में वर्ष 2008में नियुक्त निम्नलिखित 4 प्रोफेसर्स को 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के पश्चात उन्हें प्रोफेसर पद पर स्थायी किया गया था:-

नाम	स्थाई करने की तिथि
प्रो. एस.सी. राजोरा	6.9.2010
प्रो. एन.के. जैमन	13.11.2010
प्रो. आशुरानी	6.9.2010
प्रो. के.सी. गोयल	6.9.2010

परन्तु उक्त प्रोफेसरों द्वारा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत अभ्यावेदन पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयानुसार इनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के

(उच्च शिक्षा मंत्री)

लगभग चार वर्ष पश्चात पूर्व में प्रसारित आदेशों में संशोधन करते हुए परिवीक्षा काल अवधि भूतलक्षित प्रभाव से एक वर्ष की गई तथा परिवीक्षा काल अवधि कम किये जाने के फलस्वरूप उन्हें प्रोफेसर पद पर वेतन निर्धारण का लाभ एक वर्ष की परिवीक्षा काल अवधि पूर्ण मानते हुए आदेश प्रसारित किये गये।

उक्त प्रोफेसरों को स्थायी करने एवं परिवीक्षा काल अवधि एक वर्ष कर वेतन निर्धारण का लाभ प्रदान करने हेतु प्रसारित आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। विश्वविद्यालय में नियोक्ता प्राधिकारी विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल है तथा विश्वविद्यालय में प्रचलित नियम विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदन के पश्चात ही प्रभावी होते हैं। तदानुसार प्रासंगिक प्रकरण में परिवीक्षा काल अवधि एक वर्ष विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल की अनुमति पश्चात भूतलक्षित प्रभाव से की गई। प्रबन्ध मण्डल के निर्णय की प्रति एवं परिवीक्षा काल के सम्बन्ध में महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नियमों (जो कोटा विश्वविद्यालय पर भी प्रभावी हैं) की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) चूंकि समस्त कार्यवाही विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल के निर्णयानुसार की गई है, अत: कोई दण्डात्मक कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर से अपेक्षित नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय में व्याख्याताओं के रिक्त पद

54. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर में परीक्षा नियंत्रक/असिस्टेन्ट व डिप्टी रजिस्ट्रार/प्रोफेसर, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, एसो. प्रोफेसर एवं निदेशक, शारीरिक शिक्षा के कितने पद स्वीकृत हैं व कितने पद कब से रिक्त हैं? पदवार व तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री वासुदेव देवनानी)

(3) क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय में नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) एम.डी.एस. विश्वविद्यालय, अजमेर में स्वीकृत व रिक्त पदों की पदवार व तिथिवार सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। 01.04.2010 के बाद विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को भरने पर राज्य सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

(3) जी नहीं। विश्वविद्यालय में नवीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

एम.बी.एम. महाविद्यालय जोधपुर के संचालन में अनियमितता

55. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोल माइन माडल की वजह से एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर विश्व के चुनिंदा महाविद्यालयों में शामिल है, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन की अनदेखी के चलते माडल लम्बे समय से अंधेरे में है? यदि हां, तो किन कारणों से?

(2) क्या यह सही है कि महाविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण माडल में से तार, बल्ब व कई महत्वपूर्ण उपकरण चोरी हो गये हैं? यदि हां, तो प्रशासन द्वारा चोरी की एफ.आई.आर. किस पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय में मिनरल लैब के बिजली के तार जल जाने के कारण पिछले पांच साल से मशीनों का संचालन नहीं हो रहा है एवं छात्रों को लैब में प्रायोगिक कार्य करने के लिए तार के टुकड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे विद्युत दुर्घटनाए होने की आशंका बनी हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार कोल माइन माडल एवं मिनरल लैब को दुरुस्त करके पुन: संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कालेज प्रशासन द्वारा कोल माइन माडल को संचालित किया जा रहा है।

(2) जी हां। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर के विभागाध्यक्ष, खनन इंजी. विभाग द्वारा चोरी गए सामान सम्बन्धी रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु पुलिस थाना शास्त्री नगर, जोधपुर को पत्र प्रेषित किये गये हैं। पत्रों की छाया प्रतियां परिशिष्ट 'अ' के रूप में संलग्न हैं। थानाधिकारी द्वारा उपरोक्त पत्रांक पर कोई अभियोग पंजीबद्ध नहीं होना बताया है। थानाधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र की छाया प्रति परिशिष्ट 'ब' के रूप में संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बाड़ी (धौलपुर) में महाविद्यालय भवन हेतु आबंटित भूमि

56. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला धौलपुर के राजकीय महाविद्यालय, बाड़ी में स्वीकृत भवन निर्माण हेतु बाड़ी गांव, अलीगढ़ रोड पर अलीगढ़ के पास भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो क्या छात्र एवं छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय उचित है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि बाड़ी मुख्यालय से लगभग 7 किमी की दूरी पर है तथा आवागमन के साधन भी नहीं हैं, जबकि वर्तमान में बाड़ी नगरपालिका क्षेत्र में खसरा नम्बर 2688 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा सिवायचक जमीन सरमथुरा रोड पर अन्य भूमि उपलब्ध है तथा इसके अतिरिक्त, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाड़ी का एक पर्याप्त खेल मैदान रिक्त पड़ा है? यदि हां, तो क्या सरकार छात्र एवं छात्राओं की सुरक्षा की दृष्टि से उक्त दोनों में से किसी एक स्थान को आबंटित करने का पुन: विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त भूमि छात्र-छात्राओं की दृष्टि से उपयुक्त है।

(2) जी नहीं। उपर्युक्त भूमि बाड़ी कस्बा आबादी से लगभग 4 किमी दूरी पर स्थित है। उपखण्ड अधिकारी, बाड़ी की रिपोर्ट के अनुसार खसरा

(उच्च शिक्षा मंत्री)

नम्बर 2688 में से करीब 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 11 बी की अवाप्ति के लिये अधिसूचना जारी की गई है। शेष 4-13 बीघा भूमि में विवाद माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में भी विचाराधीन है।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाड़ी के खेल मैदान की भूमि को महाविद्यालय हेतु आबंटित किया जाना उपयुक्त नहीं होगा।

जोधपुर जिले में संचालित आयुर्वेदिक औषधालय

57. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जोधपुर में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र/औषधालय संचालित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां एवं नहीं, तो क्यों? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त औषधालयों में कार्मिकों के पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो किन-किन औषधालयों में किस-किस संवर्ग के, कितने -कितने पद रिक्त हैं? औषधालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में उन पंचायत मुख्यालयों पर जिन पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, वहां पर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी औषधालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं कहां-कहां पर व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में स्थापित पुराने आयुर्वेदिक औषधालयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत/पुन:निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर जिले में संचालित आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों की विधान सभा क्षेत्र वार सूची परिशिष्ट -क पर संलग्न है।

(आयुर्वेद मंत्री)

(2) जी हां। उपरोक्त औषधालयों/चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की औषधालयवार सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) जी हां। विभागान्तर्गत 1,945 आयुर्वेद, 292 होम्योपैथिक, 358 यूनानी चिकित्साधिकारी एवं 980 आयुर्वेद, 318 होम्योपैथिक, 307 यूनानी नर्स/कम्पाउण्डरों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर नियुक्ति की जा सकेगी।

(4) वर्तमान में राज्य सरकार के स्तर पर प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) जी हां। आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शीघ्र मरम्मत/पुनर्निर्माण कार्य किया जा सकेगा।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-26 का विवरण)

परिशिष्ट-अ

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जमवारामगढ़ में दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2012 तक आउटडोर में उपचार हेतु आये मरीजों का रोग के अनुसार एवं वर्षवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	बीमारी का नाम	वर्ष				
		दिसम्बर 2008	2009	2010	2011	2012
1	PUO (Pyrexia of Unknown Origin) फीवर	345	10097	9413	4645	17933
2	Diarrhoea (डायरिया) दस्त	277	1354	2310	1250	2811
3	Dog Bite	5	31	28	432	665
4	APD (Acid Peptic Disease) पेट में गैस	302	3264	3443	3632	5593
5	Scabies खुजली	111	1270	1537	2062	351
6	Mumps गलफडे	0	15	30	25	23
7	Worm Infestation पेट में कीड़े	87	176	209	228	318
8	Allergy	213	3244	3182	2001	1918
9	Herpies चमडी में वायरल इन्फैक्शन	0	18	13	20	31
10	Sciatica (सियाटिका) कुल्हे के पीछे की नस में दर्द	56	35	40	16	19
11	Other Diseases अन्य बीमारियां	2191	31582	32077	53464	51491
	Total	**3587**	**51086**	**52282**	**67775**	**81153**

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-32 का विवरण)

परिशिष्ट-अ

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आहोर के आउटडोर में वर्ष 2013 में आये मरीजों का माहवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है

माह का नाम	आउटडोर में आये मरीजों की संख्या
जनवरी	5565
फरवरी	6431
मार्च	6848
अप्रैल	6231
मई	6486
जून	6440
जुलाई	8158
अगस्त	8366
सितम्बर	7602
अक्टूबर	8869
नवम्बर	8729
दिसम्बर	8312
कुल योग	**88037**

परिशिष्ट-3

श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री द्वारा परिवर्तित आय-व्ययक 2014-15 में संशोधन सम्बन्धी सदन पटल पर रखा गया विवरण

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन से निवेदन करना है कि दिनांक 14 जुलाई, 2014 को जब मैं परिवर्तित बजट वर्ष 2014-15 का सदन में उपस्थापन कर रही थी, तत्समय बोलते समय कुछ आंकडों विषयक निम्न अशुद्धियां रह गईं :-

पैरा संख्या 43 की पांचवीं लाइन में अंकित ''289 करोड़ रुपये'' के स्थान पर ''290 करोड़ रुपये'' बोला गया;

इसी पैरे के पृष्ठ 19 की सातवीं लाइन में ''जलापूर्ति योजना भीमनी'' से आगे शब्द ''जिला झालावाड-लागत 30 करोड़ 80 लाख रुपये'' बोलने से रह गये;

इससे अगली लाइन में अंकित ''87 लाख'' के स्थान पर ''88 लाख'' बोला गया;

पृष्ठ संख्या 45 की चौथी और पांचवीं लाइन ''रैन बसेरा झालावाड़ को 2 करोड़ 24 लाख रुपये की लागत से विकसित किया जायेगा'' नहीं बोला गया;

पैरा 125 की दूसरी लाइन में अंकित ''6 करोड 25 लाख रुपये'' के स्थान पर ''करोड रुपये'' ही बोला गया; व

पृष्ठ संख्या 70 पर अंकित पैरा संख्या 207 ''झालावाड़ में जिला न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों एवं अभिभाषकों हेतु आधुनिक सुविधायुक्त पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी।'' बोलने से रह गया।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार बोलते समय मुद्रित पुस्तक से भिन्न रही त्रुटियों को, जिनका मैंने उल्लेख अभी किया, मुद्रित बजट भाषण के अनुरूप संशोधित करवाने की कृपा करें।

वसुन्धरा राजे
मुख्य मंत्री